छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **षोडश सत्र**

गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023

(फाल्गुन 25, शक सम्वत् 1944)

[अंक 09]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 16 मार्च, 2023

(फाल्गुन 25, शक् संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राज्य परियोजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा 01 जनवरी, 2020 से महाविद्यालयों को आवंटित राशि और व्यय

[उच्च शिक्षा]

1. (*क्र. 579) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कार्यालय राज्य परियोजना,राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा 01 जनवरी,2020 से कुल कितनी राशि,किस-किस मद में कौन-कौन से कार्य के लिए महाविद्यालयों को आबंटित की गई है? **(ख)** उक्त आवंटित राशि अथवा उसके व्यय, उपयोग के संबंध में अनियमितता की कितनी शिकायतें हैं? इन शिकायतों पर किसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : **(क)** कार्यालय राज्य परियोजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा 01.01.2020 से कुल राशि रूप. इक्यासी दशमलव तीरानवे करोड़ महाविद्यालयों को आबंटित की गई है। जिसमें से नवीन निर्माण रेनोवेशन/उन्नयन एवं उपकरण क्रय हेतु महाविद्यालय अद्योसंरचना विकास मद में राशि रू. तीन हजार एक सौ दो दशमलव अठयासी लाख रू., भवन निर्माण एवं उपकरण क्रय हेतु आदर्श महाविद्यालय की स्थापना मद में राशि रू. चार हजार आठ सौ चालीस दशमलव सोलह लाख रू. तथा हार्ड एवं साफ्ट कम्पोनेंट हेतु स्वशासी महाविद्यालय की गुणवत्ता एवं उत्कृठता उन्नयन मद में राशि दो सौ पचास लाख रू. आबंटित किये गये। महाविद्यालयवार विवरण **प्रपत्र पर संलग्न**[1] है। **(ख)** कोई शिकायतें प्राप्त नहीं है। शेष के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[1] परिशिष्ट "एक"

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर पढ़ा है । मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास पूर्व में कोई शिकायत लंबित है या अभी कोई शिकायत लंबित है । क्या उसकी जांच कराकर कार्रवाई कराएंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न लगाया है वह 2020 से लेकर अभी तक का है । 2020 से लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं है लेकिन हां, आपने एक साल पहले भी प्रश्न लगाया था, उस समय 2017 से 2020 का पूछा था, उस समय की एक शिकायत है, 5 कॉलेजों के लिए शिकायत प्राप्त हुई है और उसमें जांच चल रही है, बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होगी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जांच में अगर दोषसिद्ध पाया गया तो कार्रवाई कराएंगे उसके ऊपर ?

श्री उमेश पटेल :- जी हां, बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे और आपको उसका अपडेट भी देंगे ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- धन्यवाद् ।

<u>खुज्जी वि.स. क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत स्टेडियम एवं खेल मैदान का निर्माण</u>

[खेल एवं युवा कल्याण]

2. (*क्र. 1168) श्रीमती छन्नी चंदू साहू : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2020 से फरवरी 2023 तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कितने स्टेडियम एवं खेल मैदानों का निर्माण कराया गया है ? विभाग द्वारा कहां-कहां व कौन सी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? वर्षवार, विकासखण्डवार बतायें ? **(ख)** कंडिका"क"अंतर्गत क्या विभाग द्वारा पूर्व निर्मित स्टेडियम एवं खेल मैदानों का जीर्णोद्धार किया गया है ?यदि नहीं, तो कब तक जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किया जायेगा ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्टेडियम एवं खेल मैदान का निर्माण नहीं कराया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[2] अनुसार है। **(ख)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कोई स्टेडियम एवं खेल मैदान नहीं है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि विभाग द्वारा कहां-कहां और कौन सी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है । जिसमें मंत्री जी द्वारा क्रमांक 1 से 8 तक जानकारी दी गई है । सातवें नम्बर पर विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल आयोजन ।

[2] परिशिष्ट "दो"

ग्राम पंचायत खुर्सीटिकुल विकासखंड छुरिया । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कौन से मद की राशि का आहरण किया गया और कितनी राशि खर्च की गई ?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न लगा है कि कौन कौन से खेल कराए गए और कब कराए गए ? अभी अगर मैडम एक-एक खेल में कितना पैसा लगा यह जानना चाहती हैं, तो मैं इन्हें उपलब्ध करा दूंगा ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह तो बता सकते हैं कि कौन से मद की राशि का वहां उपयोग किया गया ?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है । हमने आठ बिंदुओं की जानकारी दी है । उसमें से 2 छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का है और बाकी सब खेल विभाग द्वारा आयोजित है । खेल विभाग द्वारा जो आयोजित है उसका डेटा हमारे पास है और जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खर्च हुआ है वह नगरीय निकाय और पंचायत द्वारा खर्च किया गया है । हम लोग उसका डेटा लेकर आपको बता देंगे ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- अध्यक्ष महोदय, कम से कम उस योजना का नाम तो पता होगा कि कौन सी योजना के तहत् उस राशि का आहरण किया गया । मैं योजना का नाम जानना चाहती हूं ?

अध्यक्ष महोदय :- जब खेल ही हुआ है तो खेल हुआ होगा ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, खेला हो गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह ज्वाइंट रिस्पॉसिबिलिटी है । माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि इसका उत्तर आएगा तब बताऊंगा । जब वह प्रश्न लग चुका है उत्तर के लिए खड़े हो चुके हैं तो संयुक्त जिम्मेदारी के तहत् उनको उत्तर देना चाहिए ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न लगा है इसमें कहीं पर भी आवंटन का प्रश्न नहीं है । आप प्रश्न को देखिए ना । आप मंत्री रहे हैं आप भी जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- खर्च का प्रश्न नहीं है, खेलकूद के बारे में है ।

श्री उमेश पटेल :- आप प्रश्न देखिए, उसमें कहीं भी आवंटन का उल्लेख नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको क्या कहना है, वह कह दीजिए ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने नहीं बताया है तो मैं बता देती हूं । स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना की जो राशि जनपद पंचायत में रहती है । उसी के तहत् खेल किया गया है । शासन का नियम है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में मात्र एक लाख तक की राशि का आहरण किया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए इस योजना की राशि का स्वार्थपूर्ण बंटवारा करते हुए साढ़े चार लाख की राशि का आहरण किया गया है । यह सही है या गलत है । या तो शासन का यह आदेश गलत है या जनपद पंचायत ने गलत तरीके से इस योजना के मद से आहरण किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ ओलंपिक में सब चल सकता है ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जोन स्तर में और ब्लॉक स्तर पर हुआ है उसके लिए पंचायत विभाग ने पैसा रिलीज किया है और अलग-अलग मदों के द्वारा किया गया है । जितना खर्च हुआ, उतना सरकार ने उसमें देने का काम किया है । अगर किसी तरह की शिकायत है आपको, तो आप मुझे दे दीजिए मैं उसमें जांच करवा दूंगा ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं सारे बिल वाऊचर लाई हूं । आप कहेंगे तो मैं आपके टेबल पर रख दूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे टेबल पर नहीं, मंत्री जी को दीजिए, वे जांच करा देंगे।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- जी। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि क्या इस सदन के माध्यम से जो गलत किए हैं, उनके उपर कार्रवाई करेंगे, जांच कमेटी बैठायेंगे ? मैं यह जानना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कार्रवाई करेंगे। कर देंगे भई, साढ़े चार लाख का मामला है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी तरह की शिकायत है तो आप मुझे दे दीजिए। मैं जांच करवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- जांच भी करवा देंगे, कार्रवाई भी करेंगे।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- मंत्री जी, आप सदन के अंदर घोषणा कर दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- और कैसे करूं ? मैं क्या बोल रहा हूं। (हंसी)

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- जांच करायेंगे करके बोल दीजिए ना।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- आप दे दीजिए, आप जैसे ही देंगे, हम जांच करा देंगे।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- धन्यवाद।

<u>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में प्राप्त राशि व व्यय</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. (*क्र. 1065) श्री नारायण चंदेल : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 15 फरवरी, 2023 तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? **(ख)** प्राप्त राशि में से कितनी कितनी राशि, किन-किन कार्यो अथवा दवाई/उपकरण खरीदी में खर्च की गई ? **(ग)** क्या प्रश्नांश 'ख' में व्यय राशि एवं कार्यो के

संबंध में अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"**[3] अनुसार। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"**अनुसार।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के प्राप्त राशि उसकी अनियमितताएं और व्यय के संदर्भ में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने उत्तर क, ख, ग, तीनों में लिखा है कि परिशिष्ट में संलग्न है। 'ख' के उत्तर में परिशिष्ट चार के प्रपत्र 'ब' में मदवार कॉलम दो में दवाई एवं कॉलम तीन में उपकरण के व्यय राशि के अतिरिक्त खर्च, राशि के कॉलम एक में लेख है जो कि दवाई और उपकरण दोनों खरीदी से अत्यधिक ज्यादा व्यय को दर्शाता है, नंबर एक। माननीय मंत्री जी, दवाई और उपकरण को छोड़कर कॉलम एक में उल्लेखित अन्य व्यय क्या है, यह कृपया बता दीजिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉलम एक के व्यय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो, राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता विकृति नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम और एग्जाई जो खर्च हुआ है, इसमें कई राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो दिया हुआ है। चाहें तो मैं पढ़ दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं मत पढ़िए।

श्री नारायण चंदेल :- कुछ तो परिशिष्ट में है, कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी, इसमें महासमुंद जिले का विस्तार से उल्लेख नहीं है, आपने केवल व्यय राशि बताया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्यय राशि एवं कार्यों के संबंध में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में परिशिष्ट चार के प्रपत्र 'स' में उल्लेखित क्रमांक चार जिला महासमुंद के संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को जांच करने हेतु पत्र प्रेषित करने का उल्लेख है। यह पत्र कब प्रेषित किया गया है और जांच कमेटी बनी है, जांच कब तक पूरी हो जाएगी ? शायद मुझे बताया गया है कि आपने इसमें पहले भी कार्रवाई की है। अगर इसमें अनियमितता हुई है, ऐसा आपको लगता है तो क्या इसकी पुन: जांच करायेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जी, अध्यक्ष महोदय। जांच चल भी रही है, इसमें जो आयेगा कार्रवाई करेंगे। कोई भी और जानकारी होगी तो अवश्य जानकारी मिलने पर जांच करायेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि परिशिष्ट में जवाब आया है, वर्ष 2022-23 में व्यय राशि दवाई एवं उपकरण व्यय को छोड़कर राष्ट्रीय

[3] परिशिष्ट "तीन"

रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, रेबीज की बहुत चर्चा हो रही थी कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। इसमें 26 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है। दवाई नहीं खरीदी गयी है। उपकरण नहीं खरीदा गया है। 26 लाख का व्यय हुआ है किसी और चीज में व्यय हुआ है। यहां तो बोल रहे थे कि रेबिज का टीका उपलब्ध है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, दवाई उपलब्ध है। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की कोई बात नहीं है। स्टॉक में रहा होगा, इसलिए अतिरिक्त क्रय नहीं किया गया है। उसका प्रावधान रखा गया है।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक और छोटी सी बात है। राष्ट्रीय बर्न एवं एंजुरी रोकथाम एवं प्रबंधन कार्यक्रम में पिछले दो वर्ष में एक रूपये भी खर्च नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई बर्न नहीं होता क्या या छत्तीसगढ़ में बर्न व्यवस्था नहीं की जाती ? क्यों इस मद में एक रूपया भी खर्च नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय :- कोई जला ही नहीं होगा तो कहां से करेंगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, जरूरत के हिसाब से खर्च होता है। माननीय सदस्य के पास में ऐसी जानकारी है कि कोई पेसेंट आए थे और उनका उपचार नहीं हो सका तो बता देंगे, उसको भी दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अनिता योगेन्द्र शर्मा जी।

<u>रायपुर जिले अंतर्गत नशीली टेबलेट साल्यूशन जैसे पदार्थो के विक्रय की रोकथाम हेतु कृत कार्यवाही</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क्र. 1057) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर जिले अंतर्गत कुल कितने ड्रग इंस्पेक्टर कार्यरत हैं ? वर्ष 2022 से जनवरी, 2023 तक नशीली टेबलेट साल्यूशन जैसे पदार्थो के विक्रय के रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई? विकासखंडवार संस्थावार जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : रायपुर जिले अंतर्गत कुल 08 ड्रग इंस्पेक्टर कार्यरत है। वर्ष जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक नशीली टेबलेट साल्यूशन जैसे पदार्थो के मेडिकल स्टोर्स से अवैध विक्रय के रोकथाम के लिये विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण किये जाते है एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् नियमतः कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त अवधि में नशीली दवाओं के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम

1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् कुल 38 निलंबन एवं 07 निरस्तीकरण किया गया है। विकासखंडवार संस्थावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[4] अनुसार।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया गया है। उत्तर में यह जानकारी दी गई है कि वहां पर नशीली दवाइयां बेची जा रही थीं और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो लोग नशीली दवाइयां बेचते हैं उनको ड्रग इंसपेक्टर के द्वारा खानापूर्ति के लिए 2-3 दिन के लिए निलंबित किया गया है इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि क्या आप ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि किसी कार्रवाई में कहीं कोई कमी पाई जाएगी तो उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। यह गंभीर मामला है क्योंकि पूरे प्रदेश में कुल 12,281 निरीक्षण हुए हैं। यदि कहीं ऐसी कोई बात हो या कहीं कोई शिकायत हो कि किसी अधिकारी की कार्यशैली में कोई कमी पाई जा रही हो या अनियमितता हो तो माननीय सदस्य मुझे इसकी जानकारी दे देंगे। उस पर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर बहुत ज्यादा नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं। हम लोगों ने अधिकारियों से इसकी कई बार शिकायतें भी की हैं लेकिन यदि वह दुकान बंद करवाते हैं या उनको 1-2 दिन के लिए निलंबित करते हैं तो इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर तत्काल कार्रवाई करें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनका नाम भी ले लूंगा। ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत् और बाकी जो नियमावली बनी है, उसमें कार्रवाई का जो प्रावधान है उसमें कहीं भी यह उल्लेखित नहीं है कि कितने दिन के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। जो जवाब आया है उसमें भी लिखा है कि उनको 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया और कुछ दुकानों को निरस्त भी किया गया। उनको वॉर्निंग दी जाती है और उनको 7 दिन के लिए निलंबित किया जाता है लेकिन यदि उसके बाद भी दवाई दुकान में वही कमी पाई जा रही है तो निश्चित रूप से हम निरस्तीकरण की कार्रवाई की तरफ भी जाएंगे। यदि अधिकारी-कर्मचारी की तरफ से भी कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उनपर भी जरूर कार्रवाई होगी।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- धन्यवाद, मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। ममता चंद्राकर जी।

---

[4] परिशिष्ट "चार"

प्रश्न संख्या 05 : xx xx

अध्यक्ष महोदय :- गुलाब कमरो जी।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला में आबकारी विभाग से पंजीकृत क्लब के विरूद्ध प्राप्त शिकायत

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

6. (*क्र. 455) श्री गुलाब कमरो : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में कितने क्लब संचालित हैं? **(ख)** क्या संचालित क्लब के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है? एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : **(क)** जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 01 क्लब संचालित है। **(ख)** जी हां,संचालित क्लब के विरूद्ध कुल 03 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों की जाँच किये जाने पर 02 शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई तथा 01 शिकायत सही होना पाया गया, जिसमें आबकारी नियमों के तहत् लायसेंस शर्त का उल्लंघन होना पाये जाने पर विधिवत् विभागीय प्रकरण दर्ज करते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से क्लब से संबंधित जानकारी चाही थी कि मेरे जिले में कितने क्लब संचालित हैं और उनकी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं इसपर माननीय मंत्री जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि हमें 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन 3 शिकायतों में से 1 शिकायत सही व 2 शिकायतें सही नहीं पाई गई हैं। मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि ये तीनों शिकायतें सही हैं क्योंकि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है और मैं इन क्लबों को पार करके अपने घर जाता हूं। वह क्लब नेशनल हाईवे में हैं। वह 10-20 मीटर दूर नहीं हैं। जहां पर ये क्लब संचालित होते हैं वहां पर नेशनल-हाइवे में गाड़ियां खड़ी होती हैं। उन्होंने क्लब के नाम से लाइसेंस लिया और बकायदा 2 साल तक बार का बोर्ड लगाकर उसको संचालित किया। उन्होंने मध्यप्रदेश से दारू लाकर वहां पर लगातार धंधा किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंता हूं कि यदि जांच की शिकायत सही पाई गई हैं तो क्या आप उनका लाइसेंस निरस्त करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि उनके जिले में कुल कितने क्लब हैं तो उनके पूरे जिले में केवल 1 ही क्लब हैं। इसकी जानकारी उनको दी गई है। हमें उनकी 3 शिकायतें मिलीं, 3 शिकायतों में से 2 शिकायतें सही नहीं पाई गईं और 1 शिकायत

सही पाई गई है और उनको हमारे आधिकारिक स्तर से नोटिस दी गई है। उनके नोटिस का जवाब अभी-अभी आया है। इस पर हमारे कमिश्नर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जब जांच पूरी होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 महीने हो गये।

अध्यक्ष महोदय :- आप अकेले हैं, आप उनको मत घेरिये। चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध है कि यहां पर माननीय मंत्री जी के सचिव, विभागाध्यक्ष बैठे हैं, आप उनके साथ कमरो जी को बैठा दीजिए और कमरो जी जो चाहेंगे, उसको वह करवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आज आप उनको करने दीजिए। आज वह कोशिश कर रहे हैं।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 महीने हो गये, क्या वह 2 साल से हमारे अधिकारियों को नहीं दिखा ? वहां पर लगातार शिकायतें आती रहीं और लगातार पुलिस उस पर कार्रवाई करती रही तो क्या विभाग सो रहा था ? मैं आपके माध्यम से चाहूंगा और चूंकि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। मैं स्वयं भी शराब नहीं पीता। (हंसी) मेरा क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है। वहां के लोगों को क्लब की आवश्यकता नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लब से जो सदस्य हैं, उसमें गुरूजी, इंजीनियर, पटवारी जैसे पढ़े-लिखे लोग हैं । आप पूछेंगे तो उन सदस्यों में से किसी को जानकारी नहीं है । क्लब में आधार कार्ड लेकर सदस्य बनाया गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उस क्लब का लायसेंस निरस्त करेंगे ? क्योंकि शिकायत सही पाई गई है और उसमें लीपापोती की गई है । मेरे पास पूरी जानकारी है । दो साल से बार का बोर्ड लगाया गया है । आपके विभाग का जो मापदण्ड है, उसका पालन नहीं किया गया है। स्वीमिंग पुल नहीं है । जब अभी शिकायत हुई है तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है । आपके अधिकारी चश्मा लगाकर भी नहीं देख पाते कि क्या कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है । उसको पार करके मैं अपने घर में जाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- कमरो जी, आप आराम से प्रश्न पूछिए कि मंत्री जी प्रश्न समझ जाएं ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वह क्लब नेशनल हाईवे में है, क्लब वहां से 10 मीटर दूर भी नहीं है । सारी गाड़ियां नेशनल हाईवे में खड़ी होती हैं । मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस लायसेंस को निरस्त करेंगे क्या ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत दुखी है। उनकी कोई आपसी लड़ाई होगी, ऐसी मुझे जानकारी मिली है ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या हो गया ?

श्री कवासी लखमा :- उनकी राजनीतिक आपसी लड़ाई है । उसे मैंने आपके ध्यान में लाया है । वहां जो क्लब चल रहा है, उसको निरस्त करना है या क्या करना है, उसके खिलाफ एक महीने के अंदर कार्रवाई करूंगा । आपको एक महीने के अंदर जानकारी मिलेगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपत्तिजनक है कि मैंने सुना है कि आपसी लड़ाई है । प्रश्नकर्ता के ऊपर आरोप है । ऐसा नहीं होना चाहिए। मजाक अलग बात है ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी कोई आपसी लड़ाई नहीं है । मैं न्याय संगत बात कर रहा हूं । मेरी किसी से द्वेष नहीं है, किसी से आपसी लड़ाई नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक मिनट बैठ तो जाओ, एक मिनट तो रूक जाईए। मैं कह रहा हूं कि आप जल्दी-जल्दी प्रश्न मत करिए । धीरे-धीरे प्रश्न करिए कि मंत्री जी समझ जाएं । शराब की चर्चा हो रही है तो आप आराम से प्रश्न करिए न ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न यह है कि आपसी लड़ाई का कोई मामला नहीं है । वहां का जो आम जनमानस है, वहां के लोगों की मांग है । मैं खुद भी उस विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरा स्पष्ट कहना है कि कोई आपसी लड़ाई का मामला नहीं है । तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो आपका विभाग दो साल तक क्या कर रहा था ?

अध्यक्ष महोदय :- आप कह रहे हैं कि तीन क्लब चल रहा है और मंत्री जी कह रहे हैं कि एक क्लब चल रहा है ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्लब चल रहा है, लेकिन शिकायत तीन हुई है । एक व्यक्ति शराब का बोतल लेकर कलेक्टर कार्यालय में बैठ गया । उससे मेरे विधान सभा क्षेत्र की छवि खराब हो रही है । चुनाव का समय आ गया है । चूंकि मेरे विधान सभा का मामला है । वहां पर जिला मुख्यालय है, कलेक्टर कार्यालय है । मैं माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि क्या आप उसके लायसेंस को निरस्त करेंगे क्या ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां तीन शिकायत मिली है, उसमें से एक शिकायत सही पायी गयी है, उसकी रिपोर्ट आ गई है । हम उसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे और लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसका लायसेंस निरस्त भी करेंगे, आपने ऐसा कहा ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निरस्त भी करेंगे ।

(श्री शैलेश पांडे के हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- उनके जिले का मामला है, उनको प्रश्न करने दीजिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मध्यप्रदेश से अवैध शराब लाकर बेचने का मामला है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो ढाबे और होटल संचालित है, वहां मध्यप्रदेश से लगातार शराब आ रही है, वह लगातार बिक रही है । उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि एक सुचित्रा दास है, जो हाईवे ढाबा की संचालिका है । वह सीधी-सीधी न्यूज़ चैनल में बोल रही है । (मोबाईल दिखाकर बोलते हुए)

अध्यक्ष महोदय :- मोबाईल नीचे रखिए न ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहेंगे तो मैं पटल पर रख दूंगा । वह बोल रही है कि अन्य जगह शराब बिकना बंद हो जाएगी तो मैं भी अपने ढाबा में शराब बेचना बंद कर दूंगी । ऐसे अवैध ढाबे और होटल हैं, जहां मध्यप्रदेश से लगातार शराब आकर बिक रही है क्योंकि वह बार्डर एरिया है । ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आपसे अनुरोध है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। पर्टिक्यूलर सिर्फ बार का मामला है । गुलाब कमरो जी ने जो आपत्ति किया है, उसके खिलाफ एक महीने के अंदर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- वे कह रहे हैं कि उस पर जांच करवा दीजिए ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश होगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा । अगर उस क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही होगी तो उसकी भी जांच करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- मध्यप्रदेश बार्डर एरिया से **(xx)**[5]

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये न, मनेन्द्रगढ़ और जनकपुर दोनों मध्यप्रदेश से लगे हुए हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- मेरे एरिया में **(xx)**

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मैं समझा देता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- मध्यप्रदेश के **(xx)** का जो नाम उल्लेखित किया गया है, उसको विलोपित करवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- कहां उल्लेख किया ?

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं अभी किया हूं।

श्री सौरभ सिंह :- ये नाम लिए हैं। उसको विलोपित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- उसको विलोपित कर दिया।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, आप उसको विलोपित करवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- विलोपित कर देंगे।

---

[5] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारा बार्डर एरिया है।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, मध्यप्रदेश की स्थिति यह है अगर वहां से दारू, शराब आ रहा है, वहां नियंत्रित करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी, आप बैठिये, ऐसा नहीं। एक मिनट, आप बैठिये। मैं आपको समय दे रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको समय दे रहा हूं। प्लीज आप बैठिये।

श्री अमरजीत भगत :- अगर वहां से अवैध शराब ..(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यहां की सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि कोई पंजाब से ले आये, कोई उड़ीसा से ले आये और यहां की पुलिस और सरकार इतनी निकम्मी हो गई है।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, बैठिये। मंत्री जी पहली बार खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। आप लोग उनको दाद देने के बजाय उनको मत उलझाइये।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, फूल दाद है।

श्री सौरभ सिंह :- फूल दारू है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इस तरफ (विपक्ष) भी बोल रहा हूं और इस तरफ (सत्तापक्ष) भी बोल रहा हूं। मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, उनको करने दीजिये। अकेले जवाब दे रहे हैं। उनके आजू-बाजू मे कोई नहीं हैं। उनके थोड़ा सा शांति से सुनिये।

श्री अमरजीत भगत :- He is very confident. बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विन्रम अनुरोध है चूंकि वह मध्यप्रदेश का बार्डर एरिया है, वहां वहां के माफिया से लगातार शराब लाकर वहां के ढाबे और होटल में अवैध बेचते हैं। उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कड़ी कार्रवाई करवा दीजियेगा, जांच करवा दीजियेगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुचित्रा दास एक ढाबा संचालक है, उसकी इतनी हिम्मत है कि वह मीडिया में बोल रही है कि बाकी जगह का अवैध शराब बंद करवा दें, जो मध्यप्रदेश से आ रहा है तो मैं भी बंद कर दूंगी। तो जो ऐसे ढाबा संचालक हैं।

अध्यक्ष महोदय :- पहले आप यह बताईये कि वह ढाबा संचालक महिला है या पुरूष है ?

डॉ. विनय जायसवाल :- महिला है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे प्रश्न उद्भुत नहीं होता है। आपका निर्देश है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, यदि ऐसा होगा तो उसके ऊपर कार्यवाही होगा।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वह बिहान योजना की मितानीन है।

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वह बिहान योजना के तहत चल रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 3 नोटिस दिया गया है और एक शिकायत सही पाया गया और उसको नोटिस देने की बात की है। जो शिकायत सही पाई गई वह किस प्रकार की शिकायत थी ? एक यह बता दीजिये। दूसरा, जो बार संचालक है, वह बार लायसेंस किसके नाम से बना है, यह बता दीजिये। क्योंकि हमारी जानकारी में स्थिति यह है कि वहां गैंगवार की स्थिति बनी हुई है। दो बड़े राजनेता शराब के अवैध व्यवसाय को लेकर लड़ रहे हैं और दोनों नेता सत्तारूढ़ पार्टी से रिलेटेड हैं। (शेम-शेम की आवाज) इसलिए यह स्थिति बनी हुई है। तो बार लायसेंस किसके नाम से है, दूसरा, जो शिकायत सही पाया गया है, वह शिकायत क्या है, यह बता दीजिये।

श्री कवासी लखमा :- उसका नाम ग्रीन पार्क है।

श्री शिवरतन शर्मा :- लायसेंस के मालिक नाम ?

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट भईया, इतनी बारीक में मत जाईये। शर्मा जी, आपको एक बार बोल रहा हूं, बात को समझिये।

श्री कवासी लखमा :- शशिधर जायसवाल। और कुछ बताना है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- शिकायत किस प्रकार की है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चन्द्राकर जी।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे का मैं बता देता हूं, यह शशिधर जायसवाल वही है, जिनके यहां **(xx)**[6] परसो टिमरी गये थे और उनके घर कॉफी पीये थे। ये वही शशिधर जायसवाल है। **(xx)** और रायपुर के एक नेता **(xx)** ये दोनों वहां गये हैं। **(xx)** परसो जाकर चाय पीकर आये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- देखिये सर, ये नाम विलोपित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- क्या विलोपित होना चाहिए,

डॉ.(श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- सब बात आप ही लोगों की मर्जी से विलोपित होगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, नहीं मैंने नाम पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप ही उकसाते हो।

डॉ.(श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- आप लोगों का नाम आयेगा तो विलोपित, विलोपित बोलते हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, ये ही तो नाम पूछा है इसलिए उसने नाम बता दिया। नाम नहीं बताना चाहिए क्या ? खुद कन्फ्यूज हो रहे हैं। (व्यवधान)

---

[6] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- विलोपित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं विलोपित कर दूंगा।

डॉ.(श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- अब इनकी नहीं चलेगी।

श्री सौरभ सिंह :- वह चाय पीने के लिए गए थे, अनुरोध करने गये थे। (व्यवधान)

डॉ.(श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- पहले आरोप लगाये कि दो कांग्रेसी हैं, जब भा.ज.पा. वाले का नाम लेंगे तो गलत हो गया। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- वह कहने गये थे कि अवैध संचालन मत करो, सरकार ने शराब बंदी का नारा दिया है।

श्री उमेश पटेल :- **(xx)** का बार संचालक से क्या रिश्ता है ? यह पता करना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, हो गया।

डॉ. विनय जायसवाल :- नंदकुमार साय जी का वीडियो पटल पर रख देता हूं, वहां से चाय पीकर आये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, शराब का मामला है, इसमें सब लोग एक साथ मत झूमिये । माननीय चन्द्राकर जी आप खड़े हो जाईये, आपका प्रश्न है ।

<u>प्रदेश में रोजगार व पंजीकृत बेरोजगार</u>

[कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

7. (*क्र. 406) श्री अजय चन्द्राकर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के रोजगार पंजीयन कार्यालयों में कितने पंजीकृत नवीन रोजगार चाहने वाले एवं रोजगार बदलने वालों द्वारा पंजीयन कराया गया है? वर्ष 2019-20 से लेकर 2022-23 तक वर्षवार अलग-अलग बतायें? इन वर्षो में बेरोजगारी दर क्या थी? तथा बेरोजगारी दर की किस आधार पर, किन-किन संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट दी गयी थी? **(ख)** विभाग द्वारा रोजगार हेतु क्या-क्या आयाम तय किये गए हैं और किन-किन आयामों में कुल कितने पंजीकृत रोजगार चाहने या रोजगार बदलने वालों को रोजगार दिया गया है? **(ग)** क्या सीएमआईई (सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकानोमिक) के आंकड़ों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वीकार या मान्यता दी गयी है ? यदि हां तो इस संस्था ने किस आधार पर मूल्यांकन किया है और बेरोजगार की परिभाषा क्या दी है? तथा इनके विज्ञापनों पर कितनी राशि व्यय की गयी है और दिनांक 31/1/2023 की स्थिति में कितना प्रतिशत बरोजगारी दर है और 0.4 प्रतिशत बेरोगारी दर

के हिसाब से राज्य में कितने लोग बेरोजगार हैं ? यदि नहीं तो विज्ञापन में व्यय की गयी राशि को क्या वापस लिया जायेगा ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : **(क)** प्रदेश के रोजगार पंजीयन कार्यालयों में दिनांक 07 फरवरी, 2023 की स्थिति में नवीन रोजगार चाहने वाले 1878126 व्यक्ति पंजीकृत है, प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में रोजगार बदलने वालों का पृथक से पंजीयन नहीं किया जाता है। वर्ष 2019-20 से लेकर 2022-23 तक वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[7] **अनुसार** है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पृथक से बेरोजगारी दर निर्धारित नहीं की जाती है, परन्तु सीएमआईई संस्था द्वारा बेरोजगारी दर की आंकड़े प्रसारित किये जाते हैं, जिसके अनुसार इन वर्षों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर संबंधी आंकड़े **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रोजगार हेतु पृथक से कोई आयाम तय नहीं किये गये है तथापि शासकीय क्षेत्र में रोजगार, अशासकीय क्षेत्र में रोजगार अथवा स्वरोजगार के रूप में रोजगार कतिपय आयाम हो सकते है। प्रदेश के जिलों के जिला प्रशासन द्वारा रोजगार मिशन पोर्टल में शासन द्वारा प्रदत्त रोजगार को दर्ज किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 33333 व्यक्तियों को शासकीय संस्थाओं में रोजगार, 50725 व्यक्तियों को अशासकीय संस्थाओं में रोजगार एवं 509559 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान किया गया है। **(ग)** छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीएमआईई (सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकानोमिक) के आंकड़ों को मान्यता नहीं दी गई है, परन्तु आर्थिक विश्लेषण एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्था होने के कारण इस संस्था की जानकारी को सामान्य रूप से मान्य किया जाता है। संस्था द्वारा दी गई बेरोजगारी के परिभाषा एवं मूल्यांकन का आधार उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका प्रिंटआउट **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा राशि व्यय नहीं की गई है, परन्तु जनसंपर्क विभाग द्वारा किये गये व्यय की जानकारी संबंधी प्रिंटआउट **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है। 31.01.2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.5 प्रतिशत है। सीएमआईई द्वारा सेंपल सर्वे के आधार पर केवल बेरोजगारी का अनुमानित प्रतिशत बताया जाता है। सेंपल सर्वे के आधार पर बेरोजगारोंकी संख्या बताना संभव नही है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी । माननीय अध्यक्ष जी, कल और आज में एक विशेष स्थिति बन रही है, मैं उस विशेष स्थिति में एक मिनट में आपको बताना चाहूंगा कि...।

अध्यक्ष महोदय :- सर, आपको तो वैसे प्रश्न ही करना चाहिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्न ही करूंगा । प्रश्न से रिलेटेड है । कल एक माननीय मंत्री जी ने मेरे ध्यानाकर्षण में कहा कि मैं पेपर में पढ़कर संज्ञान लिया

---

[7] परिशिष्ट "छ:"

हूँ । आज इस उत्तर में इन्होंने एक संस्था का नाम दिया है, CMIE संस्था द्वारा बेरोजगारी दर के आंकड़े प्रसारित किये जाते हैं । यद्यपि सरकार इस आंकड़े को मान्यता नहीं देती, यह नीचे लिखते हैं । हम प्रश्न के उत्तर में किसी प्रायवेट सर्वे का उल्लेख शासकीय तौर पर कर सकते हैं और एक प्रायवेट सर्वे के रिपोर्ट में यहां बहस कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है । इसमें उन्होंने ही लिखा है, कल एक मंत्री जी ने कहा है कि मैं पेपर के आधार पर जांच कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोड़िये आप इस पर आईये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसी में बताईये कि प्रायवेट संस्था के सर्वे पर सरकार बोल रही है, उसको मान्यता नहीं देते और उसका उत्तर में उल्लेख है कि इसके बेरोजगारी आंकड़े को प्रसारित...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री महोदय ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसको क्लियर कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- जानकारी तो ले लूँ । एक बात है, संस्था को मान्यता नहीं देना और संस्था के आंकड़ों का सरकार के द्वारा उपयोग करना दोनों अलग-अलग मामला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रायवेट संस्था ।

अध्यक्ष महोदय :- समझ गया ना । संस्था को मान्यता नहीं मिला है या नहीं दिया है, यह शासन का है । उसके आंकड़ों को शासन जरूरी समझता है, यहां बताना चाहते हैं तो मंत्री जी से पूछ लेता हूँ ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न लगा है, मैं चाहूंगा कि आप इस पर पढ़ लें । उसके (ग) में इन्होंने स्पेश्यली नाम के साथ पूछा है, उस चीज को नाम के साथ पूछा है, इसलिये उस उत्तर में प्रायवेट संस्था का नाम देना अनिवार्य है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, ठीक है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नाम मैंने नहीं पूछा है । इस संस्था का उल्लेख यह सरकार बार-बार करती है। आप मुझे यह बताईये कि...।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न है कि क्या CMIE के आंकड़ों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वीकार या मान्यता दी गई है । यदि हां तो इस संस्था ने किस आधार पर मूल्यांकन किया है और बेरोजगार की परिभाषा क्या दी है ? आपने पूछा है तो इसलिये बता रहे हैं कि वह आया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे अब यह पूछा हूँ कि इन्होंने कहा है कि वह आंकड़े प्रसारित करती है । यह बार-बार इस संस्था का उल्लेख करते हैं, इसके पहले भी प्रश्न के उत्तर में उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी मान्यता उनके आंकड़ों को नहीं देती है । मेरा मुख्य विषय जानने का यही है कि सरकार जिसको मान्यता नहीं देती है, क्या उसका उल्लेख बार-बार कर सकती है, क्या हम उसमें बहस कर सकते हैं ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, मैं उनसे नहीं जानना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इसमें मंत्री जी की मदद ले रहा हूँ, आपको आपत्ति है । मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिये मंत्री जी की मदद ले रहा हूँ । उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल नहीं है । मंत्री जी ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 9 साल से NSSO यह एक संस्था हुई करती थी, इसे नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाईजेशन बोलते थे । यह आर्गेनाईजेशन पहले केन्द्र सरकार के तरफ से हर राज्य के लिये बेरोजगारी आंकड़ा प्रस्तुत करती है, लेकिन पिछले 9 साल से उसको बंद कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, अभी किसी भी प्रदेश का सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं होता है । अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक ही संस्था है, प्रायवेट संस्था है, जो बेरोजगारी आंकड़ा प्रस्तुत करती है] उसके अलावा और कोई संस्था नहीं है । उसके द्वारा जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, हम उसको मान्यता नहीं देते हैं । अध्यक्ष महोदय, आप उसको कहीं न कहीं कोड करेंगे । अगर उसमें बेरोजगारी का आंकड़ा आया है तो हम उसको कोड करते हैं और यही मेरे उत्तर में है ।

श्री अजय चंद्राकर :- ठीक है, थैंक्यू। मैंने आपको थैंक्यू कहा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। अब आगे बढ़िये।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न पूछ रहा हूं। साहब, मैं तो पहले आपको आंकड़े में बता देता हूं। यह पंजीकृत रोजगार चाहने वालों का पंजीयन करते हैं। इन्होंने परिशिष्ट में जो आंकड़ा दिया है। वर्ष 2019-20 की स्थिति में 21 लाख 19 हजार 356 पंजीकृत बेरोजगार हैं। आज की स्थिति में 18 लाख 79 हजार 126 पंजीकृत बेरोजगार हैं। चूंकि यह बेरोजगारी का आंकड़ा है। मैं पहले इसको पूछ लेता हूं। इस हिसाब से इन्होंने आज तक कुल 2 लाख 40 हजार 230 लोगों को रोजगार दिया है क्योंकि अंतर यही बताता है। लेकिन उत्तर में यह बताया गया है कि शासकीय सेवा में 33 हजार 333 लोगों को रोजगार दिया गया है, अशासकीय संस्थाओं में 50 हजार 725 लोगों को रोजगार दिया गया और 5 लाख 9 हजार 559 लोगों को स्वरोजगार प्रदान किया गया है। मतलब कुल मिलाकर 5 लाख 63 हजार 617 होता है। इस ऊपर वाले कॉलम को पढ़े तो 2 लाख 40 हजार होता है। दोनों उत्तर में है। मैं पहले यह जान लूं कि कौन सा उत्तर सही है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो अलग-अलग विषय है और माननीय सदस्य दो अलग-अलग चीजों को जोड़कर बोल देते हैं और ऐसा परसेप्शन क्रियेट करने की कोशिश करते हैं कि यह कुछ और है और यह कुछ और है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं, आप आराम से बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, जो बेरोजगारी का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पंजीकृत बेरोजगार है, उनका आंकड़ा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- यह तो अपने यहां पंजीकृत रोजगार...।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह इनके 15 साल के समय का भी जोड़कर बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, भैया सीरियस मामला है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी सिर्फ अपने समय का ...।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपको पंजीयन कार्यालय से बेरोजगारों की संख्या नहीं मिलती ? यहां जो पंजीयन के कार्यालय है, जिला स्तर में भी है तो क्या आपको उससे बेरोजगारों की संख्या नहीं मिलती ?

श्री उमेश पटेल :- जी, उसी का है। वह लोग पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या का ही उल्लेख कर रहे हैं। रोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, उन्होंने उसी को बताया कि वर्ष 2018-19 में इतना था, वर्ष 2019-20 में इतना था। हमने उसी को परिशिष्ट में डाला है। यह 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 की स्थिति है, उन्होंने भी अभी उसी को बताया है। हमने उसी के आधार पर कहा है। लेकिन रोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत बेरोजगार है, उनके वेलिडेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है क्योंकि उसको न आधार कार्ड से जोड़ा गया है, न उसमें किसी तरह का वेलिडेशन है। कोई व्यक्ति रोजगार कार्यालय में गया, उसको नामांकित किया गया और उसको 03 महीने में नौकरी मिल जाती है, उसका भी कोई तरीका नहीं है। हमने हमारे कलेक्टरों से अलग-अलग जिलों से डेटा मंगवाया। जिन-जिन लोगों ने खुद से कहा कि हमको स्वरोजगार प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना जो फॉर्म भरा, हमने उसी को डेटा में बनाया और आप जो अभी डेटा पढ़ रहे हैं, वह वही डेटा है। हमने इसको पब्लिक भी किया है। वह कलेक्टरों के माध्यम से आया है। वही दो अलग-अलग चीजें हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप भी देख लीजिये, दोनों अलग-अलग चीजें हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- । इसमें जो उत्तर है, सही नहीं है। अब दूसरी बात, इन्होंने बेरोजगार चाहने वालों का पंजीयन किया है, जिसकी संख्या..।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, जब दोनों अलग-अलग चीजें हैं, तो उत्तर सही कैसे नहीं है ?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सुनिये न, अब पढ़ने दीजिये, मैंने वह लाइन छोड़ दी है। रोजगार चाहने वालों की संख्या 18 लाख 78 हजार 126 है। इन्होंने अभी बेरोजगारी भत्ता का आयोजन किया है। तो बेरोजगार कौन है ? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की परिभाषा क्या है ? जिसको सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप मुझको बेरोजगारी की परिभाषा बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से बेरोजगारी की परिभाषा उच्च शिक्षा में नहीं आती होगी।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, नहीं इन्हीं का है। इसी प्रश्न में ही जवाब आया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने प्रश्न किया जरूर है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा और रोजगार सब माननीय मंत्री जी का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, यब बताईये कि क्या पंजीयन कार्यालय भी आपके अंतर्गत है ?

श्री उमेश पटेल :- जी हां।

अध्यक्ष महोदय :- तो उसको वेलिडेट करिये। उसमें सब चीजों की जांच पड़ताल हो जाये।

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, यह एक महीने से हमारे मंत्री जी के पीछे पडे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- वह बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। उससे आपको भी फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, यह सीरियस मामला है।

श्री कवासी लखमा :- (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अरे दादा।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, प्लीज। यह पूरे प्रदेश के बेरोजगारों की संख्या, नौकरी, इन सबका का सीरियस सवाल है। यदि आपका पंजीयन कार्यालय इस लायक नहीं है तो उसको उस लायक बनाईये कि कितने पंजीकृत हैं, कितनों को नौकरी मिल गयी, कितने को नौकरी नहीं मिली। क्योंकि अभी सवाल उठेगा, जो उठा रहे है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- बहुत धन्यवाद।

श्री उमेश पटेल :- जी, हम लोग बिल्कुल सीरियस है।

अध्यक्ष महोदय :- उस समय तो पता चले कि बेरोजगार कौन है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पूरी स्थिति को समझाने के लिए मैं एक सेकण्ड लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप बताईये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है उसके वेलीडेशन की प्रक्रिया नहीं है। आप आधार कार्ड मेंडेटरी नहीं कर सकते। आप मेंडेटरी नहीं कर सकते इसलिए आप उसको वेलीडेट...।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेंडेटरी क्यों नहीं कर सकते?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोर्ट का भी आदेश है कि आप इसमें मेंडेटरी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग उसको मेंडेटरी नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय :- अगर कोई व्यक्ति रोजगार मांग रहा है, उसके पास आधार कार्ड ही नहीं है तो फिर वह आदमी कहां से आया?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

अध्यक्ष महोदय :- जो व्यक्ति रोजगार मांग रहा है, यदि उसके पास आधार कार्ड है ही नहीं फिर आपकी क्यों जवाबदारी है कि आप उसको रोजगार दें?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, उसमें आप आधार कार्ड मेंडेटरी नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय :- मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप यह क्यों नहीं कर सकते? कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, किस कोर्ट ने आदेश दिया है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेंडेटरी नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेंडेटरी क्यों नहीं कर सकते ? मैं आपके माध्यम से कोर्ट से यह जानना चाहता हूँ। जब हर चीज में आधार कार्ड की जरूरत है

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां।

अध्यक्ष महोदय :- तो इसमें क्यों आधार कार्ड की जरूरत नहीं है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या-क्या कहा है, लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से...।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। आप मुझे अलग से जानकारी देंगे कि रोजगार कार्यालय में जो रोजगार के पंजीयन होते हैं, उसमें आधार कार्ड की आवश्यकता क्यों नहीं है ? उसमें आपको कोर्ट ने क्या छूट दी है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी बिल्कुल।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले धन्यवाद् दे दूं। मैं आपको एलिगेट नहीं कर रहा हूँ आप आराम से सुनिए। यह गंभीर प्रश्न है मैं हल्के फुल्के प्रश्न नहीं करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं । यह गंभीर प्रश्न है इसलिए मैंने गंभीर प्रश्न किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए आपको धन्यवाद् दिया। यह बात परिभाषित होनी चाहिए, सरकार, विभाग को परिभाषित करना चाहिए क्योंकि बजट भाषण में बेरोजगारी भत्ता का विषय आया है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने इसीलिए कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। आप स्पष्ट निर्देश दीजिए कि यहां किसको बेरोजगार माना जाएगा ? आपको धन्यवाद्। अब मैं तीसरा और आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड। मैं इसमें अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात रखिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं आपका बात से सहमत हूँ। जो रोजगार कार्यालय है हम उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण आधार कार्ड मेंडेटरी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास वेलिडेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हम लोगों को फार्म मंगाना पड़ेगा। हमने अलग-अलग क्राईटएरिया डिफाईन किया है और उस क्राईटएरिया में जो आदमी फीट होगा, हम उसको बेरोजगार मानेंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप क्राईटएरिया पढ़ने के लिए बोलेंगे तो मैं पढ़ दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। क्राईटएरिया पढ़ना नहीं है। आप मुझे भी समझाईये और इनको भी नहीं समझ है तो इनको भी समझाईये। आप दोंनों मिलकर मुझे समझाईये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहेंगे तो हमने उसमें क्राईटएरिया डिफाईन किया है और हम आवेदन मंगवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। आपने बहुत बड़ा भार उठा लिया है कि शासन इस बार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

अध्यक्ष महोदय :- तो अपने पास बेरोजगारों की परिभाषणा होनी चाहिए, बेरोजगार चिन्हांकित होना चाहिए। उसके बगैर आप किसको बेरोजगारी भत्ता देंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो बता रहा हूँ कि हमने क्राईटएरिया बनाया है कि किसको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा, उसमें उम्र की भी डेफिनेशन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसको पटल में रखवा दीजिए। पूरा प्रदेश यह जान लेगा।

अध्यक्ष महोदय :- अभी बना है, वह बना रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- भई, अभी तो बन रहा है तो उसे पहले ही पटल में कैसे रखेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है, थोड़ा ध्यान से सुनिए।

श्री कवासी लखमा :- इन्होंने 15 सालों में नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय:- आप सुनिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। जबरदस्ती क्यों इंटरप्ट कर रहे हो ?

अध्यक्ष महोदय :- कृपया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उमेश जी, आप अच्छा जवाब दे रहे हो। आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। आपको इनकी मदद की जरूरत नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं स्थिति क्लियर कर देता हूँ। उसमें 5 क्राईटएरिया है उम्र का एक क्राईटएरिया है, एक आय का क्राईटएरिया है एक ऐसा क्राईटएरिया है कि उस परिवार से किसी को सरकारी नौकरी न हो, हमने यह अलग-अलग क्राईटएरिया डिफाईन किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बढ़िया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थिति को क्लियर करने दीजिए। यह सिर्फ आपके लिए नहीं है। यह पूरे सदन के लिए है इसलिए मैं बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपको समय दिया। आप स्थिति क्लियर करिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह 5 क्राईटएरिया तय किया और इसका उत्तर आज के ही पटल में रखने की जरूरत नहीं है। आज ही माननीय शिवरतन शर्मा जी ने जो प्रश्न पूछा है उसमें यह जवाब आया है तो यह ऑलरेडी विधान सभा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह संपत्ति हो गई है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है और जहां तक मैं आपको यह आश्वासन या इसको क्या बोलूं निश्चित करना चाहूंगा कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार सुनिश्चित है, सुदृढ़ है और वह अपने गीवन क्राईटएरिया में बेरोजगारी भत्ता देगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,चूंकि यह सरकार CMIE को मान्यता नहीं देती। मैं अगला प्रश्न पूछ लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूछिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उनकी मदद की। हमारे मंत्री, सरकार को बोले, उन्होंने डिटेल बताया। वह कितनी बार प्रश्न पूछेंगे। उनकी पूरी जिम्मेदारी है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- यह मामला गंभीर है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, CMIE के डाटा के हिसाब में आप पिरशिष्ट पढ़ लीजिए। इस सरकार ने ...।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने उनके द्वारा जो बात रखी गई थी कि आप प्राइवेट संस्था की डेटा का विधान सभा में उल्लेख नहीं कर सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं। आप पूरा सुन लीजिए। मैं समझा कि आप अच्छा उत्तर दे रहे हैं, कोई नई बात लाओगे। यह एक गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- हां जी, आप गंभीर प्रश्न ही उठाते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- वह आप मेरे ऊपर छोड़िये न।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 15-20 से ऊपर अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जो मामला छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, वह मेरे लिए ज्यादा गंभीर है। मैं उसमें 2, 3, 4, 5 जितनी जरूरत समझूंगा, उसकी अनुमति दूंगा। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न है। बहुत आपत्ति ले रहे हैं। उस संस्था सी.एम.आई.आई. जिसकी मान्यता सरकार नहीं देती है, .4 प्रतिशत, .5 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में न्यूनतम बेरोजगारी दर, इस विषय में 2 करोड़ रुपये का विज्ञापन दिया। इसी के उत्तर में है कि 2 करोड़ रुपये का विज्ञापन दिया।

अध्यक्ष महोदय :- शासन ने दिया?

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, शासन ने विज्ञापन दिया है। क्या ये अनियमितता की श्रेणी में आयेगा या नहीं आयेगा? और यदि आप अनियमितता मानते हैं, ऐसा प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट में दे सकते हैं तो क्या उसकी वसूली होगी? वह गलत है या सही है और यदि गलत है तो क्या उसकी वसूली करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपको इसकी जानकारी है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर में है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि सरकार ने 2 करोड़ रुपये का विज्ञापन दिया। अगर कोई डेटा पूरे देश के लिए भले ही प्राइवेट संस्था है, चूंकि केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पलट गई, केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार नहीं है। अभी मैंने इधर-उधर प्रश्न नहीं किया है।

श्री उमेश पटेल :- आपको उत्तर तो सुनना पड़ेगा न।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सुनना नहीं चाहेंगे, यह क्या कोई बात है? वह उत्तर दे रहे हैं तो आप उत्तर को सुनिये। आप 10-20 अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और आप सुनना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तर सुनियेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे 02 मिनट दीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको समय दे रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- N.S.S.O.(National sample serve organisation) एक आर्गेनाईजेशन है। केन्द्र सरकार इसके द्वारा बेरोजगारी का आंकड़ा प्रस्तुत करती थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में हर साल लगातार ये आंकड़ें प्रस्तुत हुए और पब्लिक होते थे जिसके द्वारा हर राज्य अपने बेरोजगारी आंकड़ें को दिखाता था। जब से केन्द्र में [xx] की सरकार बनी है, तब से ये आंकड़े आना बंद हो गये हैं। (शेम-शेम की आवाज) मेरा आरोप है कि ये आंकडें आना इसलिए बंद हुए क्योंकि बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हुई थी, उसको छुपाने के लिए यह आंकड़ा देना बंद कर दिया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर है?

अध्यक्ष महोदय :- मैं मान रहा हूं नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की आपके पास कंडीशन है और पूरे देश में सिर्फ एक ही संस्था है जिसके द्वारा बेरोजगारी आंकड़े प्रस्तुत होते हैं। हमने उस आंकड़े को कोट दिया और उसके द्वारा विज्ञापन जारी किया, इसमें क्या अनियमितता है?

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जिसको आप मान्यता नहीं देते, उसका विज्ञापन देना उचित है, अनुचित है, गलत है, सही है? आप मान्यता देकर 1 हजार करोड़ का विज्ञापन दे दीजिए न, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह [xx] की श्रेणी में आयेगा या नहीं आयेगा?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा देश जिस आंकडे को प्रस्तुत कर रहा है, पूरा देश मान रहा है, भारत सरकार मान रही है, क्या आपके अलग से आकड़ा जारी होगा?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बेरोजगारी की चिंता नहीं है, विज्ञापन की चिंता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसमें मान्यता नहीं दे रहे हैं, पूरे देश का विज्ञापन दे रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- पूरा देश उस संस्था को और उसकी गाईडलाईन को मान रहा है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैने उत्तर में दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप भी मान लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मान्यता दे दीजिए न, आपको मान्यता देने से किसने रोका है।

श्री सौरभ सिंह :- आप उस संस्था को मान्यता दे दीजिए। .. (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- इंडिया शाइनिंग के विज्ञापन को कोई नहीं भूला है। आप लोगों को बेरोजगारों की चिंता नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बेरोजगारों की चिंता नहीं है, विज्ञापन की चिंता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सीधे-सीधे [xx] का मामला है।

श्री कवासी लखमा :- नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल है। आप उत्तर को पढ़ लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो [xx] लगा रहे हैं, यह गलत बोल रहे हैं, उसको आप विलोपित कराईये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल):- कोई [xx] नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- आप शांति से बैठिये न। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- उस संस्था को मान्यता नहीं मिली है। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- हर चीज भ्रष्टाचार पर चर्चा करके खत्म कर रहे हैं।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- तिहार मानने के नाम पर बड़ा-बड़ा पण्डाल। विधानसभा को खत्म नहीं किये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- इसी बात को मान्यता दे दीजिये कह रहे हैं। दे दो न। मुख्यमंत्री जी से बोलवा दीजिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- (व्यवधान) का बड़ा-बड़ा पोस्टर लगता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- हाँ, मुख्यमंत्री जी से बोलवा दीजिये न।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मुख्यमंत्री जी से बोलवा दीजिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- पेट्रोल पंप में इतना बड़ा-बड़ा पोस्टर लगता है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संस्था को मान्यता नहीं है उसको कैसे भुगतान होगा? आप मान्यता दे दीजिये, फिर भुगतान करिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय खाली [xx]

श्री उमेश पटेल :- शिव भैया, आप उत्तर सुन लीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- पूरे हिंदुस्तान में (व्यवधान) संस्था है।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिये। हर पेज में विज्ञापन है। हर पेज में आज क्वाटर विज्ञापन है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं?

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़ यदि एडाप्ट कर रहा है तो उसमें आपको आपत्ति है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज को क्लियर कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिये। मेरी बाध्यता यह है कि मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप क्या उत्तर देंगे। आपको जो विभाग ने जानकारी दी है, वह उत्तर

दीजिये। मैं किसी भी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता कि आपके सवालों को आपके अपेक्षानुसार ही उत्तर दें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबके लिए क्लियर करने के लिए बात कह रहा हूं कि विज्ञापन उस संस्था को नहीं गया है। उस संस्था ने कोट किया, उस कोटेशन को हमने पेपरों के माध्यम से विज्ञापित किया है। यह उस संस्था को विज्ञापन नहीं गया है। इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- जिस संस्था को मान्यता नहीं है, उस संस्थ्ज्ञा ने यदि कोई कोट किया तो उसको लेकर आप विज्ञापन दे रहे हैं तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 8, श्री अरूण वोरा ।

डॉ. विनय जायसवाल :- भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान में मान्यता दी है।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- जितना पैसा किसान को फसल बीमा का नहीं मिला है, उससे ज्यादा फसल बीमा विज्ञापन हो चुका है। (व्यवधान) मांग की एक की गई है कि किसानों की बीज विक्रय और दवाई विक्रय की दुकान में मंत्री जी का फोटो लगाना जरूरी है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ के जनता के खून-पसीने की कमाई के लिए .. (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, नेता जी खड़े हैं। वे जवाब नहीं ही दे पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग खड़े हैं।

श्री नारायण चंदेल :- एक मिनट, मैं बोल लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग 6 लोग उठेंगे तो मैं किसका बात सुनूंगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गैस के साहब का आजकल बड़ा-बड़ा फोटो पेपर में दिख रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। यहां माननीय नेता जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्या जवाब देना चाहते हैं, दीजिये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय उमेश पटेल जी ने कही कि भारत सरकार लगातार चाहे अभी बेरोजगारी के सर्वे की रिपोर्ट की बात है, चाहे जनगणना की बात हो। आखिर अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को कहीं न कहीं आाधार तो लेना पड़ेगा। आखिर हेड काउंट किये तो क्यों किये। भारत सरकार यदि जनगणना करती तो क्या हूं हेड काउण्ट करने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं किया। अभी आप देखेंगे, आप नहीं करें और इस सर्वे को दुनिया मान रही है। इसको चैलेंज करके देख लीजिये। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की है और इनको तो गर्व करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेराजगारी है और उसमें इन लोगों को आपत्ति हो रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह प्रायोजित सर्वे है। यह उपलब्धि नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं दूसरी संस्था का सर्वे दूंगा। मैं प्राइवेट संस्था का दूसरा सर्वे दूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- उस संस्था को पूरा हिंदुस्तान मान रहा है तो यह [xx] वाले कौन होते हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, नेता जी खड़े हो गये तो सबको आवश्वस्त हो जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य :- अभी तो आप लोग पूरी डेटा ही तो मांग रहे हैं न।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि इनको तकलीफ इस बात का है कि [xx] ने उस सर्वे को मानने के लिए मना कर दिया तो ये लोग क्यों मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, इसमें [xx] का नाम नहीं आ रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। माननीय अजय चंद्राकर जी ने बहुत ही प्वाइंटेड प्रश्न पूछा है। यह छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो मैं भी गंभीर हो गया। मैं गंभीर हुआ या नहीं हुआ?

श्री नारायण चंदेल :- लेकिन जिस प्रकार का जवाब आया। भारत सरकार कहां से आ गया? [xx] कहां से आ गये? आपको प्वाइंटेड उत्तर देना चाहिए और अगर उस संस्था से इतना (व्यवधान) है तो आप मान्यता दे दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- जिस संस्था की रिपोर्ट को भारत सरकार मान रहा है, उसके पहले भारत सरकार रिपोर्ट जारी करती थी। जब से की सरकार आई है (व्यवधान) पेश कर रही है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नेता जी खड़े हैं तो ये लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- भारत सरकार जिम्मेदार है, क्या आप उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं ? (व्यवधान) हर साल दो करोड़ लोगों को...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी बोल रहे हैं । उन्हें बोलने दीजिये।(व्यवधान) नेता जी आप बोलिए । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज अभी नेता जी को बोलने दीजिए । नेता जी आप बोलें ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास रोजगार कार्यालय के पंजीयन का आंकड़ा है । क्या वह आंकड़ा सार्थक नहीं है, पंजीकृत नहीं है ? क्या वह आंकड़ा सही नहीं है ? आपके पास पूरे प्रदेश में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार हैं और जिस प्रकार से घुमाकर के उत्तर दिया जा रहा है यह बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की मंशा है । (शेम-शेम की

आवाज) आप जिस तरीके से घुमाकर बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के पाले में हर चीज को डालना । [xx] कहां से सर्वे आ गया ? कहां से जनगणना आ गयी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं । आपने कहा कि मैं मंत्रियों को बाध्य नहीं कर सकता । हमारा आपसे आग्रह है कि आप बाध्य नहीं कर सकते लेकिन आप ये निर्देशित कर सकते हैं कि जो प्रश्न है उसका उत्तर सही आये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से यह निर्देश हो सकता है और आज जिस प्रकार से मंत्री जी ने उत्तर दिया है । बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है । (व्यवधान) हम आपके उत्तर से असंतुष्ट हैं और इस प्रकार से खिलवाड़ करने वाली सरकार के उत्तर के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं ।

समय :

11.52 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u> ।

(नेता प्रतिपक्ष, श्री नारायण चंदेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 8 । अरूण वोरा जी ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आरोप लगाया । मैं इस सदन में बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि मैंने एक-एक उत्तर सही दिया है । मैंने एक-एक सही उत्तर दिया है उसमें कोई गलत बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने सही उत्तर दिया है । उन्होंने कोई गलत आरोप लगाया है उनको मान्य नहीं किया जायेगा, विलोपित कर दिया जायेगा । आप उसकी चिंता मत करिये । चलिये । (मेजों की थपथपाहट)

<u>हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण</u>

[उच्च शिक्षा]

8. (*क्र. 1010) श्री अरुण वोरा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- दुर्ग में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का कार्य कब शुरु किया गया? कब तक

पूर्ण किया जाना था? इसकी कुल लागत कितनी है? इसके लिए कुल कितनी एकड़ जमीन आबंटित की गई? कितने एकड़ में निर्माण होना प्रस्तावित है? वर्तमान में निर्माण कार्य की क्या स्थिति है एवं इसे कब तक पूर्ण किया जाएगा?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :दुर्ग में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का कार्य दिनांक 06.03.2019 को शुरू किया गया। दिनांक 05.03.2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। इसकी कुल लागत 1192.44 लाख हैं। इसके लिए कुल 40 एकड़ जमीन आबंटित की गई । 1.01 एकड़ में निर्माण कार्य होना प्रस्तावित है। वर्तमान में 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री अरुण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय किस महाविद्यालय में लग रहा है और वह महाविद्यालय कितना पुराना है ? और आपने कहा कि उसमें 11 करोड़ 92 लाख रूपये खर्च हुए हैं तो जो राशि स्वीकृत की गयी है इसमें अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की गयी है और आपने कहा कि भवन निर्माण का अभी 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है । बाकी काम की समय-सीमा बताना निश्चित नहीं है तो किस कारण से यह कार्य रूका हुआ है और कितनी राशि खर्च हुई है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि इसमें 11 करोड़ 92 लाख की स्वीकृति हुई है और इसमें कुल 40 एकड़ जमीन आवंटित है । वर्ष 2021 में इसको पूर्ण करने का पहले टारगेट रखा गया था, बीच में कोरोना की महामारी जब आयी तो इस काम को कुछ दिनों के लिये बंद करना पड़ा जिस कारण से कुछ देरी हुई है । यह लगभग 80 परसेंट पूरा हो चुका है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की स्थिति में आ जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- रजनीश सिंह जी ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्चयक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका भूमिपूजन किया था और 11 करोड़ 92 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की थी । मैं चाहता हूं कि यह जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है इसका निर्माण आप जल्दी पूरा करा दें ।

श्री उमेश पटेल :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । रजनीश सिंह जी ।

राजीव मितान क्लबों का गठन व उन पर व्यय की गई राशि

[खेल एवं युवा कल्याण]

9. (*क्र. 1135) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020-21 से दिनांक 31.01.2023 तक राज्य में कितने राजीव मितान क्लबों का गठन किया गया है व कितने क्लबों का पंजीयन किया गया हैं ? (ख) उक्तानुसार उपलब्ध कराई गई राशि को किन-किन कार्यों में व्यय किया जा सकता है तथा व्यय करने के लिए सक्षम कौन है ?कितने क्लबों के द्वारा कितनी राशि उक्तानुसार मापदण्डों के आधार पर व्यय नहीं की गई हैं व क्यों ? (ग) क्लबों के द्वारा अनियमित व्यय किये जाने के संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनी शिकायतों में अनियमितता पाई गई है और कितने लोग दोषी पाये गए हैं ?जिलेवार, क्लबवार जानकरी देवे ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि तक राज्य मे 13203 क्लबों का गठन किया गया। योजना की नियमावली के अनुसार क्लबों का पंजीयन नहीं किया जाता है।(ख) उपलब्ध कराई गई राशि खेल गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को संपन्न कराने के कार्य में व्यय किया जा सकता है तथा व्यय करने के लिए राजीव युवा मितान क्लब सक्षम हैं। सभी के द्वारा मापदण्ड के आधार पर राशि व्यय की गई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या राजीव मितान क्लब का पंजीयन किया जाता है और यदि पंजीयन नहीं किया जाता तो यह किस नियम के तहत् नहीं किया जाता है ? क्योंकि क्लब समिति संस्था संघ को नियमित जो अनुदान दिया जाता है उसमें नियम है कि वित्तीय संहिता में भी लिखा है तो किस नियम के तहत् बिना पंजीयन के इनको राशि दी जा रही है और दूसरा इसी में आपने कहा है कि राजीव क्लब को यह अधिकार है कि वह राशि का आहरण करे तो उसमें कितने सदस्य हैं और कौन आहरण कर सकता है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव युवा मितान क्लब की जो मेन संस्था है उसका पंजीयन हुआ है और हर जिले में, हर गांव में जो संस्थाएं बनी हैं वह उसके ब्रांच के आधार पर बनी है इसलिये जो मेन संस्था है उसका पंजीयन हुआ है और उसकी जो ब्रांचेस हैं उनका अलग-अलग पृथक से कोई पंजीयन नहीं कराया जाता। मेन संस्था का पंजीयन है । आपका दूसरा प्रश्न था कि राजीव युवा मितान क्लब में कौन कौन हैं ? तो इसके लिए बाकायदा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव का चयन किया गया है और अध्यक्ष और सचिव इसका आहरण कर सकते हैं ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- कौन आहरण करता है, अध्यक्ष और सचिव । वैसे सभी क्लब में अध्यक्ष और सचिव आहरण करके, आपने कहा है कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के लिए है । तो क्या आपने इसका परीक्षण करवाया है कि खेल गतिविधि कौन सी है, सामाजिक गतिविधि कौन सी है और सांस्कृतिक गतिविधि कौन सी है । इसमें उन्होंने कितनी राशि खर्च की गई है ?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, युवा मितान क्लब को अभी ज्यादातर जगह पर प्रथम किश्त ही प्राप्त हुई है । प्रथम किश्त के लिए ..।

अध्यक्ष महोदय :- प्रथम किश्त में कितने रूपए दिए हैं यह भी बता दीजिए ?

श्री उमेश पटेल :- 25 हजार प्रथम किश्त में दिए गए हैं और उसमें खेल गतिविधि के लिए भी है, सामग्री क्रय करने के लिए भी है, अलग-अलग क्राइटेरिया है। साथ ही साथ हमने नियमावली में इसका प्रावधान रखा है कि हर साल इनका ऑडिट होगा और ऑडिट में किसी तरह की अनियमितता पाई जाएगी तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी । अभी तक कोई अनियमितता प्राप्त नहीं हुई है । जैसे ही ऑडिट होगा उसकी जानकारी आपको प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि मापदंड के आधार व्यय किया गया है । यह मापदंड का आधार क्या है और आप खुद कह रहे हैं कि अभी ऑडिट नहीं हुआ है । तो किस आधार पर यह राशि व्यय की गई है ।

श्री उमेश पटेल :- मापदंड नियमावली के साथ ही दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- नियमावली की पुस्तक यहां रख दीजिए ताकि सब लोग पढ़ लें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 हजार से ऊपर क्लब बनाए गए हैं और प्रतिवर्ष एक करोड़ 32 लाख दिया जाना है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक क्लब को ।

श्री धरमलाल कौशिक :- पूरे प्रदेश में 1 करोड़, 32 लाख । अब आप उनको राशि दे रहे हैं तो उनका पंजीयन होना चाहिए, ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए और पंजीयन के बाद तीन साल देखने के बाद उसकी राशि जाती है । मतलब यह तो एक चारागाह बन गया । सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का । क्या नियम बना लिए, उन पर क्या नियम लगेगा ? वे खुद खर्च करेंगे, क्या खर्च कर रहे हैं सरकार उसका कोई ऑडिट नहीं कर सकती । उसमें ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है, पंजीयन का कोई प्रावधान नहीं है । ऐसी समितियों को केवल भ्रष्टाचार करने के लिए और जहां तक उसके गठन की प्रक्रिया है, जो ग्राम सभा के द्वारा होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी यह पूछना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं जब तक उनका पंजीयन न हो और पंजीयन के तीन साल बाद उनको राशि दी जाए, अभी उनकी राशि बंद कर दी जाए ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की यह समस्या है कि वे कभी भी उत्तर को पूरी तरह से सुनते नहीं हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक बार अनुदान दिया जा सकता है । प्रत्येक वर्ष उनको अनुदान नहीं दिया जा सकता, जब तक उनका पंजीयन न हो । यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह वित्त संहिता के भाग-1 में लिखा है ।

श्री उमेश पटैल :- अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न को देखिए, ये कह रहे हैं कि ऑडिट की व्यवस्था नहीं है । पंजीयन की व्यवस्था नहीं है । रजनीश जी ने अभी प्रश्न किया और मैंने उत्तर दिया है कि पंजीयन की भी व्यवस्था है और ऑडिट की भी व्यवस्था है । लेकिन ये फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं । जितने लोग विपक्ष में है, सबकी यही समस्या है । उत्तर कभी सुनते नहीं, अपनी ही धुन में रहते हैं । माननीय कौशिक जी, पंजीयन की भी व्यवस्था है, ऑडिट की भी व्यवस्था है और किसी तरह की अनियिमतता होगी तो उन पर कार्रवाई की भी व्यवस्था है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो 13 हजार क्लब बनाए हैं उनमें कितने का पंजीयन अभी तक हुआ है । आप बता दीजिए ?

श्री उमेश पटेल :- कौशिक जी, मैं आपको पूरा समझा देता हूं । मेन संस्था का पंजीयन हुआ है और उनकी ब्रांचेस हैं, पृथक से उनका पंजीयन नहीं हुआ है । जो मेन संस्था है उसका पंजीयन होता है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी यह बता दें कि उनके बैंक का जो एकाउंट नम्बर है, वह एकाउंट केवल एक जगह से संचालित है या अलग-अलग क्लब के अलग-अलग एकाउंट हैं ?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, एकाउंट खुला है वह उस गांव के अध्यक्ष के द्वारा खोला गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसमें यही लोचा है ।

श्री उमेश पटेल :- कोई लोचा नहीं है । (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- कोई लोचा नहीं है । (व्यवधान)

समय :

12.00 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवदेन वर्ष 2022

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवदेन वर्ष 2022 पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन

पशुधन विकास मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पटल पर रखता हूं।

(3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का अठारहवां का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2019-2020

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का अठारहवां का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2019-2020 पटल पर रखता हूं।

समय :

12:01 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

<u>पृच्छा</u>

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश के लाखों ऐसे हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना था और प्रदेश सरकार द्वारा राज्यांश रोके जाने के कारण वह प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गये। उनका एक बड़ा प्रदर्शन था, विधान सभा घेराव का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े, वाटर केनन छोडा, मिर्ची वाले बम फेंके गये, और सबसे दुखद बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक शामिल थे। हमारे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धरमलाल कौशिक जी के उपर अश्रु गैस का गोला गिरा। हमारे कार्यकर्ता घायल हुए। सौरभ सिंह जी के उपर अश्रु गैस का गोला गिरा और पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर हमने स्थगन दिया है, हमारा आपसे आग्रह है कि सारी कार्यवाही रोक करके स्थगन पर चर्चा कराएं, हमारा आपसे निवेदन है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैजेपुर विधान सभा के ग्राम किकिरदा तहसील सक्ति जहां खसरा नंबर 1041 है, उसमें 700 किसान की जमीन है। वहां के नायब तहसीलदार के द्वारा उन सभी किसानों के पंजीयन पर रोक लगा दिया गया है। नामांतरण पर, बटांकन पर, बंटवारा पर, फौती पर सभी पर रोक लगा दिया गया है जिसके कारण आज उस गांव के 700 किसान तकलीफ में हैं। विगत् चार पांच सालों से ना धान बेच पा रहे हैं, ना जमीन की खरीदी बिक्री कर पा रहे हैं, ना नामांतरण करवा पा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसकी शिकायत राजस्व सचिव से ले करके कलेक्टर तक सभी को किया है लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा है। वह 700 किसानों के हित का मामला है, पूरे ग्राम किकिरदा के किसानों की समस्या है, आज ध्यानाकर्षण दिया हूं कृपया ग्राह्य करके उस पर चर्चा कराएं।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास के बारे में दो दिन में काफी चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने आंकड़े सदन में रखें, माननीय मंत्री जी ने जितने आंकड़े ने रखें, उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने अस्वीकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हमको आवास से वंचित किया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कल सड़कों में थी। सरकार को जब कुछ नहीं सूझा तो वाटर केनन, लाठी, अश्रु गैस, मिर्ची बम इनका उपयोग किया, हमारे कई माननीय विधायकगण घायल हुए, कार्यकर्ता घायल हुए। यह सरकार की बर्बरता के विरोध में और प्रधानमंत्री आवास के राज्यांश के

लिए हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, आपसे आग्रह है कि उसको शून्यकाल रोककर उस पर तत्काल चर्चा करवाएं।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हद तो तब पार हो गई जब...। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि 10-15 हजार लोग एक साथ आ जाएंगे तो विधान सभा को सुरक्षित करने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था की जाएगी।...(व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- हम लोग साथ में विधान सभा आ रहे थे। हम लोग शांति से साथ में आ रहे थे। हम लोग स्वयं उसमें थे लेकिन जहां पर बैरिकेट बनाये गये थे, जब हम लोग उस बैरिकेट के पास पहुंचे तो वहां पर कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर नहीं थे। बैरिकेट को जूनियर पुलिस ऑफिसर के भरोसे छोड़ दिया गया। जिनमें निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं थी। कल हम लोगों ने देखा है कि पुलिस विभाग में इतनी भी मानवीयता नहीं है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर होकर उनको कोई गाइड करे और जिस प्रकार से वहां पर जो जूनियर लोग थे, जिनको समझ भी नहीं थी। मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री जी का आदेश मिला, उसके बाद हम पर मिर्ची बम फेंका गया।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितने सारे पुलिस वाले घायल हुए। बहुत सारे पुलिस वालों पर हमला किया गया है। पुलिस वालों को धक्का दिया गया। कई पुलिस वालों को मारा गया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अश्रु गैस के गोले छोड़े गये। यदि मुख्यमंत्री जी यह चाहते हैं कि हम दमन करके जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबा देंगे। हम लोगों ने इनकी दमनात्मक नीति को देखा है और कोई डरने वाला है। हमने इनकी पुलिस को भी देखा है। इसके लिए हमने इस सदन में प्रस्ताव दिया है यदि आप इस पर चर्चा कराएंगे तो हम इन सब बातों को रखेंगे।...(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5-10 हजार लोग एक साथ आ जाएंगे तो विधान सभा में उसके लिए व्यवस्था तो की जाएगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। सौरभ सिंह।

श्री कुलदीप जुनेजा :- वह ड्यूटी में लगे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस वालों को मारा गया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अभी आप लोग अपनी बात कहेंगे। वोरी जी, आप बैठिये। थोड़ा सुन लीजिए। वोरा जी, मैंने आपका नाम लिख लिया।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधान सभा घेराव के लिए आये तो पुलिस बल द्वारा अज्ञात स्थानों से उनपर बम फेंका गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये वोरा जी, आप बोलिये।

श्री सौरभ सिंह :- उसमें हमारे शिवरतन शर्मा जी के लड़के अविनाश शर्मा जी, सुनील यादव जी और हमारे नवागढ़ का सरपंच आज भी अस्पताल में है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आकी बात आ गई।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी वहां पर पुलिस का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं था। मेरे ऊपर लाठी चार्ज हुई है। जब मैं आगे गया तो लोगों को समझ में आया तो फिर वह पीछे हटे। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी लाठी चार्ज हुई है। इस तरह से बर्बरता का उपयोग किया गया और वाटर गैलन का उपयोग किया गया। हम पर बम फेंका गया है। इस पर क्या कार्रवाई होगी? यदि आप प्रधानमंत्री आवास नहीं दे सकते हैं तो प्रदेश के जो हितग्राही आपसे आवास मांगने आ रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ इस तरह की पुलिस कार्रवाई करेगी?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये वोरा जी, आप बोलिये। मैं सबको बोलने के लिए मौका दे रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हर पक्ष का सम्मान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- वह कुछ अरजेंट बोल रहे हैं। आप प्वाइंटेट बात कीजिए।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात को कह रहे हैं उसमें असत्यता इसी बात से झलकती है कि हम लोगों ने आज तक मिर्ची बम नहीं देखा है। हमने मिर्ची बड़ा जरूर देखा है। यह मिर्ची बम कहां से आ गया?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मिर्चा बम।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम लोग मिर्ची लगने से बम हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये मोहले जी, आपका भी नाम है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आंदोलन किसलिए किया गया ? गरीबों के लिए किये गए राजनीतिक आंदोलन में इतनी बर्बरता ? योजनाबद्ध तरीके से इतनी बर्बरता की गई कि लोग घायल होकर आज भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसीलिए यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया है ताकि इसकी गंभीरता पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- रजनीश सिंह जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूरे प्रदेश के लोग उद्वेलित थे। विधान सभा घेराव का जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था,

बिना किसी चेतावनी के उसमें वाटर गैलन का इस्तेमाल किया गया और अज्ञात स्थानों से लोगों को टारगेट कर-करके अश्रु गैस के गोले फेंके जा रहे थे। उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इस तरह से उसमें हमारे कई कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता घायल हुए। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और कई लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। हमने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है आपसे आग्रह है कि आप उसको स्वीकार करके पहले इस पर चर्चा कराइये।

उपाध्यक्ष महोदय :- रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो इस सदन में यह कहते आये हैं कि यह सरकार गरीबों से नफरत करने वाली सरकार है। कल सरकार का जिस तरह का तानाशाही रवैया रहा, वह इस बात को स्पष्ट और सिद्ध करता है कि सरकार ने कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचा। जिस तरह पूरे प्रदेश की जनता, जो हितग्राही रहे, वह यहां पर बहुत अधिक संख्या में उपस्थित रहे। वह यहां विधान सभा का घेराव करने आये थे। चूंकि वह अपना धर्म निभा रहे थे लेकिन इस सरकार ने अपना राजधर्म नहीं निभाया और वहां पर पुरूष तो थे ही, साथ ही महिलाओं की भी संख्या थी, उनके ऊपर भी अश्रु गैस छोड़ा गया, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करने का प्रयास किया गया। वहां पर अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं भी थीं और हम लोग भी उन महिलाओं के साथ में थे। वहां महिलाओं के साथ भी बर्बरता की गई। हमने इस विषय में स्थगन दिया है, कृपया आप हमारे स्थगन को स्वीकार करके उस पर चर्चा कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय :- पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास को लेकर विधान सभा का घेराव किया गया, प्रदर्शन किया जा रहा था और हम आगे बढ़े तो उन परिस्थितियों में पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई। हम पर अश्रु गैस छोड़ा गया, जिसमें हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गये।

श्री रामकुमार यादव :- बबा ते सियनहा हस। ते लबारी झन मारबे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- कई कार्यकर्ताओं की आंखों में जलन होने लगी। कई लोग वहां पर बैठे थे। मैं स्वत: वहां पर था। अश्रु गैस छोड़ गए, जिसमें हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गए ।

श्री रामकुमार यादव :- बबा, तै सियनहा हस, लबारी झन मारबे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- कई लोगों के ऑंख में जलन होने लगा, कई लोग वहां बैठे थे । मैं स्वयं वहां था । एक युवा मोर्चा के रायपुर का कार्यकर्ता को हम लोगों ने बोरो प्लस लगाया, बेहोशी की हालत में था, उस परिस्थिति में बरबरता किये और इस बरबरता में शिकायत और घटना हुई है । अभी भी अस्पताल में लोग हैं । हमने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप स्वीकार करके इस पर चर्चा कराएं ।

संसदीय सचिव (जल संसाधन मंत्री से सम्बद्ध) सुश्री शकुन्तला साहू :- ए बबा, तैं लबारी झन मार । तै काबर लबारी मारथन ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तैं मोर संग गे तो नहीं रेहे, जाके देखते तो पता चलतिस ।

सुश्री शकुन्तला साहू :- तै काबर लबारी मारथस ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तै मोर तीर में रहितेस त पता चलतिस । तहू हमार संग जातेस त देखतेस, तीर में खड़े रहितेस त पता चलतिस ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई है ।

श्री डमरूधर पुजारी (बिन्द्रनवागढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इस सत्र की शुरूआत से प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं, मगर यह सरकार छत्तीसगढ़ के गरीब हितग्राहियों को आवास नहीं दे रही है, इसके विरोध में कल 15 मार्च को गरीब जनता सड़क पर उतरी थी, उनके साथ में हमारे विधायक और कार्यकर्ता भी थे । इस सरकार ने पुलिस को अगुवा करके आंसू गैस का गोला और गरीब जनता पर पानी डाली है । यह सरकार गरीब जनता और प्रधानमंत्री आवास के प्रति गंभीर नही है । इस संबंध में हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है । आपसे निवेदन है कि इसको स्वीकार करके चर्चा कराईए ।

श्री शैलेश पांडे :- इसमें हितग्राही कहां से आ गए । कार्यकर्ता अरेस्ट हुए और आप हितग्राही की बात कर रहे हैं । हमने भी बिलासपुर में लाठी खाया है, आपने ही सबको मारा है ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल की घटना मुझे ख्याल नहीं है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में हुई हो। छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाली यह घटना जिसमें महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा है । मांग कुछ नहीं है । सन् 2019 से 2023 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य में जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे, जिनका नाम था, उन्हें आवास नहीं मिल रहा है । उसकी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में महिलाओं, पुरूष और आवासहीन यहां राजधानी में पहुंचे थे । यदि उनके ऊपर वाटर केनन फेंका गया तो उन महिलाओं के ऊपर फेंका गया । अश्रु गैस के गोले छोड़े गए और ऐसा लग रहा है कि जनरल डायर की याद आ रही है कि हथगोले फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं । यह लज्जाजनक करने वाली घटना है, लाखों लोगों ने इस घटना को देखा है । यदि आवास मांगना अपराध हो गया है और वह आवास जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है, स्वीकृत आवास का मैचिंग ग्रांट न देने की वजह से एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा । सरकार की असफलता इससे ज्यादा चिह्नांकित और क्या हो सकती है कि उसने अपना पद इसलिए छोड़ दिया कि आवास देने में असफल हुए । यह घटना छोटी घटना नहीं है। 16 लाख आवासहीनों के आजीविका के जीवन का प्रश्न है । इसलिए इस संबंध में हमने स्थगन दिया है इसलिए महत्वपूर्ण मामले में चर्चा होनी चाहिए,

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कुल 5 हजार लोग थे । इनके धरने के कारण शहर के लाखों लोग परेशान हुए हैं । लाखों लोग परीक्षा नहीं दे पाए, बच्चे लोग एग्जाम देने नहीं पहुंच पाए । मरीज अपने ईलाज कराने अस्पताल नहीं पहुंच पाये और एम्बुलेंस को भी रोका गया । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- विधान सभा के रास्ते को छोड़कर जनता को तकलीफ न हो, हितग्राहियों को आवास मिले, इसलिए आन्दोलन कर रहे थे । जुनेजा जी, एक भी सिपाही वहां पर नहीं था, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था । (व्यवधान)

संसदीय सचिव (महिला एवं बाल विकास मंत्री से सम्बद्ध) डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- कल इन्होंने असत्य बात कही कि यहां पहुंचने में 25 मिनट लगे ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, गरीबों के हित के लिए काम करने की इतना चिन्ता थी तो केन्द्रांश को क्यों रोका गया ? (व्यवधान)

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- कल आप मन के चक्कर मा कतका गरीब आदमी, मरीज मन भटके हवय । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इनकी सरकार में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस सब कर्म किये हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- जगह-जगह पुलिस तैनात थी, जगह-जगह ट्रेफिक तैनात थी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, नेता जी बोल रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- पुलिस अलग होती है, ट्रैफिक पुलिस अलग होती है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए । मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं। नेता जी बोल रहे हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल 15 मार्च को प्रदेश की राजधानी में हम इतने दिन से लगातार मांग कर रहे थे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, नये-नये नेता प्रतिपक्ष बने हो, सही-सही बोलना ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास दिया जाये । जो समाज के सबसे पीछे और नीचे रहने वाले लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो समाज में नीचे रहते हैं, पीछे रहते हैं, जिनको मकान की आवश्यकता है, दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार उनका मैचिंग ग्रांट नहीं दे पा रही है, अपना अंशदान नहीं दे पा रही है । उसके कारण हमने विधान सभा स्तर और गांव से लेकर लगातार आन्दोलन किया ।

श्री शैलेश पांडे :- तो पुलिस को मारोगे क्या ?

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आन्दोलन नहीं किये हो, असत्य फार्म भरवाए हो।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी परिणति दिखी। कल वह आक्रोश राजधानी में फूटा। लाखों लोग प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही कल राजधानी पहुंचे थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। लेकिन दुर्भाय है कि शासन की जो दमनकारी नीति है, आंदोलन को दबाने की नीति है, यह प्रजातन्त्र में उचित नहीं है, यह लोकतन्त्र में उचित नहीं है। लोकतन्त्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वस्थ परम्परा है। लेकिन कल जिस तरीके से हमारे सांसदों, वरिष्ठ नेताओं, विधानसभा के सदस्यों के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं, आंसू गैस के गोले छोड़े गये। लाठी चार्ज किया गया। अनेक लोगों को चोटे आईं। हम लोगों ने आपको इस महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव को दिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की कार्यवाही रोककर आप इस महत्वपूर्ण स्थगन पर चर्चा करायें।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। शून्यकाल में आप सबके द्वारा उठाये गये विषयों को सुना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिए जाने वाले धरने पर पुलिस प्रशासन द्वारा दमनपूर्वक कार्यवाही को लेकर श्री नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन पस्ताव पर मैं विचार किया। कल इस विषय पर गृहमंत्री जी द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। प्रस्ताव में इसके अलावा अन्य विषय भी समाहित हुआ है। इसलिए विचारोपरांत मैंने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अग्राहय कर दिया है। अब मैं ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- कल के प्रदेर्शन को लेकर आज के सारे समाचार-पत्रों में छपा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज के सारे समाचार-पत्रों में छपा है कि भाजपाईयों को रोकने छोड़े आंसू गैस के गोले।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरे शहर को किला बना दिया गया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे शहर को किले में परिवर्तित कर दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं नियम 139 के तहत ध्यानाकर्षण सूचना लूंगा। श्री डमरूधर पुजारी जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार की पूरी बर्बरता थी।

श्री धरमलाल कौशिक :- स्थगन का विषय ही यही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने व्यवस्था दे दी, कल मंत्री जी का वक्तव्य आ गया था। (व्यवधान) वैसे भी कल मंत्री जी का वक्तव्य आ चुका है। श्री डमरूधर पुजारी जी।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्या :- पुलिस प्रशासन को दबाने का कार्य किया।(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह क्या है ? इससे बड़ा कोई विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें।

श्री उमेश पटेल :- आपने नियम तोड़ा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12:18 से 12:28 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही)

समय

12.28 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुये।)**

उपाध्यक्ष महोदय:- अब मैं नियम 138 ...। (व्यवधान)

श्री सौरभ शर्मा :- बम चला, पानी चला, वाटर कैनन चला, लाठी खाये...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप ही लोगों का ध्यानाकर्षण है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- ....राजनीति से यहां तक पहुंचे हैं । (व्यवधान)

श्री सौरभ शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ढंग से नहीं होता है । इस ढंग से बर्बरता नहीं की जाती है । आपसे आग्रह है कि सारे तथ्य सामने आ जायें। विपक्ष के साथी बोल रहे थे ना...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अब नियम 138...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, कुछ बोल रहे हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :-आपकी बात आ जायेगी । हम लोग और सुनेंगे । अध्यक्ष जी, दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था । किसान जब दिल्ली घुस रहे थे तो कीलें लगाई गई थी कीलें । अंग्रेज भी कभी हिन्दुस्तान के आंदोलन में कीलें लगाकर लोगों को नहीं रोका । दिल्ली की सरकार वह काम की थी, कभी उसकी आलोचना किये हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- एक साल किसान बैठे रहे, कहीं लाठी चार्ज नहीं हुआ । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह:- कहीं अश्रुगैस नहीं छोड़ा गया, कहीं बम नहीं मारा गया । (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चला दिया था । (व्यवधान)

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- अजय चन्द्राकर जी को बोलना चाहिये धमतरी में लाठी चार्ज कैसे हुआ है । (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- मंत्री का बेटा गाड़ी से किसानों को रौद दिया था । अंदर है, बंद है । (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया था और आप लाठीचार्ज की बात करते हो। मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गयी थी। (व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- हजारों (व्यवधान) पर लाठीचार्ज किया गया।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, अजय चंद्राकर जी को बोलना चाहिए। धमतरी में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कैसे हुआ था। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- मंत्री का बेटे ने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया था। वह अभी अंदर है, बंद है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह सब आ गया है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- (व्यवधान) लाठीचार्ज भी हुई। वॉटर केनल भी छोड़ा।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- (व्यवधान) आरक्षण बिल पर साइन नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन पर चर्चा करवाएं। (व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- हजारों लोगों को पुलिस की गाड़ी में डाला गया। डंडा भी मारे। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन पर चर्चा कराएं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, उस विषय में व्यवस्था आ गई है। मैं आप का ही ध्यानाकर्षण ले रहा हूं। उनका ध्यानाकर्षण पहली बार लगा है। रजनीश भाई, डमरूधर जी का ध्यानाकर्षण पहली बार आया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं अब नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2017 में किसानों को नहर पानी मारकर उनके ऊपर लाठीचार्ज किये थे।

उपाध्यक्ष महोदय :- महोदय, मैंने उनको अभी शांत किया है।

श्री धनेन्द्र साहू :- लाठीचार्ज होने के बाद एक आदमी की मौत हो गई थी। आप लोगों ने किसानों के ऊपर अत्याचार किया था, लाठीचार्ज किया था।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय डमरूधर पुजारी जी।

श्री अजय चंद्राकर :- शकुंतला जी, तोर बबा आ गे हे।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको किसानों के भुगतान का मामला उठाने का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझको ध्यानाकर्षण में पहली बार मौका मिला है, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय :

12.31 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) महासमुंद जिले के धान खरीदी केन्द्र गौरटेक में फर्जी तौल पत्रक बनाकर अनियमितता किया जाना

श्री डमरूधर पुजारी (बिंद्रानवागढ़) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

महासमुंद जिले के बसना तहसील के ग्राम गौरटेक के किसान श्री राम कृष्ण नायक आत्मज श्री लक्ष्मी प्रसाद नायक उम्र-59 वर्ष एवं उनके पुत्र आशीष नायक उम्र 37 वर्ष की कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित गौरटेक (883) तहसील-बसना, जिला-महासमुंद छ.ग. के धान खरीदी केन्द्र गौरटेक में धान बिक्री हेतु क्रमश: 357 कट्टे (142.80 क्विटल) एवं 281 कट्टे (112.40 क्विटल) का टोकन काटा गया। गौरटेक के हमालों द्वारा 357 एवं 281 बोरियां भरी गई एवं अशोक यादव पिता राहशो यादव तौल प्रभारी द्वारा 40 किलो बोरी के हिसाब से 357 बोरी (142.80 क्विटल) एवं 281 बोरी (112.40 क्विटल) तौला गया एवं पर्ची बाद में ले जाने हेतु कहा गया। पत्रक बुक नं. 3621 पर्ची क्रमांक 24117 एवं बुक नं. 3621 पर्ची क्रमांक 24118 बाद में दिया गया। जिसमें मात्रा में काट-छाट एवं उक्त किसान की जगह घनश्याम के जाली दस्तखत कर फर्जी तौल पत्रक बना कर लगभग 4 लाख रूपये की अनियमितता की गयी। कृषक द्वारा दिनांक 07/04/2022 को माननीय कृषि मंत्री छ.ग. शासन, दिनांक 07/06/2022 को पंजीयक, सहकारी सस्थाएं महासमुंद एवं दिनांक 07/06/2022 को तहसीलदार बसना जिला-महासमुंद को आवेदन किया गया, किन्तु इस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही की गई। दिनांक 28/12/2022 को कृषक द्वारा धान बिक्री हेतु अधिकृत ग्राम गौरटेक के घनश्याम द्वारा जाली दस्तखत कर फर्जी तौल पत्रक बनाकर 400 कट्टे (160 क्विटल) धान का कम भुगतान करने का शिकायत पुलिस अधीक्षक, जिला महासमुंद को की गई। दिनांक 30/12/2022 को समस्त प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जिलाधीश महासमुंद को धान बिक्री की शेष राशि को दिलाने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु इस पर भी कोई कार्यवाही नही की गई, जिससे किसान और आम जनता में रोष और आक्रोश व्याप्त हैं।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि कृषक श्री रामकृष्ण नायक के नाम पर धान विक्रय हेतु 257 कट्टा (142.80 क्विंटल) एवं उनके पुत्र श्री आशीष नायक के नाम पर 281 कट्टा (112.40 क्विंटल) का टोकन दिनांक 30.01.2022 को सहकारी समिति व धान उपार्जन केन्द्र, गौरटेक द्वारा जारी किया गया था। यह कहना सही नहीं है कि गौरटेक के हमालों द्वारा 357 एवं 281 बोरियां भरी गई एवं अशोक यादव पिता राहशो यादव, तौल

प्रभारी द्वारा 40 किलो बोरी के हिसाब से 357 बोरी (142.80 क्विंटल) एवं 281 बोरी (112.40 क्विंटल) तौला गया एवं पर्ची बाद में ले जाने हेतु कहा गया, अपितु वस्तुस्थिति यह है कि उक्त किसानों को जारी किए गए टोकन अनुसार दिनांक 31.01.2022 को उपार्जन केन्द्र में धान लाना था, किन्तु धान विक्रय हेतु कृषक स्वयं या उनके परिवार के कोई सदस्य उपार्जन केन्द्र में उपस्थित नहीं हुए, अपितु उनके कार्य को देखरेख करने वाले श्री घनश्याम नेताम द्वारा श्री रामकृष्ण नायक के नाम पर मात्र 157 कट्टा (62.80 क्विंटल) व श्री आशीष नायक के नाम पर 81 कट्टा (32.40 क्विंटल) धान विक्रय किया गया। विक्रय किये गये धान की राशि श्री रामकृष्ण को 1,21,832.00 रू. एवं श्री आशीष को 62,856.00 रू. का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है1 यह भी कहना सही नहीं है कि कृषक रामकृष्ण नायक के शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अपितु वस्तुस्थिति यह है कि शिकायत की जांच तहसीलदार बसना, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बसना एवं पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा बसना द्वारा की गई, सभी जांच में शिकायत प्रामाणित नहीं पाई गई। अत: यह कहना सही नहीं है कि किसानों और आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गयी तो कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने क्या कार्यवाही की ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में बताया है कि इसमें शिकायत हुई थी वहां के तहसीलदार ने उसकी जांच की, वहां के पर्यवेक्षक, तहसीलदार ने जांच की, सहकारिता विस्तार अधिकारी ने जांच की। पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा बसना ने जांच की। उस जांच में कोई तथ्य नहीं पाये गये। मैंने यह कहा कि वह शिकायत निराधार है।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण होने के बाद यह शिकायत की, लेकिन कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने क्या कार्यवाही की ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कृषि मंत्री जी को शिकायत की, जो हमको नहीं मिला। उन्होंने पी.एम. पोर्टल में शिकायत की, उन्होंने तहसीलदार को शिकायत की। वहां तहसीलदार ने स्वयं जाकर जांच की और आपके जो सहकारिता विस्तार अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं जाकर जांच की। वह जांच पूरी तरह से असत्य है।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उन्हें बचत भुगतान कब दे रहे हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान ने जितना धान बेचा, उन्हें उतना का भुगतान पूरा हो चुका है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश का मामला है। माननीय डमरूधर पुजारी जी, एक उदाहरण उठा रहे हैं। प्रकरण यह है कि एक किसान गया। सोसायटी में उतना धान ले जा कर छोड़ा। सोसायटी में धान छोड़ने के बाद, जो उसको जमा पत्रक दिया गया कि हमारे पास आपका

धान जमा हुआ, उसके बाद पोर्टल में पैसा पृथक जमा होता रहता है। जो पत्रक में दस्तख्त है, वह फर्जी है, जो प्राप्तकर्त्ता का दस्तखत है वह फर्जी है, वह प्राप्तकर्त्ता है ही नहीं, जिसका दस्तख्त हुआ है तो वह एक प्राप्तकर्त्ता का दस्तख्त फर्जी है जब प्राप्तकर्त्ता को पता चला, किसान जिसने धान बेचा, जब उसको उसके खाते में पैसा नहीं आया तब उसको पता चला कि मेरा धान का कम पैसा आया। जब उसने जाकर पूछा कि मैंने सोसायटी में जितना धान जमा किया, उसका पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जब उसको पैसा नहीं मिला तब यह सारी जांच, सारी इंक्वारियां चालू हुईं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने कहा कि विक्रय किये गये धान की राशि श्री रामकृष्ण को 1,21,832.00 रू. एवं श्री आशीष को 62,856.00 रू. का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें ऑन लाईन भुगतान हो गया। जो पंजीयन है, वह ज्यादा धान का है जो जमा हुआ है, वह ज्यादा धान है, जो भुगतान है, वह कम हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अच्छा। माननीय मंत्री जी बताईये ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो टोकन कटता है, कृषक श्री रामकृष्ण के जमीन का जो पंजीयन हुआ था, यह 3.91 हेक्टयेर का हुआ था। इसने रकबे में जो धान बोया है यह 3.86 हेक्टयर में धान बोया है। धान बेचने की जो पात्रता है वह 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पात्रता है, इसका 143 क्विंटल बनता है और इन्होंने 31 तारीख को 80 क्विंटल बेचा है। इसका पूरा भुगतान हो गया है। उसकी बेटा आशीष नायक है, इसका 5.21 हेक्टेयर रकबा है और 5.21 हेक्टेयर में पूरा धान बोया था और उसने पूरा धान बेचा है। जो दूसरी बात आशीष की किये हैं तो न रामकृष्ण और आशीष किसान था। यह तो नौकरी करते हैं। इनके यहां जो काम करने वाला घनश्याम नेताम है वह पूरी खेती की देख रेख करता है। यही धान बेचता भी है और सब कुछ यही करता है। बोरा ले गया, जितना बोरा ले गया, उसमें उसकी धान बेची गई है। उसमें सबमें घनश्याम नेताम के हस्ताक्षर हैं।

(2) **<u>नगरपालिका परिषद बेमेतरा में जल प्रदाय आवर्धन योजना में अनियमितता किया जाना।</u>**

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

राज्य सरकार द्वारा जल प्रदाय आवर्धन योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बेमेतरा के 21 वार्डों में मीठा पानी पहुॅचाने हेतु दिनांक 12.03.2012 को 16 करोड़ 55 लाख रू. की राशि स्वीकृत की गई। इस योजना का कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने तथा राशि नहीं होने के कारण दिनांक 08.03.2019 को 21 करोड़ 26 लाख 44 हजार रू. की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई, किन्तु आज दिनांक तक नगर पालिका के सभी वार्डों में मीठे पानी की सप्लाई प्रांरभ नहीं हो पाई है। बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र

खारे पानी की समस्या से ग्रस्त है। राज्य शासन द्वारा 02 बार योजना के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं 10 वर्ष के उपरांत भी योजना का पूरा न होना विभाग में अनियमितता को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनेकों बार शिकायतें की गई हैं किन्तु अब तक कार्य पूर्ण नहीं होने से आम जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी का गला अभी खराब है, उनका वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाये। आप प्रश्न कर लीजिए।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- यह कथन सही नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा जल आवर्धन योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बेमेतरा के 21 वार्डो में मीठा पानी पहुंचाने हेतु दिनांक 12.03.2012 को राशि रुपये 16 करोड़ 55 लाख स्वीकृत की गई है, अपितु 20 वार्डों हेतु बेमेतरा शहर की आवर्धन जलप्रदाय योजना लागत राशि रुपये 16 करोड़ 55 लाख की दिनांक 12.03.2012 को स्वीकृत की गई थी। यह कथन सही है कि दिनांक 08.03.2019 को 21 करोड़ 26 लाख 44 हजार रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है। किन्तु यह सही नहीं है कि आज दिनांक तक नगर पालिका के सभी वार्डों में मीठे पानी की सप्लाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। सत्य यह है कि बेमेतरा शहर की योजना 20 वार्डों के रहवासियों को लाभान्वित करने हेतु स्वीकृत की जाकर कार्य पूर्ण कर दिनांक 24.06.2020 को नगर पालिका को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही यह भी सत्य है कि योजना स्वीकृति पश्चात 01 नवीन वार्ड क्रमांक 10 अस्तित्व में आया। बेमेतरा आवर्धन जल प्रदाय योजना का संचालन एवं संधारण बेमेतरा नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह कहना सही नहीं है कि राज्य शासन द्वारा दो बार योजना के राशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के बाद भी एवं 10 वर्ष में भी योजना का पूर्ण न होना विभाग में अनियमितता प्रदर्शित करता है। अपितु योजना को पूर्ण कर दिनांक 24.06.2020 को नगर पालिका परिषद बेमेतरा को संचालन संधारण हेतु सौंपा गया एवं योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

सड़क चौड़ीकरण के कारण पाईप लाईन क्षतिग्रसत होने से कुछ वार्डों की पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन वार्डों में नलकूप पेयजल स्त्रोतों के माध्यम से वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा की जा रही है।

अत: यह कथन स्वीकार्य योग्य नहीं है कि आम जनता में रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम बेमेतरा की बात करें तो बेमेतरा नगरीय क्षेत्र है और जिले का मुख्यालय है। बेमेतरा नगरपालिका का पानी काफी खारा है। सी.एम.एच.ओ. की रिपोर्ट भी हम लोगों ने मंगाई है उसमे बेमेतरा के पानी में लगभग 1100 से 1200 की मात्रा में टी.डी.एस. पाया जाता है। जबकि अगर

हम मानक की बात करें तो अधिकतम 150 से ज्यादा टी.डी.एस. की मात्रा होने पर गंभीर बीमारी की आशंकायें होती है। अगर हम शहरी क्षेत्र में देखें, किडनी, पथरी एवं बहुत सारी गंभीर बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं। उसका सबसे बड़ा कारण वहां का पानी खारा होना है। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों की मांग में इस योजना की स्वीकृति हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 11 वर्ष बाद भी आज तक ये योजना पूर्ण नहीं हो पाई है और बेमेतरा शहरवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बतायें कि यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी? क्योंकि 11 वर्ष हो चुके हैं और एक बार उसकी रिवाइज की भी राशि स्वीकृत हो चुकी है। चूंकि बेमेतरा का यह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, यहां के पीने के पानी में टी.डी.एस. की मात्रा बहुत अधिक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 1-2 महीने में योजना को पूर्ण करवा दें। 21 वार्ड वासियों को कम से कम मीठा पानी मिल सके। इसी सरकार से उनको बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार के माध्यम से हमको जल्द पानी मिल पायेगा।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी की चिंता जायज भी है। लेकिन हमारी योजना जैसे मैंने अपने जवाब में दिया था कि दिनांक 24.06.2020 को पूर्ण करके नगरीय प्रशासन विभाग को हम हेण्डओवर कर चुके हैं। तो हैण्डओवर के बाद अगर कुछ बात होती है तो फिर उसको नगरीय प्रशासन देखता है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं यह कलेक्टर को मेरे पास लिखित अधिकृत जवाब है। साथ ही साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने भी माना है कि कल दिनांक तक नगरपालिका ने इसको हैण्डओवर नहीं लिया है। इसमें दिक्कत यहीं है कि पी.एच.ई. ये बोल रही है कि हम लोगों ने नगरपालिका को हैण्डओवर कर दिया है और नगरपालिका बोल रही है कि हम लोगों ने हैण्डओवर नहीं लिया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक योजना पूर्ण नहीं हो पाई है। जब तक 21 वार्डों में पानी सप्लाई न हो जाये, टेस्टिंग न हो जाये तो अधूरी योजना को नगरपालिका कैसे हैण्डओवर ले ले। साथ ही साथ एक बात और बता देना चाहता हूं उसमें जो 10 कर्मचारी कार्यरत हैं, पिछले एक साल से उनको भुगतान नहीं हो पाया है। पी.एच.ई. का कहना है कि हम लोगों ने नगरपालिका को हैण्डओवर कर दिया है और नगरपालिका बोल रही है कि लोगों ने हैण्डओवर नहीं लिया है । माननीय मंत्री जी, यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं विनम्रतापर्वूक आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बेमेतरा की जनता की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इसमें आप तत्काल अधिकारियों को निर्देशित करिये कि एक से दो महीने के अंदर पूरे 21 वार्डों में पानी की टेस्टिंग करें और टेस्टिंग करने के बाद नगर पालिका को हैंडओवर कर दें।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने कहा। शिव भाई। नगरीय प्रशासन मंत्री जी।

उपाध्यक्ष महोदय :- नगरीय प्रशासन मंत्री जी, थोड़ा मंत्री जी से बात मिला लीजिये।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जैसा कि मैंने आपके विभाग को हैंडओवर कर दिया है और हमारे सम्मान विधायक जी की जो चिंता है। हम दोनों विभाग मिलकर ..। मैं जवाब दे रहा हूं न। आप जवाब तो सुन लें।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं उनसे बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, नगरीय प्रशासन मंत्री और पी.एच.ई. मंत्री, दोनों मिलकर इस मामले को ठीक करेंगे।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- हम दोनों मिलकर हमारा विभाग देख लेगा। मैं यह सुनिश्चित करता हूं।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी मेरा अनुरोध है कि समय बहुत कम है। पानी से जुड़ा हुआ मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- छाबड़ा जी, उन्होंने दोनों जिम्मेदारी ले ली है। आपका काम ठीक हो जायेगा।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- एक समस सीमा सुनिश्चित हो जाए। 11 साल से यह पूरी नहीं हो पाई है।

उपाध्यक्ष महोदय :- समय वगैरह बताना हो तो बता दीजिये।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- लगभग 11 साल हो चुका है। बेमेतरा वाले 11 साल से मीठे पानी का इंतजार कर रहे हैं। समय सीमा सुनिश्चित हो जाए। एकाध करा दीजिये।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- बहुत जल्द। बहुत जल्द।

समय :

12.46 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चंद्राकर
2. श्री बघेल लखेश्वर
3. श्री चंदन कश्यप

समय :

12.47 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी सिमिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय विधेयक एवं अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय विधेयक क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 10 सन् 2021)	श्री सत्यनारायण शर्मा	1 घंटा

अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 03)	श्री अजय चंद्राकर	20 मिनट
2. (क्रमांक - 05)	श्री धर्मजीत सिंह	20 मिनट
3. (क्रमांक - 08)	श्री धरमलाल कौशिक	20 मिनट
4. (क्रमांक - 12)	श्री शिवरतन शर्मा	15 मिनट
5. (क्रमांक - 13)	श्री सत्यनारायण शर्मा	15 मिनट

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी मिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12.48 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

1. श्री नारायण चंदेल
2. श्री धरमलाल कौशिक
3. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
4. श्रीमती ममता चंद्राकर

समय :

12.48 बजे **वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा**

मांग संख्या	**1**	**सामान्य प्रशासन के लिये**
मांग संख्या	**2**	**सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये**
मांग संख्या	**6**	**वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए**
मांग संख्या	**60**	**जिला परियोजनओं से संबंधित व्यय के लिये**
मांग संख्या	**12**	**ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये**
मांग संख्या	**25**	**खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये**
मांग संख्या	**32**	**जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये**
मांग संख्यां	**71**	**इलेक्टॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये**
मांग संख्यां	**65**	**विमानन विभाग के लिये**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्यां - 1 सामान्य प्रशासन के लिये - पांच सौ उन्नीस करोड़, बयासी लाख, पचपन हजार रूपये,

मांग संख्यां - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये - चार सौ इकतीस करोड़, सत्तर लाख, आठ हजार रूपये,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्यां - 6 वित्त् विभाग से संबंधित व्यय के लिए सात हजार पांच सौ अन्ठावन करोड़, तेईस लाख, सोलह हजार रूपये,

मांग संख्यां - 60 जिला परियोजनओं से संबंधित व्यय के लिये - दो सौ आठ करोड़, पैंसठ लाख रूपये,

मांग संख्यां - 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन हजार चार सौ सन्तावन करोड़, अठाईस लाख, उनचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - छः सौ चौवन करोड़, सत्रह लाख, इक्कीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 32 जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये - पांच सौ निन्यानबे करोड़, सैंतीस लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्यां - 71 इलेक्टॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये - एक सौ छयालीस करोड़, बयासी लाख, अड़सठ हजार रूपये तथा

मांग संख्यां - 65 विमानन विभाग के लिये - एक सौ अठाईस करोड़, छियानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

मांग संख्या - 1

<u>सामान्य प्रशासन</u>

1. श्री नारायण चंदेल	5
2. श्री पुन्नूलाल मोहले	2
3. श्री अजय चंद्राकर	1
4. श्री धरमलाल कौशिक	13
5. श्री केशव प्रसाद चंद्रा	7
6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1
7. श्रीमती इंदू बंजारे	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 2

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय</u>

1. श्री नारायण चंदेल	2
2. श्री अजय चंद्राकर	1

मांग संख्या - 6

<u>वित्त विभाग से संबंधित व्यय</u>

1. श्री नारायण चंदेल	4
2. श्री अजय चंद्राकर	3
3. श्री धरमलाल कौशिक	10

मांग संख्या - 60

<u>जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय</u>

1. श्री नारायण चंदेल	2
2. श्री अजय चंद्राकर	1

मांग संख्या - 12

<u>ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय</u>

1. श्री नारायण चंदेल	5
2. श्री पुन्नूलाल मोहले	4
3. श्री अजय चंद्राकर	2
4. श्री धरमलाल कौशिक	4
5. श्री शिवरतन शर्मा	18
6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	2

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री नारायण चंदेल	5
2. श्री पुन्नूलाल मोहले	2
3. श्री अजय चंद्राकर	2
4. श्री धरमलाल कौशिक	4
5. श्री शिवरतन शर्मा	18

मांग संख्या - 32

जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री नारायण चंदेल	3
2. श्री धरमलाल कौशिक	3
3. श्री शिवरतन शर्मा	10

मांग संख्या - 71

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1. श्री नारायण चंदेल	3
2. श्री अजय चंद्राकर	3
3. श्री धरमलाल कौशिक	2
4. श्री शिवरतन शर्मा	2
5. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

मांग संख्या - 65

विमानन विभाग

1. श्री नारायण चंदेल	2

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2. श्री अजय चंद्राकर	1
3. श्री धरमलाल कौशिक	2
4. श्री शिवरतन शर्मा	8

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थिति सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । श्री अजय चंद्राकर जी ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अजय भैया सही-सही बोलना। असत्य बिल्कुल नहीं बोलना ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- असत्य नहीं बोलना ।

श्री शैलेश पांडे :- हां, बिजली का तार छूकर ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप लोग केवल दो चीज के लिये ही मुंह खोलते हैं एक खाने के लिये और असत्य बोलने के लिये । तीसरी चीज के लिये आप लोग मुंह ही नहीं खोलते हो ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- सही-सही बोलो भई । इधर-उधर मत बोलना ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आज अजय चंद्राकर साहब जो बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे ।

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गयी है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें । श्री अजय चंद्राकर जी ।

वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनका भी भोजन है। आप उनको बोल दीजिये कि रात तक चलता है तो रात को 9 बजे थोड़ा चाय वगैरह रखवा दिया करें नहीं तो माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से हर रोज हम लोग रखवा देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- वे सुन रहे हैं ।

श्री शैलेश पांडे :- अब बात यहां तक आ गयी है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं । उच्च न्यायालय हो, राजभवन हो और भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और उसमें विशेषकर चूंकि मैं राज्य की राजनीति करता हूं तो सदन के नेता जो भी हों । मैं उनको एक स्टेटमेन मानता हूं, एक इंस्टीट्यूशन मानता हूं । यदि इंस्टीट्यूशन मानते हैं तो मैं सोचता हूं कि आलोचना करने की बजाय हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रदेश अच्छी स्थिति की ओर जायेगा लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दलीय राजनीति और जो अकबर के नवरत्न थे, शिवाजी का अष्ट प्रधानमंडल था वैसे ही कुछ चंद लोगों से घिरे हैं और शायद उनके लिये ही वे स्टेटमेन हैं या उनके लिये इंस्टीट्यूशन हैं । हमारे जैसे लोग जो प्रदेश का भला चाहते हैं या कुछ सुझाव दे सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं या कुछ आग्रह कर सकते हैं तो यह माना जाता है कि ये लोग तो वैसे ही हैं और जब चर्चा बढ़ेगी तो वह साबित होगा । राज्य का हित सामने है या राजनीति सामने है ? पांच साल के कार्यकाल में आप किस तरह से याद किया जाना चाहते हैं ? छठवें साल की मैं राजनीतिक बात नहीं करता कि जनादेश किसके पक्ष में जाएगा, बहुमत किसको मिलेगा । किंतु पांच सालों में आप किस तरह याद किया जाना चाहते हैं ? कांग्रेस की बात नहीं करता, छत्तीसगढ़ के लोगों में यह एक यक्ष प्रश्न है । आखिरी बजट आ चुका है । संसदीय कार्य मंत्री जी के विभाग की चर्चा होगी तो अष्टप्रधान मंडल के वे प्रमुख आदमी हैं और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे जिम्मेदार हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी उनको भी लेनी पड़ेगी । प्रदेश के सामने जो चिंता है, वित्त विभाग में बहुत चर्चा हुई है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा । किंतु 82 हजार करोड़ रूपए और 20 हजार 689 करोड़ रूपए, बाकी कर्जों को जोड़ दें तो हमारे बजट का साइज़ और हमारे कर्जे का साइज़ एक हो रहा है । दूसरी बात जो मुख्य चिंता है कि हमारे जो अल्पकालिक लोन हैं वे 2024-25, 2026-27 से मैच्योर होने शुरू हो जाएंगे, जो आने वाली सरकार है उसके समय में । तीसरी बात है कि पूंजीगत् व्यय में जितने अनुमान लगाए गए, जितनी राशि रखी गई । आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिए कि वह लगातार कम हुए हैं । 11 परसेंट, 12 परसेंट, जितने अनुमान लगाए गए । एक नवोदित राज्य जिसकी छवि समकालीन समय में बने उत्तराखंड या झारखंड के मुकाबले तेज़ी से बढ़ते हुए राज्य के तौर पर स्थापित हुई और कई क्षेत्रों में हमने मापदंड स्थापित भी किये, जिसको वो भी नकार नहीं सकते । आप मुख्यमंत्री जी के दोनों भाषण निकालकर पढ़ लीजिए । राज्यपाल के अभिभाषण पर जब मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया और बजट पर चर्चा का उन्होंने जवाब दिया । राज्यपाल के भाषण में एक ही लाईन थी । आपके 15 साल में यह था, हमारे 4 साल में यह है । आपके 15 साल में यह था, हमारे 4 साल में यह है । एक स्टेटिकल भाषण था, जो राजनीतिक शैली होती है । जो दीर्घा में बैठे हैं, वे हमारे लिए भी बनाते थे, वे इनके लिए भी बनाते हैं । विधायिका का काम नीति और कानून बनाने का है, उसको चलाने का है । वह तो बजट के एक लाख

कर्जे को एक सज्जन को मैंने पैसे की मांग की, बजट चर्चा में कहा कि साहब छत्तीसगढ़ तो मध्यप्रदेश की ओर जा रहा है । अब वे कर्जे उस समय से तीन गुना बढ़ गए तो उसके तथ्यात्मक तर्क दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मजबूत स्थिति में इसलिए है कि हमने दो साल से कर्जा नहीं लिया है । छत्तीसगढ़ इसलिए मजबूत स्थिति में है कि हमारा राजस्व व्यय बढ़ रहा है । आपने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आप पदोन्नति, क्रमोन्नति, भर्ती करेंगे । आप राजनीतिक दल हैं आपका जो भी घोषणा पत्र है । हमने जो प्रणाली स्वीकार की है, हम यदि दल के घोषणा पत्र में बंधे हैं उसमें भरोसा करते हैं, यदि किंचित सीमा तक जाते हैं । आपने 1 से 11 क्रम तक वृद्धि कर दी, ठीक किया । आपके जो घोषणा पत्र रहे होंगे । अब यह बताइए, मैं मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा कर सकता हूं कि एक अपंजीकृत क्लब, राजीव मितान क्लब जिसके बारे में आज मैंने पूछा । आप बताएंगे कि किस नियम से आप अपंजीकृत संस्था को 32 करोड़ की राशि और उसके लिए 132 करोड़ का आयोजन हो सकता है, उसको राशि दी जा सकती है, बताइएगा ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- पंजीकृत है । आप क्यों बोलते हैं कि पंजीयन नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उत्तर में दे दीजिएगा ।

श्री उमेश पटेल :- मैंने तो बताया ना आपको ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं प्रश्न के उत्तर में दे दूंगा । आपके प्रश्न को रख दूंगा । मैं जब पटल पर रखने की अनुमति मांगता हूं तो आप अनुमति नहीं देते हैं ।

श्री उमेश पटेल :- आप कहेंगे कि हर ब्रांच का पंजीयन होगा, हर गांव के राजीव मितान क्लब का पंजीयन होगा तो ऐसा नहीं होता । मेन संस्था का पंजीयन होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप दीजिए उसको भी । आपने सोसायटी में अध्यक्ष बनाया, नियम में संशोधन किया, कोई निर्देश जारी नहीं किया । शराबी बनेगा, गंजेड़ी बनेगा, कांग्रेसी बनेगा, पागल बनेगा ऐसा कोई तो निर्देश जारी कर देना था ।

श्री कवासी लखमा :- सर, ये गंजेड़ी बोल रहे हैं, उसको निकाल दिया जाए । ये खुद भी बचपन में ऐसे ही थे ।

समय :
01:00 बजे

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, कोई निर्देश नहीं, क्या शासन बिना निर्देशों के चलता है, आप नियम बनाते हैं, उसके निर्देश बनाने की जरूरत नहीं है ? आपने मंडी अध्यक्ष मनोनीत किए। नियमों में जो आदमी अध्यक्ष बन सकता है, कौन-कौन से रिश्तेदार बनेंगे, आप कृषि मंत्री हैं, उसका पूरा वाईलेशन। आपने गौठान समिति के अध्यक्षों को पैसा दिया और मुझे यह कहते हैं या मेरे दल को यह कहते हैं कि साहब यह रेवड़ी संस्कृति नहीं है। आपने कर्मचारियों के लिए किया।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, इनको पैसा देने से बड़ा दर्द हो रहा है। उद्योगपतियों को अंबानी, अडाणी को पैसा देते तो यह खुश होते। अगर हमने गौठान के उस महिला समूह, गरीब समूहों को पैसा दिया है तो इनको बड़ी तकलीफ है। अगर हम गोबर बेचकर पैसा दे रहे हैं, गांव में पैसा जा रहा है, गांव का विकास हो रहा है तो इनको बड़ी तकलीफ है। अगर कृषि उपज मंडी खाली है और वहां जो किसान हैं, उसमें सदस्य होते हैं, लोगों को अध्यक्ष बनाया गया, सोसायटी में जो लोग धान बेचते हैं, वे लोग अध्यक्ष बन गये, अगर वे बेहतर काम करें तो आपको बहुत पीड़ा हो रही है। यह अंबानी अडाणी को बना देते हैं तो बड़े खुश होते हैं।

श्री उमेश पटेल :- बृहस्पत सिंह जी, इनको तो किसानों के कर्ज माफी पर इतना पीड़ा था कि इस्तीफा का भी प्रस्ताव रख दिए थे।

श्री बृहस्पत सिंह :- पटेल साहब, किसानों की पीड़ा तो छोड़िए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नौजवान बेरोजगार हैं, उनको सरकार ने 2500 रूपये दे दिया तो इनको पेट में दर्द होने लगा। ये खूब आंदोलन करते फिर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, उनको बोलने का अवसर मिला है, आपका भी नंबर है। साहब, आपका दूसरा नंबर है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, यह जो कहना चाहें, कहें। बेरोजगारी की परिभाषा पर अभी आधा घंटा चर्चा चलही, पूरे प्रदेश के दायरे को देखा।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, परिभाषा नहीं, पैसा दे रहे हैं। 1 अप्रैल से लागू कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिए मुझे उसमें कोई बहस नहीं करनी है। ऐसा है, मैंने आग्रहपूर्वक कहा है कि अमरजीत जी, जितनी बार खड़े होंगे, मैं बैठ जाऊंगा। आप टोक लेना, जितना टोकना है।

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी, आप सत्य कथन तो कहें। राजीव युवा मितान हमारे प्रदेश में पहली बार आया है और युवाओं का भविष्य बन रहा है, आप उसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आपने तो कुछ किया नहीं। हर साल दो करोड़ लोगों को नौकरी आज तक नहीं मिली। हमारे युवा मंत्री जी, युवाओं के लिए सोचते हैं तो क्या गलत सोचते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- देखिए, सभी माननीय सदस्यों को इस अनुदान मांग में चर्चा करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। अगर कोई बिना अनुमति के खड़े होंगे तो उसको मान्य नहीं देंगे, आप बारी-बारी से बोलिए। अजय चंद्राकर जी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, मेरा नॉलेज कम है बोल देता हूं, बृहस्पत सिंह जी, अरूण वोरा जी, डहरिया जी और कवासी लखमा से मेरा नॉलेज कम है, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। (हंसी)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हम लोग आपकी अनुमति लेकर बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने अभी इनको बोला है। दूसरी बात, आप भी ऐसा मत बोलिए, मैं आपकी समय की बचत कर रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने टिप्पणी नहीं की, मैंने तो स्वीकार किया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अगर यह आपत्तिजनक बात बोलेंगे, असत्य बोलेंगे तो हम लोगों को उनको बोलना ही पड़ेगा। आपत्ति तो करना पड़ेगा।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- व्यक्तिगत आक्षेप ना करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- देखिए, सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। चंद्राकर जी सुनिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो आपकी ओर देखकर बोल रहा हूं, मैंने स्वीकार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप अभी बैठ जाईए। सभी माननीय लोग हैं, अपनी महत्वपूर्ण बात कहने के लिए सदन में आते हैं, मैं यह कह रहा था, सबको मौका मिलेगा पर अनुमति लेकर कहें और अपनी बात कह सकते हैं। आपस में ना कहें। दो विभागों की चर्चा है, बहुत आगे भी जाना है।

वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- उपाध्यक्ष जी, रमन सिंह बोलते हैं, मामा बोलते हैं, नेता जी, बोलते हैं तो इसी के लिए क्यों बोलते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- रमन सिंह जी तोर सेवक ए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें।

श्री कवासी लखमा :- यह असत्य-असत्य बोलते हैं, उल्टा करते हैं, रमन सिंह से सीखिए। उनके भाषण में कभी उठकर नहीं बोलते। प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं तो हम कभी उठकर नहीं बोलते। ननकीराम बोलते हैं, हम उठेगें नहीं। यह क्यों उल्टा-उल्टा बोलते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- संबोधन कैसे है देखिए। रमन सिंह, ननकीराम। यह उनका संबोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप भी ऐसे शब्द बोलिए और भी विपक्ष हैं। चलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने इसलिए ऐसा कहा कि माननीय मुख्य सचिव जी भी दीर्घा में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के जितने उपक्रम हैं, सोसायटी या कंपनी में पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास प्राधिकरण मेरा उत्तर था, बोले की केबिनेट से गठन है। उसमें केबिनेट से नियम बनाये गये हैं। 408 करोड़ रूपये दे दिए गए। हम कोई योजना बनाते हैं तो वह वित्त विभाग जाता है। ग्राम पंचायत की लागत 14 लाख होगी, सी.सी. 100 मीटर रोड दो करोड़ साठ लाख का होगा। कॉलेज की बिल्डिंग स्टैंडर्ड बनाती है, वह 5 करोड़ का होगा। वह वित्त से अनुमोदित होता है। उसके हिसाब से वह पैसे खर्च होते हैं। उसमें लोक कल्याणकारी में क्या लिखा है, मूलभूत कार्यों में किया जाएगा। मूलभूत कार्यों का क्या

इस्टीमेट होगा ? कैसे स्वीकृती दी जाएगी ? यह दु:ख की बात है कि शेष का पैसा लगाया गया। मैं हाईकोर्ट में गया हूं। यह सरकार एक साल से हाई कोई में उत्तर नहीं दे रही है। अभी इनको 4 हफ्ते का समय और मिला है। (शेम-शेम की आवाज) वह शेष का पैसा मुख्यमंत्री अधोसंरचना बोर्ड में दिया गया। मैंने इस देश में यह पहली बार सुना कि केबिनेट से हुआ, केबिनेट में उसके नियम बनाये गये और उसको फलाना की तरह पंजीयन करवाने और कंपनी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको एक साल 400 करोड़ रूपये और एक साल 404 करोड़ रूपये की राशि मिली है और वह राशि खर्च हो रही है। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप क्यों लगाऊंगा? यह सदन और यह देश सुने और यह तय करे कि यह सही है या गलत है कि शेष लगता किसी चीज के लिए है, खर्च किसी और चीज में होता है और इसके पंजीयन या कंपनी बनाने की जरूरत है या नहीं है या केबिनेट इसके लिए सक्षम है? यह अच्छी बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 16 मार्च, 2023 की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न क्रमांक-9 में राजीव गांधी क्लब का पंजीयन नहीं कराने पर बोल रहा था। मैं क्षमा मांग लेता हूं तो भी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इसका उदाहरण बता दूंगा। मैंने आपको विधान सभा के प्रश्न के उत्तर को बताया है। मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसकी एक विश्वसनीयता होती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धरसा योजना बनेगी। हम लोगों ने इस साल के बजट में धरसा योजना के लिए 1 रूपये भी नहीं देखा। ससंदीय कार्य मंत्री जी, आप हमें यह बात दीजिए कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं, उस पर भरोसा करें या न करें? मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि पंजीयन विभाग के अभिलेखों में अब पंजीयन शुल्क पर युवा विकास उपकर लगाया जाएगा। मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रश्न पूछा तो वह बोलते हैं कि हमने कोई उपकर वसूल नहीं किया है। अब यह सदन मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा करे या न करे या यह सदन मजाक का विषय हो गया है? मैं आज दोपहर और कल के उत्तर की जानकारी भर ला रहा हूं। एक माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मैंने पेपर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की और आज एक माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने उसको मान्यता नहीं दी है लेकिन उनकी रिपोर्ट को उसके परिशिष्ट में संलग्न किया गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैंने अपने संक्षिप्त जीवन में विधान सभा की ऐसी स्थिति नहीं देखी है। यदि आपने देखी होगी तो अच्छी बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नौकरी भर की बात करना चाहता हूं। वित्त पर बहुत चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं और उन्होंने लोकवाणी में भी 5 लाख नौकरी देने की बात कही। बिलासपुर की सभा में कुछ लाख नौकरी देने की बात कही। आपके जनसंपर्क विभाग में 4 लाख 60 नौकरी देने के बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं। मैंने एक अधिकारी को फोन किया कि आप यह बताइये कि यह कौन से आंकड़े हैं? आज इनके उत्तर में 33 हजार के लगभग आया है, मतलब उससे कम है। नौकरी में

आखिर सच क्या है? मैं इसको भगवान के घर से नहीं बोल रहा हूं। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सरकार की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो आंकड़े जारी किये गये।

श्री उमेश पटेल :- अजय भैया, क्या है कि आप बहुत सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं। आप पूछते कुछ और हैं और उसके उत्तर की आधी लाइन यहां पर पढ़कर बता देते हैं तो ऐसा लगता है कि आप क्या-क्या बोल रहे हैं? आपने जिस कंटेक्स्ट में पूछा है, उस कंटेक्स्ट में।

श्री रामकुमार यादव :- गुड़-गोबर ला दोनों ला मिला देथे।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये, मैंने उसको भी स्वीकार कर लिया कि 4 साल में जो नौकरी दी गई है, केवल उसकी संख्या को माना जाए, बाकी मैंने उमेश पटेल जी से गलत प्रश्न पूछा है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया। यदि हम नौकरी के इस डाटा को देखे तो यह अलग-अलग हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसीलिए इंस्टीट्यूशन कहा क्योंकि हमने इतनी नौकरी दी है। मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा। मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डाल रहा हूं। जो सबसे बड़ी चिंता है वह इस प्रदेश का घटता पूंजी व्यय और बढ़ता कर्ज है। यहां गरीबी उन्मूलन की कोई योजना नहीं है। जब पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी खड़े होंगे तो जैसे ही मेरे नेता सम्माननीय नारायण चंदेल जी आदेश देंगे तो मैं उनके विभाग की चर्चा में भाग लूंगा और उनसे जरूर पूछूंगा कि यह सरकार छत्तीसगढ़ में गरीबी उन्मूलन की कौन सी योजना चला रही है? वह इस बात को जानते हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसीलिए बना है और उसका मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। बजट में गरीबी उन्मूलन और गरीबों के लिए एक भी योजना नहीं है। मैं वित्त विभाग में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा । विमानन विभाग में बोल लेता हूं, अंत में सामान्य प्रशासन विभाग में बोलूंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हेलीकाप्टर के रख-रखाव में किए गए खर्च 200 करोड़ में 7 करोड़, अगस्ता में 19 करोड़, इन्होंने मेंटनेंस में कुल 27 करोड़ खर्च किया है । यह एक खेल है । विमानन संचालनालय में हेलीकाप्टर बिगड़ा है, वह कितने दिन के लिए बिगड़ा है, क्या बिगड़ा है, उसके पार्ट्स कैसे आएंगे, कितने दिन में आएंगे, इसको चेक करने वाला थर्ड पार्टी नहीं है । जो वहां का आदमी बोले, वह सच है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरहा वाला हेलीकाप्टर लेबे त ओमा पईसा खर्चा होही कि नहीं होही ? हेलीकाप्टर ला तै ह सेकण्ड हैंड में लेस ।

श्री रामकुमार यादव :- उहू गिर हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपकी विद्वता की बहुत प्रशंसा करता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निजी विमान का 26 करोड़ रूपए और हेलीकाप्टर की सेवाएं 47 करोड़ रूपए कुल 72 करोड़ रूपए सिर्फ किराए में व्यय किए गए । चार वर्षों में 115 करोड़ रूपए रख-रखाव, आवागमन में खर्च किए गए ।

मुख्यमंत्री जी तो आचार संहिता से परे होते हैं, उन्होंने खुद के लिए जितना उपयोग किया, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, हमने कह दिया कि आप इंस्टीट्यूशन हैं । मैं कम से कम दिल्ली का उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं राजनीति यहां की करता हूं । बाकी विमान सेवाएं कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, एक एयरपोर्ट बनाएंगे, एक जगह बजट में घोषणा हुई। उसके लिए राशि कितनी है ? 33 जगह जमीन अधिग्रहण करना है, उसकी कार्यवाही शुरू की जाये । जहां हवाई पट्टी है, उसको छोड़कर छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी है कि बाकी मैदानी में न जोड़ें तो हमारे छोटे विमान कम से कम सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में सभी जगह उतर जाएं । इसके लिए हम तैयारी करेंगे । नीतिगत चीजों का जो कमिटमेंट दिखता है । मैं जोगी जी के और रमन सिंह जी के समय का उल्लेख ज्यादा नहीं करता । जोगी जी क्या कर रहे थे, रमन सिंह जी किस दिशा में थे, कभी वे बोलेंगे तो उसकी चर्चा करूंगा । आप 5 साल से किस दिशा में है, जिसके लिए आपका मेन्डेट है, मुख्य चर्चा का विषय यह है । आरोप लगाने, तुलना करने के लिए आप कर लें तो उसके बारे में देश में एक पॉलिसी बनी-उड़े आम आदमी । उसके तहत जगदलपुर से, बिलासपुर से अनेक छोटी-छोटी सेवाएं शुरू हुईं । यहां से जगदलपुर जाते हैं, बिलासपुर जाते हैं । ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी मिले । इस देश में 70 एयरपोर्ट थे, वह इन सालों में 140-150 से ऊपर हो गए । उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा । मैंने बजट की चर्चा में जाते हुए कहा कि एक फैकल्टी खोलने के लिए लोग पूछते थे कि रायपुर से खैरागढ़ कितनी दूर है । तो यह हालत विमानन में है । विमानन में कोई दृष्टि नहीं है, बस मेंटेन करना है, किराया लेना है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय जी, चन्द्राकर जी बोल रहे हैं कि देश में 70 एयरपोर्ट थे । मोदी जी के आने में बाद कितने बिक गए, वह भी बता दें।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष जी, यूपीए की सरकार में प्रफुल्ल पटेल जी ने एयरपोर्ट को बेचने का काम जीएमआर को आपने चालू किया था ।

श्री उमेश पटेल :- किसकी सरकार के समय में बिका, वह भी तो बताईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं वह भी बता देता हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, आप रिकार्ड निकालकर देख लो । आपके मोदी जी के समय में कितने एयरपोर्ट बिके, कितने रेल्वे स्टेशन बिके, कितने बंदरगाह बिके और कितने हवाई अड्डे बिके । आज भी अडानी के नाम बोर्ड पर लगे हुए दिखते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी, बनाए के काम हमन करन अउ बेचे के काम एमन करय अउ दोषी भी मनी मन आन ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप लोग राज्यसभा में 3 प्योर छत्तीसगढ़िया को भेजे हो न, उन लोगों से बोलकर वहां प्रश्न लगाना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जो करते हो, उसको मैं देखता हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- जइसे बनाए के करबो तो ए मन सूची ला फैक्स कर दिही ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन बेचा, क्या बेचा, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मोदी जी को पता चलेगा कि चन्द्राकर जी ने एयरपोर्ट बेचने की बात कही है तो फिर गड़बड हो जाएगा इसलिए आप बोल नहीं सकते, आप में बोलने की हिम्मत नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में माननीय नरसिंहराव जी और उसके बाद उसको इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने आकार दिया । डिस्इंवेस्टमेंट, बाजार का खुलापन चीन जैसे कम्यूनिष्ट देश अपना रहे हैं, वह डेंग शियाउपिंग के समय में सन् 1979 में शुरू कर लिया, आज दुनिया की दूसरी व्यवस्था है । हमने विलम्ब से शुरू किया तो दुनिया की 5वीं व्यवस्था अभी-अभी बने हैं । जो शुरू से इस व्यवस्था में थे, आज दुनिया पर राज कर रहे हैं और हम इसी में हैं कि तेरा किया या मेरा किया, इसने किया या उसने किया, तेरे बाप ने किया या तेरे बाप ने किया ? सबने किया, लेकिन अलग-अलग नीतियां रहीं। विनिवेश कितना प्रतिशत किसका होगा, कितना प्रतिशत किसका होगा, किस तरह से विनिवेश किया जायेगा। लेकिन किसी सरकार ने इसको छोड़ा नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चौबे जी, खनिज विभाग में एक बयान आया। मैं तो सोचता हूं कि मुख्यमंत्री जी के विभाग में जितनी पारदर्शिता होनी चाहिए, उतना होना चाहिए। लेकिन ऑनलाईन को आफलाईन किया गया है। उसका यह स्पष्टीकरण दिया गया कि आफलाईन करने से राजस्व में वृद्धि हुई है। वाह, हिन्दुस्तान में ऐसा तर्क यहीं का खनिज विभाग दे सकता है। कहीं और प्रदेश का खनिज विभाग नहीं दे सकता है कि ऑनलाईन को आफलाइन करने से राजस्व में वृद्धि होती है। हमारे कोयला उत्पादन में कमी आई है। आप आर्थिक सर्वे को देख लीजिये, आपकी रिपोर्ट में है। जिन-जिन कार्यों में डी.एम.एफ. का उपयोग किया जा सकता है, उस सूची को देख लीजिये और कलेक्टर के स्वीकृत काम को देख लीजिये। इसमें आरोप लगाने के बजाय मुझे यह कहना है कि आपको जो स्वीकृत करना है, उसको सूची में शामिल करवा लीजिये, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें संशोधन कर लें। आपने जो प्रतिवेदन में दिया है, उन सब कामों को शामिल कर लीजिये। फिर मोहन मरकाम जी आरोप नहीं लगायेंगे कि 7 करोड़ का बंदरबांट हुआ है, उसके बाद देश के गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी आरोप नहीं लगायेंगे कि 9 हजार करोड़ का गड़बड़ हुआ है। उन सारी गड़बड़ियों को वैधानिक कर लीजिये, जैसे आप केबिनेट में मुख्यमंत्री उन्नयन बोर्ड को कर दिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, दिल्ली वाले डी.एम.एफ. का नियम बनाकर भेज रहे हैं। वहीं से करवा लो न भईया। जो कराना है, वहीं से करा लो, मोदी जी से लिखवाकर भेज दो।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. मद में संशोधन करके किसको रखा जाये, किसको नहीं रखा जाये, किसको अध्यक्ष बनाया जाये, आपकी सरकार ने दिल्ली से तय हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप भी समझ रहे हैं कि उन सब स्वीकृत कार्यों को डी.एम.एफ. के कार्यों में लिखे हैं। उसको प्रतिवेदन में शामिल कर दीजिये और जो करना है, करिये, कोई आपत्ति नहीं है। हम आरोप नहीं लगायेंगे ना मोहन मरकाम जी आरोप लगायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरण्डम खनिज परियोजना के तहत स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आप 10 गांवों को हटाने की कार्ययोजना अभी तक नहीं बना पाये हैं। कहां से छत्तीसगढ का राजस्व बढ़ेगा ? डोलोमाइट खनिज अन्तर्गत सी.एम.डी.सी. के पक्ष में खनिज पट्टा स्वीकृति हेतु किया गया आवेदन एक वर्ष से लंबित है। यह मुख्यमंत्री जी का विभाग है। 2019-2020 एवं 2020 के कोल ब्लाक आवंटन में छत्तीसगढ़ को एक भी कोल ब्लाक नहीं दिया है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- खाली पानी था न ?

श्री रामकुमार यादव :- पानी नो हे, ओ हा जल हे जल।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, अडाणी जी, अडाणी जी, अडाणी जी, तो अडाणी जी के लिए कितने गांव उजाड़ रहे हैं, उत्तर में थोड़ा बता देंगे या अडाणी को कैंसल कर रहे हैं, यह बता देंगे। मैं राजनीतिक तौर पर बोल सकता था, लेकिन मैं राजनीतिक तौर पर बोलना नहीं चाहता हूं। क्या है कि राजनीतिक तौर पर अंदर-बाहर, सड़क, सदन, माननीय राज्यपाल के हाऊस में अभिभाषण, उसको सामान्य प्रशासन में बोलूंगा। आप इसलिए जा रहे क्योंकि कुछ न कुछ निहितार्थ है। किसी व्यक्ति के नाम से आंदोलन नहीं होता है, राजनीतिक पार्टी कोई व्यक्ति के नाम से आंदोलन नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो रही है। अडाणी जी की गड़बड़ी या सही की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनी है। यदि सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था पर भरोसा नहीं है और यदि उसमें लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, तो इंतजार कीजिये, देश है।

उपाध्यक्ष महोदय, अवैध रेत खनन के 685 प्रकरण दर्ज हुए थे, सब सेटलमेंट हो गए। किसी एक में भी कार्यवाही नहीं हुई। रेत खदान, यहां सारा बड़ा प्रशासन है, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं एक दिन कलेक्टर को बोला । एक छत्तीसगढ़ के ...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ के माफिया को एक आदमी ने धमकाया । मैंने रिपोर्ट करने के लिये कहा, जिस अधिकारी को मैंने फोन किया, मेरे पास राईफल भी है और रिवाल्वर भी है बोला । यदि आप नहीं किये तो मैं उस गांव में उसके पास जाऊंगा । वह जेसीबी चला ले, दुनिया चलाना है, सड़क खराब कर दे, कल भी मैंने कहा कि 32 टन की सड़क यहां बनाईये, प्रशासन के हाथ-पैर रेती वालों को देखकर लद-लद कांपते हैं । और कौन है, आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री के जिले के और उनके निर्वाचन क्षेत्र के हैं, गृह मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र और उसके जिले के हैं । खनिज विभाग से नाम निकलवा लो ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय जी, गलत बात है, इस तरह से..।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई आरोप नहीं लगवा रहा हूँ, पूरा भाषण विलोपित कर दो । यदि आलोचना है तो, और आप सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोग खड़े होते हैं तो । मानलो नेहरू जी को आप अपना आदर्श मानते हैं ना, जिसने आलोचना को सुना है, वही बड़ा डेमोक्रेट हुआ है, वही इतिहास में नाम दर्ज कराया है। और यह संसदीय इतिहास, यह दुनिया का इतिहास, चंद लोगों का है, जो कुछ बदलने की इच्छा रखते थे । ऐसे लोगों का इतिहास नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कभी-कभी बहुत अच्छा शिक्षा देते हो । कभी-कभी अजय जी बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं । यहां आपको कह रहे हैं कि आलोचना सुनना चाहिये करके, पार्लियामेंट में क्यों नहीं सुनते ? राहुल जी जब बोलते हैं तो क्यों विलोपित कर दिया जाता है ? कभी एकाध लाईन उधर के बारे में भी बोल दिया करो ? अभी अडानी के बारे में भारी चर्चा कर रहे थे । सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है । मांग क्या कर रहे हैं, जेपीसी की ही तो मांग कर रहे हैं ? उससे ज्यादा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये ना । सुनिये तो । एक मिनट । भाई साहब, आप संसद विज्ञ हैं । आप संसदीय प्रणाली के ज्ञाता हैं । वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली में 10 लोगों का नाम लिखा जायेगा तो एक आपका भी आयेगा, मैं जिसका उल्लेख संसदीय कार्य में करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि विधान सभा की बात विधान सभा में ही हो । उदाहरण दिया, सिर्फ आलोचना में दिया । जब ये लोग बार-बार खड़े होते हैं तो मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ करके । उपाध्यक्ष महोदय, भारत की बात विदेश में नहीं हो । छत्तीसगढ़ के बाहर...। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- पहली बार प्रधानमंत्री ये...। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- जो विदेश में बोलते हैं ना, आपके नेता को समझा दीजिए..(व्यवधान) अपने नेता को समझा दीजिए । हमारे देश को बेचने की बात वहां जाकर न करें (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- हमारे नेताओं ने नहीं कहा । (व्यवधान)

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- भईया अजय जी, मोदी जी विदेशों में जाकर बोलते हैं, भारत देश को पहले कोई पूछता नहीं था, अच्छा लगता है ।

श्री रामकुमार यादव :- पहला प्रधानमंत्री है जो विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, अवैध रेत परिवहन के मामले में कोई कार्यवाही उसके बाद नहीं हुई । मैं लगातार व्यस्त हो गया, आपके एक विभाग की चर्चा में दूसरे नंबर पर मैंने कहा...।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप चर्चा कर रहे थे कि राईफल भी है, रिवाल्वर भी है । उसके आगे नहीं बढ़े ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 18 चक्के के लायक, जितना वजन आता है, ग्रामीण सड़कों को उसी एस.ओ.आर. में बनाईये । यदि उससे कम में बनाते हैं तो राजकीय धन का अपव्यय कर रहे हैं । एक बनाईये, दोबारा बनाना मत पड़े । अपने क्षेत्र का बनाईये, वहां से शुरू कीजिए । हमारे पास रेत घाट है, उसमें मत बनाईये, लेकिन शासकीय धन का अपव्यय मत कीजिए । अध्यक्ष महोदय, आपने कल भाषण देते वख्त कोयले की रायल्टी की बात की थी कि दिल्ली से कोयले की रायल्टी नहीं मिल रही है । आपने कल एक परम्परा स्थापित की है, जो लोग सदन में नहीं थे, उसका भी नाम लिया है । उस विषय में आऊंगा तो उचित समय में और लोगों का नाम मैं भी लूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, कोयले की तो यहां समानान्तर अर्थव्यवस्था है, राजस्व तो सरकार का घट रहा है । उधर आई.ए.एस. क्यों जा रहे हैं, उधर पुलिस अधीक्षक क्यों जा रहे हैं ? कोरिया से रायगढ़ तक कल कारीडोर में उल्लेख हो गया था, कोयले को लेने के कारण सारी चीज जिसकी आप आलोचना करते हैं, वह घट रही है । आपको समानान्तर अर्थव्यवस्था से मतलब होना चाहिये, न कि राजस्व से ? जो शराब में हो रहा है, जो रेती में हो रहा है, कोयले में भी वही हो रहा है । अगर आप अनुमति देंगे तो मैं तीन दिन से बोल रहा हूँ कि शराब कौन ला रहा है, पटल पर रखूंगा । मुझे जांच कराने का आश्वासन दो । आप दे नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं । खनिज में राजस्व बढ़ सकता है, आपका प्रबंधन सही हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी सही हो, आप राजनीति से परे हों तो ? इसका सही प्रबंधन करेंगे तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप शायद शराब मुक्त प्रदेश की ओर बढ़ जायेंगे। अब जनसंपर्क विभाग में बोल देता हूं। 04 साल में आपकी क्या छबि बनी है ? आपने एजेंसी भी रखी है। प्रचार प्रसार विभाग के होने के बाद आपकी क्या छबि बनी है ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- देश में एक नंबर।

श्री अजय चन्द्राकर :- सौम्य आदमी है, मुस्कुराते हुए आदमी है, दबंग प्रशासक है, सज्जन आदमी है, डेमोक्रेटिक आदमी है। आपकी क्या छबि बनी है ? मैं बता देता हूं।

संसदीय सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबद्ध (श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर) :- अजय भैया, ऐसे छबि बनी है कि छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेता मन हा काय कहाथे ...।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- भूपेश है तो भरोसा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें भी टोकना है ? अब क्या बताया जाए। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने टोकने वालों की इतनी वाइब्रेंट फोर्स तैयार की है। आप समझ रहे हैं ना। आपकी Victimhood की छबि बनी है। आप हर बात का रोना रोते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, आप याद करिये कि जब आप यहां बैठते थे और हम वहां बैठते थे, तब आपकी भाषा क्या होती थी। आप जरा उसको भी याद कर लिया करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, जब हम प्रधानमंत्री आवास की बात आयेगी तो आप कहते हैं मैं सर्वे कराऊंगा, जब जल-जीवन मिशन की बात करेंगे तो दिल्ली ऐसा हो गया, मैं जनगणना

कराऊंगा। जनहित से जुड़ी हर बात के लिये कोई न कोई बहाना, कोई न कोई तरीका और दिल्ली को खोजना। अपने आप को बेचारे के तौर पर प्रस्तुत करना। आपके जनसंपर्क विभाग ने आपकी छबि Victimhood की बना दी है, यही छपता।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, सही व्यक्ति को देने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माता जी, तै डॉक्टर जरूर हस। अब बोलहू तहान ते कभी जाकर अइसने मत कहा कर मोला की के। यह प्रवासी विधायक हे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- क्यों ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हव। भिलाई से नगरी जाथे न तोर ...भिलाई के।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय विधायक जी, बताईये कि क्या लड़कियों का ससुराल प्रवासी होता है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- भिलाई में देख लेबे ना। माननीय मुख्यमंत्री जी के पारे हे के यदि पीछू में डॉ. लक्ष्मी कही के घर मा लिखाये हे बड़े झन। ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मैं नौकरी करने गयी थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अउ मैं नगरी में कही भी गय हो। ये कहां प्रवासी विधायक ला तुमन चुन देवा हव कहथो तो मोर ऊपर भड़क गे। मे जाये ले बोलेल बंद कर देव।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह मेरी लोकप्रियता है। लोगों ने स्वीकारा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अऊ मैं बोले हव कि बहन जी अब नहीं बोलहू पक्का। ता वो दिन ले नइ कहव।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मैं लोकप्रिय बहु थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- एकदम चल भइ बहन जी अब नही कहव कहि के। यह पढ़े लिखे डॉक्टर है तो इनको टोकने के बजाय इतनी तथ्यपूर्ण बातें रखनी चाहिए कि हम लोग भी सुने। पढ़े लिखे लोग सदन में क्यों आते हैं ? हमारे यहां उच्च सदन नहीं है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जब मेरी पारी आयेगी तब अपनी बात रखूंगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारे यहां विधान परिषद नहीं है। कम से कम ऐसे पढ़े लिखे लोग विधान परिषद की कमी को पूरा करते। लेकिन यह लोग तो टोकने का काम करते हैं।

श्री कवासी लखमा :- गलत बोलोगे तो नहीं टोकेंगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- लक्ष्मी जी, इनको दवाई बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, जनसंपर्क में आप मुझे जरूर बतायेंगे कि आपने कितनी एजेंसी तय करके रखी है ? आपके पास जो प्रचार प्रसार विभाग है वह क्या करता है ? उसके लिये नये एजेंसी की जरूरत क्यों है ? कितनी एजेंसी किन-किन कामों के लिये रखी है, उनको चार साल

में कितना पैसा दिये ? यह जरूर बता दीजियेगा। अब जनसंपर्क के संवाद में, जो आपका है। आप प्लेसमेंट कंपनी के माध्यम से अयोग्य लोगों को रखे हैं या योग्य लोगों को रखे हैं या कार्यकर्ताओं को रखे हैं, इसकी जांच कर ले, यह तो आपके ऊपर है। यदि यह लोग आपकी छबि नहीं बना पा रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर रहे हैं। आपके सलाहकार लोग नियुक्त होकर आपके पैसे में राजनीति कर रहे हैं उसके बाद भी आपकी छबि Victimhood की है तो मैं क्या बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकार सुरक्षा कानून, अब एक लाइन बोल दिया। आपके घोषणा पत्र में है उसको मत बनाईये । आप जिस काम में असहज महसूस करते हैं, वह काम मत कीजियेगा। आप अधिमान्य पत्रकारों के लिये ही मकान की सुविधा देंगे ? प्रदेश में इतने सारे न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, क्या उनके लिये कुछ है, आप उनके लिये कुछ सोचते हैं ? गांव में जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। अधिमान्यता के लिये कोई नियम व शर्तें, क्या ग्रामीण का कोई लेयर बनायेंगे कि इनको ऐसे करेंगे कि शहर में जो लोग भाजपा बीट, कांग्रेस बीट, यह बीट, वह बीट, ग्रहण करेंगे कैमरा मारेंगे, वही लोग हैं। उनकी सारी सूचनाएं गांव से आती है। वह बेचारे कुछ नहीं करते हैं, न उनको कुछ मिलता है। छपने के लायक ही मेरा उद्देश्य है। मैंने आपसे एक बार व्यक्तिगत आग्रह किया था। आप संस्कृति मंत्री नहीं है। छत्तीसगढ़ मित्र ले देकर चल रहा है। मैंने आपको कहा था कि साहब, उसके लिये नियमित 50 हजार रूपये महीना दे दीजिये। उसको लोग मिलजुलकर चलाते हैं। उससे माधव राव सप्रे जी की भावनाएं जुड़ी है। देश के पहले पत्रकारों में से, पहली पित्रका में से एक है। मैं बड़े दुख और खेद के साथ आपको कहूंगा कि मैं तो सोचता था कि आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ियां बोलते हैं तो आपको दिख जाएगा। केवल गेड़ी के विज्ञापन में गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल हम लोगों को मारा-पीटा गया, वह तो ठीक है, लेकिन नीलेश शर्मा ...।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अजय जी, आप बताईये कि आपको किसने मारा ? आपने कहा कि हम लोगों को मारा-पीटा गया तो आपको किसने मारा ?

श्री बृहस्पत सिंह :- अजय जी, आप बताईये कि आपको किसने मारा ? माननीय चन्द्राकर साहब, छत्तीसगढ़ में आपको कौन मार सकता है ? ऐसी किसकी हिम्मत हो गई।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप लोगों ने ही पुलिस वालों को मारा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीलेश शर्मा जी ने क्या गलती की थी ?

श्री बृहस्पत सिंह :-आपने तो सीधे आरोप लगा दिया कि हम लोगों को मारा-पीटा गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीलेश शर्मा जी ने क्या गलती की थी कि उनको हथकड़ी-बेड़ी पहनायी गयी। एक नामदेव जी का पूरा फार्महाऊस उजाड़ दिया गया। जैसे आपने पहले साल में राजनारायण जी को किया था, यह उस तरह की घटना है। अब हमारे बीच राजनारायण जी

नहीं रहे। मेरा यह कहना है कि मैं जब चर्चा करता हूँ तो भाई लोगों को भी कहता हूँ कि सरकार की खिदमत अलग चीज है, देश के लिए लिखना अलग चीज है, तथ्य को लिखना अलग चीज है। साहब, बालगंगाधर तिलक भी मराठा केसरी निकालते थे, वह अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। उससे निर्दयी सरकार कहीं नहीं है आप चाहे जितना भी रोक लगा दीजिए, देश में लोकतंत्र है। पत्रकार हैं, गरीब हैं, नीचे हैं जरूरतमंद हैं, वह विपरीत स्थितियों में काम करते हैं देखिए। आपने अब तक, मैंने उस दिन वर्ष 2021 का पूछा था तब देश और विदेश में 315 करोड़ रूपये का विज्ञापन दे चुके थे। मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ। मैं एयरपोर्ट में एक जगह देखा, शायद हैदराबाद या कहीं का होगा कि छत्तीसगढ़ में इतनी धान खरीदी की गई। आपकी धान खरीदी देखने बाहर के लोग नहीं आएंगे। आप उस बोर्ड को पर्यटन विभाग को दीजिए। आप सिरपुर को लगाईये। आप चम्पारण को लगाईये और किसी को लगाईये। छत्तीसगढ़ की जो विविधताएं हैं, वह प्रदेश के बाहर दिखे।

संसदीय सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से संबद्ध (श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल के नेता मन हा आई.ए.एस. ला फोन करके ए बोलथे कि उहां खाद्य बटथे। उहां मोदी जी के फोटो काबर नइ हे? ओकर ऊपर चर्चा करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर साहब, आपको 40 मिनट हो चुका है और कितना समय लेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा और समय लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग के आज तीन सालों बाद बजट के डिमाण्ड मांग में चर्चा हो रही है। साहब, वह भी कम सत्रों में यह गलत है या सही है ? हमने तो यह भी कहा है कि हम चर्चा भी करेंगे और अतिरिक्त समय भी देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप और कितना समय लेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो विभाग और है। आप यह देखिए, अब मैं जनसंपर्क विभाग की बात को भी खत्म करता हूँ। अपने कार्यकर्त्ताओं को संविदा के माध्यम से भर्ती करना, संविदा के पदों को नहीं भरना, प्रचार-प्रचार विभाग होने के बावजूद एजेंसी तय करना, एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह विभाग कर रहा है। यदि अक्षम लोग हैं तो उनको नौकरी से निकालिए। यदि अलग एजेंसी की जरूरत है तो । आप ऐसे विज्ञापन दीजिए जिससे छत्तीसगढ़ को लाभ हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंतमान जी ने आपसे प्रेरणा ली है वह रोज सो उठकर उसी को भरोसे के बजट की तरह देखते हैं। मैं जल्दी-जल्दी बोल देता हूँ।

श्री रामकुमार यादव:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एमन के फोटो पेट्रोल टंकी में लगे रिहिस हे । ज्यादा भाव बढ़िस तहान ओ ला हटवा दिस।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत में ज्यादा नहीं बोलता हूँ। आपने इसके लिए 25 करोड़ रूपये बजट प्रावधान रखा है। 3 मेगावाट लगभग 8 करोड़ रूपये में बनेगा यदि आपने 25 करोड़ रूपये बजट प्रावधान रखा है। आप उसमें हाईड्रल प्रोजेक्ट बनायेंगे तो दो या ढाई बनेगा। 8 से 10 करोड़ रूपये के बीच में वह बनता है। आप क्या समझते हैं ? आपने 440 मेगावाट डिमालिस करवाया। आप बहाना बनाते हैं कि साहब, इसकी पर्यावरणीय अवधि पूरी हो गई थी। वर्ष 2024-25 तक उसकी पर्यावरणीय अवधि थी। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ उस फाईल को खोला जाए और यहां रखा जाए। आपने 280 करोड़ रूपये में कबाड़ के भाव में बेच दिया। मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप 5 सालों में क्या करना चाहते हैं ? तो आप यह बतायेंगे कि मैंने एक यूनिट विद्युत उत्पादित नहीं किया और अब 8 रूपये में विद्युत खरीदता हूँ। यह हिन्दुस्तान का एक मात्र सरप्लस राज्य था।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप शांति से बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी, ऐसा है आप थोड़ा अभी रोप वे को और चेक करने जाईए। दूसरी बात, आपकी उत्पादन क्षमता गिर रही है। सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत पानी, बिजली, आप आर्थिक सर्वे देख लीजिए, वह माईनस 1.76 है अब आपने उसको 280 करोड़ कचरे के भाव में बेच दिया । क्या आप सदन में बतायेंगे कि उसकी पर्यावरणीय अवधि एन.ओ.सी. कितने वर्ष की थी, कितने दिन की थी? आप फाईल रखवाईये, तब पता चलेगा। बिना फाईल देखे पता नहीं चलता है। रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के समय में, वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमको आपका उस दिन नरसिंह अवसर देखने को मिला था। मैं बोधघाट को स्वीकार करता हूं। बोधघाट परियोजना का सर्वे होगा। हमने देखा कि मुख्यंमत्री जी आज पूर्ण अवतार में हैं। बोधघाट जरूर बनेगा। जैसे पर्यटन वालों ने एक कंपनी खोजी है, मोहसिना किदवई की लड़की को, वैसे इन्होंने एक कंपनी वेस्काप को खोज ली है। बोधघाट के लिए भी एडवांश पैसा दे दिया गया। 5 पन बिजली परियोजनाओं का सर्वे होगा, ये चुनावी साल में उसमें सर्वे के लिए 766 करोड़ रुपये दिया गया है। आप क्यों पैसा बरबाद कर रहे हैं। गंगरेल में 10 मेगावाट बिजली बनती है। आप मेरे साथ भेज दीजिए, उधर बैठे हैं, मैं पहचानता हूं। क्या 10 मेगावाट बिजली पैदा होती है? साल में कितने मेगावाट बिजली पैदा होती है? जब पूरा प्रचंड पानी गिरते रहता है, तब कितने मेगावाट बिजली पैदा होती है? और छत्तीसगढ़ में जल विद्युत की कितनी क्षमता है, सब जानते हैं। आपके दोस्त होंगे और किसी को उपकृत करना था तो दूसरा काम देना था। अब एक चीज बताकर इसको भी खत्म कर देता हूं। किसानों का जो पंप है, 56 हजार मेच्योर है। 1 लाख 32 हजार और मेच्योर हो सकता है, आप 150 करोड़ रुपये रखे हैं, 2900 करोड़ रुपये 5 एच.पी. के लिए रखे हैं। आप नहीं चाहते कि ज्यादा बिजली पंप हो और मुझे किसानों को सब्सिडी देनी पडें। आप जानते थे कि 56 हजार बकाया है, मेच्योर है, आपका विभाग है। आप उतने पैसे का आयोजन कर सकते थे। आपके पास तो 3500 करोड़ सरप्लस है न, 15 हजार करोड़ रुपये दूसरा डीफिसियेशन है। आप पास तो चालू खर्चे के

लिए सरप्लस हैं। कर्ज लेते हैं तो जो गोठान समिति, राजीव मितान क्लब के लिए कर्ज लेते हैं तो 56 हजार लोगों के लिए हजार, दो करोड़ रुपया कर्ज ले लेना था। आप बोलते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया किसान। आपके विभाग में और किसानों की चर्चा करेंगे कि आपने उसको क्या किया है। आपके समय में एक समस्या ने जन्म ली। डॉ. साहब ने 132/220/440 के.व्ही. के सब स्टेशन लगाये थे, मैं जिस विधानसभा में रहता हूं, जगह कहीं नहीं मिली तो वह मेरे यहां चली गई, 440/220/132/34 जो है। जितनी 132/220 की संरचनाएं बनीं, आप नीचे सब स्टेशन उसके लायक 05 सालों में नहीं बनाये। छत्तीसगढ़ में हर किसान लो-वोल्टेज से पीड़ित है। आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों ने मूर्खतावश कहें, भावनावश कहें, कम जानकारी में कहें, रबी फसल लगा दिया है। गंगरेल और सीकासेर के पानी से बांगो के पानी की तरह सपोर्ट कर दीजिए। लो-वोल्टेज के कारण धान खराब हो रही है। वह जितना बोनस नहीं पाये हैं उससे ज्यादा लूट रहे हैं। वह दुखी हैं और गली-गली घूम रहे हैं। यदि आपने ट्रांसमीशन को ठीक नहीं किया तो जितने हमने सब-स्टेशन बनाये हैं उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। बाकी आप जानते हैं। निरंतर उत्पादन में आपकी गिरावट आ रही है। यह आर्थिक सर्वे भी रखा है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सामान्य प्रशासन विभाग में आता हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं प्रोटोकाल की बात नहीं करता। एक मुख्यमंत्री जी को जो न सांसद है, न विधायक है, न कुछ है, क्या उसके स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाना चाहिए? हमारे छत्तीसगढ़ की अस्मिता आपके साथ जुड़ी हुई है। क्या आपको जाना चाहिए, आपका प्रोटोकाल क्या बोलता है? आप मुझको बतायेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप जरा यह भी बता दीजिए आर.एस.एस. के मोहन भागवत जी आते हैं, पूरे बी.जे.पी. के लोग उनके स्वागत के लिए लाईन लगे रहते हैं, उसके लिए भी तो बता दीजिए। वह किस श्रेणी में आते हैं, वह कौन सा लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य हैं? वह कौन से संवैधानिक पद पर हैं। उसका भी तो उल्लेख कर दीजिए।

श्री संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति रही है कि कोई भी मेहमान आते हैं तो उसका स्वागत हम करते हैं। यह हमारी संस्कृति है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यह निर्णय आपके विवेक पर छोड़ता हूं। लेकिन यह गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी अस्मिता भी आपकी पहचान के साथ जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ के 275 करोड़ लोगों की अस्मिता जुड़ी हुई है, आप institution हैं, आप अपने कद को निर्धारित कैसे करते हैं, यह आपके ऊपर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के लिए कल मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए एक शब्द का उपयोग किया था। जैसा कि मैंने विक्ट्रीम हुड कहा, वैसे ही स्टेट्स मेन कहा था। यह विधानसभा से ऊपर हैं, राजभवन से ऊपर हैं, न्यायलयीन मामलों से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं। यह

जो कहे, पार्टी की सीमाएं हैं, उससे भी ऊपर हैं। हम अटल जी को स्टेट्स मेन कहते थे कि उनका अपना जनाधार पार्टी से भी अलग था, उनकी पहचान पार्टी से भी अलग थी। अब कैसे ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- कभी-कभी आडवानी साहब का भी नाम ले लिया करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- नाम तो ले रहा हूं। अटल जी से तुलना कर रहा हूं। अटल जी के बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्टेट्स मेन बना रहा हूं। उनका एक आभा मण्डल है, वलय क्षेत्र है, उनका अपना एक औरा है। मैं और कितनी प्रशंसा करू। नीति कैसा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुराजी गांव। जो मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, वह सुराजी गांव है। सदन को जानने का अधिकार नहीं है कि सुराजी गांव में क्या होगा? राजकीय पट्टा हो गया। राजकीय कोई चीज घोषित करते हैं। आज के सामान्य प्रशासन के कार्यों में राजकीय पट्टा नहीं लिखा है। आप यदि बनाते हैं तो बनाई। कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, क्या छपे होंगे, अशोक चक्र में कितने चक्र होंगे, क्या लिखेंगे, सारा चीज निर्धारित रहता है। उसके अधिनियम बने होते हैं। तो आपने जो बोल दिया, वह राजकीय पट्टा हो गया। सब कृतदास राजकीय पट्टा, राजीय पट्टा बोलने लगे। अब छत्तीसगढ़ मॉडल का विज्ञापन आ रहा है। आप व्यस्त रहते हैं तो आपके डी.पी.आर. को, आपके सचिव को बोल दीजिये कि छत्तीसगढ़ मॉडल क्या-क्या है। मेरे से बहस कर लें या मुझे सिखा दें कि यह छत्तीसगढ़ मॉडल है। मुझसे बहस मत करें। आप नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी बालें।

श्री कवासी लखमा :- आपको छत्तीसगढ़ की जनता बतायेगी। उप चुनाव में आपको निपटा दिये न, वैसी ही निपटा देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- नरवा, गरूआ, घुरूआ, बाड़ी में क्या होगा? मैं उस दिन बताया था। प्रश्न लगा नहीं कि डी.एम.एफ. में बाड़ी में खर्च हुआ। इसमें बनेगा क्या, होगा क्या, आउटपुट क्या होगा, कौन इसके हितग्राही है, केसे-कैसे करेंगे? रिपा बनेगा। बनाओ रिपा। मैंने उस दिन भी कहा कि कुटीर उद्योग की एक नीति बना दो। इन-इन चीजों को लगायेंगे। स्टेट गारंटी दे दो। उसकी सीमा, उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाए, लेकिन नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा दिया। रिपा बनेगा तो रिपा बन गया। अब अधोसंरचना उन्नयन बोर्ड बन गया। कोई नियम-कानून नहीं। जो मुख्यमंत्री बोले, वह कानून है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन विधायकों व सांसदों के मान-सम्मान के बारे में पत्र प्रोटोकाल में बात हो रही थी। मैं मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था कि मुझे धमतरी की बठकों में मत बुलाया जाए। आज तक उत्तर नहीं बोले हैं। न यह तक पूछने की जहमत उठाई कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। मैंने एक पत्र लिखा। आपको 15 लाख टन पैरा कहां से दान मिला, यह मुझे जानकारी दीजिये और उसके परिहवन के लिए कितना पैसा कहां से व्यय किया गया? मैं जानता हूं कि उसको कोरोना सेस के पैसे से ठुलाया गया। पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को सुने कि आप कोरोना के लिए सेस लगाते हैं और उसमें पैरा ठुलाते हैं। उसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। राजीम मेला का निमंत्रण पत्र मेरे को एक चपरासी लाकर दिया और

जो वहां के, मैं नहीं बोलना, जनता के क्षेत्र के हैं। मेरे दल के लोग भी जानते हैं कि मैं उद्घाटन समापन वाला, ज्यादा स्वागत सत्कार नाम छपे वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं बाकी सज्जनों के लिए बोल रहा हूं कि यदि सही अर्थों में डेमोक्रेट हैं तो आपने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, नहीं। आपके दल के बहुत लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं। आपके सामने भी प्रशंसा कर चुका हूं जो उन मूल्यों को समझते रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्रमोन्नति, पदोन्नति, नियमितीकरण बनाई है। दो दिन आपका क्योश्चन डे हो गया। आप नकार दीजिये न। 22 विभागों का उत्तर नहीं आया है। 42, 43, जितने भी विभाग हैं, उसका उत्तर आ गया है। 4 साल में कमेटी की एक बैठक हुई है। मैं बार-बार जो अधोसंरचना बोलता हूं। 808 करोड़ रूपये मिला है। केवल एक वर्चुअल बैठक हुई है। ठीक है। अब उसके बाद आप यह बताईये कि पी.एस.सी., सारी चीजें रूकी हुई हैं । आरक्षण के बारे में बहुत चर्चा होती है । गर्वनर ने कहा कि मैं मार्च तक, जो भी कहा मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा मार्च तक अंतिम सुनवाई है जो लोग कोर्ट में गये हैं, जैसे भी गये हैं । राज्य शासन की ओर से जहां पर भी चल रहा है वह लग जायें कि आपको जो निर्णय करना है एक समयावधि में तय कीजिये । जब न्यायालयीन मामला हो गया है तो गवर्नर क्या करेंगे ? हम क्या करेंगे ? वो क्या करेंगे इसको छोड़कर कई बार ऐसा हुआ है कि ये लोकमहत्व का विषय है इसको सुनिए । आपके अनुकूल नहीं आये तो जो आपको अनुकूल लगता है । जैसे विश्वविद्यालय अधिनियम सुप्रीम कोर्ट ने प्राईवेट विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया तो जो-जो उन्होंने निर्देश दिया था उस आलोक में हमने नये अधिनियम बनाये और वह छत्तीसगढ़ का अधिनियम पूरे देश में है । पूरे देश में वही अधिनियम गया । जो निर्णय आयेगा वह आपके विपरीत नहीं होगा, आपके अनुकूल नहीं होगा तो हम लेजिसलेशन करने के लिये फिर स्वतंत्र हैं । इसको राजनीतिक बयान से अलग कीजिये । गवर्नर ने क्या किया ? डॉ. रमन सिंह जी ने क्या किया ? आपने क्या किया ? बच्चों का सवाल है, न्यायालयीन विषय है, स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इंकार कर दिया है । आप जाईये, मुखिया हैं बोलिये कि साहब निश्चित समय में इसकी सुनवाई कीजिये और उसके बाद फिर आग्रह करता हूं कि आपके अनुकूल न हो तो आप फिर से लेजिलेशन कर लीजिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी से एक अनुरोध है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आपने आरक्षण मुद्दे को लेकर कांग्रेस के सारे नेताओं के घर घेरने का काम किया और इतना ही नहीं फिर आपने बड़ा हल्ला किया कि विशेष सत्र बुलाया जाये । आप और हम सभी लोगों ने इसी पवित्र सदन में सर्वसम्मति से पारित किया और जब पारित हुआ । ऊपर से आपके आर.एस.एस. मुख्यालय से फोन आने लगा तो माननीय राज्यपाल जी की पेशी हुई उसके बाद आपके नेताओं ने यह दबाव डाला कि दस्तखत करने से जो माननीय राज्यपाल जी ने आश्वासन दिया था कि हम करेंगे उनको मना किया और ऐसा करके आप अड़ंगाबाजी करके पूरे छत्तीसगढ़ की सारी नौकरियों में जो नियुक्ति होनी थी उस पर आपने रोक लगायी । आपका यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है ।

वह अच्छी तरह से समझती है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दिशा में न तो उत्तर देना चाहता, न बहस करना चाहता और न ही आरोप लगाना चाहता हूं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं मामला न्यायिक हो गया है तो उस ढंग से आप सोचिए । बाकी आप स्वतंत्र हैं । मैंने तो बता दिया है कि आप स्टेटमेन हैं, मेरे भी आईडियल हैं । मैं छत्तीसगढ़ के बाहर आपकी आलोचना नहीं करूंगा करके अब आपने राजगीत बनाया है । आप सामान्य प्रशासन के प्रतिवेदन में पढ़ लीजिये कि क्या राजगीत आपके कार्यों में है ? आप गैर कानूनी काम क्यों करते हैं ? आप इसमें जोड़वा लीजिये और राजगीत को विधिवत् कर लीजिये कि इतने मिनट का होगा, इतने स्टेंजा का होगा, उसमें इतने बजे गाया जायेगा, इस-इस तरह से उसका सम्मान किया जायेगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अब राज्यगीत से भी आपको तकलीफ हो गयी । उसमें पूरे छत्तीसगढ़ का वर्णन है, उसमें एक-एक नदी-नाला, पहाड़ और जिलों का उल्लेख है । आपको उससे भी तकलीफ हो रही है, उससे भी परेशानी है । छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ने से आपको तकलीफ है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसमें शामिल करवाकर उसको विधिवत कर लीजिये । उनको यह विषय समझ में नहीं आयेगा । अब थोड़ी-थोड़ी दूसरी बातें । आपके भेंट-मुलाकात के आवेदन शत्-प्रतिशत हो जायें । घोषणायें शत्-प्रतिशत पूरी हो जायें । लोग घूम रहे हैं, आपने इतनी घोषणायें कर दी हैं । भेंट में जाते हैं तो लोगों को डांटिए मत । एक वीडियो वायरल हुआ था कि तुम्हारे बाप-दादा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है क्या करके ? वह सही था कि गलत था यह मैं नहीं जानता ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये हमारे पहले मुख्यमंत्री जी हैं जो भेंट मुलाकात कर रहे हैं और वहां पर जितने लोग आते हैं । जितने बच्चों को परेशानी, युवाओं को परेशानी, बुजुर्गों को परेशानी । एम.बी.बी.एस. बच्चों को पढ़ने के लिये 4 लाख रूपये दिये हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- संगीता बोले में तोर नाम है कि नइ हे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हां, मेरा नाम है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवेन्द्र कुमार साहू इनको एम.बी.बी.एस. के लिये 2 लाख रूपये तुरंत वहीं पर दिये हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की घोषणा की, यह अभिभाषण में भी आया है । आप विनम्रता से छत्तीसगढ़ से क्षमा मांग लीजिये कि मैं इसको नहीं कर सका । इसमें कुछ नहीं हुआ है । आप बतायेंगे कि कितनी भर्ती हुई, कहां हुई ? कौन से पदों में हुई है ? आप बताईये । मैं चाहूंगा कि आपके उत्तर में यह शामिल रहे ।

श्री लखेश्वर बघेल :- बस्तर संभाग में 5000 लोगों की भर्ती हुई थी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष कर दी । उसको कम करिये, जितना था उतना रहने दीजिये । अब मैं असली चीज बोल रहा हूं कि यह ए.सी.बी. लोक आयोग में जितनी शिकायतें हैं । लोक आयोग तो हस्ति दंतवीन, पंछी पंखवीन, भोजन मान बिना बोलते हैं न वैसा वाला है। हमने बनाया चलिये, हम मान लेते हैं । डॉ. साहब बैठे हैं मैं उनके सामने बोल रहा हूं। ए.सी.बी. वाला थाना आपका है । अभी उसमें नया चलन शुरू हुआ है, थोड़े दिन पहले, अभी बंद हो गया है । जिसकी शिकायत होती थी उसको बुलाते थे, बताओ क्या करना है ? कृपा करके इन दोनों को खत्म कीजिए और अच्छा सशक्त लोकायुक्त बनाइए, हम समर्थन में हैं । आप भी उस दायरे में आएं, विपक्ष के नेता भी, विधायक भी, सांसद भी, लोक सेवक भी । कहीं से भी शुरूआत तो होनी चाहिए। अब एक बात मैं बोल रहा था कि जिसका उल्लेख करूंगा । आपने गिरीश देवांगन, रामगोपाल अग्रवाल, तिवारी इनका कल नाम लिया था उनको शहीद का दर्जा दिया था आपने। तथाकथित रूप से शहादत दी । मुख्यमंत्री जी आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं । एक पक्षीय बात नहीं होनी चाहिए । कभी आप यूनियन में भी जाएंगे । यह संघीय व्यवस्था है । आप एक राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी की आलोचना करते हैं, विधि अधिकारी की । मुख्यमंत्री के लायक स्टेटमेंट है । आलोचना करवाना है तो आपका विधि मंत्री क्या कर रहा है ? दूसरी बात, मैं इस विषय में कहने से बचता था लेकिन आपने इस विषय को बार-बार छेड़ा । (xx)[8]

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अरे, ये गलत बात बोल रहे हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्यों ?

श्री बृहस्पत सिंह :- [xx] आरोप लगाना बंद करिये । बिल्कुल [xx] आरोप लगाना बंद करिये । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप आरोप लगा रहे हैं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- बिना सबूत का [xx] आरोप मत लगाइए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चाहे जितना चिल्ला लें, मैं इस बात को खत्म करके ही बैठूंगा ।

श्री गुलाब कमरो :- बिना तथ्य के साथ आरोप लगा रहे हैं । यह आपत्तिजनक बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- विलोपित कर दो ।

डॉ. विनय जायसवाल :- [xx]

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, इनको तकलीफ हो रही है । यह बताएं कि समीर विश्नोई की गिरफ्तारी क्यों हुई है और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब तक जमानत क्यों नहीं हुई यह बता दें । (व्यवधान) समीर विश्नोई की गिरफ्तारी क्यों हुई है और उनसे क्या मिला ।

[8] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, चलिए हल्ला करते हैं तो मैं उस विषय से आगे बढ़ता हूं । जितने लोग ई.डी. में अंदर हैं 152 करोड़ की सम्पत्ति अटैच हुई है । वह कहीं जाते हैं, कोई भी जांच एजेंसी जांच करने के लिए जाती है जिसके नाम का कोई न कोई प्रमाण रहता है । यदि वह निर्दोष है तो छूटेगा । यदि हम गलत कर रहे हैं, ई.डी. गलत कर रही है तो न्यायालय बैठी है, वह जमानत क्यों नहीं दे रही है । मैं इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता था लेकिन जहां आग होती है वहीं धुंआ उठता है।

डॉ. विनय जायसवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि ई.डी. किस संज्ञान से किसकी जांच कर रही है । प्रश्न यह है कि जो केन्द्रीय संस्थान हैं और जिस तरह से वे काम कर रहे हैं, वह संदेह के दायरे में है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी बहुत विद्वान हैं । ज़रा प्रियदर्शिनी बैंक वाला भी तो बता दीजिए । उसका वीडियो भी बता दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- तुम्हर ई.डी. सी.डी. से छत्तीसगढ के आदमी मन डरने वाला नइ हे।

डॉ. विनय जायसवाल :- [xx] उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या ?

श्री अरूण वोरा :- जितना असत्य कथन यह कर रहे हैं । गीता में हाथ रखकर इनसे बोलवाना चाहिए । आप गीता में हाथ रखकर बोलिए जो कुछ बोल रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक ठो गरवा बुलवा लेना पूंछी ला धरे बर ।

श्री रामकुमार यादव :- गरवा पुछी ला।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं दो शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव के तौर पर कर रहा हूं । आप यह मत कहना कि मैं नाम ले रहा हूं । मुख्यमंत्री जी आपका राज एजाज राज है, एजाज का मतलब उर्दू में चमत्कार होता है । आपके राज में एजाज हो रहा है यानी चमत्कार । अनवर का मतलब सक्षम बनना होता है, आपके राज में हर व्यक्ति अनवर बन रहा है । हर व्यक्ति सक्षम बन रहा है । आपको बधाई देते हुए, अभिनंदन करते हुए कि आप 5 साल में एक याद करने लायक काम जरूर बताएंगे । आज नहीं बताएंगे तो विनियोग में बताएंगे, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की मांग संख्या क्रमांक 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71, 65 की मांगों पर अपनी विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अब प्यार से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी चंद्राकर जी बोल रहे थे, वित्त विभाग के बजट पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट पर कोई बात नहीं की। ऐसा लगा कि विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। चंद्राकर जी, आप मांग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इधर-उधर की बात कर रहे हैं। असत्य

आरोप लगा रहे हैं। यही आपका ज्ञान है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं मुख्यत: जो वित्त विभाग की मांग है, उस पर बात करना चाहता हूं। वर्ष 2023-24 में बजट में वित्त विभाग में कुल 21,788 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। बजट में मुख्य रूप से राज्य द्वारा लिये गये ऋणों के भुगतान के लिए पुनर्भुगतान, ब्याज भुगतान, पेंशनर दायित्वों का कोषालय की स्थापना के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा पूर्व वर्षों में लिये गये ऋणों की पुनर्भुगतान हेतु बजट में 7541 करोड़ रूपये का प्रावधान है। पूर्व में लिये गये ऋणों की आहरित ब्याज की अदायगी हेतु 6684 करोड़ यपये का प्रावधान है। राज्य में पेंशनरों के पेंशन, परिवार पेंशन अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु 7384 करोड़ रूपये का प्रावधान है। दिनांक 01.11.2004 से लागू की गयी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 01.04.2022 से समस्त शासकीय सेवकों हेतु पुरानी पेंशन योजना बहाल की गयी है। कर्मचारियों में हर्ष है और काफी प्रसन्नता है लेकिन इनको तकलीफ है। पुरानी पेंशन योजना के लिए 250 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। राज्य सरकार द्वारा गारंटी पर ऋणों के भुगतान में राज्य शासन की देयता के पुनर्भुगतान तथा आर.बी.आई., महालेखाकारों के निर्देश के तहत प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मैं मुख्यत: बजट अनुमान 2023-24 में जो योजनावार प्रावधान है, इसका भी जिक्र करना चाहता हूं। भिलाई में साफ्टवेयर पार्क की स्थापना के लिए 6 लाख 51 हजार रूपये का प्रावधान है। सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है। बिल्ड वेस्ड परियोजना के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ सेंट्रल ऑफ जीओ इलेक्ट्रानिक इलेक्ट्रोविटी परियोजना के लिए 7 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मंत्रालय विभागीय भवनों में वाई फाई सुविधा के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ स्टेट जी.आई.एस. परियोजना के लिए एक लाख रूपये का प्रावधान है। श्वान परियोजना के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। डिजीटल शासन की स्थापना के लिए 2 लाख 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है। स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए 27 करोड़ रूपये का प्रावधान है। सूचना प्रौद्योगिकी ई गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्था के लिए 20 लाख रूपये का प्रावधान है। एकीकृत ई प्रकरण परियोजना के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है। को इन्वेटर एक्सीलेंस संस्थान के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है। सेंट्रल मानिटरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख रूपये का प्रावधान है। जीओ ई गवर्नेंस सोसायटी के संचालन के लिए 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 15 करोड़ रूपये का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ स्टेट स्पेशलिस्ट डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 लाख रूपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना के लिए 15 करोड़ रूपये का प्रावधान है। स्टेट पॉर्टर परियोजना के लिए 90 लाख रूपये का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना के लिए 11 करोड़ 50 लाख रूपये का

प्रावधान है। वाई-फाई सिटी की योजना के 56 लाख रूपये का प्रावधान है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निवेश प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राज्य में 146 करोड़ 82 लाख 68 हजार रूपये का प्रावधान किया है। इसके पहले किसी भी योजना में आज तक इतनी राशि का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके साथ ही मैं विमानन विभाग की बात करना चाहता हूं। इस सरकार ने अपने प्रयासों से इस प्रदेश में अधोसंरचना के विकास के लिए अपनी परियोजनाओं को अंजाम दिया है। जगदलपुर के एयरपोर्ट को 3-सी श्रेणी के अनुसार विकसित किया गया है। घरेलू विमान सेवा का संचालन अच्छी तरह से हो, इसके लिए जगदलपुर से रायपुर, दिल्ली से रायपुर एवं जगदलपुर में 1 सप्ताह में 3 दिन की हवाई सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। इन हवाई यात्राओं का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है ताकि हमारे आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को आने-जाने में किसी प्रकार की तकलीफ न हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार प्रयासरत् है कि जगदलपुर का देश के कई बड़े से बड़े शहरों से जुड़ाव हो। हमारी सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में विमान उद्यमिता विकास के लिए कोरिया जिले में नवीन हवाई पट्टी बनाने की व्यवस्था की गई है। कोरबा में व्यावसायिक एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर कार्य किया गया है। मैं यह कहना है कि कि इससे इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक एवं आर्थिक विकास होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज विभाग की भागीदारी के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज के भरपूर एवं प्रचुर भण्डार हैं। हमारे प्रदेश में कोयला, लौह-अयस्क, चूना-पत्थर, बॉक्साइट, टीन अयस्क, डोलोमाइट के साथ ही स्वर्ण धातु एवं हीरा, कोरण्डम जैसे बहुमूल्य खनिज भी उपलब्ध हैं। राज्य में अधिकांश उद्योग खनिज आधारित उद्योग हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोयला एवं लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का नाम देश में द्वितीय स्थान पर है। देश में 3 अयस्क का उत्पादन शत-प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है, यह एक प्रसन्नता का अवसर है इस बात का भी मैं समर्थन करना चाहता हूं। वर्ष 2022-2023 में परविर्ष 2023 तक 10.725 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 13 हजार करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का पूरा अनुमान है। हमारे छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के हिरमी, करहीचण्डी क्षेत्र में चूना-पथर का लगभग 7090.4 मिलियन टन भण्डार है। जांजगीर-चांपा जिले में चूना-पत्थर का 400 मिलियन टन भण्डार अनुमानित किया गया है। ये हमारे नवीन खनिज संसाधन खोज के कार्य हैं। इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एन.एम.ई.टी. परियोजना के अंतर्गत कुल 171 करोड़ रूपये के आयरन और दो परियोनाएं तथा एम.ई.सी.एल. के द्वारा 645 करोड़ रूपये की गोल्ड एवं डायमण्ड की एक नई परियोजना संचालित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम बिजली और ऊर्जा की बात करे तो हॉफ बिजली, हॉफ बिल स्कीम में हमारे प्रदेश के लोगों को पूरा-पूरा लाभ हुआ है। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 48 लाख 61 हजार 552 हुई हैं। संख्या में में 334 कनेक्शन औद्योगिक पार्क एवं गौठानों को दिये गये हैं। इसके साथ ही घरेलू उत्पादन में प्रतिमाह की खपत में 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशाली विद्युत की दरों में आधार पर बिजली बिल की राशि आधा की गई है । मार्च, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक 42.20 लाख रूपए की घरेलू उपभोक्ताओं को 3453.17 करोड़ की तथा ग्रामीण औद्योगिक पार गोठानों को 334 गोठानों को कनेक्शन रियायत प्रदान की गई है । 2023-24 के बजट 1115 करोड़ का प्रावधान किया गया है । 2023-24 के अंतर्गत इस योजना में 1050 करोड़ का प्रावधान किया गया है । 5 एच.पी. क्षमता तक के कृषि पम्पों को नि:शुल्क देने की व्यवस्था विद्युत प्रदाय योजना में की गई है । इसमें कुल मिलाकर कुल कृषि पम्प उपभोक्ता लगभग 6 लाख, 36 हजार हैं । इसमें से 5 लाख, 5 हजार स्थायी एवं 1 लाख, 31 हजार अस्थायी सिंचाई पम्प उपभोक्ता हैं । वर्ष 2022-23 के बजट में 3253 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया था, वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना में 2900 करोड़ का प्रावधान किया गया है । कृषि पम्पों का ऊर्जीकरण किया गया है। इसमें आवश्यक लाईन विस्तार के लिए पम्प औसत मूल्य रूपए 1 लाख और अधिकतम 1.5 लाख रूपये का अनुदान भी दिया जाता है । इसको विस्तारित करते हुए मछली पालन कार्य के लिए भी विद्युत कनेक्शन की लाईन दी गई है । 2022-23 में 20520 पम्पों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक 8283 पम्पों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । शेष 12267 पम्पों का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2023 तक पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान है । इसी तरह से चार वर्षो में 88048 नग कृषि पम्पों को ऊर्जीकृत किया गया है । वर्ष 2023-24 में इसके लिए 299 करोड़ का बजट प्रावधानित है । 2014-15 से नवम्बर, 2018 तक किए गए पम्पों के ऊर्जीकरण के आधार पर प्रतिवर्ष 21075 पम्प ऊर्जीकृत किए गए हैं। दिसम्बर, 2018 से 22-23 तक पम्पों के ऊर्जीकरण का आधार प्रतिवर्ष 24806 पम्प हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीपीएल उपभोक्ताओं को भी रियायत दी रही है। 130 यूनिट के खपत के विद्युत देयक पर राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन करता है और प्रदेश में 16 लाख से अधिक बीपीएल उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया गया है। इन 4 वर्षों में 2085 करोड़ का अनुदान भी इन्हें दिया गया है । 2022-23 के बजट में 534 करोड़ का प्रावधान है, 2023-24 में 508 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । मजरा-टोला में विद्युतीकरण की व्यवस्था की गई है । ऊर्जा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा लोकप्रिय विभाग है । वर्ष 2012-13 से शहरी विद्युतीकरण योजना संचालित थी । इस योजना में 14 नगर निगम एवं नगरीय निकाय में बीपीएल कनेक्शन दिए जाने के लिए आवश्यक लाईन का विस्तार और कार्य संपादित किया गया है । इन चार वर्षों में राज्य में जन सामान्य की

विद्युत संबंधी समस्याओं का ध्यान रखते हुए 182.03 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है। इसमें 4 वर्षों में कुल 744 करोड़ रूपए व्यय किया जाकर 2780 कार्य पूरे किये जा चुके हैं । वर्तमान में लगभग 58 करोड़ रूपए का कार्य प्रगति पर है । योजना के अंदर 2022-23 में 3035.69 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया था, 2023-24 के बजट में 3500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फीडर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की अधोसंरचना में 12.17 प्रतिशत तक सीमित करना है एवं एसीएस, एआरजीएफ गैप को शून्य करना, लाईन लॉस की कमी करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है । इस समय प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए राशि 3,544 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत लाईन लॉस में कमी लाने 18,181 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाईन की विस्तार योजना, 274 करोड़ 11 के.व्ही. के अतिरिक्त कार्य का निर्माण, 17,619 ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए 44,168 किलोमीटर निम्न दाब एवं लाईन विस्तार के लिए 1 नग आई.टी. ओ.टी. कार्य स्वीकृत है।

समय :

2.10 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, कुल स्वीकृत राशि का 60 केन्द्रांश के मद से, 10 प्रतिशत राज्यांश के मद से तथा शेष राशि का वहन वितरण कम्पनी के द्वारा ऋण प्राप्त करके किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, स्वीकृत राशि 3,544 करोड़ रूपये के कार्यों में 2,222 करोड़ रूपये के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। शेष निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। अधोसरंचना कार्यों को मार्च, 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। 2023-24 की योजना में निर्धारित लक्ष्य हेतु मद राशि मे 46 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, प्री-पेड स्मार्ट मीटरिंग की व्यवस्था हेतु 4,079 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त है। स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए मीटरिंग 59.62 लाख मीटर वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग 0.10 लाख फीडर मीटरिंग के लिए 6,720 मीटर के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रति मीटर प्रति माह के आधार पर वितरण कम्पनी के द्वारा सम्बन्धित कार्य एजेंसी को 8 वर्ष तक भुगतान किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री विद्युत अधोसरंचना विकास योजना के अन्तर्गत मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसरंचना विकास योजना में विद्युत उपभोक्ताओं को एक निर्बाध गति से गुणवत्तापूर्ण पहुंचाने के लिए विद्युत अधोसरंचना की भूमिका को देखते हुए 31/11 के.व्ही. के पावर स्टेशन एवं के.व्ही.एम. के साथ-साथ 33 के.व्ही.एम., 11 के.व्ही.एम. लाईन आदि के निर्माण कार्य किये जायेंगे। 4 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री अधोसरंचना विकास

योजना के अन्तर्गत 399 करोड़ रूपये व्यय किए जाकर 67 नये 31/11 के.व्ही. उप केन्द्र निर्माण के कार्य, 156 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना के कार्य, 191 क्षमता वृद्धि के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 2022-23 और 2023-24 में 31/11 के.व्ही. 135 नग नये उपकेन्द्र स्थापना किए एवं 64 नग अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना करने और 40 नग ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से क्रेड द्वारा संचालित सुजला योजना का विवरण भी कम्पनी के द्वारा संचालित कृषि पम्प का उर्जीकरण किया गया है। उपभोक्ताओं को आधुनिक बिलिंग एवं शिकायत निवारण के लिए भी उनके बिलों "मोर बिजली मोर एप्प" के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना और प्रदेश में एच.पी. कनेक्शन के लिए आटोमेटिक रीडिंग बिलिंग की व्यवस्था की गई है। 15 हार्स पावर के एल.टी. कनेक्शनों के लिए आटोमेटिक मीटर रीडिंग एवं बिलिंग की व्यवस्था की गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष वितरण कम्पनी के 4 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करना चाहता हूं। अधिकतम मांग 4,160 मेगावाट से बढ़कर 5,443 मेगावाट हो गई है। इसी तरह से 31/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों की स्थापना की संख्या 1,213 से बढ़कर 1,342 हो गई है। वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या 1.56 लाख से बढ़कर 2.12 लाख हो गई है।

माननीय सभापति महोदय, 33 के.व्ही. लाईन की लम्बाई 21,870 किलोमीटर से बढ़कर 24,038 किलोमीटर हो गई है। 11 के.व्ही. लाईन की लंबाई 1.07 लाख किलोमीटर से बढ़कर 1.27 लाख किलोमीटर कर दी गई है। माननीय सभापति जी, निम्न दाब लाईन की ऊचाई 1.18 लाख किलोमीटर से बढ़ाकर 2.18 लाख किलोमीटर की गई है। उच्च दाब उपभोक्ताओं की संख्या 2,890 से बढ़कर 3,546 हो गई है। इसी तरह से निम्न दाब उपभोक्ताओं की संख्या 55.15 लाख से बढ़कर 61.20 लाख हो गई है । सभापति महोदय, कृषि पम्पों की संख्या 4 लाख 92 हजार से बढ़कर 6 लाख 36 हजार हो गई है । बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 19.51 लाख से कम होकर लगभग 16 लाख हो गई है । बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के द्वारा खपत की सीमा बढ़ने के आधार पर उनकी श्रेणी में किया गया है । माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अभिनव योजना प्रारंभ की है । सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम भेंट मुलाकात का हुआ । आज तक इसके पहले किसी सरकार ने ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी, जगह-जगह जाकर लोगों के बीच में समूहों से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं, लोगों की समस्यायें सुनते हैं, उसी वख्त स्पॉट पर निर्माण कार्य की घोषणा करना और उनकी समस्याओं को निदान करने के लिये योजना बनी है । मुख्यमंत्री जी हर जगह गये हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहां मुख्यमंत्री जी न गये हों, भेंट-मुलाकात में लोगों की समस्यायें न सुनी हो, उसके अनुसार उसका निदान करना, उसकी घोषणा करना, उसका क्रियान्वयन, उसकी समीक्षा, उसके आधार पर सारी योजनायें शुरू की जा रही है । माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों के लिये

अपनी योजनायें बनाकर सब कार्य किये हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सभी मांगों पर अपना समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री सौरभ सिंह जी ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनकी मांग चर्चाओं पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ जो है, भारत का बिरला राज्य है, जहां हर प्रकार के खनिज पाये जाते हैं । कोयला, लोहा, बाक्साईट, लाईम स्टोन, डायमंड, टिन हर तरह के खनिज हैं । माइनिंग के राजस्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर संभावनायें हैं तो संभावनायें यहीं पर है । सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर नहीं है, मैं कोयले से अपनी बात रखना चालू करूंगा । माननीय अजय चन्द्राकर जी अभी कोयले पर जो बोल रहे थे कि ई.डी. की रेड पड़ी, कोयले में कोल शेष का पैसा जाता था, कोल शेष का पैसा कहां जा रहा है, किसके कहने पर जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी, माईनिंग विभाग के भारसाधक मंत्री है । अगर ऐसा हो रहा था या हो रहा है, अगर उनके संज्ञान में हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है ? उनके संज्ञान में नहीं है तो कौन जिम्मेदार है ? दोनों बातें नैतिकता से गलत है । कोयलांचल में जो कोयले का खेल चल रहा है, इसमें तीन चीजें हैं । सबसे पहले कोयले की चोरी है । एससीसीएल की खदानों से, सरकारी खदानों से, केन्द्र सरकार की खदानों से, वह केन्द्र सरकार की खदान नहीं है, भारत राज की खदान है । यह इस देश की खदान है । खनिज संपदा इस देश की संपदा है, यहां के जनता की संपदा है, उस संपदा की चोरी हो रही है, अवैध कोयला निकाला जा रहा है, अवैध कोयले का परिवहन किया जा रहा है, उसमें राजस्व का जो घाटा होता है, वह एक चोरी है । माननीय सभापति महोदय, सरकार चोरी रोकने के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रही है, संगठित गिरोह बन गये हैं और कोयले की चोरी कर रहे हैं । सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, जिस माफिया को वह संरक्षण दे रहे हैं, वह माफिया किसी का नहीं होता है । माफिया को संरक्षण न दें, जनता को संरक्षण दें । उन एजेंसियों को संरक्षण दें, जो प्रदेश के हित में राष्ट्र के हित में काम कर रही है, जिससे प्रदेश और राज्य का राजस्व बढ़ रहा है, इससे जनता के फायदे के लिये पैसा खर्चा होगा ।

माननीय सभापति महोदय, यह कोयले की जो ट्रांसपोर्टिंग होती है। केंद्र सरकार का बहुत Strict निर्देश है कि जो कोयले की ट्रांसपोर्टिंग होती है, उस ट्रांसपोर्टिंग को कम से कम रोड से किया जाये और ज्यादा से ज्यादा ट्रेन से किया जाये। रोड ट्रांसपोर्टिंग को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। तीसरी चीज आती है कि हम कोयले का उत्पादन कैसे बढ़ायेंगे। यदि कोयले का उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे पास अतिरिक्त राजस्व भी आयेगा। कोयले का उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? या तो जो एस.ई.सी.एल. की सरकारी खदानें हैं, हम उन खदानों का एक्सपेंशन करें और उनका प्रोडक्शन बढ़ाये। लेकिन वहां तो माफिया आ गये हैं। मुझे यह बोलने में हिचक नहीं है कि जो कोरबा जिले के जो कलेक्टर है, वह माइनिंग को बढ़ाने

के लिये मदद ही नहीं करते हैं। एक्पेंशन कराने के लिये मदद नहीं करते हैं। ऐसे कई मामले, प्रकरण लंबित है जो आगे नहीं बढ़ते। दूसरा तरीका जो है, वह यह है कि जो प्राइवेट कोल ब्लॉक का एलोकेशन हुआ है, कोयला रहेगा तो पॉवर प्लांट चलेगा, कोयला रहेगा तो उस कोयले से जगह-जगह उद्योगों में जो कोयले की कमी आती है, वह कोयले की आपूर्ति की जा सकती है, जिससे उद्योग नहीं चलते। माननीय रमन सिंह जी के सवाल में जवाब आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में कुल 08 प्राइवेट कोल ब्लॉक का एलोकेशन किया। उस 08 प्राइवेट कोल ब्लॉक में से गरेपलमा-4 मेसर्स जिंदल पॉवर, गरेपलमा 4/7 रायगढ़ साडा एनर्जी, इन दोनों को ही राज्य शासन ने कन्सर्न टू वर्क, काम करने का आदेश जारी किया। 6 कोल ब्लॉक ऐसे है जिनमें किसी का आवंटन 2020 में, किसी का 2021 में, किसी का 2022 में केंद्र सरकार ने कर दिया है। लेकिन आवंटन करने के बाद भी खनिज विभाग स्वीकृति नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है ? सरकार की नीयत क्या है ? यह क्यों कोयले का उत्पादन बढ़ाना नहीं चाह रही है ? यह बड़ा दु:ख का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, अनेक-अनेक क्षेत्रों में माइनिंग का कार्य किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में एक नया प्रयोग चालू हुआ है, वह है छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन। छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन को लोहे की खदानें, बाराद्वार में डोलोमाइट की खदानें, एल्युमिनियम की खदानें, अंबिकापुर में बॉक्साइड की खदानें दी जा रही है। आप खदान देते जा रहे हैं। खदान के बाद का जो खेल चालू होता है। जिसकी तरह-तरह की चर्चा हो रही थी, वह है एम.डी.ओ., माइन डेव्हलपमेंड एण्ड ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो कोयले का कोल ब्लॉक है, उसका एम.डी.ओ. किसके पास है ? ये यहां पर जिनका रोज नाम लेते रहते हैं, उन्हीं के पास एम.डी.ओ. है। आरी डोंगरी के लोहे की माइन्स का एम.डी.ओ. किसके पास है ? आपके अपने लोगों के पास है। सारी जगहों पर यही है। बाराद्वार में जो डोलोमाइट की माइन्स दी जा रही है, उसका एम.डी.ओ. किसके पास है ? आपके अपने लोगों के पास एम.डी.ओ. है। यह एम.डी.ओ. का खेल क्यों है ? जो एम.डी.ओ. अंदर जायेगा, तो क्या हमारे पास यह माइनिंग मैकेनिजम है ? कि माइनिंग प्लान के हिसाब से वहां से निर्धारित मात्रा में जितना खनिज निकालना है, क्या वह निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। खनिज का सर्वे प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है ? यही पर खेल चालू होता है, यही से माफिया राज चालू होता है और जो माफिया का तंत्र होता है, वह जनता का और छत्तीसगढ़ के राजस्व का नुकसान करता है और अपनी जेब में पैसा भरता है। वह पैसा छत्तीसगढ़ सरकार के खाते में आना चाहिए और उसका उपयोग जनहित में होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के देवभोग में यह तय है कि डायमंड की माइन्स है। इस सरकार ने साढ़े चार साल में डायमंड माइनिंग के लिये क्या किया ? जब माननीय मुख्यमंत्री जी इधर बैठते थे तो डि-बियर्स के बारे में डायमंड माइनिंग का बड़ा सवाल करते थे। मैं उनसे

आग्रह करूंगा, वह यहां नहीं है लेकिन वह मेरी बात सुन रहे होंगे कि आपने साढ़े चार साल में डि-बियर्स की डायमंड माइनिंग के लिये क्या किया ? आपने माइनिंग क्यों चालू नहीं की ?

माननीय सभापति महोदय, आज के पेपर में एक बड़ी मार्मिक खबर आयी है। महासमुंद जिले में 5 मजदूर अवैध ईंट भट्टे के ऊपर सो रहे थे, उसमें आग लग गयी और उनका देहांत हो गया। अवैध ईंट के कितने भट्टे चल रहे हैं ? माइनिंग विभाग उसके लिये कार्रवाई क्यों नहीं करता ? वह पर्यावरण और राजस्व का कितना नुकसान कर रहे हैं ? कितनी टॉपसाइल को खराब कर रहे हैं। उसके लिये व्यवस्था की गयी है कि फ्लाई ऐश के ब्रिक्स बनने चाहिए। इस पर व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ? वह कोई रॉयल्टी नहीं पटाते हैं। कोई राजस्व को कुछ नहीं देते। मैं गौण खनिज के संबंध में कहना चाहूंगा कि छोटा सा गिट्टी की बात कहना चाहूंगा। सभी सदस्यों ने रेत की बात की। मैं मुरूम का बताना चाहूंगा कि इनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है? मेरे कल के प्रश्न का जवाब है कि मिट्टी , मुरूम की कितनी परमिशन दी गई ? यह मिट्टी/ मुरूम क्यों है ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप मिट्टी को अलग करिये और आप मुरूम को अलग करिये। जो मुरूम है वह अलग प्रकार की चीज है और मिट्टी है, वह अलग चीज है। वह मिट्टी, मुरूम के नाम पर भी सारा खेल होता है। इस प्रदेश में मिट्टी की परमिशन अलग होनी चाहिए और मुरूम की परमिशन अलग होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इनके, माननीय ननकीराम कंवर जी और मेरे विधान सभा क्षेत्र से भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है। हम तीनों लोगों ने अनेक बार शिकायत की कि आपको जो अधिग्रहित क्षेत्र है उस क्षेत्र से मिट्टी निकालकर, मिट्टी का वहीं पर उपयोग कर रहे हैं। तो क्या इसमें राजस्व नहीं बनता? इसमें राजस्व क्यों नहीं लिया जा रहा है वह माईनिंग का अधिकारी अपना मुंह बंदकर, क्यों रखा है ? अगर वहां पर अधिग्रहित जमीन से मिट्टी उठायी जा रही है, और उस मिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा रहा है। अगर सड़क निर्माण में उपयोग किया जा रहा है तो उसका व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। अगर मिट्टी का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है तो उसको पैसा मिलना चाहिए। वह रायल्टी क्यों नहीं ली जा रही है ? मेरा यह कहना है कि यह रायल्टी की चोरी क्यों की जा रही है? इस प्रदेश में माईनिंग से बहुत पैसा आ सकता है। हमारे यहां माईनिंग में माफिया राज का पर्दापण हो गया है और वह माफिया राज पूरे सरकार को खत्म कर रहा है। ई.डी. के छापे, ई.डी. की जो कहानियां, वह सब उसी से जुड़ी हुई हैं। इस खेल में कोई छूटा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां कोलवाशरी संचालित होती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कोल वाशरियों में जो 20 प्रतिशत रिजेक्ट का कोयला होता है उस कोयले को भी आर.ओ.एम. डायरेक्ट ट्रांसफर करके, कोयला देना है, पर आज भी कोल वाशरी संचालित हो रही है आज भी वह 20 प्रतिशत का कोयला जा रहा है। उसका अवैध परिवहन हो रहा है, अवैध स्थानों पर वह कोयला जा रहा है। उसे क्यों रोका नहीं जा रहा है ? वह कौन माफिया हैं, जिनके ऊपर कार्यवाही नहीं

की जा रही है ? आप कार्यवाही करिये और पूरा का पूरा 20 प्रतिशत भेजिए। क्यों आप 20 प्रतिशत को रोक रहे हैं, 100 प्रतिशत कोयला जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दूसरा बिजली विभाग है। पूरे प्रदेश की जनता आज की तारीख में अतिरिक्त बिजली बिल, लेट बिजली बिल, गलत बिजली बिल से परेशान है। इन साढ़े 4 सालों में सरकार ने इसके लिए कोई मैकेनिजम खड़ा नहीं किया। यहां मीटर रिडिंग कौन करता है ? किसी को नहीं पता कि यहां कौन मीटर रिडिंग करता है। मीटर रिडिंग कब होती है ?यह किसी को नहीं पता। अगर 4 महीने में मीटर रिडिंग होगी तो आप जो प्रति यूनिट छूट देते हो, वह तो आपने कितना कंज्म्प्शन किया, उसके आधार पर देते हो। तो हमारा जो उपभोक्ता है वह कंज्म्प्शन के लिमिट से बाहर चला जाता है और जब बाहर चला जाता है तो आपकी जो छूट की परिधी है उससे भी वह बाहर हो जाता है तो उसको छूट नहीं मिलती। इस प्रदेश में महीनेवार रिडिंग क्यों नहीं होती ? यहां महीनेवार बिल का वितरण क्यों नहीं होता ? एनर्जी चार्जेस, पीछे में यह आ जाता है हर साल एक बात आ जाती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर भागते रहते हैं, यह किस बात का सिक्योरिटी डिपॉजिट है ? इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिफण्ड की क्या प्रक्रिया है ? आप कैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट को करेंगे ? इस बार तो जो बी.पी.एल. कार्डधारी हैं जिनको अनुदान का पैसा दिया जाता है उनका भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जुड़कर आ गया। वह सारे विधायकों के पास घूम रहे थे कि भईया यह बिजली बिल का क्या होगा ? हमारे पास यह सिक्योरिटी डिपॉजिट का आ गया। जो एकलबत्ती कनेक्शन वाले हैं जिनको बिजली रियायत दर पर दी जाती है उनका भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया। यह सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है ?फिर उसके बाद आप बिजली बिल देखिएगा तो उसमें ईंधन उपकर आ जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं कोयले की चर्चा कर रहा था, यह ईंधन उपकर क्या है? हमारा कोयला है, इसी प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है। जब इसी प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है तो छत्तीसगढ़ की जनता ईंधन उपकर क्यों पटाये ? किसी समय प्रति यूनिट 1 रूपये 10 पैसे आ जाता है, किसी समय प्रति यूनिट 72 पैसे आ जाता है। कोयले का रेट फर्क होता है हम उसके आधार पर कर लेते हैं। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आपको कोल ब्लॉक एलॉट किया है, आपके पास कोल ब्लॉक है तो यह किस बात का ईंधन उपकर है ? यह किस चीज का ईंधन उपकर है ? मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि यह प्रदेश इस साल जो बिजली कटौती की समस्या देखेगा और अभूतपूर्व अघोषित बिजली कटौती होगी और इसलिए अभूतपूर्व अघोषित बिजली कटौती होगी। आपने साढ़े 4 साल में आपने एक भी जनरेशन का यूनिट नहीं बढ़ाया। माननीय अजय चन्द्राकर जी उसके बारे में बोल रहे थे। एक जो मडवा पावर प्लांट चल रहा था, वह भी माफिया लोगों के चक्कर में फंस गया। 500 मेगावाट की एक यूनिट चलती है और 500 मेगावाट की एक यूनिट नहीं चल रही है। अब क्यों नहीं चल रहा है, उसका कारण है। आपके पास कोयला 02 जगह से आता है। एक एस.ई.सी.एल. से

कोयला आता है और गारेपलमा की कोल माईन्स से कोयला आता है। जो एस.ई.सी.एल. का कोयला आता है, वह सस्ता कोयला है, नजदीक से आता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आजकल विदेशों से भी कोयला आने लगा है।

श्री सौरभ सिंह :- आप विदेशों से नहीं खरीद रहे हो, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। आप यहीं के कोयले में अपना प्लाण्ट चला रहे हो। गारेपलमा से जो कोयला आता है वह मंहगा कोयला है। वही एम.डी.ओ. का कोयला है जिनकी ये चर्चा करते हैं। उसका ट्रांसपोर्टिंग का कार्य जैस करके एक कंपनी को दिया गया है जो 108 चलाती है, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। अतिरिक्त रेट पर कोयला आता है और अतिरिक्त रेट पर जो कोयला आता है वह खराब कोयला आता है, वह कोयला कहां बिका है वह ई.डी. की चार्जशीट में है। उस कोयले का प्रदेश को क्या नुकसान हुआ ? जिसके जेब में जो पैसा गया होगा, गया होगा पर कोयले का नुकसान प्रदेश को यह हुआ कि रद्दी कोयले के उपयोग में मड़वा पावर प्लांट का एक बायलर उड़ गया और जो एक बायलर उड़ गया वह 500 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। जब वह 500 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो टोटल आपकी जो बिजली का उत्पादन है, रमन सिंह जी के सवाल में आया, मैं उससे बोल रहा हूं। लगभग आप 2100 मेगावाट के आसपास अपना उत्पादन कर रहे हैं और 3000 मेगावाट खरीद रहे हैं। आपको बिजली की आपूर्ति के लिए जब गर्मी आयेगी तो फिर ओपन एक्सेस से बिजली खरीदना चालू करेंगे। अब आप ओपन एक्सेस से बिजली खरीदना चालू करेंगे तब आप कुछ भी रेट में बिजली खरीदेंगे। क्योंकि आपको अपने ग्रिड को फेल नहीं होने देना है, ग्रिड को चलाना है। जब ग्रिड के लिए है तो 15 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये की ओपन बाजार से आप बिजली खरीदना चालू करोगे। क्या ये ओपन बाजार की बिजली के लिए छत्तीसगढ़ बना है ? हम सेन्सेक्स के मार्केट से बिजली खरीदें। ओपन एक्सेस से बिजली खरीदना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा पाप है और यह सरकार बार-बार कर रही है। इनके पास बिजली नहीं है और आने वाले समय में लगातार अवैध बिजली कटौती होने वाली है। अघोषित बिजली कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली है। अजय चन्द्राकर जी ने जो चिंता रखी, किसानों ने अपनी रबी फसल की धान बोई। अन्य उत्पादन किया है। सबसे पहली मार उन किसानों को पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी बिजली कटने लगेगी। उनके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ेगी। 5 घंटे की अघोषित कटौती होनी चालू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 हजार करोड़ रुपये I.C.P.D.S. योजना से मिला है। केन्द्र सरकार ने I.C.P.D.S. योजना से 12 हजार करोड़ रुपये पैसा दिया है। और किसलिए पैसा दिया है, केबल बदलने के लिए, पुरानी तारों को बदलने के लिए, केबल लगाने के लिए, सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए, नये सब-स्टेशन बनाने के लिए, नये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के लिए ये पैसा दिया गया है। पर हो क्या रहा है, आज तक टेंडर नहीं हो पाया है। जमीन में काम चालू नहीं हो पाया है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय महोदय, टेंडर हो रहा है लेकिन बिना 5 परसेंट के नहीं दे रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय विधायक जी, उसकी अलग कहानी बता दिये हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- प्रमोद भैया, ऐसा असत्य आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा। कल 9 टेंडर निरस्त किया गया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनके चक्कर में आप असत्य बोलना मत चालू कर दें।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, I.C.P.D.S. योजना की जो टेंडरिंग होनी है, 1200 करोड़ रुपये आकर पड़ा है। वह टेंडरिंग नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उसमें 4 हजार करोड़ रुपये स्मार्ट मीटर का है और 8 हजार करोड रुपये टेंडरिंग का है। वह टेंडरिंग क्यों नहीं हो रही है ? केबल बदल जायेगा तो क्या बिगड़ जायेगा ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो केबल बदलते हैं न, वह केबल के अंदर जो कोर होता है, वह कोर की क्षमता को चेक करने की आवश्यकता है। जितना एम.एम. का वह कोर बताते है, उतने एम.एम. के कोर की सप्लाई नहीं होती। उसके कारण आपका बिजली का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मार खाता है और जहां लोड़ पडता है वहां जल्दी-जल्दी ट्रांसफार्मर उड़ते हैं और सारे जनप्रतिनिधि ट्रांसफार्मर खराब हो गया, करके परेशान होते हैं। आपने ट्रांसफार्मर की खरीदी नहीं की। ट्रांसफार्मर की खरीदी के लिए कोई योजना नहीं है। ट्रांसफार्मर की एक अवधि है कि वह कितने साल, कितने दिन चलेगा। ट्रांसफार्मर तो बदलना पड़ेगा। आप I.C.P.D.S. योजना को छोड़ दिये हैं। उसके बाद I.C.P.D.S. में दूसरी बात स्मार्ट मीटरिंग की है। सरकार ये योजना को तय ही नहीं कर पाई है कि स्मार्ट मीटरिंग चलायेंगे या नहीं चलायेंगे। चाहे वह टेंडर में प्रक्रिया है या कोई अपने लोगों को अनुग्रहित करने के लिए टेंडर देना है। दूसरी समस्या जो स्मार्ट मीटरिंग की है । मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह जवाब में देंगे। स्मार्ट मीटरिंग यदि लग जाएगी तो वह ऐसी योजना है, जैसा प्रीपेड कनेक्शन। मैं एक हजार रूपये जमा कराऊंगा तो एक हजार रूपये की मेरी बिजली चलेगी, पर मैंने छत्तीसगढ़ की जनता से सिक्योरिटी डिपाजिट जमा किया है, क्या उसका समायोजन उस स्मार्ट मीटरिंग में होगा ? इसको माननीय मुख्यमंत्री बतायें। क्योंकि उनका अंतिम बजट है, अंतिम बात है। इसके बाद बात नहीं आएगी।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करियेगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। आपने 100 करोड़ रूपये उदय योजना के लिए छत्तीसगढ़ को शामिल किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहूंगा कि क्या आप उदय योजना में शामिल हो गये? उदय योजना वह central government की योजना है, जिसमें बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और बिजली की कंपनियों का जो पैसे का घाटा था, जो financial mess था उसको क्लियर करने के लिए वह योजना है। पर यह 100 करोड़ में नहीं होगा। आप टोकन के लिए जैसे

प्रधानमंत्री आवास में आप डर गये कि वह योजना यदि cancel हो जायेगी तो हमारा नुकसान हो जायेगा तो आपने 100 करोड़ टोकन का दिया। छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ रूपये में उदय योजना नहीं होगी। उसके लिए आपको अतिरिक्त एलॉटमेंट करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, हाइडल पावर की बात हुई। जब आप थर्मल की जनरेशन की केपिसिटी नहीं बढ़ा सकते तो हाइडल पावर की जनरेशन की केपिसिटी क्या बढ़ायेंगे। पर मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, अजय चंद्राकर जी जो बात को बोल रहे थे। जितने हमारे हाईडल प्लांट हैं। क्या सरकार की यह सोच थी, क्या यह सरकार का विजन था। अब तो विजन समय खतम हो गया। आचार संहिता लगेगी और उसके बाद जब दूसरी सरकार बैठेगी, हमारी सरकार बैठेगी तो हम बतायेंगे कि हाईडल परियोजना कैसे चलती है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री सौरभ सिंह :- हसदेव बांगो परियोजना में हाईडल परियोजना में 120 मेगावॉट की सबसे सस्ता बिजली प्रोड्यूस होता है। 54 पैसे में बिजली प्रोड्यूस करते हैं। क्या उसमें री-डिजाईन नहीं कर सकते? उसको अलग तरह से योजना..।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, दो मिनट। क्या उस योजना को आप री-डिजाईन नहीं कर सकते? उसके लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी के पास इलेक्टॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है। आई.टी. सेक्टर में इंडिया सबसे आगे है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सब आई.टी. की कंपनी है। आई.टी. सेक्टर में हम विश्व को कंट्रोल करते हैं। साढ़े चार साल में आपने आई.टी. पार्क नहीं बना पाया है, एक आई.टी. की व्यवस्था नहीं की है और उतना तो आपने किया नहीं। ग्राम पंचायतों में जो भारत नेट का इंटरनेट लगा है, जो खोदकर नेट का कनेक्शन लगा है, वह भी ठीक से नहीं चल रहा है। उसको तो कम से कम चला दीजिये। वह तो कम से काम ग्राम पंचायतों में चलना चालू हो जाए। उसका जो फायदा है, वह तो जनता को मिलने लगे, ग्राम पंचायतों को मिलने लगे जो ऑनलाईन केन्द्र सरकार की परिकल्पना है। तो यह आई.टी. से रिलेटेड जो बात थी।

माननीय सभापति महोदय, विमानन विभाग। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बात बोलें। हम यह एयरपोट बनायेंगे, हम यह एयरपोर्ट बनायेंगे। माननीय केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको दो-तीन बार पत्र लिखा। आग्रह किया कि एक बार बैठ कर चर्चा कर लेते हैं। अन्य और भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं। आपको उसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं, झारसुगड़ा। झारसुगड़ा का एयरपोर्ट डेव्हलप हो गया। वहां तो बीजू जनता दल की सरकार है। आप बैठकर क्यों बात नहीं करते? आप रायपुर को कारगो हब क्यों नहीं बनाते? आप इंटरनेशनल के लिए क्यों बात नहीं करते कि क्या हम कर सकते हैं। केन्द्रीय मंत्री से तो बात करनी पड़ेगी न। केन्द्रीय मंत्री जी का जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस सिंधिया जी को आप लोगों ने पटा कर ले गया । हमारी सरकार भी मध्यप्रदेश में खरीद लिया।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, बिलासपुर का एयरपोर्ट के लिए एक ठेका निकला। पहले तो वह ठेका विवादित था। वह ठेका पी.डब्ल्यू.डी. के विवाद में था। वह ठेका लगभग 10 करोड़ का ठेका है। 2.85 एकड़ जो अतिरिक्त जमीन चाहिए थी, उसको सरकार भूल गई। ऐसे में एयरपोर्ट बनेगा। पूरी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते, एयरपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर क्यों खड़ा नहीं करते? आज छत्तीसगढ़ में अपार सुविधाएं हैं। जगदलपुर की ट्रैफिक चल रही है। जगदलपुर लोग प्लेन से आना-जाना करते हैं। आप अंबिकापुर के लिए क्यों व्यवस्था नहीं करा सकते? राजा साहब तो है। आपका राजनीतिक नहीं पटता। लेकिन राजा साहब भी आना-जाना कर लेंगे। रात को ट्रेन में बैठकर जाते हैं। अब तो रोड बन गई। केन्द्र सरकार की कृपा से रोड ठीक-ठाक हो गई तो अब रोड से चले भी जाते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- रोड बन गया तो केन्द्र सरकार की कृपा से और खराब हो गया तो राज्य सरका की कृपा से। वाह साहब। वाह।

श्री सौरभ सिंह :- बिल्कुल। माननीय सभापति महोदय, जो एन.एच.आई. की सड़क बनेगी तो वह तो केन्द्र सरकार की सड़क है न। जब आप राज्य सरकार की बनायेंगे तो आपके लिए भी बोल देंगे।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी बनेगी भी न तो आप तारीफ नहीं कर सकते।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें । श्री बृहस्पत सिंह जी ।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे देश और दुनिया में हम लोगों ने बहुत सुना था । डॉ. मनमोहन सिंह जी बारे में हम लोगों ने बहुत सुना था कि बहुत बड़े विद्वान हैं, जो पूरी दुनिया में मंदी होने के बाद भी अपने भारत देश में अच्छा वित्तीय प्रबंधन होने के कारण हमारे पूरे देश में कभी भी ऐसा कोई आर्थिक संकट नहीं आया और बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से चला। दूसरा पूरे हिंदुस्तान में अगर है तो वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है जहां एक रूपये भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने न तो बाजार से लोन लिया और न ही कोई अतिरिक्त टैक्स लगाया इसके बाद भी 1 लाख 2788 करोड़ का बजट यह छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आयी है । मैं इसके लिये आदरणीय वित्त मंत्री और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। जब पूरे देश में यह हालत हो गयी कि सारे लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, तन्ख्वाह काट रहे हैं, संविदा से हटा रहे हैं, कोई रेगुलर भर्ती नहीं हो रही है । इसके बाद भी हमारे राज्य

का इतना अच्छा वित्तीय प्रबंधन है कि लगातार सरकारी नौकरी चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, व्याख्याता हो और अच्छे क्लास-टू से, थ्री से, फोर से सभी वर्गों से लगातार हम हजारों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, रेगुलर भर्ती करने में सफल हुए हैं । यह हमारे अच्छे वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है । हम यहीं नहीं रूकते हैं, किसानों का धान जैसे इन लोगों ने महापाप किया था । 2100 रूपये की घोषणा की थी और 300 रूपये बोनस, पूरी सरकार को चिल्लाते-चिल्लाते छत्तीसगढ़ की जनता रह गयी लेकिन इन्होंने नहीं सुना । नतीजा यह हुआ कि किसानों ने इनकी 15 साल की सरकार को 14 सीटों में लाकर यहां बैठा दिया । हमारी सरकार ने भी, चूंकि हमारे घोषणा-पत्र में आया था कि हम 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदेंगे और इनका कर्जा माफ करेंगे और हमारी सरकार बनते साथ ही हमारी सरकार ने कर्जा भी माफ किया और 2500 रूपये क्विंटल धान किया । इसके बाद जबकि लगातार दिल्ली में, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की सरकार है । इनकी सरकार ने लगातार अड़ंगेबाजी की कि अगर आप 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदेंगे तो हम आपका धान नहीं उठायेंगे । केंद्रीय पुल में नहीं उठायेंगे इसके बावजूद भी मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और छत्तीसगढ़ की जनता के सहयोग से उन्होंने खरीदा और पूरा का पूरा, भले ही अलग से किसान न्याय योजना का नाम देकर 2500 रूपये क्विंटल धान खरीदने का काम किया और उनको कभी भी आर्थिक संकट से गुजरने नहीं दिया, सीधे उनके खाते में डालने का काम किया ।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो बजट आया है । हमारे वित्तीय प्रबंधन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनें जो कि लगातार इस बात की मांग कर रहीं थीं कि हमको कम से कम साढ़े 8 हजार रूपये दे दो, कलेक्टर दर पर दे दो । लगातार ये लोग रोज भारतीय जनता पार्टी के मित्र आंदोलन में जाकर उनको भड़काने का काम कर रहे थे । लगातार इनका यही भड़काने का काम था कि सरकार के विरोध में चुनाव तक ये अड़ जायें । इनका प्रयास था लेकिन उल्टे मुंह खाकर वापस आ गये क्योंकि हमारा वित्तीय प्रबंधन अच्छा था । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जहां 10,000 रूपये देने का काम किया, वहीं मिनी कार्यकर्ताओं को भी देने का काम किया।

श्री रामकुमार यादव :- कका जी, 15 साल तक एमन नइ दिन अऊ अभी भड़काये रिहिन हे । अब इही मन ला ओमन बहरी-मुठिया धर के खोजत हें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इसके आगे हमारे मितानिन कार्यकर्ता बहनों ने जिन्होंने कभी नहीं मांगा था उनको लगातार इन्होंने भड़काने का काम किया । चूंकि कोरोना काल में हमारी मितानिन बहनों ने बहुत अच्छा काम किया था, लोगों की जान बचाने में मदद की थी, टीकाकरण में मदद की थी । उन सारी संवदेनाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने उन मितानिनों को आज साढ़े 22 सौ रूपये देने का निर्णय लिया है जिसके लिये मैं

माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । हमारे कोटवार भाईयों के लिये भी, चूंकि 15 सालों में इन्होंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हमारे कोटवार जो कि गांव में रहते हैं, जिनके पास कम जमीन है उनको भी इन्होंने देने का काम किया और हमारे फायनेंस में उसकी व्यवस्था की । बजट में उनको देने की व्यवस्था की है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बृहस्पत सिंह जी, आप जब इधर रहकर बोलते थे तो आपके भाषण में आनंद आता था । इधर जाने के बाद आपके भाषण में रस नहीं है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप क्या चाहते हैं ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं, वह रस वाला भाषण दीजिये । आप उधर ही रहें। हम यह नहीं बोल रहे हैं कि आप इधर आयें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- रस रहे न रहे, बृहस्पत जी यहीं रहेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- का हे न विधायक जी ओ मेर रहकर सिर्फ गोठियाना हे, कुछ करना तो हे ही नइ । करना ऐती ला हे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने लगातार इनके मुखिया ने जो देश में दाढ़ी वाले बाबा कहलाते थे, कभी क्या बाबा कहलाते थे । कहा था कि हरेक साल दो करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और 15-15 लाख खाते में देंगे । इनका ऐसा वित्तीय कुप्रबंधन हुआ कि पूरे देश के लोग देखते रह गए, कभी नहीं दिया । हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद् देता हूं जिन्होंने हमारे बारहवीं पास नवजवान जिनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है, उनको 2500 रूपए प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है । इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूं । सभापति जी, इतना ही नहीं, गांव के पटेल जो पूरे गांव की माजगुजारी वसूल करके ट्रेजरी में जमा करता था उसको मात्र 300 रूपया मिलता था । उनके लिए भी 3000 रूपए वार्षिक प्रावधान किया है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- दादा, आम बजट पर चर्चा नहीं हो रही है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों पर चर्चा हो रही है । आप ही के लोग कह रहे हैं उसमें थोड़ा प्रकाश डालें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अच्छा, अच्छा । हम वित्तीय प्रबंधन की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं कि इनके समय में बच्चे बहुत भटक रहे थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बृहस्पत जी, जिस सरकार में आपकी जान सुरक्षित न हो । जिस सरकार में आपको धरने पर बैठना पड़ता हो । जहां का एस.पी. दंगा कराने का प्रयास करता हो, उसकी तारीफ कर रहे हो । यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आप बोलते रहे हो । इसलिए बता रहा हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपकी विचारधारा के जो अधिकारी होते हैं उनको ठीक करने का काम कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- राजा साहब से आपका जीवन सुरक्षित है ?

श्री रामकुमार यादव :- राजा साहब हमारे राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बहुत बढ़िया । सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सरगुजा के बहुत सारे बच्चे, बस्तर के बच्चे दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, आई.आई.टी. में पढ़ाई कर रहे हैं । उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा शर्मा जी आपके मित्र नेताम जी हैं, जो बहुत लम्बे समय रहे उनके पड़ोसी हैं । एक भगवान नाम का आदिवासी लड़का है, उसकी बेटी आज दिल्ली के आई.आई.टी. में पढ़ती है और लास्ट ईयर की स्टूडेंट है । उसकी पढ़ाई का खर्चा भी हम लोग लगातार दे रहे हैं। आपको बता दूं कि बलरामपुर में एक मजदूर की बेटी है उस बच्ची ने लगातार प्रतियोगी परीक्षा दी, पिछले साल आई.ए.एस. की परीक्षा दी, 3 नम्बर से पीछे रह गई और उसकी भी मदद हमारी सरकार ने किया है । इस साल दिल्ली में पढ़ाई की उसका नाम सुनीता कुजूर बलरामपुर के राजपुर ब्लॉक की आदिवासी बच्ची है । उन्होंने आई.ए.एस. की परीक्षा पास कर ली, इंटरव्यू में भी पास कर ली, मेडिकल भी हो गया और बहुत जल्दी ईश्वर चाहेगा तो छत्तीसगढ़ कैडर मिल जाता है तो यहां आई.ए.एस. बनकर आएगी । यह हमारी सरकार की उपलब्धि है । मजदूर की बच्ची भी आई.ए.एस. कर सकती है । ऑटो चलाने वाले की बच्ची भी आई.आई.टी. में पढ़ाई कर सकती है । यह हमारी सरकार की योजना है और ऐसी हमारी वित्तीय वयवस्था है कि हम उसको वित्तीय लाभ पहुंचा रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- तुम्हर मन कस नो हन । आदिवासी मन ला जर्सी गाय देबो कहे रहा । अभी ले खोजत हे तुमन ला । भाजपा वाला मन ला ।

श्री बृहस्पत सिंह :- किसानों की बात होती है । हम लोगों ने नहीं कहा था 26 रूपए 40 पैसे देंगे । हमने सिर्फ 2500 रूपए किसानों को देने की बात की थी । लेकिन हम उस 2500 के साथ-साथ 26 रूपया 40 पैसे किसान न्याय योजना के तहत् दे रहे हैं और आप चिंता मत करो आने वाले समय में इनका धान 2800 रूपए में खरीदेंगे । किसान आपके भड़काने से भड़कने वाले नहीं हैं । साहब, हम लोग इतने में ही नहीं रूकते । आपने तो यहां तक बोल दिया कि कुछ भी नहीं मिला । आप तो किसान भी हैं, आपके आधे से अधिक विधायक किसान हैं । अपने अपने खाते में चेक करो और अगर सही में विरोध करते हो तो उस योजना का पैसा जो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, समर्थन मूल्य से अधिक की राशि को वापस करो । कह दीजिए कि हम बहिष्कार करते हैं, नहीं लेंगे । लेकिन आपमें इतनी हिम्मत नहीं है । क्योंकि आप तो नागपुर से संचालित होते हैं । यहां बोलते कुछ है और बाहर जाकर कुछ भी करते हैं । साहब, इतना ही नहीं । हम सामान्य प्रशासन की बात कर लेते हैं । प्रशासनिक कसावट के लिए हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ में जिला बनाने का काम किया है, राजस्व सब-डिवीजन बढ़ाने का काम किया है, तहसील बढ़ाने का काम किया है, उप-तहसील बढ़ाने का काम किया है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ाने का भी काम किया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप सुनो तो पम्मू भइया । पहले तय तो कर लो कि उधर के हो या इधर के हो किधर के हो । क्योंकि आप हमारे एक साथी को इतना भावुक कर दिये ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं सत्य की तरफ हूं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, आदरणीय पम्मू भैया, भ्रष्टाचार की बात हर काल में होती है लेकिन वह दिखाई नहीं देता।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- भाभी, इसमें बहुत ज्यादा हो गया है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- नहीं-नहीं, उसके पहले का देखिए ना। दिखलाई नहीं देता, बोलते बस हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- इसमें बहुत ज्यादा हो गया है।

श्री रामकुमार यादव :- दिल्ली के सरकार बोलिस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सफ्फा ला खा के ढकार दिस। कम से कम हवा पानी ला तो खोल देव।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अब मे हा अकेला हों तो सब झन चढ़ बईठत हो। ए बात ला स्वीकार करव, जेन बाहर में स्वीकार कर सकव।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 609 नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। कैसे आया ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय प्रमोद भाई के साथ बड़ी विडंबना है। गलत समय में सही जगह और सही समय में गलत जगह, इनके जाने की आदत बन गयी है। इसलिए मैं तो अभी भी कहूंगा कि आप राईट जगह में पहुंच जाईये। यह बड़ी अच्छी होगी। क्योंकि आप जिन-जिन नेताओं के साथ में जाते हैं, वह आपके साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ऐसा काम मत करें। आप सही जगह में पहुंच जाईये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- एक शायरी है, कोई साथी अकेला है तो अकेला ही काफी है, यह हमारे लिए है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आप तहसीलों की हालत देख लीजिए। मैंने तो हमारे क्षेत्र का तहसील देखा है, सेमरसेत अभ्यारण्य क्षेत्र बोलते हैं। 51 गांव चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, आप रोज पेपर में पढ़ रहे हैं कि वहां शेर आते हैं। वहां के आदिवासी जब वहां की तहसील में पेशी के लिए जाते थे तो वह सातू बांध के जाते थे और रहना पड़ता था, उनका रात बित जाता था और आना मुश्किल हो जाता था। आपने वहां भी सरगुजा संभाग के दूरांचल क्षेत्र में कई तहसीलें खोलकर किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साहब, बिजली की बात कर लें, हम लोगों ने भी बिजली देखी है, यह मेरा दूसरा कार्यकाल है। जहां प्रमोद भैया बैठ रहे हैं, वही सीट मेरा था। मैं वहीं बैठता था। डॉ. साहब और चंद्राकर जी लगातर भाषण देते थे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बृहस्पत जी, इसीलिए आपकी ताकत मेरे में आ गयी है।

श्री बृहस्पत सिंह :- हां बहुत अच्छा। मैं आपको बता दूं कई ऐसे गांव थे, जहां अभी भी ढिबरी बरते थे, आप ढिबरी समझते हैं, मिट्टी का इतना बड़ा गोला होता है, जिसके अंदर बत्ती लगाते हैं, नीचे में मिट्टी तेल भरा होता है। ढिबरी और लालटेन से हमारे गांव जलते थे, उन गांवों में भी बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज देखने में लगता है। हम लोग शहरों में बिजली देखने जाते थे। आज हर एक गांव मोहल्ले में भी जंगल में बसा हो या पहाड़ में बसा हो, उन गरीबों को बिजली मिल रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विपक्ष के साथी बिजली के मामले में बहुत हल्ला करते हैं कि कोई छूट नहीं है। आप बिजली बिल को चेक करके देख लीजिए, उसी बिजली बिल में लिखा रहता है कि कितना बिजली बिल है और कितनी आपकी छूट की राशि है। उसमें इंगित है। आपके जैसे नहीं कि मुख्यमंत्री जी और मोदी जी की फोटो छापकर सिर्फ धोखा देने का काम करते थे। हमारी सरकार आने के बाद हम उस पर सीधा कितना बिजली बिल है और उसमें कितनी छूट दी है, वह भी उसमें उल्लेख है। साहब, आपके समय में बिजली बिल आता था तो गांव वालों को करेंट लग जाता था। हमारे समय में कम से कम बिजली बिल आने के बाद रात में रेस्ट करते हैं। बिजली बिल किसानों के लिए बड़ी विडंबना थी कि 3 एच.पी. 5 एच.पी. मोटर पंप का भी हम लोग छूट दे रहे हैं। अभी हमारे विपक्ष के मित्र कोयले की बात बड़ी लंबी चौड़ी सुना रहे थे। कोयला तो हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा है कि पूरे हिंदुस्तान की फैक्टरी को चलाने का काम हम करते हैं, कोयला हम देते हैं। आप देख लीजिए, जितनी मालगाड़ी कोयला भरकर हमारे छत्तीसगढ़ से जाती है, इसके बाजवूद भी केन्द्र की सरकार लगातार हमारे उपर थोपकर दबाव बना रही है और दूसरे देश से कोयला खरीदने को मजबूर कर रही है और महंगी दरों पर खरीदकर महंगी बिजली देने के लिए दवाब बना रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोग लगातार प्रभावित हो रहे हैं। उसमें भी छत्तीसगढ़ को विचार करना चाहिए और केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहिए कि इस तरह से थोपना बंद करें और छत्तीसगढ़ को महंगाई से झोकना बंद करें। सभापति महोदय, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा निवेदन करूंगा। आपका आदेश है तो कम ही बोल देता हूं। अपनी क्षेत्र की कुछ मांगे बता देता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में हम लोगों ने गांव-गांव में बिजली पहुंचा दिया लेकिन कई ऐसे बड़े गांव हैं, जहां बिजली बाकी रह गयी है। मैं बता देता हूं। यह हमारे रामचंद्र ब्लाक के त्रिशुली गांव हैं, जहां इनकी पार्टी के केन्द्रीय नेता रहते थे। वह सारे गांव अधूरे रह गये हैं। त्रिशुली में 6 पारा मोहल्ले में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पायी है। तालकेश्वरपुर में 4 मोहल्ला-पारा में बिजली नहीं पहुंच पाई है। मरमा के पास एक ढोढ़ी गांव है, जहां 200 घर की एक बस्ती है वहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। मरमा एक बहुत बड़ा गांव है जहां 4 मोहल्ले में बिजली नहीं पहुंच पाई है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बृहस्पत भैया, अभी-अभी आप ही बोले कि हर जगह बिजली पहुंच गई है और अब आप ही बिजली की मांग कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- शर्मा जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- सलवाही आदिवासियों का पारा है वहां 5 मोहल्लों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। वहां पर लोग अभी भी बड़े दु:खी हैं। रेवतीपुर गांव में 5 पारा-मोहल्ला में और कोड़ाखुपारा आदिवासी मोहल्ले में बिजली नहीं पहुंच पाई है। डुमरपान में 5 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। दोलंगी में 3 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। सनावल से आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उस गांव में भी 3-4 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। उसके बाजू में पचावल गांव है वहां भी अभी तक 4 मोहल्ले में बिजली नहीं पहुंच पाई है। भितयाही में 3 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। महावीरगंज बहुत बड़ा गांव है वहां आदिवासियों के 5 मोहल्ले में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। लुर्गी गांव में 4 पारा में बिजली नहीं पहुंच पाई है। निलकंठपुर में 3 मोहल्ले में बिजली नहीं पहुंच पाई है। बरवाही एक बहुत बड़ा गांव और पंचायत है वहां 4 पारा में, पंडो पारा सहित आदिवासियों के सारे मोहल्ले में बिजली नहीं पहुंच पाई है। बराहनगर एक बहुत बड़ा गांव है और पहाड़ों के बीच बसा हुआ है वहां पर में 4 मोहल्ले में पंडो और कोरकू और गोड़ समाज के लोग रहते हैं वहां भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। ढोढ़ी में 3-4 मोहल्ले में आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। धमनी जो कि हमारा पुराना तहसील हुआ करता था, उस गांव में भी 4 मोहल्ले में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। रामपुर में 2 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। नगरा में 4 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। धनपुरी में 2 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। तालकेश्वरपुर में 4 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। कमलपुर में 3 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। कंचननगर में 2 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। बुलगांव में 4 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। जामवंतपुर में 2 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। धरमी में 3 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। महाराजगंज में 5 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। भीतरसौनी में 2 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। मानिकपुर में 2 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। केरता में 1 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। सुर्रा में 2 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। करकेपा में 2 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। लिलौटी में 3 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। सरगढ़ी में 3 पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बृहस्पत जी, आप बोल रहे थे कि हर घर-घर में बिजली पहुंच गई है और आप खुद ही बता रहे हैं इतने जगहों में बिजली नहीं पहुंची है।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैंने हर घर में नहीं, हर गांव तक बिजली पहुंचने की बात कही। लेकिन जो आदिवासी बहुत पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, अंतिम छोर में पहाड़ व जंगलों में बसे हैं, उनके पारा-मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंच पाई है। कण्डा और पुटसू हमारे दो ऐसे गांव हैं जो कि चारो तरफ से पहाड़ के बीच में बसा हुआ है और वहां आये दिन भालू-चीता जैसे जानवर आते हैं और विडम्बना यह है कि ये दोनों गांव अभ्याण्य क्षेत्र में आते हैं। वहां तक बिजली लाइन को ले जाने नहीं दिया जाता है। सीतारामपुर तक बिजली पहुंच गई है लेकिन इन दोनों गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। वह बिल्कुल अंतिम छोर में बैठने वाले आदिवासी हैं। वहां कोरकू, पण्डो और, परिहा आदिवासी रहते हैं और वह बहुत गरीब हैं। मुख्यमंत्री जी भी उसके लिए घोषणा कर चुके हैं लेकिन अभी तक वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। इसलिए आप कृपा करके इन दोनों गांवों में भी बिजली की व्यवस्था जरूर करवा दीजिएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उन पारा-मोहल्ला में भी बिजली पहुंचाने का काम किया जाए और आप उनको भी लाभान्वित करने की कृपा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का विरोध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ऊर्जा, खनिज, जन संपर्क और विमानन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। ऊर्जा विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे प्रदेश का प्रत्येक परिवार प्रभावित होता है और खनिज ऐसा विभाग है जो प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। पहले मैं ऊर्जा विभाग की बात करूंगा। जब वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था तो हम विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। उस समय छत्तीसगढ़ में लगभग 1500 मेगावाट विद्युत की खपत थी और हमारा उत्पादन 1360 मेगावाट का था। माननीय जोगी जी ने छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल को अलग बनाकर एक मजबूत पहली की थी। जोगी जी और उनके बाद लगभग 15 साल तक डॉ. रमन सिंह जी की सरकार रही और 18 साल में विद्युत उत्पादन 1360 मेगावाट से बढ़कर 3424.7 मेगावाट हुई और विद्युत के मामले में छत्तीसगढ़ देश का पहला सरप्लस स्टेट बना ।

समय :
3:00 बजे

मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जब सरप्लस स्टेट बनने की घोषणा हुई तो छत्तीसगढ़ में विद्युत कटौती लगभग-लगभग समाप्त हो गई थी, पर आज क्या स्थिति है ? साढ़े 4 साल से माननीय भूपेश जी की सरकार है और ऊर्जा विभाग स्वयं भूपेश जी के पास है । हर राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है, विद्युत की खपत बढ़ रही है, पर छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां विद्युत उत्पादन में 446 मेगावाट की कमी हुई है । सरप्लस स्टेट के सामने यह स्थिति निर्मित हुई है कि अब हमें दूसरे प्रदेशों

से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है । अभी आपने जो प्रतिवेदन दिया है, उसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ में जो विद्युत उत्पादन है, वह 2978 मेगावाट का है और उसमें से 2840 मेगावाट थर्मल से है और 138 मेगावाट हाइड्रो से है । सभापति जी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन हंसदेव-बांगों में होता है । क्या हमारे प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन 12 महीना होता है ? हंसदेव से 120 मेगावाट, गंगरेल से 10 मेगावाट और सिकासेर से 7 मेगावाट उत्पादन होता है । हाईड्रो में विद्युत का सबसे सस्ता उत्पादन होता है, पर हमारे यहां 12 महीना इसका उत्पादन नहीं होता है । इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम विद्युत उत्पादन में पीछे हुए हैं । हमारा 446 मेगावाट उत्पादन कम हो गया और उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है ? उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि आज छत्तीसगढ़ में अघोषित विद्युत कटौती पूरे प्रदेश में चालू है। किसानों को जो अटल ज्योति का कनेक्शन दिया गया है, उसमें 5 घंटे की कटौती घोषित रूप से हो रही है, अघोषित तो दूर की बात है । ग्रामीण क्षेत्रों की यह स्थिति बन गई है कि एक बार बिजली बंद होती है तो 4 से 6 घंटे बंद रहती है और विशेषकर जब गांव के व्यक्ति को सबसे ज्यादा आवश्यकता शाम को साढ़े 6 से 9 बजे तक होती है तो ज्यादातर गांव में उस अवधि में विद्युत की कटौती रहती है।

माननीय सभापति जी, यह किसानों की सरकार है, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं । मुख्यमंत्री जी बड़ी-बड़ी घोषणा करते हैं । स्थायी पम्प कनेक्शन के 58 हजार आवेदन लंबित हैं, जिनकी स्थायी पम्प कनेक्शन की राशि पट चुकी है। वर्ष 2022-23 में इनका लक्ष्य 20550 पम्प कनेक्शन देने का था और स्वयं प्रतिवेदन में स्वीकार कर रहे हैं कि लक्ष्य के विरूद्ध हम 5724 किसानों को पम्प कनेक्शन दे पाए हैं । एक तो लक्ष्य कम रखा और जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के चौथाई लोगों को आप कनेक्शन दे पाये हैं । 25550 के लक्ष्य के अतिरिक्त लगभग 58000 पम्प कनेक्शन पेंडिंग हैं, जिसमें किसानों ने पैसा पटा दिया है । प्रदेश में ट्रांसफार्मर की स्थिति क्या है ? मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां कृषि आधारित उद्योग राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल सबसे ज्यादा मेरे क्षेत्र में लगे हैं । किसानों के 200 आवेदनों में से 100 से ज्यादा आवेदन पोहा मिल और दाल मिल वालों के लगे हुए हैं । मैंने स्वयं सी.ई. से, एम.डी. से बात की है तो 7 ट्रांसफार्मर गए हैं, जिनकी पोहा मिल, राईस मिल, दाल मिल लग गयी है । सबने फायनेंस करके मिल लगाया है। खाली ट्रांसफार्मर नहीं लग पाने के कारण 3 से 4 लाख रूपया महीना ब्याज भर रहे हैं। अब कृषि आधारित उद्योग में जब ट्रांसफार्मर देना होता है तो उद्योगपति ट्रांसफार्मर की पूरी कीमत जमा करता है। परन्तु आप समय पर ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहे हैं। मैंने फोन किया तो मुझे जवाब मिला कि 200 का ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। एक ही व्यक्ति को टेण्डर दिया गया है और वह व्यक्ति सप्लाई नहीं कर पा रहा है। उसका दुष्परिणाम कौन भोग रहा है ? ये दो सौ के ट्रांसफार्मर उद्योगपतियों के लिए है। परन्तु किसान को 100, 63 और 25 का ट्रांसफार्मर लगता है और 100,63, 25 के ट्रांसफार्मर भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लो वोल्टेज की

समस्या के चलते बार- बार ट्रांसफार्मर फेल हो रहे हैं और किसान की फसल सूख रही है। अधिकारों का केन्द्रीकरण हो रहा है। आजकल विकेन्द्रीकरण की बात चलती है परन्तु आपके सरकार के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कैसे हो रहा है ? पहले ट्रांसफार्मर का आर्गमेंन्टेशन होता था, केपेसिटी बढ़ाना होता था तो कार्यपालन यंत्री को अधिकार होता था कि वह कैपेसिटी बढ़ाने का निर्णय ले लें। कहीं अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना है तो कार्यपालन यंत्री को अधिकार रहता था कि अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्वीकृत कर दें। परन्तु आज कैपेसिटी बढ़ाना है, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना है तो वह एम.डी. तक फाइल आयेगी और जब तक उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक किसान की फसल सूख जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार कहा जाता है कि हमने 42 लाख लोगों का बिजली बिल आधा कर दिया। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब गांव में सभा लेते हो तो जरा खड़े होकर पूछा करो कि सबका बिजली आधा हुआ क्या ? हाथ उठाओ। कितने लोग हाथ उठायेंगे, आपको पता चल जायेगा। बिजली बिल आधा करने की बात करते हो और 4 साल में प्रति यूनिट दो बार दर बढ़ा चुके हो। आपने जितना छूट दिया उससे ज्यादा बिजली की दर बढ़ा दी है। पिछले 20 साल में छत्तीसगढ़ में विद्युत लाईन का विस्तार हुआ है, विद्युत की खपत बढ़ी है, वह लगभग ढाई गुना हो गई है। परन्तु आपके पास स्टाफ की क्या स्थिति है ? एक लाईनमेन के पास 15 से 20 गांव है। आप प्रतिवेदन में स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि 487 डाटा एन्ट्री आपरेटर और 3 हजार लाईन परिचारक के पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। अब जिस प्रदेश में 3 हजार लाईनमेन की कमी हो, उस प्रदेश में विद्युत व्यवस्था कैसी होगी, इसकी आप स्वयं कल्पना कर सकते हो।

माननीय सभापति महोदय जी, कोई घरेलू कनेक्शन वाला है, उसका बिजली बिल पटने में 4 दिन देरी हो गई तब आप सरचार्ज करते हो, कनेक्शन काट देते हो। परन्तु छत्तीसगढ़ में कितने उद्योगपतियों का बिल बाकी है ? यह बिल हजारो-लाखो रूपये में नहीं, करोड़ों में बाकी है। इनको क्यों छूट दी गई है ? क्यों इनसे वसूली नहीं हो रही है ? माननीय मुख्यमंत्री जी, जब जवाब देने आये तो इस बात का जवाब देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, क्रेडा की क्या स्थिति है ? पूरे प्रदेश में क्रेडा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। क्रेडा के माध्यम से जिन किसानों को पम्प कनेक्शन दिया गया है। यदि उसमें एक बार गड़बड़ी हो जाती है तो किसान दो महीने, तीन महीने, चार महीने तक चक्कर लगाते रहता है और किसान की फसल खत्म हो जाती है। कहीं कोई समय-सीमा का निर्धारण नहीं है कि हम कितने दिन में आपकी लाईन सुधारेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी है तो कितने दिन में ठीक करेंगे। आपके विभाग की लापरवाही का दुष्परिणाम किसान को भोगना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार एक विषय आता है अडाणी, अडाणी, अडाणी। महाराजा साहब बैठे हैं, अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं, आप ही जानो। एक बात का जवाब तो दे दो...।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जो आपसे रिश्ते हैं, वैसे ही हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तो आज तक देखा नहीं हूँ प्रभु । अडानी को केवल अखबारों में ही पढ़ा हूँ । हसदेव जंगल किसके लिये उजाड़ा जा रहा है, किसकी अनुमति से उजाड़ा जा रहा है, राजस्थान में तो आपकी पार्टी की सरकार है ? कोयला खनन का ठेका उसमें किसको दिया है, ठेका देने के पीछे भाव क्या है, अडानी के विज्ञापन क्यों लगते हैं, जरा बता दें । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- गौतम अडानी जी हा विश्व में 700 नंबर में 3 नंबर में कइसे आईस, अऊ पूरा भारत में कैसे नंबर म आईस तेला बता । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- तोला समझ नई आय, तैं बैठ । सभापति जी, अडानी से छत्तीसगढ़ में किसी के अंतरग रिश्ते हैं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से है ।

श्री सौरभ सिंह :- अडानी तोर डर मा छोड़ के भाग गे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, हमारे जनघोषणा पत्र के जननायक हमारे महाराजा साहब थे, मैं स्पष्ट सदन में बोल रहा हूँ । अमितेश जी सुन रहे हैं, नोट करते जाईये । माननीय सभापति जी, सामान्य प्रशासन विभाग भी है, जनघोषणा पत्र वर्ष 2018 में गंगा जल उठाकर शपथ लिये । सारे अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों को हम नियमित करेंगे । सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में आप स्वयं ने स्वीकार किया है कि 50,385 अनियमित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या है । 36,871 संविदा कर्मचारियों की संख्या है, दोनों मिलाकर 87,256 की संख्या बनती है । आपका नियमित करने का वादा था, आपने इसके लिये क्या किया ? पहले एक समिति बनाई अपर कलेक्टर की अध्य अध्यक्षता में और समिति बनाते ही अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी है उसको निरस्त कर दिया । प्रमुख सचिव वाणिज्य की अध्यक्षता में फिर दूसरी समिति बनाये हैं । इस समिति ने सवा चार साल में क्या किया, सिर्फ दो बैठकें की है ? एक बैठक को हुई है, दूसरी बैठक 16-8-2022 को हुई । पहली बैठक में सभी विभागों से जानकारी मांगी गई कि कहां-कहां कितने दैनिक वेतन भोगी, अनियमित और संविदा कर्मचारी हैं । दूसरी बैठक में, सभी विभागों से 5 बिन्दुओं की जानकारी मांगी गई । पहली बैठक में महाधिवक्ता का राय के लिये पत्र लिखा गया । महाधिवक्ता की राय सवा चार साल में प्राप्त नहीं कर पाये । ये सरकार काम कर रही है । आप क्या कर रहे हैं, महाधिवक्ता के ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, आपकी मिलीभगत है, आपको टालना है इस आधार पर राय भेजने की जरूरत ही नहीं है ? माननीय महाराजा साहब, आप जनघोषणा पत्र के जनक थे, इन 87 हजार लोगों का क्या होगा, क्या होगा गंगा जल की शपथ का, इनके भविष्य का क्या होगा, जरा आप बतायेंगे ? अनियमित कर्मचारियों को आपने धोखा दिया, आप 4 साल में कितनी भर्ती कर पाये हैं, 21 हजार से ज्यादा नियुक्तियां रूकी हुई है, बहाना क्या लेंगे कि आरक्षण का विषय क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हम नियुक्ति नहीं कर रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- यह 2003 के आपके घोषणा पत्र हे । छत्तीसगढ़ ला पानी में बोर देव । 15 साल में पानी में बोर देव तुमन ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसमें जो फैसला आया है, सितम्बर 2022 में आया है । सितम्बर 2022 को तो 6 महीने हुये हैं । इसके पहले आप भर्ती क्यों नहीं कर पाये । आरक्षण पर पूरे प्रदेश की जनता को धोखे में रखने का प्रयास हो रहा है । बार-बार यह कहते हैं कि राज्यपाल के यहां अटका है, राज्यपाल के यहां अटका है। आप हस्ताक्षर कराने क्यों नहीं जाते हैं ? आप चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं ? आपने रोकवा रखा है। मुख्यमंत्री जी, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के पीरेड में आरक्षण विधेयक आया था और पास हुआ था। लगभग 10 वर्ष तक लोगों को आरक्षण का, उस विधेयक का लाभ मिलता रहा। आज यदि छत्तीसगढ़ की जनता इस आरक्षण से वंचित हुई है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही से हुई है। मैं तो इसे लापरवाही नहीं कहता, मैं बोलता हूं कि आपके षडयंत्र से। यह षडयंत्र इसलिये है ..।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ये मन राज्यपाल ला गुमराह करथे। (व्यवधान) ला जगा दे। ये मन राज्यपाल ला गुमराह करथे। ओला पूरे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार ओला माफ नइ करै।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं षडयंत्र इसलिये बोल रहा हूं कि आपकी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हम पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। जो व्यक्ति, कुणाल शुक्ला कोर्ट में गया, आपने उसको सरकारी पद से नवाजा। आपने उसको कबीर शोध विद्यापीठ का अध्यक्ष बना दिया। आपकी सरकार के निर्णय के खिलाफ जो भी गया आपने उसको उपकृत किया। यह सिद्ध करता है कि आप षडयंत्रकारी है। अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन बना है ? उपाध्यक्ष कौन बना है ? जो आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गया, वह अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष। आप आरक्षण के मामले में षडयंत्र करते हो और दोषारोपण और किसी पर करते हो। इनका तो इतना षडयंत्र है कि आज उससे राजभवन भी अछूता नहीं रहा और सदन भी अछूता नहीं रहा।

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय सभापति महोदय, आप लोग 2011 में आरक्षण के संबंध में एक बैठक किये। आप उसके बाद आरक्षण के मामले में क्या कर रहे थे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ तब आप भी उपस्थित थे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, उन्होंने अपने 43 नंबर के बिंदु में जिस बात को कहा।

श्री राजमन वेंजाम :- अभी तो हम लोगों को केवल चार साल ही हुए हैं। इस 4 साल बाद हमारी सरकार ने आरक्षण के मुद्दे में क्वांटीफियेबल डाटा उपलब्ध कराने के लिये कोर्ट में आवेदन दिया।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय विधायक जी, आपको तो मौका मिला था यदि आप दे देते तो आज यह नौबत नहीं आती।

श्री राजमन वेंजाम :- आप लोगों ने कोर्ट में एक भी क्वांटीफियेबल डाटा पेश नहीं की है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उन्होंने खुद कहा राज्यपाल का जो अभिभाषण प्रकाशित किया गया, उसमें पूरी तरह से अंतर था। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, 15 साल में एक भी मण्डल 27 प्रतिशत आरक्षण काबर नहीं दिहा ? मण्डल कमीशन के आधार पर काबर नहीं दिहा ? 15 साल तक तुमन ला पिछड़ा वर्ग के ख्याल नहीं रिहीस। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- तुहर मन के (व्यवधान) ठीक नहीं रिहीस आरक्षण ला। (व्यवधान) एकर मंशा ठीक नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों ने उसे 9वीं अनुसूचि में क्यों शामिल नहीं किया ? प्रधानमंत्री मोदी थे और आपकी सरकार थी तो आपने उसे 9वीं अनुसूचि में शामिल क्यों नहीं किया ? शामिल किये रहते तो यह नौबत नहीं आती।

सभापति महोदय :- चलिये राजमन जी बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- (व्यवधान) 27 प्रतिशत आरक्षण ..। (व्यवधान)

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी देना चाहते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- राजमन जी बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, 14 कुर्सी में पिछड़ा वर्ग ला रोक के रखे हे। अउ ऐ मन अभी-भी रोक लगाथे।

सभापति महोदय :- चलिये, दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, बस 5 मिनट में समाप्त करूंगा। इनके षडयंत्र से तो राजभवन और यह सदन भी अछूता नहीं रहा। आज ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उमेश पटेल जी ने कहा कि हमने 33 हजार 333 लोगों को शासकीय स्तर पर समायोजित किया है, रोजगार दिया है। 5 लाख लोगों के लिये स्वरोजगार की व्यवस्था की है। 50 हजार लोगों को अशासकीय संस्था में रोजगार दिलाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ था कि हमने 2 लाख 40 हजार लोगों को शासकीय सेवा दी है। आप बोलेंगे तो मैं मुख्यमंत्री जी के भाषण की क्लिपिंग सदन के पटल पर रख दूंगा। रायपुर में बड़े-बड़े फ्लैक्स लगे थे कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आप जरा स्पष्ट कर दें कि 33 हजार 333 लोगों को कौन-कौन से विभाग में रोजगार दिया गया ? किन अशासकीय संस्थाओं में 50 हजार लोगों को रोजगार दिया गया ? इन्होंने कहां के 5 लाख लोगों को स्वरोजगार दिलाया ? जरा

यह स्पष्ट कर दें। यह सरकार तो इतनी संवेदनाहीन है कि छत्तीसगढ़ में लोग अनुकम्पा नियुक्ति के लिये भटक रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, यह पहली सरकार है जो 15 दिन में अनुकम्पा नियुक्ति ला कर के देथे।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, हमारी जो बहनें कोरोना में विधवा हुई। वें 150 दिन से धरना पर बैठी हैं।

श्री रामकुमार यादव :- हमारे भूपेश बघेल जी की पहली सरकार है जो 15 दिन में अनुकम्पा नियुक्ति दे रही है। दशकर्म नहीं हो पाथे (व्यवधान)। ओमन का बात करथे।(व्यवधान) ते हा जो रोक के रखे सब मन के नियुक्ति करथे। 15 दिन नहीं लागथे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपकी सरकार में तो चपरासी तक की भर्ती नहीं हुई है। जितने भी हायर एजुकेशन है वह सब मानसिक प्रताड़ना के शिकार हैं, आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप दोनों का नाम है, उस समय बोलिएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार की संवेदनहीनता है। माननीय बृहस्पत सिंह जी चले गये हैं वह सामान्य प्रशासन विभाग में बहुत जोरदार बोल रहे थे। शायद मुख्यमंत्री जी के अंडर में, सामान्य प्रशासन के अंडर में ही एस.पी. का ट्रांसफर, पोस्टिंग आती है। सत्ता पार्टी का विधायक अपने यहां के एस.पी. के ऊपर आरोप लगाता है कि एस.पी.दंगा करा रहा है। शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं एस.पी. अपने कार्यकत्ताओं के साथ धरना दे रहा है, चक्काजाम कर रहा है, यह सरकार क्या कर रही है ? अगर एस.पी. दंगाई हो तो अब तो वहां पदस्थ क्यों है ? उस एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? और अगर वहां के विधायक ने एस.पी. के खिलाफ असत्य आरोप लगाया है तो उस विधायक के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? यह अक्षम सरकार है। इस प्रदेश में कोई कुछ भी करते रहे, यह देखते रहेंगे।

माननीय सभापति जी, आपने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि ए.सी.बी. का चीफ महानिदेशक स्तर का अधिकारी होगा। ठीक है अभी ए.सी.बी. का चीफ महानिदेशक स्तर का अधिकारी बन गया, पर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें कि तीन सालों तक ए.सी.बी. का चीफ किस स्तर का अधिकारी था ? जब आप अपने प्रतिवेदन में लिख रहे हो कि ए.सी.बी. का चीफ महानिदेशक स्तर का अधिकारी रहेगा तो तीन साल तक उससे नीचे का अधिकारी जो आई.जी. रैंक का भी न हो, वह कैसे चीफ रहा ?

माननीय सभापति जी, खनिज विभाग में कोयले की बात तो बहुत हो गई। 1 साल में वर्ष 2022 में 2122 करोड़ रूपए डी.एम.एफ. फण्ड में आया है। अब तक डी.एम.एफ. में 11 हजार 86 करोड़ रूपए आ चुका है। अगर 1 साल में डी.एम.एफ. मद में 2122 करोड़ रूपए आ रहा है तो यह कोई छोटी रकम

नहीं है। प्रदेश की मूलभूत समस्याओं के निराकरण में यह राशि की बड़ी भागीदारी हो सकती है, पर डी.एम.एफ. मद की राशि का उपयोग क्या हो रहा है? सिर्फ खरीदी में उपयोग हो रहा है जिसमें 30 से 40 करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार हो। ट्रेनिंग जिसमें 60 से 70 प्रतिशत का भ्रष्टाचार हो। इस सदन में दसों बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है..।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अउ ट्रेनिंग में 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार होथे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन में 10 बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, पर इस डी.एम.एफ. मद का स्वार्थपूर्ण बंटवारा बंद होगा या नहीं होगा ? ट्रेनिंग, खरीदी और सप्लाई में रोक लगनी चाहिए। मैंने कल भी अपने भाषण में एक बात कही थी कि स्वामी आत्मानंद हमारे प्रदेश के गौरव है और उनके नाम पर जो स्कूल बन रहा है उसमें जो खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है...।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पूरा प्रदेश इससे अपने आप आहत हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जनसंपर्क विभाग है। जनसंपर्क विभाग की स्थिति क्या है ? विज्ञापन में 346.41 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं प्रिंट मीडिया को 100 करोड़ 41 लाख रूपये, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 136 करोड़, 26 लाख, राज्य के बाहर प्रिंट मीडिया को 64 करोड़, 18 लाख रूपये ..।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन के दिल्ली के सरकार के प्रधानमंत्री के कोई भी टी.वी. ला चाहू करव तो भगवान कस उही निलथे, मोदी जी हा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, राज्य के बाहर इलेक्टॉनिक मीडिया को 45 करोड़, 56 लाख रूपये । आज ही सदन में चर्चा हुई है कि एक ऐसी संस्था जिसको राज्य शासन ने मान्यता नहीं दी उसने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट प्रसारित की और सर्वे रिपोर्ट को कोड करते हुए, उसे 2 करोड़ रूपये का विज्ञापन दे दिया गया। केवल वह सर्वे क्या है ? पूरे देश में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम है जिस संस्था को मान्यता नहीं है उस संस्था की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आप उसे 2 करोड़ रूपये का विज्ञापन दे रहे हैं। चिटफण्ड कंपनी का 32 करोड़ रूपये वापस होता है उसके लिए विज्ञापन में कितना खर्च होता है ? गोधन न्याय योजना में 200 करोड़ रूपये का गोबर खरीदते हैं, उसके विज्ञापन में कितना खर्च होता है ? जो काम नहीं हुआ, ऐसा विज्ञापन करो, ऐसी छवि बनाओ कि लोगों को लगे कि सबसे ज्यादा काम करने वाली सरकार है। राज्य शासन ने चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, चाहे अभी हमारे नये जिले बने हैं, इनके जो सेट अप स्वीकृत हुए हैं, इस सेटअप के आधार पर वहां कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह प्रदेश प्रगति नहीं कर रहा है, हम

पीछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पूरे देश और दुनिया में बदनाम हो रहा है। इसलिए मैं इन अनुदान मागों का विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मागों पर इस पवित्र सदन में चर्चा की जा रही है। मैं बजट मांगों के पक्ष में अपनी बात को रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष में बहुत बडे-बड़े नेता हैं, काफी अनुभवी हैं और अनुभवी नेताओं से मैं यह अपेक्षा करता था कि ये सदन में कुछ ऐसी अच्छी बातें करेंगे जिससे सदन में सीखने को मिलेगा ।

सभापति महोदय :- पांडे जी, दो मिनट। अभी 16 सदस्यों की ओर से बोलना है। मैं माननीय सभी वक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि अपने भाषण में पूर्व के सदस्यों के द्वारा रखी गई बातों की पुनरावृत्ति न करें और 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, अगर हम अच्छे नेताओं को सुनते हैं, प्रदेश की जनता अच्छे नेताओं को सुनती है या सुनने जाती है तो इसलिए जाती है कि वह अच्छी बात करेंगे। वह अच्छी बातें बतायेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मैं सबसे पहले इस बात को कहूंगा कि इस प्रदेश को जिन हालातों से कांग्रेस की सरकार ने खड़ा किया, 2001 से कांग्रेस की सरकार ने इसको एक सही दिशा दी, इसके कारण आज यह प्रदेश यहां पहुंचा है और जो सरप्लस रेवेन्यू स्टेट कहलाने लगा है। माननीय सभापति महोदय, हम ऋण की बात करते हैं, बहुत सारी बातें ऋण में बोली जाती हैं, प्रदेश के प्रति व्यक्ति के ऊपर 25 हजार का ऋण चढ़ा दिया गया है, ऐसा हो गया है, पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपने ऐसा कर दिया। हम संवेदनशील सरकार चला रहे हैं, संवेदनशीलता से सरकार चला रहे हैं, ऋण तो लेंगे न। आपने 42 हजार करोड़ रुपये का ऋण चढ़ा दिया। आपने इतना ऋण क्यों चढ़ाया? अगर ऋण लेना गलत बात है, बुरी बात है तो आपने क्यों ऋण लिया था? आप इसको जस्टिफाई करिये। माननीय सभापति महोदय, वहां बैठना बहुत अच्छा लगता है, यहां बैठना अच्छा नहीं लगता है। जिनको वहां बैठने की आदत पड़ जाती है उनको यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए पूरे समय उत्तेजना होती रहती है। ऋण एक ऐसी चीज है, सब कोई जानते हैं कि ऋण क्या होता है। यदि मैं ऋण लूंगा तो मुझे चुकाना पड़ेगा। यह मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आप भी पढ़े-लिखे हैं। सब कोई पढ़े-लिखे हैं। सरकार पढ़ी-लिखी है, अधिकारी पढ़े-लिखे हैं, कर्मचारी पढ़े-लिखे हैं। सबको पता है कि ऋण लेते हैं तो चुकाना पड़ता है। आप हमारे ऋण की बात करते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण में बोल रहे कि प्रधानमंत्री जी ने देश के ऊपर ऋण कितना चढ़ा दिया है। चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। सबको पता है कि हम अपने जी.एस.डी.पी. का कितना प्रतिशत ऋण ले सकते हैं और उनको भी पता है कि अपने जी..डी.पी. का

कतिना प्रतिशत ऋण ले सकते हैं। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी.एस.डी.पी. का लगभग 16-17 प्रतिशत ही ऋण लिया है जो कि सीमा के अंतर्गत है। आपने कितना लिया है? केन्द्र सरकार ने कितना लिया है? केन्द्र सरकार ने उस ऋण को 45 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। आज इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्जा है? आपने इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख से ऊपर कर्जा चढ़ा दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि ऋण किस चीज के लिए लिया जा रहा है? आपने 15 साल किस चीज के लिए ऋण लिया और हमने 4 साल किस चीज के लिए ऋण लिया? आज प्रदेश का किसान जानता है, आज प्रदेश का मजदूर जानता है, आज प्रदेश का गरीब आदमी जानता है कि हमने ऋण किसलिए लिया और उस ऋण का हमने क्या किया? हम बोल सकते हैं। हम स्काई वॉक नहीं बना रहे हैं। हवा में स्काई वॉक। इसमें करोड़ों रूपये खर्च हो गया। 500 करोड़ रूपये बिलासपुर में खर्च हो गये। सीवरेज बर्बाद कर दिये गये। आपने अरपा भैंसाझार बनाया। उसको हम ठीक कर रहे हैं। बार-बार जांच बैठी हुई है। 1200 करोड़ रूपये की योजना थी। कुछ तो अच्छा काम करते। मैं मुख्यमंत्री जी को आभार भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने की प्रदेश की जनता के हितों में ऋण लिया, प्रदेश की प्रगति के लिए ऋण लिया और उनके लिए हुए निर्णयों के कारण ही आज हमारा प्रदेश, हमारी सरकार सरप्लस रेवेन्यु सरकार बनी है। दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब बिलासपुर में मेरे पास लोग आते हैं, सरकार का धन्यवाद देते हैं। 15 साल में आपने कितने लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दिया? आपने कितने लोगों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए नियमों का शिथिलीकरण किया? आप किसी के लिए संवेदनशील नहीं थे। किसान मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। 15,000 किसानों ने आत्महत्या की हैं। आप क्या कहते थे कि कोई शराब पीकर मर गये, कोई पत्नी से लड़कर मर गया। आपकी यही स्टेटमेन हुआ करते थे। आपके अंदर किसानों के लिए भी संवेदनशीलता नहीं थी। यह तो गजब की बात है कि आपने उस अधिकारी, कर्मचारी जो आपकी जिंदगी भर सेवा की, उस आदमी के परिवार के लिए भी नहीं सोचा कि इसके परिवार वाले को अनुकंपा नियुक्ति मिले, नियमों में शिथिलीकरण किया जाए। मैं चंद्राकर जी से बहुत अपेक्षा करता हूं। वह एकदम दबंग मिनिस्ट हैं। वह हम लोगों के रोल मॉडल हैं। लेकिन वह नहीं कर पाये। अपने कार्यकाल में थोड़ी-बहुत किये होंगे जो नियमपूर्वक होती होंगी।

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, 2023-24 के बजट में बोलो न।

श्री शैलेश पांडे :- उसी में तो आ रहा हूं।

सभापति महोदय :- विषय में आये।

श्री शैलेश पांडे :- सभापति महोदय जी, मैं विषय में ही हूं। यह जी.ए.डी. का ही विषय है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने वह काम किया जो प्रदेश के लोगों के लिए, सरकारी लोगों के लिए, हजारों परिवारों के लिए जरूरी था। यह संवेदनशील सरकार का दूसरा चेहरा है । मैं सिर्फ एक विभाग, शिक्षा विभाग का बताता हूं। हमने 2173 अनुकंपा नियुक्ति दी। माननीय मंत्री जी, मैं आपको

बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अब आप विषय वाली बात पर फिर टोकेंगे। मैं बोलना नहीं चाहता हूं। जब बजट आयेगा तब राजीव युवा मितान क्लब में बोलूंगा। मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा। आप विश्वास कीजिये, आपसे फालतू बहस नहीं करेंगे। आपको अच्छी बात बतायेंगे। आपको खुशी मिलेगी। इस सदन को खुशी मिलेगी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। उनका नाम था राजीव गांधी। जो डिजिटल क्रांति, कम्प्यूटर क्रांति के जनक थे। उन्होंने जो नींव डाली उसके बाद डॉ. मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने । आदरणीय चंद्राकर जी बहुत इंटेलीजेंट हैं इस बात को बहुत जल्दी केच कर लेंगे । मुझे याद है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्व मंत्री हुआ करते थे । मैं वर्ष 2001 से 2003 की बात बता रहा हूं तब प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे सोचा जाता था कि हम कैसे खसरा बी-वन नक्शा बांटेंगे, कैसे हम लोगों को सुविधा दे सकेंगे ? क्यों हमारे लोगों को तहसीलों के, एस.डी.एम. कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे ? इसके लिये हमने डाटा डिजिटलाईजेशन के बारे में सोचा । माननीय सभापति महोदय, मुझे याद है, मैं उस कार्यक्रम में साक्षी था जब माननीय मुख्यमंत्री अजीत जोगी हुआ करते थे और हमारे मुख्यमंत्री जी उस समय राजस्व मंत्री हुआ करते थे तब इस प्रदेश में पहली बार खसरा बी-वन नक्शा किसानों को ऑनलाईन दिया गया था और वह पाटन विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, एक स्कूल में हुआ था । मुझे वह क्षण याद है, 20 वर्षों से ऊपर बात हो चुकी होगी । मैं उस स्कूल में गया था, यह कांग्रेस की सोच थी । यह हमारी सरकार की सोच है । आपने उस विषय को आगे बढ़ाया, आपने और अच्छी नीति लायी, आपने और अच्छा काम किया, आपने और अच्छी पॉलिसी बनायी लेकिन कैसे बनायी ? मैं आपको बताता हूं क्योंकि जब आपने सरकार चलायी तब उस समय देश में प्रधानमंत्री कौन था ? डॉ. मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने क्या किया, चूंकि वे वर्ष 2004 से 2014 तक थे । उन्होंने नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान लाया और नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत 3 घटक बनाये गये । पहला घटक था उसका कॉमन सर्विस सेंटर बनाना, दूसरा घटक था स्वान परियोजना और तीसरा घटक था डाटा सेंटर को बनाना ।

माननीय सभापति महोदय, इन 3 घटकों ने पूरे देश में नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान उसके बाद आपने आई.टी. पॉलिसी बनायी, उसके बाद आपने किया जब केंद्र सरकार हमारे मनमोहन सिंह जी की थी तब उन्होंने पैसा दिया और तब उन्होंने योजनाएं बनायीं । किसलिये योजना बनायी कि देश के लोगों को, देश की जनता को, गरीबों को, किसानों को बाहर न आना पड़े । उनको वहीं पर खसरा बी-वन नक्शा और जो सरकारी योजनाएं होती हैं जिन्हें हम जी-टू सी कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन और बी-टू सी बिजनेस टू सिटीजन । वहां पर जी-टू सी और बी-टू सी योजनाओं को बनाया गया । आपने क्या किया ? बांधी जी, आपने 11 हजार आई.टी. सेंटर बनाये। आप उस समय मंत्री थे । उस समय छत्तीसगढ़ में 11 हजार से ऊपर कॉमन सर्विस सेंटर बनाये गये । आज एक भी कॉमन सर्विस सेंटर जिंदा नहीं है । क्यों ?

आपने उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की ? जब वह अपनी पूंजी लगाकर बनाने गया था, जब वह तैयार हुआ कि मैं प्रदेश की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाये । आप केवल कलेक्टर द्वारा दिया हुआ चिप्स का च्वाईस सेंटर बोलते हैं न उसको, ग्रामीण च्वाईस सेंटर खोले गये थे । कॉमन सर्विस सेंटर का नाम ग्रामीण च्वाईस सेंटर रखा गया । आपने उस योजना पर ध्यान नहीं दिया । आप अपनी पीठ थपथपाते रहे । आप बड़ी-बड़ी मैगजीन में बड़ी-बड़ी फोटो छपवाते रहे, आप बड़े-बड़े अखबारों में अपनी वाहवाही लूटते रहे लेकिन वास्तव में, धरातल में यदि देखें तो धरातल में बिल्कुल शून्य था ।

माननीय सभापति महोदय, आज इतने सालों बाद और आपने जो काम किया। स्टेट डेटा सेंटर बनाया, आपने स्वान परियोजना लागू की, वह कहां से चालू हुई ? आप बोलते क्यों नहीं हैं ? आपको तो मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए लेकिन क्या आपने कभी धन्यवाद दिया ? नहीं दिया । आज हमारे प्रदेश में लोग खुश हैं । आज हमारे प्रदेश में इतनी जो तरक्की हुई है, यह तरक्की अगर हम आज डिजिटल स्टेज में आगे हैं, अगर हम डेटा डिजिटलाईजेशन में आगे हैं, आज हम आई.टी. के सेक्टर में आगे हैं । आज लोगों को ऑनलाईन सुविधा मिल रही है । आज अगर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और सरकार में उसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह डॉ. मनमोहन सिंह जी थे और इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए । मैंने यह नहीं कहा कि आपने खराब काम किया । आपने जो खराब काम किया, मैंने केवल उसके बारे में बोला है ।

सभापति महोदय :- चलिये, आप एक मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति जी, अभी तो एक ही विभाग हुआ है ।

सभापति महोदय :- आपने 5 मिनट कहा था और 15 मिनट हो गए हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- 10 मिनट, 10 मिनट । सभापति महोदय, आपका आरक्षण, संरक्षण सब चाहिए । सभापति महोदय, हम बिजली बिल हाफ की बात करते हैं । हम बिजली सरप्लस स्टेट थे, हमने इस बात को मान लिया लेकिन आपने इसका लाभ किसको दिया ? अगर हम सरप्लस थे तो उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए था, गरीब लोगों को मिलना चाहिए, बी.पी.एल. परिवारों को मिलना चाहिए था। अगर मुख्यमंत्री जी ने, अगर हमारी सरकार ने उस बात को नीचे पहुंचाया और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया, इसमें डाटा है, यह गलत नहीं है । शिकायतें होंगी, नीचे स्तर पर समस्याएं होंगी, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा नेटवर्क है । 2019-20 में 977 करोड़ रूपए, 2020-21 में 850, 2021-22 में 900 करोड़ और 2022-23 में 1000 करोड़ से ऊपर । यानी लगभग 42 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिला । लोगों को बताया गया कि अगर हर महीने बिजली बिल जमा करते रहोगे तो बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा । जो नहीं करते हैं, उनको नहीं मिलता है । बाद में बोलते रहते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ । लेकिन सरकार की योजना सही है । सभापति महोदय,

आज हम मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना की बात करते हैं । मैं पहले एक बात और बताता हूं कि आज हमारे लिए और हमारे राज्य के लिए खुशी की बात है कि जिस राज्य में 2019 तक बिजली कनेक्शन के 47 लाख उपभोक्ता थे वह आज चार साल बाद बढ़कर 60 लाख हो चुके हैं । इन चार वर्षों में लगभग 13 लाख लोगों ने बिजली का कनेक्शन लिया है और सरकार ने दिया है । यह बिजली कहां से आ रही है और आप कह रहे हैं कि उत्पादन कम हो रहा है । 4 साल में 13 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन दिया गया है 47 लाख से बढ़ाकर 60 लाख पहुंचा दिया गया है । कहां से कम उत्पादन कम हो जाएगा ? सभापति जी, बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे अधिकारी जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं हमारे बिलासपुर जिले में लगभग 1 लाख 30 हजार उपभोक्ता हैं और शहर के आसपास लगभग 5 विद्युत के सब-स्टेशन हैं । वहां का हर सब-स्टेशन बरसों से 15 से 20 और 20 से 25 प्रतिशत ओवर लोडेड है । बिजली ब्रेक डाउन होती है । अरे सरप्लस बिजली स्टेट था तो बिजली ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए । क्यों हो रही थी, क्योंकि आप नीचे भार क्षमता नहीं बढ़ा रहे थे । आप सब-स्टेशन नहीं बढ़ा रहे थे । आपको 33 के.व्ही.ए. के, 132 के.व्ही.ए. के सब-स्टेशन बनाने थे, जो कि क्षमता को बढ़ाते जिससे की लोगों को उसका लाभ मिलता । ओवर लोडिंग की समस्या कम होती । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं उन्होंने बिलासपुर में 22 करोड़ रूपए का 132 के.व्ही.ए. का विद्युत सब-स्टेशन दिया। मैं मांग करूंगा कि जल्दी से उसके लिए जमीन ढूंढी जाए ताकि उसका लाभ जनता को दिया जा सके ।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना, मजरा टोला की बात करता हूं । यह एक ऐसी योजना है जिसका लाभ मिलता है । अभी माननीय शिवरतन शर्मा जी बोल रहे थे कि हमने इतने ट्रान्सफार्मर राईस मिलों के लिए दिये, मैं जानता हूं आज मांग है, आज छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है । अगर अकेले शिवरतन शर्मा जी 70 ट्रांसफार्मर चाहिए तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है । राईस मिलें क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों हमारे लोग उद्योग में आना चाहते हैं । क्योंकि यहां का किसान आगे बढ़ रहा है और यह राज्य समृद्ध हो रहा है । इसलिए इनको 70 जगहों पर ट्रांसफार्मर चाहिए, मिला नहीं यह अलग बात है, कितने मिले यह अलग बात है । यह दिया जाता है ।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त कीजिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- पांच मिनट । माननीय शिवरतन जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपके बारे में बोल रहा हूं और ज़ोर से बोल रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान् जी मैंने आपके भाषण के कुछ अंश सुने हैं । लोग 6-6 लाख रूपया ब्याज दे रहे हैं जबकि पूरा ट्रान्सफार्मर का पेमेंट कर चुके हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति जी, मुझे पाचं मिनट और दीजिए मैं जल्दी से समाप्त करता हूं । वितरण कंपनी की बात करते हैं । सारा विद्युत मंडल अच्छा काम करता है लेकिन सबसे ज्यादा कहीं का अधिकारी परेशान होता है तो वह है वितरण कंपनी का । एक ही कंपनी है जो सीधे सीधे जनता से जुड़ती है, एक ही कंपनी है जो सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों से जुड़ती है । वितरण कंपनी के लोग लगातार काम करते हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वितरण कंपनी के अधिकारियों को पुरस्कार दिया करें क्योंकि वे बहुत सिरदर्द झेलते हैं । लोगों की शिकायतें सुनते हैं, बहुत काम करते हैं । सभापति महोदय, अधिकतम् मांग 4160 मेगावाट से बढ़कर 5433 मेगावाट हो गई है । यह उपलब्धि है हमारी विद्युत कंपनी की । यानी कि मांग बढ़ रही है, लगातार मांग बढ़ रही है । यह कितनी बड़ी बात है कि 1300 मेगावाट मांग चार साल में बढ़ गयी है। 3311 के.व्ही.ए. और केन्द्रों की संख्या 1213 से बढ़कर 1342 हो गयी है। 33 के.व्ही.ए.. के लिए 21 हजार से 24 हजार हो गए हैं। 11 हजार के.व्ही.ए. के लिए 1 लाख 7 हजार से 1 लाख 27 हजार हो गए हैं। यह कितनी बड़ी बात है। यह बढ़ोत्तरी हो रही है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान जी, सुनिए ना, मैंने जो रिकार्ड प्रस्तुत किया है, वह प्रतिवेदन के आधार पर किया है। उत्पादन कितना कम हुआ है।

श्री शैलेश पाण्डे :- यह वही रिकार्ड है जो आपकी 15 साल सेवा किए हैं, उन्होंने ही भेजा है। मैं वही बता रहा हूं। वे या तो आपके समय असत्य बोलते थे या हमारे समय असत्य बोलते थे।

श्री उमेश पटेल :- शिवरतन जी, आज बता दीजिए, कितना असत्य बोलते थे।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति जी, यह शर्मा जी है ना, आप इनको बैठाईए। उसमें कुछ मैग्नेट लगाईए, कुछ गोंद लगाईए।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रतिवेदन का है। मैं पेज क्रमांक बता देता हूं।

सभापति महोदय :- चलिए बैठिए।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति जी, शिवरतन जी को असत्य बोलने में महारथ हासिल है। 10 हजार की भीड़ को लाखों में बताते हैं। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, मैं इस सदन के लिए बहुत खुशी की बात बताना चाहता हूं। आदरणीय अजय चंद्राकर जी के लिए, उनके क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। हमारी ट्रांसमिशन कंपनी ने 400 के.व्ही.ए. का एक नया उपकेंद्र उर्जीकृत किया है और धमतरी कुरूद क्षेत्र में किया है। आपको बधाई हो।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आपके लिए है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप देखिए, इतना बड़ा सेटअप कुरूद में गया है और यहां हम पर नाराज होते रहते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वित्त मंत्री को बधाई देना चाहिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, 220 के.व्ही.ए. के तीन उप केन्द्र जगदलपुर, नारायणपुर, बिलासपुर में उर्जीकृत किए गए। धरदेही में 132 के.व्ही.ए. के बीजापुर, उदयपुर, खैरागढ़, खड़मोरा, इंदामारा, मालखरोरा, सिलतरा उर्जीकृत किए गए। बिलासपुर भी हो जाता लेकिन जमीन नहीं ढूंढ पाए।

सभापति महोदय, अब बड़ा काम आता है जिसको जनरेशन कंपनी बोलते हैं। जनरेशन कंपनी वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के अंतर्गत स्थापित ताप एवं जल विद्युत संयंत्र में कुल 17945 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया। यह हमारी क्षमता है। हमको दो-दो पुरस्कार मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने हमको पुरस्कार दिया। हमको दो पुरस्कार दिए कि हमने सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किया है। सर्वाधिक बिजली का उत्पादन करने के लिए हमारे बिजली विभाग के अधिकारियों को बधाई हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में बिजली विभाग काम कर रहा है। उनको बधाई देना चाहता हूं कि दो-दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- शैलेश जी, क्या है, आप जितना भी बोलिए, जितना भी तारीफ करो लेकिन आपका कोई काम नहीं आएगा। सही बात है उसी को रखिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप तो तारीफ कर रहे हो ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- शैलेश जी, आप जिस ढंग से बोल रहे हो ना, ना घर के रहोगे ना घाट के। वहां तारीफ कर रहे हो, वह तो विश्वास करेंगे नहीं और यहां जिनका छप्पा लगा हुआ है वह भी सोचेंगे कि उधर चला गया ।

श्री उमेश पटेल :- शिवरतन जी, आप चिंता मत करिए। यह पूरा 71 एक हैं। आप इसका टेंशन मत लीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- यह पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप मेरे बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाईए। आखिरी दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी This is a big achievement to our government. (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय सभापति महोदय, आखिरी दो मिनट में आपका संरक्षण चाहता हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण काम है, यह प्रदेश की जनता को जो बिजली विभाग के द्वारा राहत दी गयी है। हम क्या-क्या काम आनलाईन कर रहे हैं। नये विद्युत कनेक्शन, पुराने विद्युत कनेक्शन परिवर्तन के लिए आज आनलाईन कर सकते हैं। नये विद्युत कनेक्शन के लिए 8 पेपरों में सिर्फ दो पेपर जमा करने पड़ते हैं। यह सुविधा है। नये विद्युत कनेक्शन नगर निगम अनापत्ति प्रमाण पत्र में छूट दी गयी है।

जनता को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दे दी गयी है कि आज जनता को डायरेक्ट नहीं आना पड़ेगा। आखिरी एक मिनट और बोलूंगा, उसके बाद बैठ जाऊंगा। माननीय सभापति महोदय, विमानन की बात करते हैं। मैं सच कहता हूं कि आपने 15 साल तक पूरे प्रदेश की जनता को इतना मुगेलीलाल का सपना दिखाया। हमारे बिलासपुर के बाबा यहां बैठे हुए हैं, यह वहां स्वयं परेशान हो गये थे। इतनी बड़ी-बड़ी बातें, हवाई चप्पल पहनकर हवाई सेवा करेंगे । ये लोग 15 साल में बिलासपुर से एक चिरईयां नहीं उड़ा पाए। टू सी, टू सी, लेकर बैठे हुए थे, टू सी में कहां चढ़कर जाओगे, कौन आएगा, कौन जाएगा ? बिलासपुर में एस.ई.सी.एल. है, एन.टी.पी.सी. है, एस.ई.सी.आर. है और बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीजें हैं। आपको बिलासपुर को आगे बढ़ाना था। आप बिलासपुर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। आपने बिलासपुर को खोदापुर बना दिया था। आपने ऐसा ही सब कुछ किया। आपका उद्देश्य केवल रायपुर, रायपुर, रायपुर था। रायपुर में अमिताभ बच्चन जैसे मंत्री हैं।

श्री उमेश पटेल :- पाण्डे जी, यह सुनने में आया था कि यह बिलासपुर धान बोने लग गये थे।

श्री शैलेश पाण्डे :- हां, धान बोने लग गये थे।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी।

श्री अमरजीत भगत :- देखिये, अमिताभ बच्चन जी सो रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी तो गहरी नींद में है। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, केवल एक मिनट। आज सरकार की इच्छा है और सरकार इच्छाधारी है। सरकार काम कर रही है। (हंसी)

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, आप बैठिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय, आप इच्छाधारी का मतलब बता दीजिए कि वह क्या है?

श्री शैलेश पाण्डे :- इच्छा को धारण करने वाली, इच्छाधारी। (हंसी)

श्री धरम लाल कौशिक :- बिलासपुर में इच्छाधारी नागिन है और इनको...। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यह इच्छाधारी क्या होता है ?

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, आज हमारी इच्छा शक्ति है जिसके कारण एयरपोर्ट बने हैं। माननीय धर्मजीत भैया, आप यह बताइये कि यदि आज बिलासपुर में 3-सी का एयरपोर्ट है तो वह किसकी इच्छा के कारण हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उसको आपने थोड़ी न खोला है।

श्री शैलेश पाण्डे :- उसको आपने नहीं खोला है, हमने खोला है। आप चवन्नी नहीं ला पाते थे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह दिल्ली से, केन्द्र से खुलता है।

श्री शैलेश पाण्डे :- बबा, आप चुप बैठिये। माननीय सभापति महोदय, आज बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में हम 3-सी स्टेज में आ गये हैं इसके लिए मैं इस पूरे प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को बहुत-बहुत आभार व्यवक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) हम एयरपोर्ट को बेच नहीं रहे हैं हम देश की संपत्ति को बना रहे हैं और हम छत्तीसगढ़ को विकास के पंखों में उड़ा रहे हैं। इसके प्रमाण हमारे बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर के हवाईअड्डे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बैकुंठपुर और कोरबा को नया हवाई पट्टी मिल गया है।

सभापति महोदय :- धरमलाल कौशिक जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप उनके हक का क्यों बोल रहे हैं और उनका हक क्यों मार रहे हैं ?

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, मैंने उनके हक का कभी कुछ नहीं लिया और आगे भी नहीं लूंगा। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- धरम भैया, देख ले, कुछु लोचा नहीं हो जाही।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- क्या है कि मुझे बोलते नहीं बन रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनके विभागों से संबंधित जो अनुदान मांगें प्रस्तुत की गई हैं, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे मित्र बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। कहां जब छत्तीसगढ़ विकास के दृष्टिकोण से 5 राज्यों में आता था और आज इन्होंने इसकी हालत यह बना दी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के आई.ए.एस. अधिकारी (कलेक्टर) जैसे को फरार होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के राज में छत्तीसगढ़ की यह स्थिति हो गई है। हम लोग तो आरोप लगाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो स्थिति बनी हुई है तो मुख्यमंत्री जी इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ को कहां से कहां ले गये। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको मालूम होगा और आपने भी इंडिया टूडे का सर्वे पढ़ा होगा। उस सर्वे में छत्तीसगढ़ की देश में क्या स्थिति है तो जब हम पूरे देश में इसकी तुलना करते हैं तो वर्ष 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति पूरे देश में पांचवे नंबर पर थी और वर्ष 2018 के बाद में वर्ष 2022 में देखते हैं तो वर्ष 2022 में यह फिसल कर पंद्रहवें नंबर पर आ गया है और पिछले साल यह ग्यारहवें नंबर पर था। मैं आपको बता रहा हूं।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय सभापति महोदय, 2003 से लेकर 2018 तक पूरे भारत में 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में थी, यह भी बता दीजिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- इंडिया टूडे का सर्वे आया। आपको आगे बढ़ना चाहिए तो आप पीछे छलांग लगा रहे हो ।

संसदीय सचिव (स्कूल शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध) (श्री द्वारिकाधीश यादव):- सभापति महोदय, धान खरीदी में भी बताईए कि देश में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है?

श्री धरम लाल कौशिक :- सारे मामलों में, कृषि में आपकी यही स्थिति है, शिक्षा में आप पूरे भारत में 31वें नम्बर पर हैं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अगर हम लोग नक्सली घटना में पीछे गए तो अच्छी बात है, अगर हम लोग क्राईम में पीछे गए तो अच्छी बात है।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपको विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए तो आप पीछे जा रहे हैं। यह सरकार किसानों की बात करती है । छत्तीसगढ़ 11वें 2021 में नम्बर पर था और 2022 में 19वें नम्बर पर आ गया । यह छत्तीसगढ़ में स्थिति है, आपकी प्रगति की दिशा है ।

सभापति महोदय, पर्यटन, कृषि अधोसंरचना और कानून में हम सब लोग देख रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है । अब तो हमारे पक्ष के साथी भी उसकी पुष्टि करने लगे हैं, जो बात हम बोल रहे थे । बाकी की बात तो छोड़ दीजिए, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी जिस बात को हम करते हैं, अब वे उस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि उनको सद्बुद्धि आ रही है कि वे इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिए हैं ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धरम भैया, आपसे निवेदन है । आप छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन को कम आंककर बता रहे हैं, उसमें आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2022-23 में जो अखिल भारतीय वृद्धि दर की तुलना में हमारे कृषि क्षेत्र में 5.93 का है, जबकि केन्द्र का 3.45 है तो हम सभी सेक्टरों में अच्छे हैं। उद्योग क्षेत्र में हमारा 7.83 है, जबकि केन्द्र का रेश्यों 4.11 है । इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में 9.21 है, जबकि केन्द्र का 9.14 है । आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन है।

श्री उमेश पटेल :- वे कहना चाहते हैं कि हम लोग क्राईम में पीछे आये हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति जी, जो जन घोषणा-पत्र जारी किया गया और जन घोषणा-पत्र जारी करने वाले हमारे सामने में बैठे हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जन घोषणा-पत्र की क्रियान्वयन समिति में आज वे नहीं हैं । मुख्यमंत्री जी को आज भी यह नहीं मालूम कि हमने जन घोषणा-पत्र में क्या जारी किया है ? इसलिए इन 4 सालों में उन्होंने अपना जन घोषणा-पत्र भूला दिया है । जो वायदे किए गए, मैं तो कहूंगा-असत्य वायदे । असत्य वायदे किए गए, जो 36 वायदे की बात करते हैं, इस मंत्रिमण्डल के बैठे हुए एक भी सदस्य नहीं बता सकते कि कितने वायदे पूरे किए हैं ? राजा साहब को पूछिए, वे आपके सामने में हैं । वे ईमानदारी से बताएंगे कि कितने वायदे पूरे हुए हैं । आखिर इस प्रदेश को क्या हो गया, यह सरकार किस दिशा में इस प्रदेश को लेकर जा रही है ।

सभापति महोदय, इन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद हम बिजली बिल माफी करेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- धरम भैया, आप बोल रहे हैं कि वादे पूरे नहीं हुए । आप ही बता दीजिए कि कितने वादे पूरे किए, कितने वादे पूरे नहीं हुए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आधी-अधूरा 14 वादा ।

श्री उमेश पटेल :- हमने 14 वायदे पूरे किये न ?

श्री धरम लाल कौशिक :- आधी अधूरी । जैसे आपने कर्ज को माफ करने की बात की थी, लेकिन आपने कर्ज माफ नहीं किया । कुछ बैंक का कर्ज माफ किया, कुछ बैंकों का कर्ज माफ नहीं किया । मुझे तो मौखिक याद है, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुझसे गिनवा लो । मैं ऊंगली में गिन रहा था । 12 में नहीं पहुंचे हो, आप 24 वायदे पूरे होने की बात करते हैं । मैं 14 वायदा बोल रहा हूं, वह भी आधे-अधूरे।

श्री उमेश पटेल :- धरम भैया, आप भी अच्छे से जानते हैं जिस स्तर पर कर्ज माफी हुआ, इसके पहले किसी सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया । आज तक की किसी सरकार ने कभी इस तरह का कर्ज माफ नहीं किया ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं आपको बता देता हूं, बैठ जाईए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कौशिक जी, तै अइसन भाषण देवथस कि अजय चन्द्राकर ह सोवथे, वह निद्रा में लीन हो गे हे । अतेक नीरस भाषण मत दे, अईसे कहात हवं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- उन्हें सोने दीजिए, आप चिन्ता मत करो । अभी वे जाग जाएंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है । (हंसी)

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बैठिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- लेकिन अतेक कम्भकरणी नींद में सोना उचित बात हे का ।

श्री अमरजीत भगत :- जैसे ही आपके भाषण शुरू होईस हे, नेता प्रतिपक्ष गोल हो गे हे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, जब से कौशिक जी भाषण शुरू किये हैं, तब से अजय चन्द्राकर जी सो गए हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- वे ध्यान में हैं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों की पूरी सहानुभूति धरम भैया के साथ है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे भाषण पर हमारे सत्तापक्ष के मंत्री लोग जागृत हैं। वे जाग गए हैं और मैं यही चाहता हूं कि वे नींद से जागे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बोलते हैं तो आपत्ति, चुप रहते हैं तो आपत्ति।

श्री उमेश पटेल :- का हे ओखर पहली तै सुतत रहे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर पेट बाढ़त काबर हे, तेला बता।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बिजली बिल आधा करेंगे की बात की। इन्होंने सरकार में आने के बाद क्या किया ? 400 यूनिट तक आधा बिल लेंगे कहा। 400 यूनिट में क्या किया ? पहले साल कुल 800 करोड़ रूपया सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को दिया गया और

उपभोक्ताओं से रेट बढ़ाकर एक हजार करोड़ रूपया वसूला गया। आपने केवल उपभोक्ताओं का 800 रूपया माफ किया और आपने बदले में उन लोगों से एक हजार करोड़ रूपया लिया। दो सौ करोड़ ज्यादा ले लिया, वह आपके जवाब में है। मैं जो बात करता हूं, आप लोग उसको मान लो, नहीं तो मैं आपको दूसरे दिन लाकर दे दूंगा।

श्री उमेश पटेल :- गला का हो गय हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- गला बैठ गया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमन आपके स्वास्थ्य के ख्याल रखना चाहत हन।

श्री उमेश पटेल :- धरम भईया, कल कुछु लगे तो नहीं रहिस हे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कल धुआं-वुआं थोड़ मिले रहिस हे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मोर गला मा थोड़े लगही। हाथ-पैर मा लगही।

श्री उमेश पटेल :- कोनो ऐती-वोती थोड़े लगे रहिस हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, ओ धुआं थोड़ा पीया गय रहिस हे।

श्री उमेश पटेल :- आंखी अउ गला ला थोड़े परेशान करिस ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मोला बोले तो दे। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने समाज से वादा किया और वादा करने के बाद इनके द्वारा छलने का काम किया गया है। हमारी सरकार ने 2018 तक 15 साल में जो विकास किया था, हम लोगों ने 2018 तक जो विकास किया, उसको पीछे ढकेलने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं, जिन योजनाओं को इस सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया या उन योजनाओं को ठप्प करने का प्रयास किया गया। ठप्प करने के प्रयास के कारण वह योजना बद से बदतर स्थिति में है। आप एक तरफ वित्त विभाग के द्वारा आकड़ा प्रस्तुत करते हैं और यह कहा जाता है कि सरप्लस राजस्व है। सरप्लस राजस्व की बात आती है। मैंने उस दिन बजट के सामान्य चर्चा में अपनी बातें रखीं थीं कि आपका बजट कितने का है और जब लेखा प्रस्तुत होगा तो वह कितने तक आयेगा। उसका कारण यही है कि ये जो भी आकड़ा बोलते रहे, आकड़े का मायाजाल बताते रहे। मैंने हैसियत की बात बोला था। इस सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि केन्द्र सरकार के द्वारा जो राशि दी जा रही है, उसकी मेचिंग ग्रांट की राशि दे सके। आप प्रधानमंत्री आवास योजना को देख लीजिये। उसके बाद अमृत जल मिशन को देखिये, यह अमृत जल मिशन का काम 2023 में समाप्त होना चाहिए था। लेकिन उसका 50 प्रतिशत नहीं, आपकी सरकार के द्वारा एक चौथाई काम भी नहीं किया गया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भईया, मध्यप्रदेश में कई जगह चालू नहीं होय हे। हमर इहां छत्तीसगढ़ मा सब जगह चालू हो गय हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने कहा न कि झूठे आकड़ें प्रस्तुत करो। आप उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भईया, मैं एक लाईन बोल रहा हूं। जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में केन्दांश क्यों घटा दिया गया है ? जितनी भी योजनाएं संचालित है, सभी योजनाओं में केन्द्रांश मिलता है, वह घटा दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, एक छोटी सी कहानी है। जो जरासंध थे, उसके हंस और डिम्भक दो सेनापति थे। मैदान में डिम्भक मर गया, कहकर अफवाह उड़ा दिया गया तो हंस ने आत्महत्या कर ली। दोनों में इतना प्रेम था। तो जरासंध जी महाराज उधर गये हैं, हंस और डिम्भक यहां हैं। समझ रहे हैं न ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये अभी नींद से जगे हैं। सपना देख रहे थे क्या ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इसीलिए बोल रहा था कि मत जगाओ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो बोला कि सोने दो, मत जगाओ।

श्री सौरभ सिंह :- अभी मेडीटेशन किए हैं, ध्यान लगाये हैं, फिर ज्ञान की बात बताये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, ये सर्वे की बात बोल रहे हैं कि हम सर्वे करायेंगे। कल मुख्यमंत्री जी और रविन्द्र चौबे जी साथ में खड़े थे। उन्होंने कहा कि कहां से 16 लाख आवास आ गया। जब चौबे जी का विषय आयेगा तो उनको बताऊंगा और मुख्यमंत्री जी को बोलूंगा कि आप चौबे जी के ऊपर और उनके अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करें, यदि हमने 16 लाख का दावा किया है, यदि वह निकल रहा है तो उनके ऊपर दावा करें और नहीं तो उनके खिलाफ में कार्यवाही करें । मैं मुख्यमंत्री जी को बोलने वाला हूँ । सरकार के तरफ से जवाब प्रस्तुत हुआ, जवाब आपने खुद प्रस्तुत किया और नकारने का काम आपके द्वारा किया जाता है । यह सरकार की नीति है । सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके द्वारा क्वांटिफायबल डाटा आयोग बनाया गया, इसके बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया, प्रस्तुत होने के बाद आज वह कहां पर है, क्वांटिफायबल डाटा आखिर इनके द्वारा प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के जनता की जानकारी में क्यों नहीं लाया जा रहा है ?

श्री अमरजीत भगत :- धरम भईया, यह बताईये कि आपकी ही सरकार ने जो सर्वे पेश किया है, मकानविहीन लोगों की सूची जो बताया था, वह 18 लाख बताया था । उसमें से 11 लाख मकान को स्वीकृत कर दिये हैं, 7 लाख ही तो बचा है । आप कहां से 16 बताते हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- देखिये, आप मंत्री जी के खिलाफ बहुत अन्याय कर चुके हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अमरजीत भगत जी जो हैं, वह हंस है । डहरिया जी जो हैं डिम्भक हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके सरकार के कारण में और कथनी तथा करनी के कारण में पंचायत मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा । यह शर्म की बात है । आपके मंत्री जी को त्यागपत्र देना पड़ा । इतना असत्य सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- कोई त्यागपत्र नहीं दिया है । हमारे मंत्री जी हमारे पास बैठे हैं और आप इस तरह की बात करते हो ?

श्री सौरभ सिंह :- पूरा त्यागपत्र दे देतिस राजा साहब हा । अमरजीत जी जानथ रहिसे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अजय जी ने बात कही है कि अमरजीत जी हंस हैं और आप डिम्भक हैं, हंस और डिम्भक का संबंध क्या होता है, यह आप बता दो ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- उही ला पूछ ना । वो ज्यादा अच्छा जानही । वोखर से ज्यादा ज्ञान छत्तीसगढ़ में काखरो जगह नहीं है । पूरा प्रदेश के सबसे बड़े ज्ञानी हावय ।

श्री अमरजीत भगत :- I hope you are brilliant person and Your everything is well. 18 लाख मकानविहीन थे । आपने उसमें 11 लाख स्वीकृत कर दिये । 7 ही बचा ना । आप कहां से 16 बोल रहे हो । वही तो बोल रहा हूँ ।

श्री उमेश पटेल :- अमरजीत भाई, आप टोका-टाकी मत करिये । हमारी पूरी सहानुभूति धरम भईया के साथ है । आप आराम से बोलिये ।

श्री अमरजीत भगत :- चाहे धरम भईया हो, चाहे धर्मजीत सिंह जी हो, आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सम्मान है । बोलिये, भईया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- We are friend.

श्री अमरजीत भगत :- I also your friend.(हंसी) आज मैं सबेरे से बहुत चिंतित हूँ अमरजीत जी ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- I also your dear friend.

श्री धर्मजीत सिंह :- My dear brother. आज सबेरे-सबेरे अमरजीत जी का एक बयान बढ़ा । मैं बोला इसको क्या हो गया भई । नंदकुमार साय जी बोले, जब तक कांग्रेस की सरकार नही जायेगी, मैं बाल बढ़ाऊंगा । चाहे वह बाल यहां रहे या कट जाये, तू मूछ क्यों कटा दिया भाई । एक तो नत्थूलाल जी जैसी मूंछे हैं आपकी, उसको भी कटवाने में दांव में लगाये हैं और बीजेपी वाले क्लीन शेव फोटो लगाके उसमें कैप्शन लिखे हैं, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो ।

श्री अमरजीत भगत :- देखिये, धरम भईया क्या है, नंदकुमार साय जी बहुत सीधे-सादे आदमी हैं । जब भी फंसने वाली बात होती है, उसको आगे कर देते हैं। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो जोगी जी के साथ उसको लड़ा दिये । जब लाठी डंडा चल रहा था तो उनको आगे कर दिये और हाथ पैर

तोड़वा दिये । अभी भी वही स्थिति हो रहा है । उनसे बाल नहीं कटवाऊंगा, बेचारे को फंसाने का काम करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, वो हंस और डिम्भक जो थे ना, वह गे थे । (हंसी)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- यहां कोई नई हे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मेरे तरफ भी इशारा किया था, मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- ये दोनो है, एक और दो ।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, आपको अगर टेस्ट करना है तो कर सकते हो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने इस साल बाजार से कोई ऋण नहीं लिया है। जब आप इस बात को खुद बोल रहे हैं तो आप इस साल के बजट डॉक्यूमेंट को देखेंगे, उसमें बाजार ऋण मूल्य का पुनरीक्षित अनुमान 99 सौ करोड़ रूपये लिखा हुआ है। आपको उसको हटा देना चाहिए। यदि आपने बाजार से ऋण नहीं लिया है तो आपने इसको यहां से क्यों नहीं हटाया? मुख्यमंत्री जी ने उस दिन सदन में कहा कि 2003 तक राज्य पर 4 हजार करोड़ का ऋण था और दिसंबर 2015 में बढ़कर 51 हजार करोड़ हो गया। मुझे आंकड़ा मालूम है, वह कम है लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी के अनुसार से चले तो हमारी 15 साल की सरकार ने 47 हजार करोड़ का ऋण लिया। हमने जो भी कर्जा लिया तो उससे आज पूरे प्रदेश की जो सड़कें बनी है, जो स्कूल बने हैं, लगभग वनवासी क्षेत्र के कॉलेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी काम हुए हैं, हमने कर्जा भी लिया, धान भी खरीदा, बोनस भी दिया और हमने विकास भी किया। लेकिन इस सरकार ने 4 साल में प्रदेश के ऊपर कुल 1 लाख 3 हजार करोड़ रूपये का कर्जा लाद दिया। सरकार ने 4 साल में कुल 52 हजार करोड़ रूपये का कर्जा लिया है। मतलब 13 हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष। यदि आप देखेंगे तो उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो गया। हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। वे सड़कों का, पुल पुलियों का विवरण, वर्ष 2020 से प्रिंट करा रहे हैं और वही 2020-21, 2021-22 में, 2022-23 और वही 2023-24 में भी प्रिंट करा रहे हैं। जब आप बनाने की स्थिति में नहीं हो तो आप बजट में रखते क्यों है ? उसको केवल बजट में डाल-डालकर बढ़ाने का काम कर रहे हैं यदि वास्तविक में इनकी यह स्थिति होती तो प्रशासकीय स्वीकृति मिलती, उसके बाद सड़कों और पुलियों का निर्माण होता। लेकिन मैं तो यही जानना चाह रहा हूं कि यदि आपने 13 हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष कर्जा लिया। आखिर वह पैसा कहां है, वह कहां गया ? मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आपने बाजार ऋण नहीं लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में कुल ऋण, जो उनके हिसाब से मिला, हमारे बाजार ऋण का हिस्सा 25 हजार करोड़ रूपये था, हमको जो टोटल लोन था, उसका 50 प्रतिशत मान लो। उसके बाद अभी 1 लाख करोड़ में 62 हजार करोड़ रूपये बाजार ऋण है, मतलब 60 प्रतिशत से अधिक आपका बाजार ऋण हो गया है। आप किस बात की शाबाशी ले रहे हैं कि हमने बाजार ऋण नहीं लिया। आपने

पहले ही इतना ऋण ले लिया है कि आप उस पैसे को चुकाने की स्थिति में नहीं है। आपने तीन सालों में इतना बाजार ऋण लिया है कि अब आप उसको भी चुकाने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने प्रदेश का पूरा भट्ठा बैठा दिया है।

समय :

4.13 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और यह स्थिति बनने के कारण पूरे प्रदेश का विकास कार्य ठप्प हुआ। यदि वास्तविक में वित्तीय अनुशासन की बात करें और जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में जो विकास का क्रम चल रहा था, आज एक सेक्टर में नहीं आप सभी सेक्टर में देखेंगे तो आपके सामने इसका परिणाम दिखाई दे रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग के बारे में बताना चाहूंगा। एक समय था जब मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद हम सब लोगों को पम्प कनेक्शन के लिये वेटिंग में ही रहना पड़ता था। वह जारी होता था कि इस साल इतना पम्प कनेक्शन दिया जायेगा, बिजली की कटौती होती थी। उसके बाद 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने उस स्थिति में लाकर खड़ा की कि छत्तीसगढ़ स्टेट, जीरो कट पॉवर, सरप्लस स्टेट पॉवर, छत्तीसगढ़। इस चार में कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने फिर कबाड़ा करने का काम किया है। आज हम देख रहे हैं कि 2018 में जो विद्युत की उत्पादन क्षमता 3424 मेगावॉट और जो घटकर आज 2984 मेगावॉट हो गयी । जब हमारे शैलेश पाण्डे जी मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा गुणगान कर रहे थे कि हम बिजली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यह कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने बिजली में काम किया , आप उसको मैनटेन भी नहीं कर पाये। हम सरप्लस स्टेट थे। जीरो पॉवर स्टेट थे और इनके द्वारा प्रदेश में बिजली के मामले में भट्ठा बैठाने का काम किया गया। आप उसको मेनटेन भी नहीं कर पाये। इनकी सरकार के कार्याकल में पुन: कटौती प्रारंभ हो गई है। 5 बजे से लेकर 11.00 बजे रात तक कटौती होती है। किसान परेशान है पता नहीं, यह लोग ट्रांसफार्मर कहां से खरीद कर ला रहे हैं। यह लोग जो ट्रांसफार्मर खरीद कर ला रहे हैं किसान को लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जो ट्रांसफार्मर खरीद कर ला रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार का मामला है। उसकी क्वालिटी नहीं है। नहीं तो नया ट्रांसफार्मर लगाने के बाद, पम्प चलना चाहिए। हमारे पास किसानों का फोन आता है भईया, हमने ट्रांसफार्मर लगाया है, हमारा पम्प नहीं चल रहा है तो उसमें भी भ्रष्टाचार का मामला है। आपका कहीं पर लाईन विस्तार नहीं हो पा रहा है और आज हमारे साथियों ने किसान की चर्चा की कि एक लाख 32 हजार अस्थाई कनेक्शन है जिसको हम रेग्युलर कर सकते हैं। हमारे 56 हजार कनेक्शन जो स्थायी हैं, जिसकी

प्रक्रिया पूरी हो गई है हम उस स्थिति में नहीं है कि उनको हम दे सकें। क्योंकि यह सरकार एक लाख रूपये देने की स्थिति में नहीं है। मैं इसका एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहां पर जो टेण्डरों में गड़बड़ी हो रही है। बाकी विभागों टेण्डरों में गड़बड़ी चल रही है और वही बिजली, ऊर्जा विभाग में भी जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊर्जा विभाग कंपनी द्वारा कोल ट्रांसपोर्टेशन का टेण्डर किया गया। रायगढ़ के किसी को यह टेण्डर मिलने वाला था, लेकिन उसी समय ई.डी. का जो मामला हुआ वह रायगढ़ की उस कंपनी को टेण्डर नहीं दिया और उसके बाद में उसे दूसरे को दिया गया। उसमें कोल कंपनी का रेट लगभग 643 रूपये प्रति टन के हिसाब से जो दिया गया, ए.सी.सी.एल. का जो ट्रांसपोटेशन का रेट है स्टैण्डर्ड रेट के हिसाब से 60 किलोमीटर मतलब दारेपलमा से मड़वा तक के लिए 400 रूपये प्रति टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह ए.सी.सी.एल. का है। 25.07.2022 को ए.सी.सी.एल.के जारी सरफेस ट्रांसपोटेशन चार्जेस 20 किलोमीटर के लिए 116 रूपये प्रति टन का है और यह जो ऊर्जा विभाग के द्वारा दिया गया है उसमें दिया गया है कि 643 रूपये में जो किया गया है वह लगभग 400 रूपये का होना चाहिए, जिसको 643 में दिया गया। उसके पीछे भी कारण है आखिर, वह अधिकारी क्या करे? इनकी वसूली से अधिकारी परेशान हो गए है। चाहे वह किसी विभाग का अधिकारी हो, चाहे बिजली विभाग का अधिकारी हो...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय धरम भईया, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। आप डेटा सहित जानकारी बता रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 साल में छत्तीसगढ़ के किसी भी आदमी को काम नहीं मिला। राज्य से बाहर के लोग आकर काम करते थे। अगर रायगढ़ के किसी आदमी को काम मिल रहा है तो आपको छत्तीसगढ़ के आदमी से क्या तकलीफ है?

श्री धरमलाल कौशिक :- भाई, आप ही लोग तो ट्रासंपोर्टिंग का काम कर रहे थे। आप मुझसे क्यों बोलवाना चाहते हो?

श्री अमरजीत भगत :- उस समय छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग आ कर काम कर रहे थे । जब से हमारी सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ के लोकल लोग काम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- हम बता रहे हैं आप चिंता मत करिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जय अम्बे, जो कोयले की ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, उसके खिलाफ ई.डब्ल्यू.ए. में शिकायत है आपकी जानकारी के लिए वह आदमी दुर्ग, भिलाई का रहने वाला है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप थोड़ा जांच करवा लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि वह जांच करवा लेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय धरम भईया, मुझे सही में आपकी तबीयत की चिंता हो रही है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुनकुरी में स्कूटी में ट्रांसपोर्ट किए थे।

श्री सौरभ सिंह :- आप दारू का बता दीजिए कि कौन ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 तक हमारी सरकार थी। उस समय जो विद्युत की खपत 20 हजार मिलियन यूनिट था..।

श्री उमेश पटेल :- कुनकुरी में कहां, किससे ट्रांसपोर्ट किए थे, आप यह भूल गए ? कुनकुरी में स्कूटी में ट्रांसपोर्टिंग कर दिया था।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय हमने उत्पादन 21 हजार 84 मिलियन यूनिट किया और इस प्रकार से जो मांग है उसका उत्पादन है उस रेश्यो को हम लोगों ने बनाकर रखा और इन 15 सालों में एक दिन की भी कटौती नहीं होने दी। हम लोगों ने उसको मेनटेन करके रखा।

श्री उमेश पटेल :- क्या है, सौरभ जी, आप उस समय हाथी छाप में थे। तो इसलिए आपको पता नहीं होगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- स्कूटी मे ढोए तो कम लागत में ढोए। इनको धन्यवाद् देना चाहिए और लागत कम आया। उसमें एवरेज 70 किलोमीटर रहता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे 04 साल में ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, एक भी ऐसा काम नहीं हुआ कि इनको शाबासी दे सकें।

श्री उमेश पटेल :- वह खरसिया के निवासी, खरसिया के बड़े मंत्री के भाई।

श्री सौरभ सिंह :- उमेश भैया, यह भी खरसिया और रायगढ़ में ही रहा है जो जैस का गारेपलमा हो रहा है। आपके पास भी ट्रांसपोर्टर लोग पहुंचे थे कि वह 200 रुपये जो रहा है, उसमें 10, 20 रुपये हमारा भी बढ़वा दो।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उमेश भाई, स्कूटर वाला किस्सा नही सुने क्या ?

श्री उमेश पटेल :- सुनो तो, मंत्री जी के भाई स्कूटी में ट्रांसपोर्ट कर देत रहिस।

श्री सौरभ सिंह :- अभी 200 रुपये जा रहा है, धरम भैया जो 670 रुपये बोल रहे हैं, 670 रुपये मिल रहा है, वह ट्रांसपोर्टर लोग आपके पास भी गये थे कि उमेश भैया इसमें से 10, 20 रुपये हमको दिला दो, सिर्फ जैस वाले को 200 रुपये मत लेने दो।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपकी ताकत नहीं थी कि दिला सको।

श्री रामकुमार यादव :- जे काम ला बडे-बड़े ट्रक नई कर सकत हे, तुंहर जमाने में स्कूल से करके बताये रहव।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली घोटाला के संबंध में कहना चाहता हूं। यह जो बिजली घोटाले की बात है। बिजली वितरण कंपनी में पिछले दिनों बिजली बिल की संग्रहण

राशि में गड़बड़ियां उजागर हुई है। अंबिकापुर, मस्तुरी, शिवरीनारायण में बिजली कंपनी को 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की क्षति पहुंचाई जा चुकी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आदरणीय धरम भैया, बिजली ला कैसन छू सबके, बिजली ला छूबे तो करंट लगही।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हम बिजली विभाग में देख रहे हैं, आज आप गावों में देखेंगे जो वर्षों से पुरानी लाईन है, वह लाईन गिर रही है। लेकिन आज भी लोगों की जो मांग है उसके अनुसार से यह सरकार काम नहीं कर पा रही है। दूसरी बात मजरा-टोला की है, मैंने बजट में देखा कि फील्ड में कहीं भी मजरा-टोला की उपस्थिति नहीं है कि मजरा-टोला के नाम से वहां पर लाईन का विस्तार किया जा सके। बिजली, ऊर्जा के मामले में छत्तीसगढ़ की मजबूत स्थिति थी, उसका भट्ठा बैठाने का काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, अगर आप जो बात बोल रहे हैं ननकीराम जी अगर सही बोल दें तो मैं मान जाऊंगा। आप उनकी तरफ देख लीजिए। अगर वह सही बोल दें तो मैं उनकी बात मान जाऊंगा।

श्री रामकुमार यादव :- वह लबारी के मारे सुतत हवै।

श्री सौरभ सिंह :- बबा ला, झन छेड़ा तुमन।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनिज के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि खनिज के मामले में छत्तीसगढ की चर्चा छत्तीसगढ़ तक नहीं है, अब ये पूरे हिन्दुस्तान में जन चर्चा होने लगी है। खनिज के मामले में हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है और उस मामले में अधिकारियों की क्या स्थिति है। अधिकारी जेल में बंद है, उसको जमानत नहीं मिली है। आई.ए.एस. अधिकारियों की ये स्थिति हुई है। तो क्या छत्तीसगढ़ को उससे पूरे हिन्दुस्तान में बड़प्पन बढ़ रहा है ? इन 04 सालों में उसकी छवि बनाने का या बिगाड़ने का काम किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, आपको आधे घंटे से ज्यादा हो गये हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं रखूंगा, मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, बिल्कुल।

श्री धरमलाल कौशिक :- भूपेश बघेल जी जिस बात को बोलते हैं, कोयला के क्षेत्र में अपने लोगों को किस प्रकार से उन्होंने दिया है, आरीडोंगरी आयरन ओर और माईन्स अपने चहेतों को आवंटित किया गया है। उनके लीज की स्वीकृति नहीं हुई और खुदाई शुरू हो गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- आरीडोंगरी वाले आदमी, वह अमरजीत भगत जी के सबसे खास आदमी हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- और अभी भी छुपा करके बालोद के गांव में रखे हुए हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या राज्य सरकार किसी को लीज आवंटित करती है ?

श्री सौरभ सिंह :- अमरजीत जी, आप जान रहे हैं कि राज्य सरकार आवंटित नहीं करती, राज्य सरकार तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को दी है। जिनका नाम ले रहे हैं, उसको भी आपने ही दिया है। आप ही वह रेवडी को उसके बाद बांट रहे हो न।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके कोरबा, जांजगीर, सक्ती, दुर्ग से लेकर डी.एम.एफ. राशि की बहुत चर्चा हुई है। अभी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने सीधा-सीधा आरोप लगाया जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा जो जिले में बैठे हुए हैं, डी.एम.एफ. की राशि जारी की जाती है और वसूली के लिए तुरंत उनका फोन आ जाता है कि ये इसका इतना कमीशन हुआ, ये पैसा कहां है, पहुंचा क्यों नही है। यह जो बंदरबाट चल रहा है। रेत की खदान के बारे में तो हम सब लोगों को मालूम है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में किसके सरंक्षण में रेत माफिया पनप रहे हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की सरंक्षण में रेत माफियाओं का छत्तीसगढ़ में कब्जा हो गया है। रामकुमार यादव जी बड़ी-बड़ी बात बोलते हैं। कल मुख्यमंत्री जी से मांग रहे थे कि गांव के साहब ओला कम पैसा मा देवा देते हें, ओकर बाद भी मुख्यमंत्री तोर बात ल नइ सुनीस रामकुमार। तोरे गांव के रेत घाट हावय, तेमा तोला गांव वाल के रेती के अधा पैसा मिल जाय। इसके लिए भी तैयार नहीं है। जो illegal माइनिंग हो रहा है। अधिकारियों की स्थिति नहीं है कि उनको जाकर खदान में रोक सके। जब वहां पर अधिकारी जाते हैं तो मार खाकर आ रहे हैं। गाड़ी से कुचल रहे हैं। आखिर किसका संरक्षण है? यह कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में आज पूरे छत्तीसगढ़ को माफियाराज बना दिया है और माइनिंग में जिस प्रकार से माफियाओं का बोलबाला है, जो छत्तीसगढ़ के खनिज के पैसा जो यहां लोगों के विकास के लिए जाना चाहिए, उसको कुछ चंद लोगों के जेब में यह पैसा कैद हो रही है। यह गंभीर मामला है। मैं जनसंपर्क में बात करूं तो वास्तविक में वह जनसंपर्क के अधिकारी नहीं है, वह कांग्रेस के कार्यकर्ता के बतौर काम करना शुरू कर दिये हैं। आजकल जनसंपर्क अधिकारियों का एक ही काम हो गया है कि भाजपा के नेताओं का पेपर में फोटो मत छपे, उनको कैसे रोका जा सकें, उसके लिए संपादक को धमकी देना, पत्रकारों को धमकी देना और यहां से लेकर सुकमा तक, सरगुजा तक यही स्थिति बन चुकी है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, दिल्ली में क्या हो रहा है? मीडिया को खरीदकर रखा है, उसको कौन बोलेंगे। उधर बोलने कोई मतलब नहीं है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- टी.व्ही. में दिन भर कौन आता है?

श्री धरमलाल कौशिक :- यह जनसंपर्क अधकारियों का दुरूपयोग हो रहा है। आज जनसंपर्क के अधिकारियों का एक ही काम हो गया है कि जो सरकार के खिलाफ में या मुख्यमंत्री के खिलाफ में जो कारगुजारिया हैं और फ्रंट पेज में आनी चाहिए, उसको फ्रंट पेज से कैसे रोका जा सकें, आज इसी काम में

लगे हुए हैं। जो रावाभाट भूमिका है, वह जनसंपर्क अधिकारियों की भूमिका हो गई है। दबाना, उनको झूठे केस में फंसाना, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना। जो 4 लाख 65 हजार का प्रश्न था, वह मेरा ही प्रश्न था। 4 लाख 65 हजार में मुख्यमंत्री जी ने कितना दिया था, उसका जवाब दिया कि मैंने 18 हजार लोगों को नौकरी दिया और 18 हजार में मैंने कहा कि 2018 को निकाल दो तो आपने केवल 16 हजार लोगों को नौकरी दिया। यह जनसंपर्क विभाग का काम हो गया है कि आंकड़ों के खेल में मुख्यमंत्री की वाहवाही कैसे हो सके। बाद में होल्डिंग उतारना पड़े। यह कारगुजारियां तो कम से कम न करें। यह कारगुजारियां करने से मुख्यमंत्री जी का सम्मान बढ़ेगा नहीं, बल्कि सम्मान को अधिकारियों के द्वारा घटा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इतना व्यस्त रहते हैं कि वह देख नहीं पायेंगे कि कौन सा चीज जारी करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से यहां के अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। मैं इसमें अनेक उदाहरण बता सकता हूं। चाहे एम.ओ.यू. के मामल में हो, जो बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़ा दिया जाता है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। यहां पर जो इतने पूंजी निवेश हुए, लेकिन जब जवाब में आता है तो आप देखेंगे कि एम.ओ.यू. के मात्र 19 लोगों का जहां पर 1 लाख से ऊपर पूंजी निवेश होनी चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय जी, आपको मालूम होगा कि जब माननीय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो यहां पर उन्होंने यहां पर ग्लोबल मीट कराया था और ग्लोबल मीट में पूरे वर्ल्ड के लोगों को बुलाया था और कितने लोगों के साथ एम.ओ.यू. हुआ था? आज तो हम कहने की स्थिति में है। हमारे कई प्लांट चालू हो गये हैं, लेकिन उस समय तो केवल कागजों में था, आंकड़ों में था और यदि हम पिछले बात को भुल जाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। आपके संज्ञान में रहना चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आंकड़े बढ़ाये जाने से कुछ नहीं होना है। वास्तविक में जनता को लाभ कैसे मिले, हितग्राहियों को कैसे लाभ मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेंदूपत्ता के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। वर्ष 2017 और कांग्रेस के कार्यकाल का 2021। वर्ष 2017 में मानक बोरा संग्रहण 17 लाख 20 हजार और इनके कार्यकाल में 9 लाख 13 हजार हुआ। मंत्री जी, 2017 और 2021 का मिलान कर लेना। हम लोग 2500 रूपये प्रति मानक बोरा दे रहे थे। यह 4000 रूपये दे रहे हैं। इन्होंने पारिश्रमिक भुगतान दिया। हमने 749 करोड रूपये दिया और कांगेस ने 110 करोड़ रूपये दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको प्रोत्साहन राशि 749 करोड़ रूपये मिली और कांग्रेस की सरकार में 110 करोड़ रूपये मिला और हम लोगों ने 2017 में जो कुल भुगतान किया, वह 11 करोड़ 76 हजार रूपये और 4000 बढ़ाने के बाद में 2021 में इन्होंने 6 हजार 30 करोड़ रूपये किया है। तो यह झूठी वाहवाही लेकर या झूठी आंकड़ों से लेकर आप खेल खेलना चाह रहे हैं, यह खेल बहुत दिन तक नहीं चलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बिलासपुर में एयरपोर्ट है ।

बिलासपुर एयरपोर्ट के बारे में अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने बात की कि हमने यह काम किया, वह काम किया ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- वह तो बन गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी बना नहीं है । वह तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का बना हुआ है । आपने उसका कुछ नहीं किया है । धर्मजीत जी बैठे हुए हैं, आपने देखा नहीं है । आपको जानकारी नहीं है । आपका बनाया हुआ नहीं है और हमारा बनाया हुआ नहीं है ।

श्री कवासी लखमा :- हमारे जगदलपुर में डॉ. रमन सिंह जी चला रहे थे लेकिन वह चला ही नहीं । अभी हम लोग चला रहे हैं तो लगातार चल रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चकरभाठा बिलासाबाई केंवटीन एयरपोर्ट । यदि प्लेन लेट हो जाये तो नाईट लेंडिंग की सुविधा नहीं है तो प्लेन को कैंसिल कर देते हैं । यह जो प्लेन चलाने की बात कर रहे हैं न । आज वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, न तो उसमें आप कोई विमान उतार सकते, न जमीन का अधिग्रहण करना चाहते हैं और इनके प्रतिवेदन में है । हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि या तो आप उस जमीन का अधिग्रहण स्वयं करिये और अधिग्रहण करके आप एयरपोर्ट की लंबाई को बढ़ायें जिससे डॉयरेक्ट दिल्ली का हो, कलकत्ता का हो, मुंबई का हो, चेन्नई का हो आप प्लेन चला सकें क्योंकि बिलासपुर में हमारा जो भी प्लेन है तो मैं यह कह सकता हूं कि आज के समय में 45 परसेंट हमारे वहां के जो यात्री हैं वे बिलासपुर संभाग के हैं, बिलासपुर रीजन के हैं, उसमें हम सरगुजा को भी जोड़ लें तो बिलासपुर रीजन की है लेकिन उस एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिये इनके पास कोई काम नहीं है । वहां पर न तो नाईट लेंडिण्ग की व्यवस्था है और न ही वहां पर बिल्डिंग बना पा रहे हैं, वहां पर न तो यात्रियों के लिये बैठने की सुविधा है । केंद्र सरकार बोल रही है कि हमको दे दो, हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तय कर लेंगे, बना लेंगे। न तो ये देने के लिये तैयार है और एक प्रकार से इनके द्वारा केवल धोखा देने का काम किया गया है । जो प्लेन चलाया जा रहा है वह भी अभी बंद हो गया है । इंदौर-बिलासपुर प्लेन बंद कर दिये और बंद करने का कारण है कि ये यहां पर सुविधा नहीं दे पा रहे हैं । भोपाल जो प्लेन चल रहा था वह बंद हो गया, इंदौर वाला बंद कर दिये । इसी तरह रहेगा तो आगे उस एयरपोर्ट का कोई भविष्य नहीं है इसीलिये या तो आपमें ताकत है । आपमें ताकत है तो आप उसको चलवायें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें । डॉ. लक्ष्मी ध्रुव ।

श्री कवासी लखमा :- आप 15 सालों में तो कुछ नहीं कर पाये । हम कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उस एयरपोर्ट की लंबाई को बढ़वायें और ताकत नहीं है तो आप भारतीय विमानन को सौंप दें । केंद्र सरकार यह काम कर लेगी ।

श्री कवासी लखमा :- कितना रेल्वे बंद हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं । आज वहां पर धरने में लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं । धरना-प्रदर्शन में लोग बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने के बाद यदि उनकी मांग पूरी न हो । यात्री सुविधायें यदि बंद हो जायें, प्लेन बंद हो जाये, यात्री सुविधायें बढ़ा न पायें तो इस सरकार को उस एयरपोर्ट को चलाने की आवश्यकता ही नहीं है । इसे केंद्र सरकार को सौंप देना चाहिए । भारतीय विमानपत्तन को सौंप देना चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने के लिये बहुत सारे विषय हैं । मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज की अनुदान मांगों पर जो चर्चा हुई और उसको देखने के बाद में जो बड़े-बड़े दावे किये गये और जो बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं वह सब खोखली साबित हुई हैं इसलिये इनकी जो जनविरोधी मांगें हैं और जिस विकास की दिशा में जाना चाहिए । चूंकि आज कुछ लोग भटक रहे हैं । जो सब्जबाग दिखाये गये । आज लोगों में निराशा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अनुदान मांगों का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिये जो समय प्रदान किया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 21,788 करोड़ की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता यह बोल रहे थे कि अकबर के शासनकाल में 9 रत्न और शिवाजी के कार्यकाल में अष्ठप्रधान की सलाह से वे कार्य किया करते थे । मैं कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया के न तो नौरत्न हैं, न अष्ठप्रधान हैं वो जनता से डायरेक्ट मुलाकात करते हैं, भेंट करते हैं । कौन से जिले में कौन सी समस्या है उसका हल कैसे करना है और उन सभी का हल इस बजट में बहुत आसानी से किया गया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं । दूसरी बात, जब हम लोग नए-नए विधायक बनकर आए तो हमारे एक विपक्ष के विधायक ने कहा कि तुम लोग एक साल नहीं बैठ पाओगे । आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि तुम लोग छर्री-दर्री हो जाएगे, छर्री-दर्री । लेकिन आज आप देखिए, शानदार चार वर्ष, किसान, मजदूर, भूमिहीन किसान, असहाय और आम जनता के लिए काम किया है और 4 वर्ष कुशलतापूर्वक पूर्ण किया है और हमने पांचवे और चुनावी वर्ष में प्रवेश किया है । निश्चित तौर पर हमने जनता के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, मजदूर के लिए काम किया है । कांग्रेस का आने वाला समय भी उज्जवल होगा । आप आर्थिक स्थिति को देखिए, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, सेवा हो तीनों क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केन्द्र से अधिक है । राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को देख लीजिए 8 प्रतिशत की वृद्धि है । प्रतिव्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है । 1 लाख, 33 हजार

898 रूपए यानी 10.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । राज्य के बजट में वृद्धि के साथ-साथ कर प्राप्तियों में 11.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हम जब जनता के बीच जाते हैं तो किसान, मजदूर सब खुश हैं । सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं सबको मिल रही हैं। इस तरह राज्य की स्थिति बहुत खुशहाल है । उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं सामान्य प्रशासन की बात कहूं तो प्रदेश में 33 जिले बनाए गए हैं । क्योंकि बहुत सारे दूरस्थ अंचलों में पहुंच पाना और अपना काम कराना बहुत मुश्किल था । ये 33 जिले बनाकर जनता को सुविधा दी गई है, जिससे जनता का काम बहुत आसानी से होगा। उसी तरह से नए युग के अनुसार नवाचार करना भी बहुत ज़रूरी थी, इसके माननीय मुखिया ने छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया । इसमें चाहे राजीव किसान न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे नरवा, गरवा, घुरूवा, बारी की बात हो । सबके लिए बजट दिया है और इन योजनाओं पर धरातल में काम चल रहा है । मेरे क्षेत्र में जो नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी की जो बात कही गई है वह सारा काम प्रगति पर है और इससे जनता बहुत उत्साहित है कि कुछ तो नया हो रहा है । इस बेरोजगारी के दौर में यदि छोटे छोटे लोगों को प्रशिक्षित करके काम दिया जा रहा है तो वह बहुत ही सराहनीय प्रयास है । इसी कड़ी में रीपा का निर्माण किया जा रहा है वह भी बहुत सराहनीय है । मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जनचौपाल मेरे क्षेत्र में भी दो जगह हुआ था, उसमें लोगों ने जो मांगा, मैंने जो मांगा, सब दिया है । वह सब बजट में आ गया है । निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता में संतुष्टि मिली है । हमारे यहां कोविड-19 में लोग परेशान हो रहे थे । रूस-यूक्रेन के युद्ध से भी लोग बहुत परेशान हो रहे थे ।

उपाध्यक्ष महोदय, यू.पी.एस.सी. के कार्यक्रम में लोग दिल्ली जाते हैं तो सोचते हैं कि कहां रहें । शासन ने सोचा कि यदि इनको अचानक जरूरत पड़ती है तो रूकने की ठहरने की व्यवस्था से लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाता है और इसके लिए दिल्ली के चाणक्यपुरी में छत्तीसगढ़ भवन बनाया गया है । यह छत्तीसगढ़ शासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है । उसी तरह से हमारे बच्चे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ नहीं पा रहे थे । एक तो बेरोजगार थे, फिर फीस कौन देगा, गाली खाते थे । क्योंकि एक बार इंटरव्यू देने से नौकरी नहीं मिलती थी । इस दर्द को हमारे माननीय मुखिया ने समझा और परीक्षा शुल्क माफ किया गया है, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जनता के कल्याण के लिए काम किया है । उसी तरह से 15 साल में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उस समस्या को हल किया गया और विशेष अभियान चला करके इनको भी राहत प्रदान किया गया। उसी प्रकार से पिछड़ी जनजाति के लोगों को भी नौकरी दी गयी। मेरे यहां कमार प्रजाति के लोग हैं। पिछली सरकार ने खेत देंगे, नांगर देंगे, बैल देंगे, यह बातें कही गयी थी लेकिन यह ढपोसला था। अभी यथार्थ में देखा जाए तो पिछड़ी जनजाति के लोगों को जिसमें जितनी योग्यता है, उसके अनुसार नौकरी दी गयी है। उसी तरह से आनलाईन पोर्टल प्राप्त

शिकायतों का भी निवारण किया गया है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में शिकायत आएगी तो उसका निवारण होगा और इससे समझेंगे कि जनता को क्या समस्या है, हमको कानून कैसे बनाना है। इसके लिए आनलाईन पोर्टल के माध्यम से 98 प्रतिशत शिकायत आई थी, उन सभी का हल किया गया है। उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, कहीं अचानक एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कोई बीमारी है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रूपए स्वेच्छानुदान दिया है। हमारे क्षेत्र के लोगों को भी लाखों रूपए स्वेच्छानुदान के रूप में दिया गया है, यह भी एक बहुत बड़ी मानवीय सहायता है। यदि राज्य शासन से सहायता मिलती है तो लोगों की जो बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं होती हैं, वह थोड़ी बहुत कम हो जाती है। उसी तरह से हर चीज को पारदर्शी रखने के लिए सूचना का अधिकार दिया गया है। आज के समय में वह बहुत बड़ी बात है। जो अधिकारी बेईमानी करते थे, उससे बहुत हद तक राहत मिली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विमान सेवा की बात कहूं तो सब लोगों ने बताया और मैं कहती हूं कि जब भी आदिवासी अंचलों और पिछड़े अंचलों में जब कोई विमान या हेलीकाप्टर जाता है तो जितनी भीड़ सभा में नहीं रहती, उतनी देखने के लिए भीड़ रहती है। इस सपना को छत्तीसगढ़ में साकार किया गया है। जगदलपुर जो हमारा आदिवासी अंचल है, जहां वाणिज्य और व्यापार है, वहां जो सैनिक नक्सलाईड समस्या होने के कारण रहते हैं, उनके आने-जाने के लिए तीन दिन तक दिल्ली से कनेक्टिविटी दी गयी है। यह बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। उसी तरह से कोरिया जिले में भी नवीन हवाई पट्टे, बिलासपुर में भी बिलासा देवी केंवटीन के नाम से विकसित किया जा रहा है। कोरबा और बैकुंठपुर में भी नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही विमानन अधोसंरचना गतिविधि के लिए एरोसिटी विकास कार्यक्रम बनाया गया है, वह भी सराहनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए समाप्त करिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष जी, हम लोग बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगे। मैं जनसंपर्क विभाग की बात बताना चाहती हूं। हमारे पत्रकारों को गृह निर्माण, ऋण अनुदान योजना पहले 25 लाख से बढ़कर 50 लाख रूपए किया गया है, वह निश्चित तौर से राहत देने वाली है। पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गयी है। जिसमें उनके साथ-साथ उनके रिश्तेदारों के लिए गंभीर बीमारियों में सहायता देने की बात कही गयी है। वह निश्चित तौर से मानवीयता का परिचायक है। इसी तरह से इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की बात कहना चाहती हूं। चाहे वह मुख्यमंत्री ई समीक्षा हो, श्वान परियोजना की बात कहें, चाहे डिजीटल शासन की स्थापना की बात कहें, चाहे जिला ई-परियोजना की बात कहें, चाहे स्टेट डाटा सेंटर की बात कहें, चाहे वाई फाई सिटी योजना की बात कहें, एक तरफ से दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है और आनलाईन सेवा के माध्यम से हर व्यक्ति को सुविधा देने का प्रयास किया गया है। इससे शासन के काम में तेजी आई है। जब काम में तेजी आई है तो यह बात विकास को दर्शाता है। मैं ऊर्जा विभाग की बात करना चाहती हूं। पहले 37 लाख उपभोक्ता थे, अब 60 लाख उपभोक्ता हो गये

हैं, जिनको कनेक्शन दिया गया है। हमारे क्षेत्र में कृषि पंप का ऊर्जीकरण किया गया है। 5 हार्स पॉवर तक फ्री में दी जा रही है। सब स्टेशन बनाया गया है, मेरे क्षेत्र में तीन चार सब स्टेशन हैं, जो पहले 15 साल तक शाम होते ही बिजली टिम-टिम दीया टाईप से दिखते थे, अब वह स्थिति नहीं है। इसके अलावा जंगल क्षेत्र होने के कारण जगह-जगह ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी होती थी, वह भी नहीं थी, उसको भी बढ़ाया गया है और बिजली बिल हाफ की बात को कौन नहीं जानता। हम व्यक्ति को लाभ मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- लक्ष्मी जी, एक मिनट। अभी 14 माननीय सदस्य और बचे हैं। कृपया आप लोग 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजराटोला में भी दिखाई देने लगा है तो निश्चित तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। मेरे क्षेत्र में दो तहसील कुकरेल और बेलरगांव, ए.डी.बी. की सड़कें, पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें, पी.एम.जी.वाय. की सड़कें, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, प्रत्येक गांव में गोठान, आवर्ती चराई योजना, गोधन न्याय योजना, आधा दर्जन नालों की मरम्मत हुई है, जन चौपाल लगे हुए हैं, जिनमें सड़कें, पुलिया, सामाजिक भवन और वहां की जो भी समस्याएं थीं, उनको मुख्यमंत्री जी ने मांगा तो उन सब लोगों को संतुष्ट किया गया है। इसके अलावा मेरे यहां कर्णेश्वर धाम और पोटेश्वर धाम का विकास मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। दो बड़े स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गये। नये ट्रांसफॉर्मर के साथ-साथ मैं सौर ऊर्जा के बारे में कहूंगी कि मेरा क्षेत्र एक जंगली क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जो गांव आते हैं वहां बहुत जंगल है और नक्सली समस्या भी है और वहां बिजली की भी बहुत समस्या होती है। सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा की व्यवस्था की गई है लेकिन उसका रख-रखाव नहीं हो पाता है। वहां अधिकारी भी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि यदि उनको सौर ऊर्जा के लिए अनुदान दिया जाता है तो निश्चित तौर पर वहां के लोग इस ओर ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप समाप्त कीजिए। डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, मैं उनके समाधान की मांग करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जी। चूंकि सिंहपुर जंगली क्षेत्र है और जंगल के बीचो-बीच है इसलिए वहां पर पुलिस चौकी की जरूरत है। कुकरेल से बासीखाई आदिवासी क्षेत्र है और वहां की सड़क बहुत खराब है। उसके लिए आप बजट दीजिए। सिरपुर से हीरापुर, रावनसिंगी तक की सड़क भी बहुत जर्जर हो गई है और वहां बरसात में चलना मुश्किल होता है। केरेगांव का थाना टीना (शेड) वाला है उसको पक्का बनवा दीजिए। बरपदर बहुत ही आखिरी सीमा में है, वहां पर चलने के लिए रास्ता भी नहीं है वहां डब्ल्यू.बी.एम. कैम्पा के माध्यम से परमिशन दे दें। वहां पानी की बहुत ज्यादा समस्या है तो धमतरी में गंगरेल बांध

के पास यदि एनीकट बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर वहां की पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी और पानी का लेवल ऊपर आएगा। तो भू-संरक्षण की दिशा में यह कार्य होना बहुत जरूरी है। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं। मैं और बहुत कुछ कहना चाहती हूं लेकिन आपने जो बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉ. साहब।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी, आज मांग संख्या-1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71, 65 से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों के बजट का अनुमोदन होना है, मैं इस अनुदान मांग का विरोध करता हूं और इसके विरोध में कुछ बातें और तथ्य रखता हूं कि यदि कोई राजा होता है तो उसका एक कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की समस्या का निवारण करने के लिए कुछ प्रयास करे। कम से कम वह जाने तो सही कि सरकार और राज्य की जो इतनी योजनाएं हैं, वह जमीन और धरातल में कैसे चल रही हैं ? किस तरह से उनकी योजनाओं का इम्प्लीमेन्टेशन हो रहा है ? क्या-क्या समस्याएं पैदा हुई हैं ? क्या आपने कभी उसको झांक कर देखने की कोशिश की है कि आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर काम करते हैं ? क्या आपने उनको कभी देखा है ? आपके नहीं देखने के कारण से किस तरह से वह योजनाएं जमीन के अंदर चल रही हैं। मैं जमीन की बात कर रहा हूं। आज उनके कारण प्रशासनिक अधिकारियों के मनोबल बढ़ने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जनपद पंचायतों की बैठक में किसी भी आदमी समस्या सुनने के लिए नहीं जाते हैं। इसका परिणाम क्या होगा ? क्या आपने इसका सुध लिया ? आप किस तरह से प्रशासन करते हैं ? आपको अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ देना है और आपकी प्रशासनिक क्षमता की अकर्मण्यता इतनी है कि जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कोई भी जनपद पंचायत हो, आप अपने जनपद पंचायत में ही देख लीजिए कि उसकी इसमें कितनी सक्रियता है ? दूसरी चीज यह है कि आप यह देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री (राजा) जाता है तो प्रशासन में हलचल मचती है। पटवारी भी सुध लेता है, तहसीलदार भी सुध लेता है, प्रशासनिक अधिकारी भी सुध लेते हैं और इसका परिणाम यह है कि इनके नहीं जाने के कारण और समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर ग्रामीणों से प्रेस-कान्फ्रेन्स लेकर बात करनी पड़ी कि किसानों को फाउती उठाना है, सीमांकन, बंटवारा, नामकरण, यदि किसी किसान के दस्तावेज में ऑनलाइन संशोधन करने की भी कोई बात आती है तो उसके लिए बिना 10 हजार लिए प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करते । काम क्यों नहीं कर रहे हैं ? उसका एक मात्र कारण है कि मुख्यमंत्री गांव में जाकर नहीं देखते हैं कि योजना कैसी चल रही है, प्रशासन कैसा चल रहा है । उससे उनका मनोबल बढ़ता है, जिसका दुष्परिणाम भ्रष्टाचार के रूप में सामने आ रहा है । आप पंचायतों या कोई भी जनपदों में देख लीजिए, सरपंच को ऐसे ऐठते हैं, इंजीनियर ऐठेगा, चेक काटने वाला ऐठेगा, सी.ई.ओ. ऐठेगा, ये सब सरपंच की

हालत खराब करके रख देते हैं । सरपंच परेशान हो जाता है । क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं देखता कि जनपद की व्यवस्था कैसे चल रही है। कभी राशन कार्ड बनाना होता है तो उसके लिए दलाल लोग घूमते हैं, डेढ़ हजार के बिना बनता नहीं है । श्रम विभाग के अंतर्गत किसी को सिलाई मशीन देना हो, सायकल देना हो, सरकार की योजना का फायदा देना हो तो बिना कमीशन दिए फायदा नहीं मिल रहा है । जनता अपनी बात किससे कहेगी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- डॉ. साहब, कार्यकर्ता मन काए करही, ओकरो मन के तो मुंह, पेट हे । (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्रा जी, आपका भी नाम है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उनके मुंह, पेट के लिए व्यवस्था बना दिए हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- डा. साहब, तुहर जमाना में तो सूजी माटी घलो नही धरत रिहीसे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अगर तुमन ला सरपंच मन के शोषण बहुत अच्छा लगथे तो बहुत अच्छा हे । तुमन ला ए दारी सरपंच मन ह सुधारहीं ।

उपाध्यक्ष जी, कुल मिलाकर जो जन समस्या निवारण शिविर है, उसकी उपयोगिता क्या रह गई ? अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने में उपयोगिता है । उनका मनोबल कौन बढ़ा रहा है, उनको भ्रष्टाचार की ओर कौन लेकर जा रहा है ? जब आपका राजा ही सरकार की योजनाओं को देख नहीं सकता कि जमीन में क्या चल रहा है तो ऐसे राजा का मतलब क्या है ? मकान की तो बात ही नहीं है । इसलिए इसकी दुर्गति है ।

उपाध्यक्ष जी, वित्तीय प्रबंधन की बातचीत करूंगा । सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और जो भी बड़े-बड़े विभाग हैं, वे अपनी क्षेत्रीय जरूरतों को लेकर प्रक्रिया कराते हैं, स्वीकृत कराते हैं और उसको बजट में शामिल करते हैं । आपका वित्तीय प्रबंधन का भगवान ही मालिक है । आप ए.एस. जारी करने की क्षमता नहीं रखते। आपकी कैसी वित्तीय प्रबंधन की क्षमता है कि आप ए.एस. जारी नहीं कर पाते। किसी योजना को दो-तीन साल में आप हमेशा बजट में शामिल करते हैं, लेकिन आप ए.एस. जारी नहीं करते । आपका वित्तीय प्रबंधन की क्षमता कैसी है । लोगों ने आप पर विश्वास किया था, वे आपके ही प्रदेश के कर्मचारी हैं, आपकी प्रजा हैं, वे सब आन्दोलन में हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं । उन्होंने विश्वास किया और उनके विश्वास को किसने धोखा दिया ? यह कांग्रेस की सरकार है, जो अपनी वादाखिलाफी करती है और छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है । इसलिए मैं इस वित्तीय प्रबंधन का विरोध करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके विभाग का जो प्रमोटिंग पोस्ट है या किसी भी विभाग का प्रमोटिंग पोस्ट है, उस प्रमोटिंग पोस्ट पर आप संविदा में नियुक्ति देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है ? प्रमोटिंग पोस्ट पर संविदा की नियुक्ति देंगे, संविदा की परम्परा बनाकर रखेंगे तो फिर प्रमोशन में

आपको प्रमोटेड आदमी कहां से मिलेंगे ? आप उनको भी धोखा देने का काम कर रहे हैं और संविदा की परम्परा को जिस तरह से लागू कर रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं इसीलिए तो ठीक से प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. बांधी जी, यह सिस्टम कब से चल रही है ? जब पिछले समय आपकी सरकार थे, उस समय से यह प्रक्रिया चल रही है और अभी तो कुछ नहीं है । पिछले सरकार में तो जितने आई.ए.एस. अधिकारी हैं, उनकी पत्नियां भी उसी विभाग में पदस्थ होती थीं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अब तो बेरोजगारी दर भी बढ़ गयी है, बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ गई है तो अब यह परम्परा समाप्त करिए या उसी परम्परा को ढोते रहोगे, जो गोबर को लेकर आये, उसी गोबर को आप और लादकर लेकर जाने की बात कर रहे हैं । उस संविदा की परम्परा को समाप्त करने का मेरा सुझाव है, ताकि उसमें जरूरतमंद को प्रमोशन मिल सके । आप वित्त मंत्री हैं तो उस नाते आप समझें कि संविदा की नियुक्ति प्रमोटिंग पोस्ट में करना है या नहीं करना है ।

श्री रामकुमार यादव :- ये ज्ञान ला मोदी जी ला घलो कह देथा। 35 साल, 40 साल कहिथा। ओला कुछ नहीं करना हे। कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, बस ऐतका कहथ हे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- तै टाइट गोबर ला लीटर मा खरीदबे या लीटर मा खरीदबे तै पहली ये बता ? बाद मा सोच के बता देबे

श्री रामकुमार यादव :- ओला हमन छटाक मा खरीदबो। तुमन खरीदा का ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उर्जा विभाग में बोलता हूं। जरूरतें बढ़ रहीं हैं। आपकी कल्पना है कि छत्तीसगढ़ में उर्जा की मांग बढ़ी हुई है और मांग की पूर्ति के लिए गांवों में क्या स्थिति है ? आज जितने ट्रांसफार्मर हैं, 60 के हैं, बदलने लायक हैं। आपने उसके लिए कौन सी नीति अपनाई ? आपने उसको बदलने के लिए क्या सोचा है ? बार-बार ट्रांसफार्मर भस्ट हो रहा है। गांव के लोग चंदा करते हैं, आपस में तय करते हैं और खुद की गाड़ी में लादकर ट्रांसफार्मर लगाने का काम करते हैं, ये आपके उर्जा विभाग का प्रबंधन है। दूसरा, बढ़ी हुई बिजली की मांग की पूर्ति करने के लिए उर्जा विभाग कितने उप केन्द्र खोलने का बजट में प्रावधान किया है ? कितने उपकेन्द्र खोले गये ? 2-2 साल से स्वीकृत उपकेन्द्र को ए.ए. जारी नहीं होने के कारण लंबित पड़ा हुआ है। आपके उर्जा विभाग की क्या कल्पना शक्ति है ? आप एक तरफ आधा करते हैं। जिन गांवों में लोगों का बिजली बिल 10 गुना आया उन लोगों ने कलेक्टर का घेराव किया। उन लोगों ने कलेक्टर का घेराव कर बताया कि 20 हजार, 25 हजार रूपया बिजली का बिल आ रहा है। क्यों आ रहा है ? ये बात कलेक्टर के सामने कहा गया तो क्या परिणाम आया आपको मालूम है ? कहा गया कि आपने 10 साल से बिल पटाया नहीं था। उसके ऊपर 10 साल से कृपादृष्टि हो रही थी, ऐसा कारण बता करके बढ़े हुए बिलों का स्पष्टीकरण देते हैं। क्या यह उचित है ? अब ये करेंट मारेंगे। जब कांग्रेस की सरकार गांवों में जायेगी तो बिजली बिल हॉफ

का करंट है, वह इनको लगेगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार का जिस तरीके से रवैया चल रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। गांवों के हितों में नहीं है, यह ऊपरी-ऊपर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी बात ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का है। अगर लाईन का विस्तार होता है, लोग शिफ्टिंग के लिए कह डाले। इस रोड से उस रोड में जाना हो, तो वहां पर गांव से टेका लगाकर जाते हैं, तब गाड़ी क्रास हो पाती है। उस बिजली के लाईन को ठीक करने के लिए बजट नहीं है। इससे आप अंदाज लगा लीजिये कि उस विभाग की कार्यक्षमता कितनी होगी ? अगर आज किसी ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करना है, ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए 4 साल तक आवेदन देते चले गये, लेकिन ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने में कांग्रेस सरकार असक्षम रही है। यह कैसी सरकार है ? आप ग्रामीणों की हितैषी बनते हैं और दूसरी तरह की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- बांधी साहब, समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-थोड़ा सा और है। दूसरा, सोलर पंप कितनी बढ़िया योजना है। उसका किसने बैण्ड बजा दिया ? कौन सा नियम है, किस योजना के तहत बैण्ड बजा दिया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डाक्टर साहब, तोर ट्रांसफार्मर सही सलामत हे कि नहीं ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- नहीं हे यार, ठीक नहीं हे।

श्री केशव चन्द्रा :- ओ डाक्टर करा ई.सी.जी. कराके आ हे। ई.सी.जी., ब्लड टेस्ट कराके आय हे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सोलर पंप बहुत उपयोगी है। उसमें क्यों आर्थिक सहायता नहीं देना चाहिए ? जो असिंचित एरिया है, उस असिंचित एरिया में सोलर पम्प रामबाण की तरह काम करता है। उससे खेती का रकबा भी बढ़ेगा और जी.डी.पी. भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। लेकिन आपका क्या नजरिया है ? आपका नजरिया है कि सोलर केन्द्र सरकार की परिवर्तित योजना है, उसमें सहयोग नहीं करना है। कांग्रेस सरकार और उसका संचालन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का यह दुर्भाग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुसुम योजना कितनी बढ़िया योजना है। किसानों को कितना अच्छा फायदा हो सकता है। इस कुसुम योजना में सोलर पार्ट के अन्तर्गत, लेकिन आपने इस कुसुम योजना के लिए भी बजट में कितना प्रावधान किया है ? केवल ऊंट के मुंह में जीरा, इतना बड़ा प्रबंधन है ? इससे किसानों में कैसे समृद्धि आयेगी। असिंचित एरिया में कैसे परिवर्तन आयेगा ? कुसुम योजना के लिए भी आपकी दृष्टि नहीं है और किसान का हितैषी बनने का प्रयास करते हैं। आपके जितने उप केन्द्र हैं, उस उप केन्द्र में कर्मचारी का अभाव है। आपके नियमित कर्मचारी भी नहीं हैं, संविदा कर्मचारी नहीं है, लाईन मेन पार्टटाईम लेकर करते हैं अगर वह आ जाये तो शिकायत का निराकरण बिजली में होगा । अगर वह नहीं आयेंगे तो आपके पास कर्मचारी नहीं है । आपके कर्मचारी की जो भर्ती की स्थिति है,वह

खराब है । आपके उर्जा विभाग के क्षेत्रों में आप कैसा प्रबंधन कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय जी, थोड़ा सा खनिज के मामले में कहना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप समाप्त करेंगे ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, खनिज के मामले में बोलकर मैं समाप्त कर दूंगा ।आप जिस तरह से रेत का छत्तीसगढ़ में संचालन कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार जिस सोच के साथ काम कर रही है, इससे माफिया बढ़ा है । इस रेत आम लोगों को कितने में उपलब्ध होगा, कभी किसी ने उसके बारे में सोचा है । आपने उपभोक्ताओं के बारे में सोचा है क्या । कांग्रेस ने केवल रेत माफिया पैदा किया है । आपतो छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के हितैषी बनते हैं, आपने कितने छत्तीसगढियों को और कितने गैर छत्तीसगढ़ियों को रेत का ठेका दिया है, उसे आंकड़े देख लें । आप इनका नजरिया देखें कि कितने बाहर के रेत ठेकेदार हैं जो उपकृत किये जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोग वहां किस तरह से परेशान हो रहे हैं । गांव के लोग जो नदी नालों के पास रहते हैं, यदि वह अपने घर के उपयोग के लिये ट्रैक्टर खड़ा कर दिये तो पुलिस के कर्मचारी जो हैं, एजेंट बनाकर रखे जाते हैं और तुरंत मोबाईल करते हैं और पुलिस वाला उसे पकड़ कर ले जाता है, उसे माइनिंग वाला लेकर नहीं जाता है । उससे अवैध वसूली किया जाता है, बिना पांच-दस हजार लिये उस ट्रेक्टर वालों को नहीं छोड़ा जाता है, यह परम्परा आपने बना कर रखा है । क्या इससे मुक्त नहीं होना चाहिये ? क्या इस तरह से खुली छूट दे देनी चाहिये ? गांव में रेत की उपलब्धता पर हमको नहीं सोचना चाहिये ? राजस्व तो मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, आपने गांव की रेत के लिये सुलभता पर क्यों नहीं सोचा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह साहब ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- जिला प्रशासन खनिज नियंत्रण करता है, डी.एम.एफ. फण्ड का है, इसे प्रशासनिक अधिकारी अपने तरीके से परिभाषित करते हैं । जिलों में डी.एम.एफ. की परिभाषा अलग है और खरीददारी में सबसे तगड़ा है । उपाध्यक्ष महोदय, कई बार डी.एम.एफ. मद में भ्रष्टाचार के लिये विधान सभा में आया है, क्या इस पर नियंत्रण नही होना चाहिये ? क्या इस पर समग्र विचार नहीं होना चाहिये? यह यह अंतिम बजट है । आप डी.एम.एफ. के लिये नहीं करेंगे तो आप ग्राम पंचायत के लिये डेवलपमेंट का पैसा नहीं दे पायेंगे, उसमें पंचायत विभाग असफल है, आपकी समग्र विकास की योजना फेल हो चुकी है, एक भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं । अगर कुछ पैसे गांव के लिए डी.एम.एफ. फण्ड से आ जाते हैं, उसके लिये उचित व्यवस्था क्यों नही होनी चाहिये ? उसके लिये प्रशासन अलग है । एक करोड़ में 10 गांव के बराबर नही होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह साहब । डॉ.साहब अब समाप्त करें । आपका लगभग-लगभग आ गया और मिलेंगे साथ में, आपने बढ़िया बोला ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :-आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट और वित्त विभाग के बारे में बहुत ज्यादा समझता तो नहीं हूँ, यह मेरे लिये वैसा ही विषय है, जैसे किसी विद्यार्थी के लिये मिडिल हाई स्कूल में गणित का परीक्षा जब आ जाता है तो इधर-उधर देखने लगता है । यह मेरे लिये गणित की परीक्षा जैसे है, मैं आंकड़े तो पढ़ूंगा नहीं, न मैं उसको ज्यादा समझने की कोशिश करता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रेक्टिकल बात करना पसंद करता हूँ कि जिस काम से फायदा मिल सके, उसको कर दो, जिससे फायदा न मिल सके, उसके बारे में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है । ऐसा भी नहीं है कि रमन सिंह की सरकार में सब खराब काम हुआ है कि आपकी सरकार में भी खराब काम हुआ है । आपकी सरकार में भी बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन बहुत से काम बहुत खराब हुए। उन खराब कामों की ओर हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं और उसमें सुधार के लिये आपसे निवेदन करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मुख्यमंत्री जी का विभाग नहीं है लेकिन मैं इसी विभाग से शुरूआत करना चाहता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुखिया है। बिना विभाग के वितरण हुए भी हर विभाग उनके अधीन है। कटघोरा वनमंडल में हसदेव अरण्य एक जंगल है। वहां पर खदान खोलने के लिये अडाणी साहब का कोई खदान, राजस्थान पॉवर लिमिटेड के एम.डी.ओ. बन गये हैं, मतलब उनकी तरफ से काम को वही करेंगे। मैंने उसके लिये विधान सभा में लगातार एक घण्टे तक कई तथ्य और तर्क दिये कि कौन-कौन सी नदी का जल स्त्रोत खत्म होगा, कौन-कौन से झाड़ कटेंगे, कितनी संख्या में वृक्ष कटेंगे, कितना पानी कम होगा, विद्युत का उत्पादन कितना कम होगा, खेती में सिंचाई का असर कितना कम होगा, लेकिन आपने सिर्फ यह कहा कि यह अनुमति तो दिल्ली से दी गयी है। आपकी भी सरकार उनकी सहभागिता के लिये जो आरोप लग रहे हैं, उससे बच नहीं सकती है। क्योंकि आपने Environment Department से और अन्य विभागों से उसे अनुमति दी है। जब दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी और आपकी कांग्रेस पार्टी अडाणी के विरोध में और रायपुर में आपके कैबिनेट मंत्री और संगठन राज्यपाल के पास विरोध करने के लिये जा रहे हैं तो फिर आपकी सरकार ने उसको अनुमति क्यों दी है ? यदि दी है तो उस अनुमति को समाप्त कर देना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ का वह वन सम्पदा बच सके। अडाणी को खदान देना है तो छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत सी जगह है, जहां पर झाड़ कम है, जंगल का कम नुकसान होगा, उसे वहां खदान दे देना चाहिए। हम किसी उद्योग या उद्योगपति के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, न उसके समर्थन में बोल रहे हैं। लेकिन हम इस प्रदेश के आदिवासियों के समर्थन में खड़े हुए हैं, इस प्रदेश की वन सम्पदा की रक्षा के लिये बोलेंगे, इस प्रदेश के वन्य प्राणियों की रक्षा के लिये बोलेंगे, इस प्रदेश के किसानों को मिलने वाले पानी की सुरक्षा के लिये बोलेंगे। मैं आपसे इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार जरूर विचार करियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी-सी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। शायद आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग भी हैं। मैंने एक प्रश्न लगाया कि क्या यह सच है कि बिलासपुर के नेहरू चौक में नेहरू जी की मूर्ति के पास आइलैंड बना है, उसमें इधर से उधर और चारों तरफ के लोग आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। इस आइलैंड में टेक्निकल प्रॉब्लम है। यदि इस आइलैंड को ठीक करेंगे तो जनहानि भी नहीं होगी और नेहरू जी की प्रतिमा, जिसे प्रकाश चंद सेठी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पित किया था, उसकी रक्षा भी हो पायेगी। इसी सदन में जवाब आता है कि उस आइलैंड में कोई टेक्निकल खराबी नहीं है। आपके अधिकारी कुछ भी जवाब भेज देते हैं और आप हमें बोल रहे हैं कि हम उसे माने। आप वरिष्ठ मंत्री है। आप तो उधर आते जाते हैं। अमरजीत भगत जी, एक दिन जरा खड़े होकर देखिये। किसी एक जगह में खड़े होंगे तो चारों तरफ दिखता नहीं है। मुझे उस आइलैंड से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं उस आइलैंड की तरफ इसलिये बोलना चाहता हूं, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि उस आइलैंड के ऊपर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की मूर्ति लगी है, जिसका उद्घाटन या लोकार्पण सेठी जी ने किया है। यदि शराब के नशे में कोई ट्रक वाला आयेगा और उसको डैश करेगा तो नेहरू जी उस ट्रक में गिरकर सरकण्डा के पार चले जायेंगे। मैं नेहरू जी की हिफाजत की बात कर रहा हूं लकिन आपके अधिकारी उल्टी-सीधी बात करते हैं, उल्टा-सीधा जवाब देते हैं। इनके चक्कर में मत रहिये। ये वही जवाब देंगे जो आपको पसंद होगा। यह 15 साल वही जवाब दिये हैं। हम तो देखते थे ना, वही कुर्सी है, वही अधिकारी है, दो-चार बदल गये हैं, उधर से उनका सिर झुकता है, इधर से मंत्री का सिर झुकता है, उधर से स्लीप आती है, हमार वही वाला चपरासी, भृत्य, सेवक बैठा है वह स्लीप पहुंचाता है। आप उधर के चक्कर में मत रहिए। अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय धर्मजीत भईया, व्यवस्था तो वही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप व्यवस्था को बदलिए।

श्री अमरजीत भगत :- आप व्यस्था को कैसे बदलिएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- मान लीजिए कहीं पर गंदगी दिख रही है तो उसको साफ नहीं करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बोल रहे हैं कि उनके चक्कर में मत पड़िए। इनकी चले तब तो? इस बारे में ध्यान दीजिए। इन लोगों की नहीं चलती तब क्या करेंगे?

डॉ. विनय जासवाल :- माननीय धर्मजीत भईया, आपने नेहरू जी की बात की तो 30 सेकण्ड में मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। क्या है कि माननीय मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया कि जातियों की व्यवस्था पंडितों ने की। तो मोदी जी ने कहा कि हां, यह पंडितों ने किया। पंडित नेहरू ने यह किया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने बिलासपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति की बात कह रहा हूँ। मोहन भागवत जी क्या बोले, मोदी जी क्या बोले? आप क्या बोले?

आपके नेता क्या बोले, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि फिर से इंजीनियरों से उस आईलैण्ड का परीक्षण करा लीजिए। अगर वह आईलैण्ड नहीं बदला तो किसी दिन कोई भीषण दुर्घटना होगी, अगर वह आईलैण्ड ठीक से सुधारा नहीं जाएगा तो शायद नेहरू जी मूर्ति सहित सरकण्डा और कोनी के साथे में दिखाई देंगे। इसलिए उसकी हिफाजत करिये। ये रेत-रेत की बात होती है। यहां इस प्रदेश में खुलेआम रेत माफिया सक्रिय हैं कहीं मार रहे हैं, पीट रहे हैं कहीं टेण्डर हुआ है, कहीं टेण्डर नहीं हुआ है, कहीं निकल रहा है सत्ताधारी राजनीतिक दल के लोगों के संरक्षण में रेत माफियाओं का काम चल रहा है। माईनिंग ऑफिसर्स की हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर कार्यवाही कर सके। आज भी त्राही-त्राही कर रहे हैं। रेत के नाम पर कुछ भी [xx] हो रहा है, लेकिन यह [xx] वहीं तक हो तब तो ठीक है। कुछ दिन पहले तक आप पंचायत मंत्री थी। एक दूरस्थ वनांचल में एक छोटा सा कोई अतिरिक्त कमरा बनना है तो वह रेत तो वहीं की नदी से लाएगा। उसका कोई ऑक्शन होता नहीं, उसका कोई टेण्डर नहीं होता। वह ट्रेक्टर में भरकर लाता है दूसरे दिन वन विभाग वाले उसका ट्रेक्टर राजसात कर देते हैं। अब मुझे यह बता दीजिए कि अगर वहां से वह रेत न लाए तो कहां से रेत लाए? आपका स्टीमेट इतने का नहीं है कि वह शिवरीनारायण का रेत ले जाए। आपकी सरकार में आपके राज में रेत का कोई कारखाना नहीं है कि रेत के कारखाने से दो बोरी खरीदकर ले आए। गौठान में रेत नहीं बनता, जो वहां से लेकर रेत में आ जाए। आप अपने अधिकारियों को निर्देशित करिये कि जो बड़े-बड़े चोर हैं रेता माफिया हैं, उनको कुचलने का काम करे, सरकार राजस्व बढ़ाये। वहां पर जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के संरक्षण में रेत की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन गांव का कोई आदमी अपनी परछी छाबने के लिए कोई छोटी सी नदी से रेत निकाल कर ला रहा है तो उसको थाने में बंद कर दो। उसको तहसीलदार जप्ती कर लेता है, राजसात भी कर देता है। भारत का तमाम् कानून उसके ऊपर लागू होता है। यह कहां का न्याय है, उसकी छूट के लिए कुछ विचार जरूर करिएगा। मुख्यमंत्री जी से निवदेन है कि आपकी मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना बहुत अच्छी योजना थी। जिस दिन यह योजना लॉन्च हुई, मैंने विधान सभा में भी इसकी तारीफ की थी। अभी भी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का अफसोस है कि आपने इसमें पहले साल ही डेढ़ सौ करोड़ का प्रावधान किया। हमारे क्षेत्र में कुछ-कुछ काम मिला, उसमें से कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ, पर जब उस योजना की मांग बढ़ी तो जब हम लोग कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पहले ही साल माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, आपने 500 करोड़ रूपये का काम मंजूर कर दिया। वह 3 सालों का पैसा उसी योजना में चला गया। अभी तो ऐसा वक्त है कि बजट में हवाई अड्डा, एव-तेव, आप भी जानते हैं आप बहुत वरिष्ठ हैं। आप तो मुख्यमंत्री हैं हम लोगों से ज्यादा ही जानते है। यह कैसा-कैसा ऑरनामेंटल रहता है, लेकिन आप इन छोटी-छोटी योजनाओं में बजट बढ़ा देंगे तो 4 महीने के अंदर फटाफट कई गांवों में कई सड़कें पहुंचमार्ग बन जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री सड़क योजना में 500-700 करोड़ रूपये डालिए ताकि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के माध्यम से जहां गांव में उन भवनों तक

कीचड़-पानी में आना-जाना पड़ता है वहां सुगम सड़क बनेगी तो गांव के लोगों को फायदा होगा । लेकिन मेरी जानकारी में इस बजट में भी दिये गये पैसे को पुराना भुगतान करने के बाद 30 करोड़ रुपये ही बचेगा। अब उसमें आप कितना बांट पायेंगे, कितना होगा, इस पर आप जरूर विचार करियेगा। वित्त विभाग में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मुंगेली और बिलासपुर जिले में पी.डब्ल्यू.डी. के कौन-कौन से काम स्वीकृत हुए, नामवार जानकारी दें और यह बतायें कि वित्त विभाग से कितने को ए.एस. जारी हुआ? यह पूरी सूची है। इसमें 80 प्रतिशत बिल्कुल अस्वीकृत, अस्वीकृत, अभी स्वीकृत नहीं हुआ, अभी स्वीकृत नहीं हुआ लिखा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि बजट में चाहे 10 प्रकार के प्रावधान हों, आपको जिसको-जिसको करवाना हो, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि लोरमी में आपने बजट में 5 सड़क को स्वीकृत कर दिया। आप बोल दीजिए न एक कोई सड़क बताओ, हम उसको करेंगे। ऐसी लिस्ट लेकर, आप वित्त में बोल दीजिए उसको सबको क्लीयर कर दें। एक-एक साल, 12-12 महीने finance में लगता है। मुख्यमंत्री आप तो जब कड़े-कड़े निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इसमें भी ले लीजिए। अभी जैसे बरसात के पहले ये सब finance से क्लीयर हो जाये जो टेंडर लग जायेगा। लेकिन ये अभी के बजट में अगले साल के मार्च-अप्रैल तक के administrative sanction होता ही नही है। जिससे काम मंजूर होता नहीं। काम मंजूर होने के बाद वित्त विभाग से टेंडर लगेगा, टेंडर के री-टेंडर होगा, फिर टेंडर होगा, फिर री-टेंडर होगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- कल तो जवाब दिये होंगे न।

श्री धर्मजीत सिंह :- कल कुछ जवाब नहीं दिये। कल हम पूरा भाषण सुने, कोई टोकाटाकी नहीं किये। उन्होंने अपना ये प्रावधान, ये प्रावधान, ये बनायेंगे, वो होगा, बताया। हम लोग जो भी बातें बोले थे, उसमें एक शब्द भी नहीं बोला। आप तो कृपापूर्वक कम से कम बोले कि इन्होंने भी मांग किया, उन्होंने भी मांग किया, मेरा नाम लिया, मैं दूंगा, विचार करूंगा या सोचूंगा। आपने तो बोला। पर वहां तो कोई जवाब आया नहीं था तो ज्यादा पूछना भी उचित नहीं समझा। वित्त विभाग की व्यवस्था में जो स्वीकृति की प्रक्रिया है, आदरणीय, उसको सरल कराईये। आप बजट में लाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बता भी देते हैं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन वित्त विभाग के अधिकारियों से तो डर जाता हूं। पता नहीं उनको क्यों देने में तकलीफ है ? तो आप उनकी कुछ तकलीफ का निराकरण कराईयेगा। सी.एस.ई.बी. में, मेरे को इससे कोई लेना-देना नहीं है।

<u>सदन को सूचना</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना काम तो आप रनिंग में कर देते। मैं बोलते रहता और आप चाय की घोषणा भी कर देते।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात को सुनना भी जरूरी है न।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले बोल दिया हूं कि वित्त के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं। आंकड़ेबाजी की बात करेगा तो मैं हार जाऊंगा और आप जीत जाओगे, मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- वह आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- मैं सुन रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका ध्यान चाहता हूं करके मैं रूक गया था। सी.एस.ई.बी. में सिर्फ आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर उठा रहा हूं जिसमें सदन के 90 विधान सभा के 90 विधायक उससे सहमत होंगे। आपके एक टेलीफोन पर उनकी सारी समस्या का निराकरण होगा। जिन-जिन गांव में ये समस्या है सारे लोग आपको धन्यवाद देंगे। आप एक टेलीफोन में 72 घंटे के अंदर समस्या का हल कर सकते हैं। हर गांव मे जब पुराना स्कूल बना, बिजली का खंभा कैसे लगा, नहीं लगा, यह मालूम नहीं। कहीं पर वायर इधर से निकला है, कहीं पर उधर से निकला है, वायर पुराना है, बच्चों के ऊपर कभी-कभी टूटकर गिरता है। या कोई नई इमारत की अनुमति मिलती है तो बन नहीं पाता है। उस स्कूल और सार्वजनिक सरकारी स्कूल भवन के ऊपर जाने वाले वायर को आप हटवाने के लिए छतीसगढ़ के जिन-जिन गावों में है, एक जनरल आर्डर कर दीजिए। वह खंभा वहां से उखाड़कर किनारे गाड़ दे और वहां से वायर ले जाये। उससे बच्चों की भी सुरक्षा होगी और गांव वालों को भी तसल्ली होगी और स्कूल के ऊपर कल इमारत दो स्टोरी, तीन स्टोरी का बनाना है तो बनेगा। यह बहुत जरूरी है। छतीसगढ़ में बहुत पुराने समय से तार लगा है। तार क्या है कि टूट जाता है। बिजली सप्लाई बाधित होती है। अधिकारियों को आदमी परेशान करता है, बोलता है या घेरता है तो इसके बारे में भी एक सर्वे करा लीजिये कि यह पुराने वायर को हम कब तक बदल सकत हैं, क्योंकि इतना बड़ा छत्तीसगढ़ है। सब वायर तो एक साथ बदले नहीं जा सकते, परंतु उस वायर को बदलने के लिए कोई ऐसा प्लान बनवा लीजिये, जिसमें चरणबद्ध तरीके से वह गांव के वायर मंजूर हो। 40-50 साल पुराने वायर गांव में लगे हुए हैं। कई खंभे, जब गांव छोटा था तब गड़ा था। अब गांव बढ़ गया है तो खंभा भरे दरवाजे के सामने आ गया है। उसका वायर घर की छत से ऊपर चला जा रहा है। जब कोई मांग करके आता है, कोई 5-10 हजार रूपये मदद की बात करें तो अच्छा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, पर एक खंभा हटाने की लेकर बात करते हैं तो सर से लेकर पैर तक की सिहरन हो जाती है, क्योंकि बिजली विभाग पता नहीं हटायेगा या नहीं हटायेगा। हटायेगा तो पता नहीं कि कितने किस्म का स्टीमेट देगा। माननीय

मुख्यमंत्री जी, आपके ही नाम से एक अपील कर दीजिये कि जिनको जो प्राब्लम है, वह कलेक्टर, सी.ई., डी.ई. या जो भी है, उनको आप लिख कर दीजिये। वह भी कर लीजिये। query करा लीजिये। जिसके घर के ऊपर बिजली का वायर हो, जिसके घर के दरवाजे में खंभा हो, उसे आप हटवा दीजिये, चौक-चौराहे से हटवा दीजिये ताकि दुर्घटना भी मत हो और वह तनाव से मुक्त हो। मृतको को थोड़ा मुआवजा भी दिलवा दीजिये। उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। आपकी सोलर लाईट बहुत अच्छी योजना है। हाई मास्क लाईट लगाये हैं, वह तो और भी अच्छी है। परंतु उसमें ज्यादा नहीं मिल रहा है। इनको मिला होगा तो मैं नहीं जानता। खैर इन लोगों को तो मिला ही होगा। थोड़ा आपकी नजरें इनायत इधर भी कर दीजियेगा। हमको भी दे दीजियेगा। उससे गांव वाले खुश हुए हैं और जो गांव में, जैसे खासकर वन ग्राम में एक लाईट भी जल रहा है तो लोग वहीं पर शाम को बैठते हैं। कंपनी गार्डन, बूढ़ा तालाब सरीके उसी को बनाकर उन लोग मजा करते हैं। उसमें भी ध्यान दीजियेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कल बात नहीं करना चाहता था, परंतु एक छोटा सा जिक्र तो कर रही देना चाहता हूं। बाद में फिर डिटेल में बात करेंगे। बिलासपुर में आप विशेष रूचि लेते हैं। वहां के बिजली के खंभों को हटवा कर अंडरग्राउण्ड कराने के लिए भी कम से कम सर्वे तो करवाने का आदेश कर दीजिये। इस प्रस्ताव को हां कह कर स्वीकार तो कर लीजिये। हम समझ रहे हैं कि उसमें पैसा बहुत लगेगा। कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन यदि आप एक बार हाँ भी बोल दिये तो यह नैतिक रूप से हम लोगों को ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मांग मत करिये। रायपुर में पांच साल से चल रहा है। आज तक एक भी अंडरग्राउण्ड नहीं हुआ है। मास्टर प्लान से पैसा भी मिल गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अंडरग्राउण्ड करा दीजिये न। अंडरग्राउण्ड करा देंगे तो और सुंदर दिखेगा। मुख्यमंत्री जी, भारतवर्ष में इस सदन में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अशासकीय संकल्प पर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री निर्माण कार्यों के लिए रूपये दिये हो। आपने दिया। हमने उसका स्वागत यहां पर भी किया, बिलासपुर में भी किया, अखबारों में भी हुआ, टेलीविजन में भी हुआ। आपने पैसा भेज दिया, लेकिन आपके अधिकारी उसका टेण्डर नहीं लगा रहे थे। आपने अभी किया । वह लोग बहुत लेट किये। कोई ई.ई. को भेजता है, कोई सी.ई. को भेजता है, कोई सी.ई. को भेजता है। उसी चक्कर में बहुत देरी हो गई, लेकिन आपने उसको कराया है तो उसमें अब थोड़ा-सा काम होने की संभावना बलवती हुई है और कुछ काम हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि फोर सी लाइसेंस के लिए 200 एकड़ जमीन तो लेना ही पड़ेगा। अब हमारे ही प्रदेश की पिछली सरकार ने सरकार ने डिफेंस को लैण्ड दे दिया था। अब हमारे पास उसी जमीन को लेने की मजबूरी आ गई है। 200 एकड़ जमीन लेना है। अब वह कैसे मिलेगा? आप बड़े हैं और वह भी बड़े हैं। आप ही दो बड़े लोग फैसला लेकर कोई रास्ता निकालिये। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हम लोग आपसे ही निवेदन कर सकते हैं कि बिलासपुर

की 200 एकड़ जमीन को डिफेंस से लेकर उसमें एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाया जायेगा तभी फोर-सी केटेगिरी का बड़ा प्लेन बोइंग वगैरह जो उतरता है वह वहां पर उतरेगा और जब वह उतरेगा तभी हम लोग ठीक से सफर कर पायेंगे । मुख्यमंत्री जी, अभी मैं एक-बार बीच में एक पारिवारिक कार्यक्रम में भोपाल गया था। जाने का और आने का, मैं बिलासपुर से उस छोटे वाले प्लेन में उड़ा और जब वह एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा तो वह दौड़ाकर उसको फिर चढ़ा लेता था तो दो बार ऐसे ही किया तो मैंने वापसी में अपना प्रोग्राम बदल दिया, मुझे ट्रेन से आना पड़ा तो आप बड़ा वाला चलवा दीजिये न । उसमें डर नहीं लगता है, इसमें तो बहुत डर लगता है । उसको आप ही कर सकते हैं । मैंने सुना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं बजट वगैरह के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं । मैं बजट की कॉपी को किसी अधिकारी के पास बैठूंगा, उसको बोलूंगा कि इसमें देख भाई पी.डब्ल्यू.डी. का क्या काम है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अभी तक जो करे हे इही करे हे । बाकी ओमन तो 15 साल में कुछू करेच नइ हे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, मैंने आपको बोला । आप शायद नहीं थे, मुख्यमंत्री जी भी नहीं थे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आज तोर गला हा थोकन बइठे-बइठे लागत हे । अजय भाई के असर हे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं । मैंने शुरूआत ही इस बात से की थी कि हर सरकार गलत नहीं करती और हर सरकार का हर काम अच्छा भी नहीं होता है । कुछ अच्छे काम हैं, मुख्यमंत्री जी के काम की हमने खुलेआम सराहना की है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया 22 मिनट हो गये हैं, समाप्त करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं । यदि कहीं पर कोई कमी है तो बोल तो सकते हैं, ध्यान तो आकृष्ट कर सकते हैं न । हम कोई इनका अपमान थोड़ी न कर रहे हैं, हम तो इनका बहुत सम्मान करते हैं । आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंदर से पता नहीं कितना सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं लेकिन हम खुलेआम सम्मान करते हैं । मुख्यमंत्री जी, एक बात का बहुत दुख हुआ । हम लोग हर-बार यहां फोर-सी लायसेंस, थ्री-सी लायसेंस, 200 एकड़-300 एकड़ मांग करते रहते हैं, बिलासपुर में रहते हैं । वहां धरने में सबसे ज्यादा बैठने वाला विधायक मैं हूं और वह भी धरना दिल्ली की सरकार के खिलाफ हो रहा है लेकिन जब वह एयरपोर्ट का कभी एकाध हवाईजहाज उड़ने का समय आता है न तो आपके बिलासपुर के कलेक्टर हमको बुलाते नहीं । क्यों भैया ? वह हवाई जहाज बिलासपुर का है कि बिलासपुर जिले भर में उड़ेगा ? यदि दिल्ली की सरकार के हिसाब से भी देखोगे तो पार्लियामेंट्री कांस्टेंसी बिलासपुर उसमें मुंगेली और लोरमी दोनों आते हैं । 10-11 बार का जीता हुआ सीनियर आदमी उसको भी नहीं बुलाते । हम लोग लड़ रहे हैं, हमको भी नहीं बुलाते और जो एक शब्द यहां बोले नहीं हैं उनको सबको बुला लिया जाता है । वहां मुख्यमंत्री जी

बताते हैं कि यह हाउस से कन्फर्म हुआ है । आप कर रहे हो और हाउस-हाउस क्यों बोल रहे हो ? हर बात में हाउस बोलने की क्या जरूरत है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अइसनहे तारीफ करे बर बोलेन धरम भैया तोला । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसा नहीं है । मैं आपको इसलिये बता रहा हूं कि अब जब भी ऐसी बात होगी ।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, एमन तो ट्रेन के उद्घाटन करथें ता मंत्री ला घलो नइ बुलाये । इंहे रायपुर में करथे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐहा हवाई जहाज के बात हे यार । तें हा कहां चबूतरा के बात में आ गे हस ? यह थोड़ा उस लेवल का मामला है न । आप अपने अधिकारियों को बोलिए न कि वे फैसला मत किया करें कि ये आयेंगे, वो नहीं आयेंगे । आप कौन होते हो बोलने वाले कि ये आयेंगे, वो नहीं आयेंगे । मुख्यमंत्री बोल दें कि नहीं आना है तो एक-बार हम मान भी लें तो आप थोड़ा इस बात का ख्याल रखियेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक समस्या बहुत गंभीर है । मुझे पेंशनर्स समाज के लोग मिले थे और उनकी मांग है और कोई बहुत नाजायज मांग नहीं है । मैं आपको पढ़कर दो मिनट में सुना देना चाहता हूं । अविभाजित मध्यप्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया है और अविभाजित राज्य के अधीन कार्यरत शासकीय सेवकों को 74-26 प्रतिशत के अनुपात से बंटवारा किया गया है । ये कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ शासन में बंटवारे से आये, उनकी अधिकांश कर्मियों की सेवानिवृत्ति हो चुकी है जिनकी संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है । इन सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन के अतिरिक्त महंभाई भत्ता एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के लिये राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 (6) के तहत् छत्तीसगढ़ शासन को मध्यप्रदेश शासन से अनुमति की बाध्यता है । जिससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पेंशनभोगी कर्मचारियों को समय पर महंगाई एवं अन्य भत्ते और सुविधायें नहीं मिल पाती हैं। जिससे इनको तकलीफ होती है। यदि छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन की धारा 49(6) को विलोपित किया जाता है तो इस विसंगति को समाप्त किया जा सकता है । अत: उनके हित में यह निर्णय लें । ललित भानोट जो मध्यप्रदेश के कांग्रेस के एमएलए हैं उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव मध्यप्रदेश की विधान सभा में पास करा दिया है । अशासकीय संकल्प मैंने भी माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया है । अब यह आएगा या नहीं आएगा, मैं नहीं जानता । लेकिन इसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । एक लाख बुजुर्ग-बुजुर्ग कर्मचारी हैं । बंटवारे के टाइम 74/26 का जो फार्मूला रहा होगा, उससे उनको सुविधा मिल जाएगी और उन बुजुर्गों को आप थोड़ा सा सहयोग कर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता । मैं जान रहा हूं कि मैं अगर हवाई अड्डे की मांग करूं और आप मंजूर कर दें तो भी वह बनेगा नहीं । इसलिए मैं तो आपसे ऐसी दो मांगें करना

चाहता हूं जिस पर आपने यहां एक शब्द भी बोल देंगे तो जुलाई के महीने में वह तोहफा वहां की जनता को मिल जाएगा । उसमें एक लालपुर थाना, लालपुर धाम जहां आप हर साल जाते हैं, वहां पर आसपास के 50-60 गांव सतनामी बाहुल्य गांव हैं । बाबा जी ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार की बात भी कही थी । वहां एक मिनीमाता के नाम से या जैसा भी आप उचित समझें, एक शासकीय महाविद्यालय की घोषणा कर दीजिएगा, आज नहीं तो विनियोग में । दूसरा, लोरमी को नगर पालिका का दर्जा दे दीजिए । वह नगर पंचायत तो है ही, केवल दर्जा ही देना है । बोर्ड नगर पालिका का लगेगा, पूरा काम तो हो ही रहा है । उसमें भी कुछ खर्चा नहीं आएगा । ये दोनों घोषणाएं आप कर देंगे तो बड़ी कृपा होती। लोरमी की जनता की ओर से यह मांग आपके समक्ष प्रस्तुत है । मैं आपकी मांग का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभी माननीय सदस्यों को 10-10 मिनट का समय दिया गया है । कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में आपकी प्रमुख मांगें भी आ जाएं । श्री रामकुमार यादव जी ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मागों के समर्थन में खडे हौं ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- धर्मजीत भइया, अब तो न एती के डर हे न ओती के डर हे, तैं तो स्वतंत्र हस, तो तारीफ करे मा दिक्कत हे । विरोध काबर करथस ? मांगथस भी अउ विरोध भी करे ला धर लेथस ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तारीफ नइ करते रहेंव तो का करत रहेंव ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अइसने तारीफ करथें कहिके हमला का पता हे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री शिवाय नमः अइसने तो करे ला पड़थे ना । मैंने तो तारीफ की है, मैं चोरी छिपे कोई काम करता ही नहीं । अगर तुम बोलोगे कि पीते हो क्या, तो बता देंगे, तुम बोलोगे बीमार थे क्या तो हां बीमार है, तुम बोलोगे यहां जाते हो वहां जाते हो, तो जहां जाते हैं वहां का पता बता देंगे । आप चिंता मत करो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी, आपके एक माननीय मंत्री जी तारीफ तारीफ की बात कर रहे हैं तो बारह मंत्रियों में सबसे ज्यादा काबिले तारीफ मंत्री वही हैं । आज उनका नामकरण भी हुआ है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कल के ओखर सुतली बम के असर नइ गे हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अतना अच्छा प्रशंसा करे हौं । समसे सक्षम मंत्री हस ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन भइया दिखात रहिस हे । मैं बांच गेंव, बाजू मे रहेंव, दूसर जगह फट गे । मोर जगह फटतिस तो दिक्कत हो जातिस ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अउ तोरो पास दू झन हंस अउ डिंभक हे ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आज अइसे सरकार के सदस्य हौं । मैं अपन आप ला गौरवान्वित महसूस करथौं कि आज मोर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हे अउ मैं ओखर सरकार के सदस्य हौं । मैं ओ दिन ला भी याद करथौं जो 15 साल एमन राज करिन, यही छत्तीसगढ़ के खनिज सम्पदा ला लेकर, यही छत्तीसगढ़ के धन ला एमन 15 साल ले उपयोग करिन । अउ जो 15 साल मा नइ कर सकिन तेला मोर सरकार अल्प समय में 4 साल में करिस, अउ 4 साल मा 2 साल करोना खा दिस । तभो ले चार गुना करके दिखाइए, वो सरकार के मैं सदस्य हौं ।हमर पुरखा कहे हे छत्तीसगढ़ के पानी अउ छत्तीसगढ़ के जवानी एखर कोई तुलना नइ हे । ए छत्तीसगढ़ के पानी बर हमर पुरखा कहे हे कोस कोस मा पानी बदले, अउ पंद्रह कोस मा बानी । छत्तीसगढ़ में जतके कन नरवा हे, नाला हे, नदी हे, पहाड़ हे, पर्वत हे, यही तो ए प्रदेश के संपदा ए। 15 साल ले ए मन ला मौका मिलिए लेकिन ए मन गरीब ला अउ गरीब करीन, अउ कुछ लोग मन ला ए मन बड़े पईसा वाला बनाय के काम करीन। उही ला छत्तीसगढ़ी में कहावत कथय, भरे ला भेर अउ जुच्छा ला ढरकाय। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बात किया जाए, ए छत्तीसगढ़ के गौठान में महिला समूह मन ला काम करे के मौका मिले हे। हम टी.व्ही. समाचार में देखथन, कोई सीरियल देखथन, फिल्म देखथन ता बीच में प्रचार आथे, वाशिंग पाउडर निरमा, वाशिंग पाउडर निरमा। अउ ओ निरमा के कोन प्रचार करथे, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, उही मन प्रचार करथय।

श्री सौरभ सिंह :- तै बारात कब ले जाबे।

श्री रामकुमार यादव :- ठाकुर साहब जी। लेकिन आज मोर मुख्यमंत्री जी हा ओसने महिला समूह ला सर्फ बनाय के ट्रेनिंग देत हे, अउ आज ओमन ट्रेनिंग ले करके जे काम ला माधुरी दीक्षित हा प्रचार करथे, तेला मोर गांव के गरीबीन बहनी घलोक आज पाउडर ला बनावत हे, ए काम आज मोर सरकार ट्रेनिंग दे के काम करत हे। आज एमन फिनाईल बनाथे, ओ आजकल एखर पार्टी में एक झन हीरो आना जाना करथे, मैं नाम ला धरव नहीं, लेकिन धर भी देहां अक्षय कुमार जी हे। ओ काखरो घर ला ट्रीन ले घंटी मारथे, अउ जा के कथय आपके बाथरूम को बताओ, अउ कथय, अब इसको डालो, सफाई हो जाएगा। मोर सरकार धन्य हे अइसने सरकार। फिनाईल बनाय के काम करत हे। जेला एमन कभी सोचे नई रिहिस हे। हमर मन के पुरखा कहे गेहे, तेल के प्रकार के होथय, तिल के तेल, मूंगफली के तेल, जाड़ा के तेल अगर मैं गनत जाहां तो एक बेर हो जाही, ओतेक तेल के तेल निकाले जाथे। लेकिन एमन छत्तीसगढ़ के आदमी ला सबला ओमन ला बंद करे के करिस लेकिन मोर सरकार मोर भूपेश बघेल जी के सरकार गौठान में तेल पेरे के मशीन देत हे। अब हमन कोई उद्योगपति के तेल नई खान, मोर गांव के, मोर गौठान के, मोर बहनी के तेल पेरे ला खाबो। ए व्यवस्था हमर सरकार हा करत हे। ओखर बावजूद भी ओमन अतका विरोध करत हे। धीरे-धीरे मोर गांव के महिला समूह मन जागत हे, ओमन

सोचत हे, ओमन गुनत हे कि आज ए सरकार के अतेक कन विरोध करत हे, समय आन तो हमन बताबो। आज एमन के बात ला सुन करके ओमन महसूस करत हे। उपाध्यक्ष जी, आरक्षण के बात होईस। अभी मैं एखर मन के आरक्षण के बात ला सुनथव, आरक्षण ऐसा हो गया, आरक्षण वैसा हो गया। ए देश ला आजाद कराने वाला महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बिस्मिल्ला खां जी, ए देश ला आजाद कराईन। अउ आजाद कराय के बाद में अब देश कइसे चलही, तो ओ समय के अती पिछड़ी समाज ला, आरक्षण दे के बार करिस। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ला डायरेक्ट आरक्षण के बार करिस। अउ ए प्रदेश में, अउ ए देश में आरक्षण के व्यवस्था हे। छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत आदिवासी समाज, ओला 32 ठक कुर्सी, ए प्रदेश में एस.सी. वर्ग जे मन 12.44, 12 से कुछ ज्यादा अउ 13 से कुछ कम, ओमन के आरक्षण ला ए मन 12 करिन लेकिन मोर सरकार भूपेश बघेल जी ओला 13 करे के बात करिस। ओखर बाद ए पिछड़ा वर्ग हे। भारतीय जनता पार्टी हा सब जगह साहू समाज ला अपन वोट बैंक समझथे। बरेठ समाज ला एमन वोट बैंक समझथे। यादव समाज ला एमन वोट बैंक समझथे।

श्री शिवरतन शर्मा :- यादव जी, ए तोरे सरकार ए, हमर सरकार नई हे का गा। तोर अकेला के सरकार ए, हमर सरकार नई ए का। हमर सरकार अउ कोनो ए का।

श्री रामकुमार यादव :- बईठो ना महाराज जी। बईठा सरकार, बईठा बईठा। तुंहर सरकार ला 15 साल देखेन।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, ओ नई रूकने वाला, कुंआरा लईका ए।

श्री रामकुमार यादव :- उपाध्यक्ष जी, निषाद समाज, जेला एमन वोट बैंक समझथे, ओमन ला मात्र 14 ठन कुर्सी देवय।

उपाध्यक्ष महोदय :- सदस्य, आपस में संवाद ना करें, समय का महत्व है। आप लोग टोका टाकी ना करें।

श्री रामकुमार यादव :- मोर ददा हा गरवा चरात-चरात कहे रहिस हे, गांव भर के बरदी रथय, खईरखा रथय ओमा एक बीड़ा पैरा हा नई पूरय। जब 52 प्रतिशत, 48 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग होथय ओमन ला मात्र 14 ठन कुर्सी देवय, कइसे ऐमन ला पुरतिस, ओखर खातिर मोर सरकार हा ओला 27 प्रतिशत करिस। (मजों की थपथपाहट) एमन जा के राज्यपाल ला ओमा कोचे के काम कर दिस। पहली बार में ज्यादा पढ़े लिखे नई हंव, मैं बहुत कम पढे हंव लेकिन मैं अतके दिन ले कभू नई सुने रहेव, जेला विधान सभा में सर्व सम्मति से पास हो जाथे, ओला राज्यपाल में रूकथय करके, मैं आत तक नहीं सुने रहेव। लेकिन एमन पहली बार करके दिखा दिस। हम आज तक कहूं मेर नई सुने रेहेन, जहां विधान सभा में पास होथे, ओला राज्यपाल हा रोक करके तीन-तीन महीना, 6-6 महीना तक रोकथे, हमन आज तक नई सुने रेहेन। आज जब ए सदन मा कोई ला आपत्ति नहीं हे तो ओ आपत्ति करइया ला खोजे

जाए। ए छत्तीसगढ़ के जनता ऐला देखत हे। एमन ए सोचथे कि हमन एमेर तनक-तनक के भाषण ला देबो तो जनता हा हमर ऊपर विश्वास कर लीही। आप मन याद रखौ कि इतिहास गवाह है कि जेन-जेन भी छत्तीसगढ़ के जनता ला या भारत के जनता ला धोखा दे के काम करथे ओला आने वाला पीढ़ी कभी माफ नहीं करे। (मेजों की थपथपाहट) ऐमन ए बात ला याद कर ले। यदि छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के बात करे जाए तो हर प्रदेश के अलग-अलग स्वाभिमान होथे। हर प्रदेश के खाना-पीना होथे। एमेर कई झन विधायक अइसन हें जेमन का खाथे तो राजस्थानी खाना खाथे। ओमन के घर में जाके देखिहौ ता उछल-मंगल होथे तो उखर इहा का बनथे ता बाटी बनथे अऊ चुरमा बनथे लेकिन हमन छत्तीसगढ़िया आदमी हन, हमन खुश होथन ता हमन का खाथन? अंगाकर रोटी, पान रोटी, चरिहामस्का रोटी, ठेठरी रोटी, चीला रोटी। (मेजों की थपथपाह) हर प्रदेश के एक सम्मान होथे। ए प्रदेश मा छत्तीसगढ़ी बोली बोलथे। हमर दाई-ददा हा हमला छत्तीसगढ़ी बोली सिखाहे। लेकिन जब भी एमन ला देखिहौ तो एमन हमेशा छत्तीसगढ़ के बोली अऊ भाषा के, गेड़ी अऊ त्योहार के विरोध करथे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यादव जी, कल ते उंहा चाऊमिन खावत रहे हस।

श्री रामकुमार यादव :- ए महाराज जी के सीट मा कोई स्प्रिंग लगे हबे, ए घेरी-बेरी खड़े होत रहीथे। उपाध्यक्ष जी, आप ओखर थोड़ा जांच करा देहौं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काखरो विरोध नहीं होना चाहिए। का होथे? आज हमरे प्रदेश के सम्मान होथे। पहिली जब हम जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई कमाए-कोड़े बर जावन ता हमन छत्तीसगढ़ के हरन कहान तो कोई नहीं जाने। लेकिन आज हमन छत्तीसगढ़ के आदमी हरन, कथन ता कहिथे अच्छा, आप उसी प्रदेश के हो जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक नंबर काम कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) अइसे में हमर छाती हा अऊ चौड़ा हो जाथे अऊ एमन के राज में का होवे? ए बात ला आज पूरा प्रदेश हा देखत हे। यदि बात करे जाए कि आज जिस प्रकार से हमर सरकार काम करत हे, पहिली जमाना में काए रीहिस हे कि 15 साल के सरकार में, एमन गरीब आदमी के ऊपर ध्यान नहीं देवें। अभी हमर सरकार नदी के किनारे विद्युतीकरण करत हे। जइसे नदी तो बहुत हें, नदी के तीर मा खंभा लगा दीही तो ओ किसान आदमी के खेत मा एक पानी, दू पानी के लिए धान हा मर जाथे, ओमन ऊहा से मोटर लगा के धान में पानी पलो डारही। ए कतका सुंदर योजना हे। आज हमर मन के चंद्रपुर क्षेत्र मा महानदी के धारा बोहोहे लेकिन हमन ए पानी ला एक बूंद नहीं पावत रहे हन लेकिन जब मोर मुख्यमंत्री जी हा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गे रीहिस तो मैं अऊ मोर क्षेत्र के जनता निवेदन करीस अऊ कहीस तो आज मोर क्षेत्र मा विद्युतीकरण के लिए आज उहा जेमा 3000 एकड़ जमीन हा पलही, आज ओखर व्यवस्था ला करे लेकिन ए मन हमेशा ओखर विरोध करथे। आज मैं एक ठन अऊ बात कहना चाहत हो कि जइस मे पहिली रहे हवो मैं जानथो काबर कि मैं गांव के रहवइया हरव। बिजली

बिल हा नहीं पटे रहाय अऊ गरीब आदमी खात-पियत घर में रहाय अऊ साग-भात ला साने रहाय ततकी बेर ऐखर लाइन मेन मन जावे, हलो-हलो, सुनो गांव वालो, जो बिजली बिल नहीं पटाया है उसको पुलिस ऐसे करेगी ता गरीब हा भात ला खावत रहाय ओला ढकेल देवै अऊ कहाय फलानीन, ए बिजली बिल ला पटाबो ता हमन ला जेल हो जाही कहाय। एमन अतका दु:ख देहे अऊ आज एमन घड़ियाली आंसू बोहाथे, आज एमन इंदिरा आवास के बात करथे। मैं इंदिरा आवास में रहने वाला व्यक्ति ओ अऊ गरीब आदमी ओ। गरीब के बात ला मैं जानथो, एमन का जानही? गरीब कइसे होथे तेला एमन खाली पढ़थे अऊ पढ़ के आके इहा भाषण ला देथे। गरीब के बात ला एमन का जानही? इंदिरा आवास तो कांग्रेस सरकार हा हमर जमाना में लइका रहे हन, जे समय हमन चड्डी-बनियान में किंजरन, ते समय के जानथन कि इंदिरा आवास का होथे तेला। पूरा केन्द्र के सरकार देवै। अभी पढ़ के मुड़ मा नौ सियान। हमन देबो अऊ एमन सियानी मारही। फिर भी मोर सरकार ए व्यवस्था बना हे। बात किया जाए तो बहुत सारा हे। अंत में मैं एक ठन बात कहिहौ कि मैं छोटे रहे हो ता एक ठन तमासा देखे रहे हवौ, ओला कहते हुए अपन बात ला समाप्त करिहौ काबर कि एमन असत्य बोलथे ता एमन ला आधा-आधा घण्टा समय मिलथे अऊ सही गोठियाथन तेला आप 10 मिनट देथो। हमन ए असत्य ला कतका सहिबो?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामकुमार भाई, इंदिरा आवास में रहते ता सियानी ला लेन ना। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मेरा सभी सदस्यों क लिए एक सा व्यवहार रहता है। पक्ष-विपक्ष दोनों के लिए समय रहता है। मैं सभी सदस्यों को समय दे रहा हूं। मैंने तो अभी तक आपको टोका भी नहीं है। आपको जितनी देर बोलना है, आप बोलिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब सदस्यों को पूरा समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- क्या आपको भी समय दूं ?

श्री रामकुमार यादव :- उपाध्यक्ष जी, पहिली हमन छोटे रेहेन त गांव में तमाशा होवय । सांप धरे रहाए अउ डबडीब, डबडीब, डबडीब बजावय । सुनहौ थोड़ा सा, ये तुहर मन बर हे । ओ आकर बोरा ला बिछा देवय अउ कहाए कि आईए, सांप और नेवला लड़ेगा, ये ओकर बात रहाय । हमन नान, नान रहान, आगू मा बइठे रहान की सांप अउ नेवला लड़ही करके अउ ओ ह दवाई ला बेच डरय, ओ हमर चाऊंर ला ले लेवय, लेकिन सांप और नेवला ह नहीं लड़य । उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी कहाय कि मैं काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रूपए डालूंगा । अउ कहिस कि नोटबंदी करेंगे । हमू सोचे रेहेन कि बड़े-बड़े आदमी के पइसा फंस जाही, सबके पइसा बुलक गे हमरे जईस गरीब आदमी ह लाईन में लगे रहान, जैसे हमर मेर काला धन हे । आज उसी प्रकार ले न कभू सांप अउ नेवला लड़िस नहीं, अउ एमन कभू काला धन ला लानय नहीं, एमन बोलिन कि काला धन लाबो, काला धन लाबो करके । इसी प्रकार ले मैं अपन मुख्यमंत्री जी ला शाबासी देवथौं, जुग-जुग जीयय अउ

छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता तरफ से मैं नमन करते हुए अपन वाणी ला विराम देवथव । आपला बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री पून्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज विभाग के संबंध में बोलना चाहूंगा । डी.एम.एफ. फंड की जो राशि है, वह राशि जिस जिले में उस फंड में जाती है तो एक काम के लिए दो, तीन करोड़ रूपये स्वीकृत किया जाता है। मैं उस काम का नाम नहीं बताऊंगा । ग्रामीण क्षेत्र है, जिस एरिया में लोगों को जरूरत है चाहे वह सी.सी. रोड़ हो, गली हो या छोटे काम हो, जो 10 लाख, 20 लाख, 5-6 लाख रूपये के काम में या सामुदायिक भवन में स्वीकृत होता है । ऐसे कार्य के लिए अधोसंरचना मद में पिछले वर्ष मैंने मुख्यमंत्री जी से उनके भाषण में आश्वासन चाहा था और राशि को बढ़ाने की मांग की थी तो उस राशि को इतना प्रतिशत बढ़ाया जाये, जिससे गांवों या शहरों में ज्यादा काम हो । बड़े काम हो तो वह बजट में दिया जाये । चाहे वह पीडब्ल्यूडी हो या अन्य विभाग हो तो बड़े काम बजट में दी जाये, जिससे ग्रामीणों के काम की स्वीकृति होगी और काम की बढ़ोत्तरी होगी, यह मैं कहना चाहता हूं । यह सभी क्षेत्रवासियों के लिए है । उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेली छोटा जिला है, उस जिले में खनिज मद की राशि कम है, उस जिले में राशि दी जाये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। बिजली विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय कहते हैं कि बिजली का बिल हमने हाफ किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी थी कि 400 यूनिट तक बिजली का बिल माफ है । जब 400 यूनिट तक बिजली बिल माफ है तो तो फिर हाफ कहने की आवश्यकता नहीं है? मैं यह कहूंगा कि अगर कोई किसान है या उपभोक्ता है उसका बिजली का बिल ज्यादा आता है और बिल ज्यादा आता है तो वह दे नहीं पाता, उस समय वह परेशान हो जाता है । जब तक वह उपभोक्ता बिजली का पूरा बिल नहीं देगा तो माफी योजना में उसकी कटौती नहीं होती । इसको रोका जाये । उसका जितना बिल है, उतना माफ होना चाहिए । अगर वह तीन महीने रूक गया तो जब तक तीन महीने का पूरा भुगतान नहीं होता तो न उनका बिजली का बिल माफ होता, न वो पैसा पटा सकता है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बबा, सुनना । हमन चुनाव के समय नारा लगात रेहेंन कि किसान के कर्जा माफ और बिजली के बिल हाफ । तो बिजली के बिल हाफ होगे । अब तोला चार महीना बिल ला मत पटा, अईसे थोड़े बोले हन । तै हर महीना पटाना, तब तो तोला छूट मिलही ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो । 400 यूनिट तक ही बिजली बिल माफ है, आप मेरी बात समझ लीजिए । हाफ नहीं है, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे । जो गरीब बिजली बिल पटा नहीं सकते, उनको राहत दी जाये ।

सुश्री शकुन्तला साहू :- बबा, तोर बिजली बिल माफ हाईस कि नहीं, ऐला बस बता दे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मुख्यमंत्री जी ह तोला सीखो दे हे का । मुख्यमंत्री जी, शकुन्तला ला सीखो दे हस का, जब मैं बोलव त शकुन्तला खड़े हो जाही ।

सुश्री शकुन्तला साहू :- बबा, तोर बिजली बिल माफ हाईस कि नहीं, तेन ला बताना गा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- शकुन्तला बोलथे तो तोर बोलती काबर बंद हो जथे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- काबर बोलती बंद होही, मैं झगड़ा तो नहीं करे हंव ना।

श्री उमेश पटेल :- तैं सब करबे, बंबूज, बंबूज मत करबे । प्वाइंट ला तै बंद चालू मत करबे न भई (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- बबा, शकुन्तला तोला काबर ज्यादा टोकथे । आज शकुनतला तोला बहुत टोकथे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ओला मैं का जानव । (हंसी)

श्री कुलदीप जुनेजा :- तोर बिजली बिल माफ होईस या नहीं, ऐला तैं शकुन्तला ला बता दे। ओ ह वही चीज तोर से पूछथे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं नहीं सुन पाएव ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बबा, तै ह 10 ठी घर राखबे तो कतेक माफ होही।

श्री कुलदीप जुनेजा :- कोन कोन घर के बिजली बिल माफ होएहे, कोन घर के बिल माफ नहीं होएहे, वहू ला सबला बता दे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि अभी तक 5 हजार किसानों को स्थाई पम्प कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि वह सबको पम्प कनेक्शन दें। कुछ ऐसे भी किसान होते हैं, जो गरीब होते हैं। एक लाख से ज्यादा राशि विद्युत खम्बे के लिए, कनेक्शन हेतु राशि जमा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन किसानों के ऊपर ध्यान देंगे ताकि उनका कनेक्शन लगे। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, जिनको 5-7 खम्बे लगवाना होता है। ये खम्बे लाईनवार लगते रहता है तो लग जाता है। यदि खम्बे नहीं लग पाते हैं तो किसान परेशान हो जाते हैं और वह किसान विद्युत कनेक्शन लगा ही नहीं पायेगा। केवल अस्थाई कनेक्शन से ही काम चलाते हैं। उसमें एक और परिस्थिति है। उसमें भी लोगों का बिल ज्यादा आ जाता है। 6 हजार यूनिट या जितना यूनिट माफ है, तो उन परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर में मीटर हो। यदि मीटर नहीं होगा तो कैसे बिल बनेगा ? कितना बिल बना, कैसे जानकारी हो पायेगा। ये अंदाजी बिल देते हैं। तो अंदाजी बिल समाप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे कि उनको किस तरह से बिल मालूम हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव में पहले से खम्बे लगे हुए हैं। कई खम्बे 15-20 साल पहले से लगे हैं, वे टूट गए हैं, खराब हो गए हैं। खम्बों के तार खराब हो जाते हैं, उससे लोगों को बिजली नहीं

मिल पाता। पहले सरप्लस बिजली था, अब चार घंटे बिजली की कटौती होती है। ऐसे तार को बदलने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं कि यहां ऐसा नियम नहीं है। उसमें भी राशि दी जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में बिजली बिल, जिनके पास सिंगल कनेक्शन है, उसको 40 वॉट तक माफ है, उसको बढ़ाया जाये। इन परिस्थितियों में लोगों को सुविधा मिलेगी, मैं ऐसी आशा करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं खनिज विभाग में बात करूं। गांव वाले मुर्रूम और रेत उपयोग करते हैं, ग्राम पंचायत उसका उपयोग करती है तो ऐसे लोगों को खनिज विभाग के अधिकारी लोग पकड़कर ले जाते हैं और एक ट्रेक्टर पर 20 हजार रूपया जुर्माना लेती है। उस जुर्माने की राशि को घटाया जाये। कीमत 4 हजार रूपये होती है, 8 हजार रूप्ये की वसूली हो रही है, 16 हजार-20 हजार रूपया नही दे पाते तो उनको कोर्ट भेज दिया जाता है। इससे उन लोग परेशान हो जाते हैं उससे उन लोग समय पर खेती-किसानी नहीं कर पाते, जिससे उनको तकलीफ होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे, ऐसी आशा करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि मुंगेली जिले के जरहागांव भी गये थे, वहां पर लोगों ने मांग किया था तो मैं वहां के लिए महाविद्यालय की मांग करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर ध्यान देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रस्ताव दीजिये। इसी प्रकार भालापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भारत महान है। क्योंकि मेरे देश की पहचान है, वह किसान है। हमारे मुखिया जहां से आते हैं, वे भी एक किसान पुत्र हैं। ऐसे हमारे मुखिया के विभाग की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देती हूं। उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले भेंट-मुलाकात की बात करूंगी। क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी पूरी चर्चा में भेंट-मुलाकात की बात की चर्चा की है। हमारे आदरणीय मुखिया जी, माननीय भूपेश बघेल जी ने भेंट मुलाकात की।

अब मैं छत्तीसगढ़ी मा आ जाथव।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपकी जो मर्जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात करे बर गइस तो इनखर पेट मा काबर दर्द होइस ? हमर माननीय मुखिया जी हा, हमर मख्यमंत्री जी हा भेंट-मुलाकात करे बर पूरा छत्तीसगढ़ राज्य मा दौरा करिस हे। मैं तो बोलथव कि ये छत्तीसगढ़ राज्य

मा पहला मुख्यमंत्री नहीं, पूरा देश मा पहला मुख्यमंत्री हे, जो भेंट-मुलाकात करे हे। (मेजों की थपथपाहट) पूरा प्रदेश मा जाकर क्षेत्र के जनता से रूबरू होय हे, उहां जनता के समस्या ला सामने मा खड़े हो के उनखर जो-जो समस्या आय हे, ओखर निराकरण करे हे। ओमा कहीं भेदभाव नहीं आय हे। वहां पर सिर्फ मंच लगाय हे, चेयर मा बैठे हे अउ वहां आ के कोई भी व्यक्ति आ के अपन क्षेत्र के बारे मा बोलत हे। बीच मा विपक्ष के साथी मन कहत रहिस हे कि घोषणा नहीं करे हे। मैं हा तो निकाल के भी लाय हव कि मोर क्षेत्र के शिवेन्द्र कुमार साहू पिता भोलराम हे, ओ हा एम.बी.बी.एस. करत रहिस हे। बहुत गरीब परिवार के बच्चा हे, एम.बी.बी.एस. करे बर पैसा के जरूरत रहिसे, हमर मुखिया हा तुरंत दो लाख रूपया दे हे, वो बच्चा पढ़ाई करथे अऊ वोहा डाक्टर बन के आही । अइसने हमर कमलेश निषाद जी है, जेखर पिता दामनलाल ए, एहा सिवनी के हरे, एहा ओलम्पिक राष्ट्रीय खिलाड़ी हे, वोभी बहुत गरीब तबका के हरे, वोला 4 लाख रूपया दे हे, ऐसन हमर भेंट मुलाकात हरै, उपाध्यक्ष महोदय जो हमर में काबिलियत हरे, एखर में नई ए कि जाके मुलाकात करैं, मोदी जी में भी काबिलियत नहीं हे कि प्रेस वार्ता करे । उपाध्यक्ष जी, मैं विद्यत बिजली के बात करहूं, आज के हमर जो जनरेशन है, आज के जो परिवेश है, वोमा बिजली बहुत महत्व रखथे । बिजली के बिना एक मिनट भी रहना हमर लिये नामुमकिन है । वो बिजली 15 साल में हमन देखे रेहेन, थोकिन हवा भी आये, तूफान भी आये त दो दिन के लिये लाईट गोल रहाय । आज हम देखथन तो पूरा तरफ लाईट ही लाईट हे । आप चौक चौराहा में भी जाके देखो तो पूरा विधान सभा में लाईट ही लाईट रहिथे । कहीं पे अंधेरा नई ए । जंगल में जहां बिजली खंबा भी नई रिहिस उंहा लाईट हावय, अइसन हमर मुखिया हरै । ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली बिल हाफ होय हे, जहां बिजली के व्यवस्था नई रिहिस वहां बिजली बिल हाफ होय हे, घोषणा पत्र के दूसरा नंबर के रहिसे । उपाध्यक्ष महोदय जी, हमर विपक्ष के साथी मन चैलेंज करिस, जब बिजली बिल हाफ होइसे, हमर प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय चंदेल जी के हे रहिसे, जब मैं जात रेहेंव त लाईट जलथ रहिसे, लट्टू जलत रहिसे, कंडिल धर के देखाय हंव, लाईट हा जलत है कि नहीं । ये बात होय रहिसे । वो बात ला मैं अभी तक याद करथंव । इतना भी मत फेंको कि पचे मत । आप भ्रष्ट्राचार के बात करो, विपक्ष के बात करो, हमर विरोध करो, लेकिन इतना मत फेंको कि जनता के विश्वास उठ जाये । नई झोंकाय तैसे मत फेंको ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नेता जी, पूरा सुनथ हस न ।

श्री अमरजीत भगत :- शुरूआत कोन करे रिहिस । शुरूआत तो आप करे रेहेव ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नेता प्रतिपक्ष बन गे हे, अब नई फेंकय । जतका फेंकिन ततका फेंक डरिन ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- अनलिमिटेड हे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- काबर कि सही चीज ला झुठलाय बर भी विरोध करे जथे ।

श्री उमेश पटेल :- नेता जी, जबसे नेता प्रतिपक्ष बने हे, तब से अपने संम्हारू को भूल गये हैं ।

श्रीमती संगीता सिनहा :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, बिजली बिल हाफ होय हे, 2019-2020 में 9 करोड 77 लाख रूपया के वर्ष 2020-2021 में 8 करोड़ 50 लाख, 2021-2022 में 90 करोड़ रूपया, वर्ष 2022-2023 में 10 करोड़, 96 लाख 34 हजार रूपये के लाभ छत्तीसगढ़ के 48 लाख लोगन ला प्राप्त होय हे । ए बिजली बिल हाफ योजना के लाभ ए । वर्ष 2022-2023 के बजट में 1115 करोड़ के प्रावधान ए, 2023-2024 के योजना में 1050 करोड़ के प्रावधान हे, जो बी.पी.एल.उपभोक्ता ए, जेला बहुत जरूरत हे, जेखर मेर बहु कमी रहिथे, बी.पी.एल. के जो हमर साथी मन हे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ला प्रत्येक माह 30 यूनिट के नि:शुल्क विद्युत प्रदान किये जाथे, जो कि बहुत ही सराहनीय हे । साथ में राज्य शासन द्वारा 4 वर्ष के लिये करोड़ों रूपया के अनुदान दिये जाथे । वर्ष 2023-2024 में ए योजना म 508 करोड़ के बजट प्रावधान हे । भूमिहीन किसान योजना हे, गोधन न्याय योजना हे, सब के लिये प्रावधान हमर सरकार हा रखे हे । एखर लिये हमर सम्मानीय मुखिया ला बधाई देवथंव । ग्रामीण तबका के जो लोग हैं ओ मन ला फायदा महसूस होही, लाभ होही। साथ में जो 2023-24 का जो पूरा कम्प्लीट बजट है, उसमें कुल 21 हजार 788 करोड़ का प्रावधान है। मैं इतना कहना चाहत हव कि हमर जो विपक्ष के महोदय जी मन हा भ्रष्टाचार की बात करथे तो कल ही हमर जो गृहमंत्री रहिसे, जब राजिम कुम्भ के बात चलिस, राजिम कुम्भ के भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहत हव। राजिम कुम्भ हे वो 13 करोड़ की राशि में वो कार्यक्रम होये हे। अब राजिम माघी पुन्नी मेला, 3 करोड़ में होवथे। मतलब हम ला कम्प्लीट 10 करोड़ के बचत होये हे। यह बहुत बड़ी बात है। जितना खर्च होथे, हम जनता के राशि ला उचित उपयोग करथन और भ्रष्टाचार तो इकर 15 साल में होये हे। अगर राजिम कुम्भ में 13 करोड़ की राशि खत्म होथे, तो भ्रष्टाचार होथे। वो तो जनता के पैसा हे का। वो तो 13 करोड़ रूपया जनता के पैसा हे, तेला ऐसे उड़ा देथे, जेला बाहर से जो भी कार्यक्रम करिसे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, हमर जो मुखिया हे ओ हा जनता के हित के लिये कार्य करथे। वइसने जनसंपर्क के लिये पत्रकारों के लिये आवास निर्माण करे बर बड़ी मुश्किल होथे, आवास निर्माण के लिये भी प्रावधान रखे हे। साथ में 6 सौ करोड़ के सौर उर्जा के प्रावधान है। अब हर जगह सोलर लाइट लगथे अऊ हमर पूरा छत्तीसगढ़ राज्य चमकथे। हमर लखमा जी ओ चैन ला निकालिस तो याद आ गिस। ये मन भ्रष्टाचार के बात करथे, जो भ्रष्टाचार करथे ना ओकर आंख में पट्टी रहिथे। ओला बांस के माला भी सोना दिखाई देथे। ऐसे हमर विपक्ष के साथी हे। जो भ्रष्टाचार से निकले हे, जो भ्रष्टाचार वो करहे हे, हम ला अनुसरण करने के मौका मत दे। मे हा समर्थन करते हुए अपन वाणी ला विराम देथो, जय हिन्द।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद्।

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्। श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदा-बाजार) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों की चर्चा पर खड़ा हुआ हूं। आपने 10 मिनट का समय दिया है लेकिन 9 विभाग है, यदि सब में दो-दो मिनट भी बोला जाए तो 18 मिनट होते हैं। मैं सबसे पहले ऊर्जा विभाग के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। यह सरकार बोलती है कि यह किसानों की सरकार है। आज आप हर डी.सी. में जाकर देख लीजिये, जहां किसानों के पम्प कनेक्शन ज्यादा है। पहले जिस डी.सी., विद्युत केन्द्र में 2 हजार, 3 हजार कनेक्शन होते थे, वहां आज 200 कनेक्शन के लिये भी लाइन लगाना पड़ रहा है। सीधी-सीधी बात है कि किसान को किसान समृद्धि योजना में सरकार के द्वारा जो 60 हजार की छूट मिलती थी, वह छूट, छूट नहीं है सिर्फ एक बहाना है। सरकार योजना को बंद नहीं कर रही है। यदि यह योजना को बंद कर देगी तो वह किसान विरोधी सरकार कहलायेगी। लेकिन सरकार किसानों को पैसा नहीं देना चाहती। यह सरकार किसान का किसी प्रकार का भला नहीं चाहती है इसीलिये उसको अटका कर रख दी है। हर विद्युत केन्द्र में कम से कम 3-4 हजार आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज विद्युत मंडल की स्थिति इतनी खराब है कि जब से छत्तीसगढ़ बना है, तब से लेकर अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि यदि ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़े तो उसके लिये सालों-साल इंतेजार करना पड़ता था। आज यह स्थिति है कि यदि गांव में वोल्टेज की समस्या हो जाये यदि 63 की जगह 100 का ट्रांसफार्मर लगाना पड़े तो वहां कम से कम 6 महीने इंतेजार करना पड़ता है, विद्युत मंडल की यह स्थिति है। विद्युत मंडल की स्थिति खराब करने में सबसे बड़ा हाथ यहां के सबसे बड़े अधिकारियों का है। मैं नहीं जानता इसमें क्या स्थिति है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा स्थिति बिगाड़ने में हाथ अधिकारियों का हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको, जिसको 34 सौ करोड़ रूपये का ..।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, तू अधिकारी मन के बड़ विरोध करथे। वो हा काबर ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अधिकारी मन ही सब हवय। ये अधिकारी ही है जो लड़वाये-तुड़वाये वाले काम करथे। ऐ मन कोकरो नहीं हे, ये बात याद रखो। ये पार, कोनो पार बैठही ता ओ कति हो जाही। ओ मन बाजा वाला हन, बाराती वाला नहीं हे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको 34 सौ करोड़ रूपये के विद्युत शुल्क की छूट दी गयी है। 2001 से 2016 की उद्योग नीति की बात करना चाहूंगा । भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वर्ष 2013-14 से बालको कंपनी का यह आवेदन लंबित पड़ा हुआ था और पता नहीं, ऐसा क्या हुआ ?इस कार्यकाल में इस सरकार में उनको 3400 करोड़ रूपये छूट दी गई है। अगर किसी गरीब का बिल ज्यादा आ जाये 5 हजार रूपये, 10 हजार रूपये आ जाये तो सरकार के पास

इसके लिए कोई योजना नहीं है कि उनको किसी प्रकार की छूट दें। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कंपनी के हित में छूट भी दे दी तो आपको बताना चाहूंगा वर्ष 2005 से 2020 तक इन 15 सालों के लिए बालको कंपनी को विद्युत उत्पादन में छूट दी गई, लेकिन इस बीच में वर्ष 2005 से 2007 तक डेढ़ सिर्फ तकनीकी फाल्ट के कारण यह कंपनी बंद थी और इन डेढ़ सालों के दौरान बिजली की जो छूट मिलनी थी, वह कंपनी वाले लोग धोखाधड़ी से विद्युत मण्डल से लिए। यह बहुत बड़ा अपराध है अगर आर्थिक अपराध शाखा में इनके नाम से कम्प्लेन करें तो इनके नाम से एफ.आई.आर. भी होगी और कंपनी के जो सी.ई.ओ. हैं जो विद्युत मण्डल को गलत जानकारी देकर, जो लाभ उठाएं हैं इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। यह हो सकता है कि वह अंदर में क्या खेला हो, यह पता नहीं है, लेकिन डेढ़ सालों तक कंपनी में केप्टिव प्लांट है इनको अपने उत्पादन के लिए विद्युत शुल्क दिया गया था जब कंपनी बंद थी। जब वह पॉवर प्लांट चालू था तो अन्य राज्यों में बेचकर, उसका पैसा कमाये और लगभग 200 से 300 करोड़ रूपए का सीधा-सीधा चूना लगाए।

श्री शैलेश पाण्डे :- आज बहुत अच्छा लग रहा है माननीय प्रमोद भाई आबकारी से ऊठकर ऊर्जा में कुछ कह रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं यहां ऊर्जा विभाग के बारे में 1 घण्टा पोल खोल सकता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इससे पहले ठेकदार भी था।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अउ ऊर्जा विभाग के पूरा लोचा ला जानत हे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- कहां ले गड़बड़ होवत हे, तेला भी जानत हे।

श्री शैलेश पाण्डे :- वह सारे लोचा को जानते हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :-पूरा लोचा ला करके आए हे। पूरा लोचा ला जानत हे।

श्री शैलेश पाण्डे :- लेकिन कल आपने आनंद में भाषण दिया, आज आप वैसा भाषण नहीं दे रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं। मैं गंभीर होकर कर रहा हूँ।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप गंभीर हो जाते हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यहां अब भाषण देने से कुछ थोड़ी होना है।

श्री शैलेश पाण्डे :- कल आपने कितना, क्या-क्या किया ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय पाण्डे जी, आप भी जानते हैं कि भाषण देने से कुछ नहीं होना है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपने एफ.आई.आर. का नहीं बोला था।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन 4 सालों में देख डाला कि यहां कुछ नहीं होता। हम लोगों को उम्मीद थी कि ...।

श्री शैलेश पाण्डे :- आज आपने 26 एफ.आई.आर. का भी नहीं बोला।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय पाण्डे साहब, आपस में संवाद न करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारी उधर सुनते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां भाषण देने से कुछ नहीं होना है। सिर्फ अपने मन को ठण्डा करते हैं, तसल्ली देते हैं कि कुछ हो, क्योंकि उधर जो बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अपने आप में संतुष्टि लगती है, लेकिन इसमें होगा। माननीय पाण्डे जी, मैं आपको बता दूं कि मैं आर्थिक अपराध शाखा में इस सी.ई.ओ. के खिलाफ जाऊंगा चाहे मुझे हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। इसमें यह सदन एक्शन नहीं करेगी, लेकिन कोर्ट तक इसको ले जाऊंगा। मैं आपको इसके लिए वायदा कर रहा हूँ। मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदयस, आज खनिज विभाग में डी.एम.एफ. के बारे में बोलना चाहूंगा। बलौदा बाजार जिले में 80 से 100 करोड़ रूपए के डी.एम.एफ. मद की राशि है, जिसमें बलौदा बाजार जिले में सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र कोई आता है तो मेरा विधान सभा का क्षेत्र आता है, जिसमें 36 गांव प्रभावित हैं। डी.एम.एफ. मद का एक नियम भी है कि जो गांव प्रभावित रहेगा, उसकी 50 प्रतिशत राशि उस गांव में खर्च करना है। बलौदा बाजार में सिर्फ डी.एम.एफ. मद की राशि का स्वार्थपूर्ण बंटवारा किया जाता है। पता नहीं, कहां से रायपुर से ठेकेदार आते हैं, किसके द्वारा आते हैं यह नहीं मालूम। अब ज्यादा भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बलौदाबाजार में डी.एम.एफ. मद की राशि का फुल दुरूपयोग हो रहा है तो हमारे यहां हो रहा है। वहां जिला पंचायत के एक को डी.एम.एफ. की राशि के लिए अधिकृत कर दिया गया है। अपने हिसाब से चाहे जिस गांव में हो, चाहे 2 करोड़ रूपये का हो, चाहे 4 करोड़ रूपये का हो, अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं मतलब कुछ नहीं होना है। आपसे थोड़ा निवेदन है कि आप जांच करवा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर डी.एम.एफ. की राशि का बहुत ही स्वार्थपूर्ण बंटवारा हो रहा है। आपसे निवेदन है कि कम से कम इतना खुलापन अति मत हो। थोड़ा सा पर्दा के पीछे हो जाए। हम लोगों का लिहाज कर लिया जाए। हम लोग को डी.एम.एफ. की राशि का मालूम भी नहीं होता। मेरे क्षेत्र में मेरे एरिया का पैसा कहां-कहां जा रहा है, यह कुछ पता ही नहीं चलता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विद्युत मण्डल की बात हुई। मैं आर.डी.एस.एस. स्कीम का बताना चाहूंगा । आर.डी.एस.एस. स्कीम में भारत सरकार के द्वारा यहां जो योजना चलाई जा रही है जिसमें नये ट्रांसफार्मर लगेंगे, नया केबल लगेगा, नया सब स्टेशन लगेगा, जिसमें केन्द्र सरकार का 60 प्रतिशत, विद्युत मण्डल का 30 प्रतिशत और राज्य सरकार का 10 प्रतिशत का हिस्सा होता है। इसके टेण्डर की प्रक्रिया का बताना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमारे धरम लाल कौशिक जी भाषण दे रहे थे, माननीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी यह बात बोल रहे कि छत्तीसगढ़िया को ठेका मिला गया तो

आपको तकलीफ हो रही है। माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूंगा कि इस स्कीम में R.D.S.S. स्कीम में छत्तीसगढ़ का कोई लोकल ठेकेदार भाग नहीं ले पा रहा है। यह छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है, छत्तीसगढ़ की सरकार है। इसका नियम ही ऐसा बनाया गया है ताकि जितने बाहर के ठेकेदार हैं इसमें आकर competition करें और यहां वाले को ठेका न मिले। माननीय मंत्री जी ये स्थिति है। अगर आप चाहेंगे तो आप दिखवा भी सकते हैं। ये ऐसा पैकेज बनाया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- प्रमोद शर्मा जी, जोन किसान मन ला हे, ओ मन ला तो धान के पैसा मिलत हे, जो किसान धान नई बेचत हे, ओमन ला भी न्याय योजना के पैसा मिलत हे। गांव में पंडित, पुजारी मन ला मिलत हे। ओमे तोरो नाम हे ना?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- एखर बर सब ला बधाई के पात्र हो। लेकिन मैं जेन कहत हंव तेन सत्य बात हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पम्मू, पौनी-पसारी वाला मा महाराज मन ला भी आथे। जो कथा कहते हैं न।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- कोरोनाकाल में बेचारा मन भूख मरत रहिस हे। एक झन कोई सहयोग नई मिलिस।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चिंता काबर करत हस। ओकरे सेती तो भैया 7 हजार रुपये देत हे। नाम भेज, तुरंत ओला जोड़े जाही।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ब्राम्हण विरोधी सरकार हवै ऐहा। आरक्षण ला नई देव, 10 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर देव, ओकर बात कहत हस।

श्री शैलेश पांडे :- नामी महाराज हे, इसके ऊपर 26 एफ.आई.आर. हे।

श्री अमरजीत भगत :- पूजा के मंत्र जानथस कि नई। ओम गण-गणपतै नम:। ये कुछ जानथस कि नई ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपस में संवाद न करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, R.D.S.S. स्कीम के तहत लोकल के जितने छोटे-छोटे ठेकेदार हैं जिनके अंदर छत्तीसगढ़ के मजदूर लोग काम करते हैं, इनकी अवहेलना करके ऐसा बड़ा-बड़ा पैकेज बनाया गया है ताकि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग आकर यहां ठेकेदारी करें और छत्तीसगढ़ वालों को कोई प्रकार का लाभ न मिले। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सिर्फ ये टेंडर को देने के लिए 5 प्रतिशत लिया जा रहा है। यहां वालों का पता नहीं, लेकिन ये जो टेंडर हो रहे हैं इसमें 5 प्रतिशत की राशि वसूली जा रही है। विद्युत मंडल में इतना भ्रष्टाचार है। मेरे पास शब्द नहीं है, इतने सारे भ्रष्टाचार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें, आपका समय हो गया।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अभी तो 10 मनिट नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- 10 मिनट हो गया है। चलिये, 1 मनिट में अपनी बात कहकर समाप्त करिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विमानन विभाग के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रायपुर में जो एक प्लेन सड़ रहा है, उसको हमारे बलौदाबाजार में स्थापित कर दें ताकि एक शो-पीस घूमने के लिए हो, बच्चों लोगों को देखने के लिए काम आ जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय पर अपना भाषण खत्म कर दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों की और इधर-उधर की बात नहीं करूंगा। जिस तरह से प्रदेश में प्रशासनिक सौन्दर्यीकरण करने के लिए जिलों का निर्माण हुआ। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस नवीन जिले से हम लोग आते हैं और जिस विधान सभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां हमारे लोगों की लगभग 40 सालों की मांग थी कि उस पूरे क्षेत्र को जिले के रूप में पहचान मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में जिले का निर्माण किया। क्योंकि वहां क्षेत्र के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि 40 साल पहले जिन लोगों ने जिला बनाने के आंदोलन में लगभग 6-6 महीने जेल की सजा काटी थी। एक प्रकार से विस्मृत कर दिये थे कि यह कभी हो पायेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में नवीन मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को जिले के रूप में सौगात दी। यह निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी मांग पूरी हुई। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा आज हमारे एक वरिष्ठ सदस्य मुझे बोल रहे थे कि ये नवाचार आयोग क्या है ? इसमें कहां कोई बजट का प्रावधान है। केवल बातों को बोलने से कुछ नहीं होता या केवल आलोचना करने से कुछ नहीं होता। आप यह बताईये कि गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि कृषि मजदूर योजना, नरवा, घुरवा, बाड़ी योजना, आज यह जो योजना है, इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। सभी लोगों ने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि जो हमारे भूमिहीन कृषक हैं, उनको किस प्रकार से 7 हजार रूपये का फायदा हो रहा है, किस तरह से उनका आय बढ़ रहा है, किस तरह से उनका सम्मान हुआ है। निश्चित रूप से आज जितनी भी योजना है। आज गोधन न्याय योजना की कितनी भी बुराई करिये, लेकिन आज गोधन न्याय योजना के जितने भी काम हैं, उसको केन्द्र की सरकार appreciate कर ही है, उसकी बड़ाई केन्द्र की सरकार कर रही है और जो बहुत सारे राज्य सरकारे हैं, वह आज गोधन न्याय योजना को आत्मसात कर रही हैं और गोधन न्याय योजना के जो फायदे हैं, उसको समझ रही है। यह नवाचार है। इस तरह से सरकार ने इतने सारे नवाचार किए हैं, उसके लिए आयोग बनाये हैं, उसके लिए शोध हो रहा है और कैसे करना है। किस तरह से जो बोलते हैं

न कि अंत्योदय की जो योजना है कि अंतिम व्यक्ति का कैसे लाभ होगा, उसको लाभ पहुंचाने का काम और जितना भी हमारा कार्यक्रम बन रहा है और क्रियान्वयन हो रहा है, यह दिखता है। यह जमीन में दिखने वाली चीज है। मैंने आपको बताया भी था कि मेरे मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से एक बालक गोधन न्याय योजना के पैसे से आज कवर्धा में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। हमारे काफी माननीय सदस्यों ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बारे में बताया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हमारे पूरे प्रदेश के मुखिया जब वहां चौपाल लगाकर बैठते हैं तो उस चौपाल की गरिमा को देखिये कि कैसे हमारे जो कोई दिव्यांग हैं, उनको तुरंत फायदा हो जाता है। मैं आपको बालना चाहूंगा इसके पहले अभी माननीय बांधी जी अधिकारियों के बारे में बहुत सारी बात बोल रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भेंट मुलाकात कार्यक्रम से जिस तरह से पूरे जिले में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जब आगमन होता था तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से फौती, बंटवारा, नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार पट्टा, हजारों-हजार की संख्या में अधिकारियों ने कैंप लगा-लगाकर बांटा है। यह काम हमारी सरकार ने की है। यह काम माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट मुलाकात ने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नई दिल्ली में जो छत्तीसगढ़ भवन का निर्माण होने वाला है। सबसे बड़ी बात, मैं तो डॉक्टर हूं। मैं चिकित्सा का भी छात्र रहा हूं और मैंने मेडिकल इंट्रेस्ट की तैयारी भी की है। चिरमिरी छोटा सा जगह है, जहां से मैं आता हूं। जब मैं पी.एम.टी. का फार्म भर रहा था, उस समय का जो परीक्षा फीस था, जो मेरी हैसियत थी, मेरी घर की हैसियत थी, वह फीस मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था। आज जितने भी व्यावसायिक परीक्षा हैं, जितने भी पी.एस.सी. की परीक्षा हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा शुल्क को जीरो किया है, उसको माफ किया है। इससे बड़ी बात छात्रों के लिए नहीं हो सकती। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनको नौकरी देने का काम इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने जनजाति के ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से आज हमारे ट्रायबल के लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको वनाधिकार पट्टा से लेकर, सामुदायिक वनाधिकार पट्टा से लेकर उनके जाति प्रमाण पत्र का जो सरलता हुआ है, जो सरलता से यह सब स्कूल में मिल जा रहा है, इससे बड़ी बात छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वेच्छानुदान। इसके पहले स्वेच्छानुदान ऐसी राशि थी, जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। आज स्वेच्छानुदान से लोग अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, अपना ईलाज और क्या-क्या नहीं करवा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पेपरों में पढ़ते थे कि स्वेच्छानुदान का उपयोग एक ही होता था कि हमारे जो माननीय साथी थे, जो पहले सत्ता में था, इनका जूता-चप्पल और कपड़े के बिल भरने का काम करते थे। आज स्वेच्छानुदान से हमारा अंतिम व्यक्ति को फायदा मिल रहा है और हमारा अंतिम व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्त विभाग बार-बार बोलता है कि वित्तीय प्रबंध कैसे होगा, वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा। आज

माननीय मुख्यमंत्री जी का वित्तीय प्रबंधन है कि आज जब यह बोल रहे थे कि यह किसानों को कैसे 2500 रूपये देंगे। यह कैसे इतना कर्जा माफ करके सड़क, पुल-पुलिया बनायेंगे। आज छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन इतना अच्छा है कि बाजार से बिना ऋण लिये, आज इनसे दस गुना ज्यादा काम हमारी सरकार ने की है, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है। मैं ऊर्जा के बारे में बोलूंगा। हमारे बहुत सारे साथियों ने ऊर्जा के बारे में बहुत सारी बात बोल दिया है। मैं तो केवल इतना बोलना चाहूंगा कि चिरमिरी, जहां मैं रहता हूं जो मेरे विधानसभा का नगर- निगम क्षेत्र है। नगर-निगम में ये एक बहुत सोचने वाली बात है और बहुत लज्जा वाली बात है कि आजादी के बाद में नगर-निगम जैसे क्षेत्र के हमारे वार्ड नंबर-एक का जो लामीगोड़ा क्षेत्र है, वह विद्युतविहीन था । आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से आजादी के बाद हमने लामीगोड़ा में विद्युतीकरण करने का काम किया है । यह सब काम हमको ग्राउंड में दिख रहा है, हमको जमीन में दिख रहा है, जो काम आजादी के बाद नहीं हुआ । जो काम इनकी 15 साल की सरकार ने नहीं किया वह काम माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी अभिनव योजनाओं से हो रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बाल्टी वाला जो ट्रांसफार्मर हुआ करता था उसको भी ये 15 साल जिन्होंने राज किया है वे अपना बड़ा-बड़ा फार्महाऊस बनाते थे तो गांव से निकालकर जाकर अपने फार्महाऊस में लगा लेते थे । इन सवा 4 सालों में पूरा का ट्रांसफार्मर आप जाकर देखिये, हमारे जो 51 पंचायत हैं उनको चेंज करने का काम जो है इस सरकार ने किया है । ट्रांसफार्मर की बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्युत उपकेंद्र की मांग लगातार कई वर्षों से वहां हमारे जो क्षेत्रवासी कर रहे थे, आज छोटेकलुआ में विद्युत उपकेंद्र का कोई टेंडर वगैरह नहीं है । वहां काम चालू हो गया है, वहां लगभग 40 प्रतिशत काम विद्युत उपकेंद्र का पूरा हो गया है और लगभग वहां पर 15 पंचायतों को जो लो-वोल्टेज की प्रॉब्लम थी वह प्रॉब्लम लगभग खत्म हो रही है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विमानन विभाग में जिस तरह से हमारे जो सबसे दूरस्थ क्षेत्र है । हमारा जो कोरिया जिला है, अभी जो हमारा एम.सी.बी. (मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर) जिला बना है वहां बैकुंठपुर में हवाईपट्टी का जो इस बजट में प्रावधान किया है उसके लिये मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आज हमारा जो बैकुंठपुर जिला है, हमारा एम.सी.बी. जो जिला है वह भी हवाई मार्ग से जुड़ जा रहा है उसी प्रकार से कोरबा में जो व्यावसायिक हवाई-पट्टी का प्रावधान इस पूरे बजट में है। निश्चित रूप से...।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस दो मिनट में समाप्त कर दूंगा । कोरबा में जो व्यावसायिक हवाई पट्टी बनने से निश्चित रूप से वह जो एक बड़ा एरिया है । कोरिया लोकसभा की बात करें तो हमारा पूरा कोयलांचल और काफी व्यापारिक एरिया है तो कार्गो की जो

कल्पना है वह भी आगे जाकर साकार होगी जिससे वहां के लोगों को बडा रोजगार और बड़े संसाधन वहां पैदा होंगे । निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों की अगर बात करें तो मैं सभी से चाहूंगा कि पूरे ध्वनिमत से पूरा जो अनुदान मांग है उसको समर्थन दें और उसको पारित करें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । अउ बोले के पहिली निवेदन करना चाहत हंओं हमरो क्रम ला कछू निश्चित कर देतेओ कि कोन क्रम मा हमन ला बोलना हे । नौ साल के विधायिकी मा पहिली बार मैं [xx] निवेदन करेओं कि मोला हॉस्पिटल जाना हे, बोलवा देवा करके । लेकिन वो भी अनुरोध ला स्वीकार नइ करिन । एक राष्ट्रीय दल के, विधायक दल के नेता हंओं तो मोर आपसे आसंदी से निवेदन हे कि हमरो क्रम ला आप सुनिश्चित कर देवओ कि कौन क्रम मा हम ला बोलना हे करके ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बिल्कुल ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुदान मांग मा चर्चा करे बर खड़ा होए हंओं । हमर बहुत सारा साथी मन बतईन हे अउ विशेष रूप से जब पक्ष अउ विपक्ष बोलथें ता स्वाभाविक बात हे कि अच्छा काम के चर्चा करहीं । तो जेहर धरातल में अच्छा नइ दिखत हे तेकर भी चर्चा होना चाही अउ ये सदन हर एक सुधार के अवसर रहिथे । ये सदन मा विपक्ष हा अगर अपन समस्या ला नइ रखही, पीड़ा ला नइ रखही तो कहां रखही ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से ये भी सरकार रिहिस हे ता कुछ अच्छा काम करे रिहिस होही, कुछ कमी करिस होही । आज भी सरकार हे ते हा अच्छा काम भी करत हे ता अइसे नइ हे कि सब अच्छा-अच्छा ही करत हे, ओमा कमी भी होही । समय और परिस्थिति के हिसाब से प्रदेश के बजट भी बढ़िस, विकास भी ज्यादा होइस । आज मुख्यमंत्री जी करा ऊर्जा हर हे । बहुत अकन विकास करेन । पहिली गांव के केवल मुख्य बस्ती मा बिजली रिहिस हे, पारा-टोला मा नइ रिहिस हे । अधिकांश गांव मा नइ रिहिस । पहिली कोई गांव मा एक ट्रांसफार्मर लगे रिहिस हे, आज एक-एक गांव मा 10-10 ट्रांसफार्मर लग गे हे । पहिली पूरा क्षेत्र मा 100 किलोमीटर मा एक सब-स्टेशन रिहिस हे, आज 5-5 किलोमीटर मा सब-स्टेशन बन गे हे ता स्वाभाविक रूप से जइसनहा-जइसनहा साधन-संसाधन उपलब्ध होत जाही, जइसनहा आवश्यकता बनत जाही स्वाभाविक रूप से ओकर विस्तार होत जाही । लेकिन ऊर्जा विभाग मा समय अउ परिस्थिति के साथ मा जहां लाईन के विस्तार होइस, उपभोक्ता बढ़िस, ट्रांसफार्मर बढ़िस, सब स्टेशन बढ़िस, विभाग के कर्मचारी कम होत हे । अउ विभाग के कर्मचारी कम होए के कारण ठेका पद्धति आइस । आज एक खंभा टूट जाही तो बिजली विभाग करा एक खंभा नइ हे, खंभा बदले

बर । वो ठेकेदार पर आश्रित हे, ठेकेदार जेन दिन खंभ लगा दिही तेन दिन खंभ लगही । तेखर कारण आम उपभोक्ता ला काफी दिक्कत होत हावय ।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है, आप बिजली बिल हाफ करे हौ । ये भी सही है जेहर हर महीना बिजली बिल ला पटाही ओला हाफ बिजली बिल के लाभ मिलही । लेकिन बिजली बिल के दिक्कत आत हे । मोर एक प्रश्न मा एक डी.सी. केवल जैजैपुर मा बिजली बिल ज्यादा आए के 10 हजार से भी ज्यादा आवेदन आए हे, 10 हजार से भी ज्यादा । अइसन पूरा प्रदेश में हे, ओखर कारण एके ठन हे, अनट्रेंड व्यक्ति ला एमन बिजली रीडिंग के ठेका दे दिन । पर मीटर एक रूपया, दो रूपया, ओखर मर्जी वो जाए या मत जाए । घरे ले बना दिस, मीटर चले नइ हे ज्यादा रीडिंग लिखकर बिल दे दिन । ओखर ऊपर कोई कार्रवाई नइ हे । तेखर कारण आम उपभोक्ता परेशान हे । अगर बिजली बिल आ गिस, अतका कन समस्या हे, एक सामान्य आदमी बिजली ऑफिस जाही तो कोई सुनवाई नइ हे । अब लड़ झगड़ के सुनवाई हो गे तो जे.ई. कही ये मोर अधिकार नइ हे, ए.ई.करा जा, वो गलती से ए.ई.करा चल दिस तो ए.ई. कही कि ठीक हे तोर बिजली बिल मा तो गलती हे लेकिन केवल मोर करा 10 हजार तक सुधारे के अधिकार हे, 10 हजार ले ज्यादा है तो मैं डी.ई. के पोर्टल मा डालत हौं, डी.ई. देख लिही ता होही । गांव के आदमी अंगूठा लगाकर कोऑपरेटिव बैंक ले पइसा निकालथे । बिजली बिल ला हमर कस आदमी पढ़े नइ जानन, वो गांव के आदमी का पढी अउ कौन करा बिजली बिल ला सुधारही । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ला बताना चाहत हौं कि गांव के वो गरीब आदमी जेखर आप चिंता करे हौ । आप सरकार बने हौ आप गरीब आदमी के चिंता करौ, उद्योगपति चाहत हे तो ओला एक दिन मा बिजली मिल जात है, कोई उद्योग लगात हे तो ओला एक दिन मा ट्रांसफार्मर मिल जात हे। एस्टीमेट बनत हे, अतका अकन राशि पटाना हे अउ दूसर दिन लग जात हे रामकुमार यादव जी । लेकिन आज एक किसान 63 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर ला 100 के.व्ही. ए. के कराए बर कहत हे तो डी.ई. कहत हे फंड नहीं है । फंड के कमी हे, फंड आही ता होही, स्कूल के ऊपर तार गुजरे हे, करंट लग जात हे, छानही जल जात हे, वो बिजली के पोल ला शिफ्टिंग करे बर काहत हैं तो बिजली के साहब कहत हे, शिफ्टिंग के चार्ज देबे, तो कतका शिफ्टिंग चार्ज 1 लाख रूपया ।

श्री रामकुमार यादव :- विधायक जी सुनव ना । हमर समय में तो कम से कम लाईन हे, एमन के राज मा थोड़ा हवा पानी करतिस तो 5 दिन तक लाईन गोल।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- तो ओखरे बर तो तोर सरकार बना देव । सुधार देहौ तो तुम्हर बिगड़ जाही का । 63 के ला 100 लगा दिहौ तो पम्प मा पानी के धार थोड़कन बढ़ जाही तो तुम्हर कुछ बिगड़ जाही का ? तुम्हरे क्षेत्र में सबले ज्यादा पम्प हावय । नइ तो मैं कहूं 100 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर मांगत रहेंव तो रामकुमार विरोध करत रिहिस भाई ।

श्री रामकुमार यादव :- ओमन तुम्हर गोठ ला पतियाबे नइ करय । वही तो बुता हे तुम्हर मन के रोज के, कतेक ला सुनहीं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सही समस्या हे स्वीकार करौ ओला ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ा मा बात नइ करौं, बहुत व्यवहारिक चीज के बात करत हौं । आम आदमी ला जौन परेशानी हे, जौन दिक्कत हे । सौर ऊर्जा बहुत अच्छा है धीरे-धीरे हमन ला सौर ऊर्जा के तरफ जाना हे । काबर कोयला के कमी रही । थर्मल पावर कोयला बिना चल नइ पावय । तो स्वाभाविक है कि सौर ऊर्जा के तरफ जाबो । लेकिन सौर ऊर्जा मा अतका करप्शन अउ भ्रष्टाचार हे चाहे सौर ऊर्जा में चलने वाला पम्प राहय, कौन ठेकेदार गिस, कौन लगाइए ? एक साल के गारंटी हे लेकिन आज किसान के पम्प खराब हो गे हे तो चिट्ठी लिखत लिखत थक जात हे । सौर ऊर्जा के जिला मा जो अधिकारी बैठेहे वो कहिथे विधायकजी हम नइ जानन कौन ठेकेदार हे ? छठो सातों पेटी हर इहां बुता करे आथे, पेटी के ऊपर पेटी, छोटे पेटी, अउ पेटी, अउ पेटी अउ पीला पेटी हर उहां काम करे ताथे, कोई गुणवत्ता नइ हे । आज सौर ऊर्जा मा आधारित नलजल योजना बनाए हे टंकी चले हावय । मैं दावा करत हौं, पूरा प्रदेश के बात नइ करौं ।

श्री अमरजीत भगत :- केशव जी, आप पेटी वगैरह के चक्कर में कहां पड़े हव, आप सीधे बोतल से मिला करो। (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मंत्री जी, का हे, मोला खाता, अउ पीता दोनो छोड़ देहां। (हंसी) मंत्री नई रहाव तब तो आव केशव करके पीठ थपथपावव, जे दिन ले मंत्री बने हे ते दिन ले खाता पीता दोनों छोड़ देहां। (हंसी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जा मा चलने वाला जतका नल जल योजना लगाय हे, मे दावा करत हंव, जैजेपुर विधान सभा मा, एक भी अधिकारी जा करके, एक भी सौर ऊर्जा मा चलने वाला, ओ नल जल योजना ला चालू हालत मा बता देवव, रामकुमार जी, एक सौ ले ज्यादा लगे हे। 25 लाख के एक स्कीम, 5 ठोक घर मा पानी नई जात हे। हाईमास्ट लाईट लगे हे, बड़ा उत्साहित हन, गांव के चौक मा लग गिस करके, लेकिन जलत नई हे, हमन विधायक मन शिकायत करत थक गेहन, 4 लाख 85 हजार के पांच साल के गारंटी, 5 साल मा गन के पांच दिन तो चल जतिस। ये जो हे समस्या हे। माननीय मुख्यमंत्री करा, ए प्रदेश के सबसे बड़े संसाधन खनिज संसाधन हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रा तो, भैया सोलर वाला लाईट हा घाम मे जलथे, तोर क्षेत्र मा घामे नई होवत होही तेला हमन काय करबो। (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ओ सोलर लाईट हा पंजा, फूल अउ हाथी ला नई देखय। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- महोदय, ओ हा घाम जरूर देखथय।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बिना घाम के बिल्कुल नई जलय।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सबसे बड़े जेखर हमर असीम संभावना हावए...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब नवा आविष्कार होही, जिहां घाम नई रहाय, उहों जलय अइसे तोर बर देखबो।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, नवा आविष्कार के जरूरत नई हे, 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत के लोचा हे तेला, 2, 4, 5 प्रतिशत कर देवव तो ओ लाईट जल जाही। (हंसी) ऐ लोचा ला थोड़ी झोल ला। थोड़े से झोल ला कम कर देवा। (हंसी)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मंत्री जी, एकात ठन गोबर से चलही तइसन वाला आविष्कार करव।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- गोबर से अजय चंद्राकर चलथे, अउ दूसरा नई चलय। (हंसी)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आविष्कार हो गेहे।

श्री रामकुमार यादव :- गोबर के अपमान मत करव। रंजना बहनी तुंहर मन के शादी बिहाव हाईस होही ना ता गोबर के ही हर चीज ला बनाथन। सुख अउ दुख सबमा काम आथय।

श्री राजमन बेंजाम :- हमारे जगदलपुर में गोबर से लाईट जल रही है, आप आईए दिखायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपस में संवाद ना करें। समय का ध्यान रखें। इसके बाद 5 मिनट का समय दूंगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ए रामकुमार जी पूरा लोचा कर दिन, मोला पांच मिनट समय देवव। खनिज मा आय हावन, रेता के बहुत अकन समस्या बतईन, रामकुमार जी बताईस, ओमा हमन रोज जूझत हन। काबर कि ठेका दे रहिन हो खत्म होगे, ठेका खत्म होगे लेकिन घाट खत्म नई होईस। ठेकेदार आज भी चलात हे, लेकिन पुलिस प्रशासन अउ खनिज विभाग ओला नई देखत हे। केवल गांव के गलती से कोई एको ठन ट्रैक्टर चल दिस, ओखरे उपर ध्यान हे, ओला थाना मा खड़ा कर देत हे। खनिज विभाग करा चल दिन ता 10 दिन ले कलेक्टर साहब करा चक्कर लगाथन, तो दस हजार, पंद्रह हजार जुर्माना करके ओ ट्रैक्टर छूटत हावय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमाम तकलीफ ला हम सहत हन।

श्री शैलेश पाण्डे :- कल पुलिस की बुराई कर रहे थे, आज बड़ाई कर रहे हैं। ऐसी तो तरफी बात नहीं चलेगी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उपाध्यक्ष जी, तमाम तकलीफ ला हम सहत हन, ओ नदी के बाढ़ ला हम किसान झेलत हन, ओ तट में रहने वाला गांव के निवासी, लेकिन ओ बाढ़ झेलने वाला, ओ तट में रहने वाला, ओ किसान हा अभी घर बनात हे तो ओला एक झाहू रेती लेहे के अधिकार नई हे, मैं तो सरकार करा निवेदन करना चाहा, आप रेत के जतका नया नीति लाय हावए, खनिज के जतका नया नीति लाय हावए, ओतके अकन आम आदमी अउ गांव के रहईया किसान हर परेशान होत हावए। डोलोमाईट के खदान चलत हावए, बढ़िया हे, सरकार करा पईसा आत हे, ग्राम पंचायत कर पईसा आत हे, लेकिन धूल, धक्कड़, सिलकोसी, जैसे बीमारी दमां के बीमारी जो सड़क टूटत हे तेला आम आदमी

भुगतत हावए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अउ कइसे प्रशासन चलत हावए, एक ठन उदाहरण दे के बतात हंव। रामकुमार जी सुन लेवव। मोर क्षेत्र के मोर जिला के डुमरपारा मा बालाजी मेटल्स एंड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड हे, एखर मालिक उड़ीसा के हे, आय कहां हे, ओ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल मा कहां ले खोज के आ गेहे, अउ सरकार हा ओला 42 हेक्टेयर छोटे बड़े झाड़ के जंगल ला ओला डोलोमाईट निकाले बर अनुमति दे देहे। 42 एकड़ दे दिस, अनुमति दे दिस। लेकिन ओ ठेकेदार 42 एकड़ मा भी संतुष्ट नई हे, ए सरकार के तहसीलदार के प्रशासन जो कमेटी बनाय रहिस तेखर खसरा नंबर 2349/1 रकबा 2.115 हेक्टेयर मा ओ डोलोमाईट पत्थर के अवैध भंडारण करे हे।

श्री रामकुमार यादव :- कब से हे, कब से हे ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अभी, तुहर सरकार मा।

श्री रामकुमार यादव :- ओ तो बड़ दिन के चलत हे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं, खदान चलत हवे, लेकिन ए तुहर सरकार में करे हवे।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन हा कहां जानहुं ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- खसरा नं.- 2348/12, रकबा-.77 हेक्टेयर मा ओहा खदान बनाहे।

श्री शैलेश पाण्डे :- बात नहीं बनी होगी न।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ओहा खदान भी बना डरीस अऊ 2348/12, रकबा-1.42 हेक्टेयर मा क्रेशर भी स्थापित कर डारिस। ए तहसीलदार के रिपोर्ट हे। ए मोर रिपोर्ट नो हरे। मेला ऐखर से कोई आपत्ति नहीं हे। सरकार बन गेहे। क्षेत्र के जनता अतके बहुमत में जीता देहे, का मे ऐखर विरोध करके मरहुं ? (हंसी) लेकिन अब ए सरकार हा 42 हेक्टेयर ला दे दीस तभो ऐखर मन नहीं भरत हे अउ वतका अकन ला कब्जा दे दीस। दुर्भाग्य हे कि डिप्टी कलेक्टर एमे स्टे दे हे। ते ओ ठेकेदार ला अऊ ओखर मालिक के कुछ नहीं कर सकस। ए प्रशासन चलत हे।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कहां चले गये ? आप पुलिस भेजकर उनको ढूंढवाइये। एक भी सदस्य नहीं दिख रहे हैं। वह किधर चले गये ?

श्री शैलेश पाण्डे :- मिर्ची बम।

श्री कवासी लखमा :- मिर्ची तोड़ने चले गये। (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के नीति चाहे कतको अच्छा रहाय, जब तक प्रशासन के ऊपर सरकार के नियंत्रण नहीं हे, आपके योजना कतको रहाय लेकिन जब तक योजना आम आदमी करा बिना भ्रष्टाचार के नहीं पहुंचीस तो मैं समझथो कि ओ सरकार फेल हे। प्रशासन में नियंत्रण कहां हे ? सब जगह के आरोप है। हल्ला होवत हे। का पेमेंट शीट, पेमेंट शीट कहिथे। ओला

हमन नहीं जानन। मंत्री जी हांस दीस, ओ समझ गे। ए पेमेंट शीट का होथे, ऐला हमन नहीं जानन। लेकिन पेमेंटशीट के बात के पूरा प्रदेश में चर्चा हे।

श्री रामकुमार यादव :- ते मान गेस न कि जेला ते नहीं समझ पावस तेला मोर ददा समझथे। वइसने हे, वन मेन आर्मी।

श्री कवासी लखमा :- चंद्रा जी, बहन जी के पास पेमेंट से चलता है। जब जन्मदिन में पेमेंट होता है तो टिकट में पेमेंट चिट मिलता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- चंद्रार जी, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पेमेंट शीट का बता रहे हैं यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बता देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- जी, बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या है कि वह पेमेंट शीट वाले लोग निकले थे तो उनको एक फॉर्म हाऊस मिला तो वह बोले कि सब मुर्गियां ज्यादा अण्डा देना शुरू करो। अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है इसलिए कमाई का जरिया खोजना है। वह उनको फटकार के, डांट लगाकर आया और जब दूसरे, तीसरे, चौथे दिन अण्डा लेने गया तो बड़ी ऊपर वाली मुर्गी 5, नीचे वाली 4, उसके नीचे वाली 3, उसके नीचे वाली 2 और नीचे वाला एक अण्डा दिया। वह सबका हिसाब करते गया। वह नीचे वाले से पूछा कि बेवकूफ, तुझे मैं अण्डा देने के लिए इतना बोलकर गया था तो वह बोला हुजूर, मैं तो आप ही डर में अण्डा दिया हूं, वैसे मैं मुर्गा हूं। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- आप धर्मजीत जी से सीखिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक प्रशासन में नियंत्रण नहीं रहही। माननीय मुख्यमंत्री जी ला राजस्व के समीक्षा करे के आवश्यकता पड़ गे। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के समीक्षा करे के आवश्यकता पड़ गे कि अतका अकन प्रकरण काबर पेंडिंग हें ? ए प्रशासन के सिस्टम ला बतात हे।

श्री शैलेश पाण्डे :- भैया, आप प्रशासन को वहां टाइट कीजिए न, आप उपाध्यक्ष जी को क्यों टाइट कर रहे हों ? (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पाण्डे जी, जतका दु:खी हमन हन, शायद हमन अपन पीड़ा ला भी व्यक्त कर डालबो, आप तो अपन पीड़ा ला...। सुनो न।

श्री शैलेश पाण्डे :- हम सब आपके दु:ख में दु:खी हैं। मैं उपाध्यक्ष जी से यह मांग करता हूं कि इनके घर में चोरी हुई है उसको पूरे प्रदेश की पुलिस लगाकर पकड़वाया जाए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- भाई, आप तो उस दिन आश्वासन दिये हैं कि बहुत जल्दी चोरी पकड़ में आएगी। मैंने आपसे कहा भी है। पहले आप पुलिस का विरोध करते थे और मैं सुना हूं कि अब आप पुलिस के प्रवक्ता बन गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम विषय है।

श्री ननकीराम कंवर :- वह वहीं से तो मिलेगा। मिलता तो वहीं से है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ला समीक्षा करे बर जाएल लागत हे। ए प्रशासन के जो कमजोरी हे। मैं अंत में ज्यादा नहीं बोलो। हमर पंचायत मंत्री करा पंचायत प्रतिनिधि मन के अधिकार के बहुत अकन चर्चा होइस हे। हम मुख्यमंत्री जी ला संवेदनशील मुख्यमंत्री भी कहेन। हम तो चाहत रहे हन कि जे हमर प्रदेश के मुखिया हे अऊ जेला ए पूरा जनता मन चुने हे, ओ मुख्यमंत्री के घोषणा के सम्मान होवे। पंचायत ला 50 लाख काम दे के अधिकार देहे तो हमन ए चाहत रहे हन कि मुख्यमंत्री जी के सम्मान होए। लेकिन ओखरे मंत्री मन नहीं चाहत हे, ओमन मुख्यमंत्री जी के बात ला अधूरा रखना चाहत हे। ओखरे मन मन हा हल्का बनाही तो बाकी जनता मन भी ओला हल्का समझही। मैं पुन: माननीय मुख्यमंत्री जी करा अनुरोध करना चाहत हो कि ओ पंचायत के चुने हुए 11 हजार जनप्रतिनिधि मन के अधिकार ला सुरक्षित करें अऊ अंत मा छोटे से मांग के साथ, भले मुख्यमंत्री जी हा इंहा नहीं हें लेकिन रामकुमार जी कहिथे कि मुख्यमंत्री नहीं रहाये तभो ओहा टी.वी. में देखत रहिथे। अउ टी.व्ही. में नहीं देखत होही तो हमर पड़ोसी विधायक रामकुमार जी बताही । हमर जैजैपुर अनुविभागीय कार्यालय बनत रिहीसे, राजपत्र में प्रकाशन होगे, दावा आपत्ति होगे । भाई रामकुमार के कारण वह नहीं बन पईस । अउ वो जहां चाहत रिहीसे, तिहां मालखरौंदा मा बन गे । मोर मुख्यमंत्री जी करा निवेदन हे कि मुख्यमंत्री जी, केवल दुर्भावना मा राजनीति नहीं होवय । जिहा आवश्यकता हे, तिहां बनना चाहिए। आप जिहां चाहव, तिहां बना देवव । आपके कृपा होतिस कि आप जैजैपुर में भी राजस्व के अनुविभागीय कार्यालय आप बना देतेव । नहीं तो हम क्षेत्र के जनता ला कबे करबो कि ये सरकार के दुर्भावना हे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भोथिया और पिरदा । जैजैपुर विकासखण्ड के भोथिया, जेन ला अभी तहसील के दर्जा दे हें । रामकुमार जी, ओकर बर धन्यवाद । आप भोथिया ला तहसील बनवाए हवव, ऊंहा माला पहिने बर चल देहव । मालखरौदा विकासखण्ड के पिरदा, यह पूरा पम्प वाले एरिया हे, बहुत सिंचाई एरिया हे, बहुत लो वोल्टेज के समस्या हे, आदमी झेलत हवय । अभी हमर सिन्हा भाभी कहिन हे कि कंडिल धरके गिस । तो अभी स्थिति वइसने हो गे हे । कंडिल धरके हमन बलफ ला देखथन । ओतके लो वोल्टेज ओ क्षेत्र मा हो गे हे । ये दूनो जगह अगर सब स्टेशन बन जतिस त निश्चित रूप से वोल्टेज के समस्या हे दूर होतिस । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बोले के मौका देव, ओकर बर धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- इस विषय में निर्धारित समय से काफी लंबी चर्चा हो चुकी है । कृपया जो 7 माननीय सदस्यों को बोलना है, उनके लिए 5-5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है । अपने क्षेत्र की जो प्रमुख मांगे हैं, वह 5 मिनट में आ जाना चाहिए ।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर-सोनहट) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बोलना तो ज्यादा था, पर आपने समय शार्ट कर दिया है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन चार सालों में पूरे देश में जब कोरोना का संकट आया था तो देश में सांसदों का मद हो या अन्य राज्यों के विधायकों का मद हो, उसमें कटौती की गई थी। पर हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, कोरोना काल की विपत्तियों के बाद भी विधायक निधि में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई और हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी रही । इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि कोरोना संकट के बाद भी छत्तीसगढ़ में कटौती नहीं की गई ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बापू जी का सपना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है । उसी तरह माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने इन चार सालों में विकास कार्य किया है । हम आय व्ययक की बात करें, उसके बाद भी हमारा वित्तीय प्रबंधन अच्छा है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत से वरिष्ठ सदस्यों ने कहा, चाहे वह सामान्य प्रशासन की बात हो या जिला बनाने की बात हो । आपने समय सीमित किया इसलिए मैं भी अपनी बात सीमित करूंगा और अपनी बात अपने जिले की ओर ले जा रहा हूं । हमारे मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यों की तुलनात्मक बात बताना चाहूंगा । हमारी 40 साल पुरानी मांग थी, हम दोनों विधायकों ने मांग की थी कि मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाया जाये । मुख्यमंत्री जी ने उसे जिला बनाकर जिले के रूप में स्थापित करा दिया । इसके साथ ही हमारी सरकार ने दो तहसील और दो अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना की। यह है भूपेश बघेल का काम । भूपेश के नाम का मतलब होता है पृथ्वी का राजा । उस तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस्तर और सरगुजा आदिवासी क्षेत्र है । विपक्ष के साथी बड़ी-बड़ी बात करते हैं, आदिवासियों के नाम से वोट मांगते हैं, पर 15 साल की सरकार ने कभी आदिवासियों की चिन्ता नहीं की । मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो आदिवासी होने के कारण मुझे राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है । मैं प्राधिकरण का उपाध्यक्ष हूं, पर इनकी 15 साल की सरकार ने किसी भी आदिवासी को उस पद पर नहीं बैठने दिया । मैं प्राधिकरण का उपाध्यक्ष हूं, मुझे राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है । आज हम लोगों को अधिकार है, वहीं पर हम लोग काम करते हैं । नहीं तो एक काम सैंशन कराने में एक साल लगता था । यह हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश जी ने काम किया है । इतना ही नहीं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए कनिष्ठ कर्मचारी बोर्ड का गठन किया गया है । बस्तर में

भर्ती हो गई है, सरगुजा में भर्ती की कार्यवाही की जा रही है । साथ ही 50 साल के रिकार्ड के कारण हमारे बच्चों का जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन पाता था । मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दो जिले हो गए हैं, पर मैं दोनों जिले में हूं । कोरिया जिला ऐसा जिला है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद से 50 साल के रिकार्ड के कारण जिन लोगों का जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन पाता था, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कैम्प लगाया गया । हमारे जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के 44 हजार लोगों का जाति प्रमाण-पत्र बना है। ये है भूपेश बघेल जी का काम। (मेजों की थपथपाहट) इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे साथी बिजली की बात कह रहे थे। हमारी बिजली बिल हाफ योजना चालू है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । हमारे दो मंत्री चौबे जी डॉ. प्रेमसाय टेकाम जी बैठे हैं, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। भूपेश है तो भरोसा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- कमरो जी, किस बात का भरोसा है ? क्षेत्र में अवैध दारू बिकेगी उसका भरोसा या भ्रष्टाचार का भरोसा है ?

श्री गुलाब कमरो :- उपाध्यक्ष महोदय, हम सब बता रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवरतन भइया, चाहे कोई भी, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे भा.ज.पा. का विधायक हो, अगर कोई गलत करता है तो उस पर कार्यवाही होती है। हमारी संवेदनशील सरकार है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिये जरा। सुन तो लो भईया मैं जूनियर हूं, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं। हमारी बात को जरा सुन तो लीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी में तुलनात्मक अंतर बताना चाहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री जी कोरिया जिला को गोद लिए थे कि मैं जिला बनाऊंगा। किल्हारी को तहसील बनाऊंगा, जनकपुर में ये करूंगा, सोनहत में ये करूंगा, लेकिन कुछ नहीं किए। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नया जिला बनाया, ये दोनों में अंतर है। इसको कहते हैं भूपेश बघेल।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको दूसरा बताना चाहूंगा। मुझे कहने में गर्व होता है कि हमारे यहां दो तहसील है। हमारी सरकार बनने के बाद जनकपुर तहसील में वर्तमान में 188 गांव है, जहां पर मध्यप्रदेश से बिजली आती थी। लेकिन कभी भी कोई ध्यान नहीं दिये, पुरानी 15 साल की सरकार ने बड़ी-बड़ी बात करने बाद कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार ने, सरकार बनते ही मध्यप्रदेश से जो बिजली आती थी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ से बिजली जा रही है, ये हमारा कांग्रेस का काम है। इतना ही नहीं, 110 किलोमीटरकी लंबी लाईन है। वहां लंबी लाईन होने के कारण बिजली कटौती की परेशानी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो-दो सब स्टेशन स्वीकृत किया है। 132 के.व्ही. का सब स्टेशन भी स्वीकृत है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट बताना चाह रहा हूं। अभी रेत की बात कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि रेत ऐसा हो गया, भू-माफिया आ गया है, ऐसा हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। भरतपुर विधानसभा में रेत का भण्डारण होता है। लेकिन जब इनकी सरकार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप मेरी बातों को समझ सकते हैं, इनकी सरकार थी, इनके लोग, इनके परिवार के लोग, जिनका बुढ़वा गांव है, वहां से सौ-सौ हाइवा आते थे, रेत ले जाते थे, 30 हजार, 40 हजार रूपया रेत का रेट हुआ करता था। लेकिन हमारी सरकार ने बकायदा टेण्डर किया है। अभी ग्राम पंचायतों को रायल्टी मिल रही है। यह दोनों सरकार में अंतर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बोलना तो बहुत था।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री रजनीश कुमार सिंह , 5 मिनट मे अपनी बात समाप्त करें।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांग संख्या- 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71 एवं 65 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले उर्जा विभाग पर बोलूंगा। हम सबके लिए उर्जा विभाग एक ऐसी चीज है, जैसे जिस तरह से भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आज हमारे जीवन में बिजली की आवश्यकता है।

अभी हमारे मित्र लोग छत्तीसगढ़ की पिछले 15 साल की बात कर रहे हैं, अब ज्यादा समय नहीं है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उर्जा में सबसे बड़ी दिक्कत है। एक विशेषज्ञ कमेटी ने अपने अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि जहां 33 के.व्ही. का लाईन है उसके बाद का सब स्टेशन है। वहां से बिजली ट्रांसफार्मर तक आते-आते लगभग 25 से 30 प्रतिशत का लाईन लॉस होता है। उसके पीछे कारण है कि पुराने कण्डक्टर हैं, जो ट्रांसफार्मर हैं, वह मापदण्ड के नहीं हैं। उसी प्रकार उसमें डी.ओ. लगता था, फ्यूज कण्डक्टर लगता था, वह नही है। इसके कारण 25 से 30 प्रतिशत ट्रांसफार्मर तक आते-आते विद्युत लॉस होता है। उसके बाद बिजली जब उपभोक्ता तक पहुंचता है, तो निश्चित रूप से लो वोल्टेज की समस्या और तरह-तरह की समस्या होती है। जिनका दूर कनेक्शन है, उनको लाईन नहीं मिलता था। इसके लिए सरकार को एक बड़ी योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। हमारी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है, उसका 20 से 30 प्रतिशत लाईन लॉस में जा रहा है, तो निश्चित ही हम सबके लिए, हम चाहे कितना भी बिजली उत्पादन कर लें, हम सबके लिए समस्या का कारण बना रहेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार को एक बड़ी योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है । हमारी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है, उसमें 20 से 30 परशेंट यदि लाईन लॉस में जा रहा है, हम कितना भी बिजली उत्पादन कर लें, हमारे लिये दुर्भाग्यजनक है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम किसी भी जगह गांव में देखें, यहां पर अधिकारियों की बात आई है, लाईनमेन की, हेल्पर की कितनी कमी है, निचले स्टॉफ की इतनी कमी है, गांव के लोग यदि न बनाये, कई गांव ऐसे हैं, जहां हफ्ता भर लाईट ही न आये । गांव

के लोग सब सीख गये हैं, छोटा-मोटा फाल्ट को बना लेते हैं, वह बन जाता है, नहीं तो हफ्ता तक लाईट नहीं रहता है । हमें संविदा में जो ठेका दिये हैं, उसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, कई ऐसे सब स्टेशन है जहां, एक-एक, दो लोग हैं, गांव 20-20, 30-30 हैं, इसके कारण ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा, कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। किसानों का जो पम्प कनेक्शनों का शाम 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिजली कटौती हो रहा है, रबी का सीजन है, बहुत लोग धान भी लगाये हैं, अन्य प्रकार की भी फसलें लगी है, उसके कारण लगातार शिकायतें आ रही है, बिजली का लो वोल्टेज और रात को हमारा 5-6 घण्टे का जो कटौती हो रहा है, इसके कारण किसानों को भारी समस्या आ रही है, उसको बंद किया जाये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेलतरा विधान सभा और कोटा विधान सभा के कई ऐसे गांव है, जो रतनपुर में ए.ई. आफिस है, लेकिन उनका डी.ई. आफिस पेंड्रा गौरेला है, यह 100 किलोमीटर दूर है, वैसे ही सीस एक गांव है, उसका कोरबा है, वह भी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, वहां से ट्रांसफारमर रतनपुर का होता है, ट्रांसफारमर बेलतरा विधान सभा के रतनपुर के और कोटा विधान सभा के है, उसी डी.ई. आफिस बिलासपुर के सीपत है, बिलासपुर तिफरा है, ऐसे जगहों पर जोड़ा जाये । माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनसे आग्रह करना चाहूंगा, इसमें बड़ा ही व्यावहारिक कठिनाईयां होती है, कई-कई दिन एक-एक ट्रांसफार्मर को बदलने में लगता है । आग्रह है कि उसको बिलासपुर में ही ...।

सदन की सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 तक का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है ।

वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो ट्रांसफारमर है, 25 को 63 करना है, 63 को 100 करना है, उसमें भी कई प्रकार की दिक्कतें है । प्रक्रिया भी जटिल हो गई है, ओव्हर लोड होने के कारण बार-बार ट्रांसफारमर जलता है, 25 को 63 करना है तो प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि जिसके कारण 63 होने में दिक्कत होता है । 63 को 100 करने में दिक्कत होता है। उस प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाये, जिससे कि लोड है वह बढ़ सके और किसानों को सुविधा मिल सके । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा खनिज है, इसमें मैं अपनी विधान सभा की बात करूंगा । केन्द्र सरकार का निर्णय है कि ताप विद्युत केन्द्रों में कोल वाशरी का साफ धुला हुआ कोयला रहता है, उसको सप्लाई नहीं करना है, लेकिन इसके आड़ में कोल वाशरी अच्छा कोयला बाजार में बेच रही है और खराब

कोयला विद्युत तापकेन्द्रों को दे रही है । बेलतरा विधान सभा में जो कोल वाशरी हैं, आज ही के मेरे प्रश्न में आया है कि पर्यावरण के हिसाब से बहुत सारी कमियां उसमें है । उसमें शिकायत भी हुई है और ग्रामीण बहुत परेशान है । बिलासपुर से लेकर बेलतरा तक अवैध कोल का प्लॉट और तीन-तीन जो कोल वाशरी हैं, उनके परिवहन के कारण और उनसे धूल गुबार जो हो रहा है, आसपास बेलतरा, गतौरी, कछार, तीनों जगह के हैं, यहां के किसान लगातार शिकायत करते हैं । उनकी सब्जी खराब हो रही है, उनका फसल खराब हो रहा है, रोड खराब हो रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका समय समाप्त हो गया है । एक मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय को जरूर ध्यान दें । यह ग्रामीणों से जुड़ा हुआ मामला है । एक विषय के बारे में पिछले साल भी बोला था, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चूंकि विभाग नगरीय प्रशासन का है, लेकिन इसको मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बिलासपुर नगर निगम बहुत बड़ा हो गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उसको दो भागों में किया जाये । अरपा पार की संख्या भी 2 लाख के आसपास है, उसको नया नगर निगम बनाये । नया तहसील बना रहे हैं, अनुभाग बना रहे हैं, नगर निगम को भी किया जाये । बिलासपुर नगर निगम को इन 4 वर्षों में बहुत कम राशि मिला है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। 200 करोड़ की राशि दी जाये । शिक्षा विभाग के बारे में बोलना चाहूंगा। बेलतरा के मोपका में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। इसी प्रकार चिंगराजपारा, सेलर, लिम्हा, कर्रा, यह बड़े-बड़े हाईस्कूल हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इनका हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाये। एक विषय सरस्वती साइकिल योजना से जुड़ा हुआ है। सरस्वती साइकिल एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की छात्राओं को दिया जाता है। मेरा आग्रह है कि इसमें बहुत कम छात्र-छात्राएं शामिल नहीं हो पाते, इसमें सभी को जोड़ा जाए। सभी छात्राएं नहीं बल्कि सभी छात्रों को भी जोड़ा जाए। बहुत कम बच्चें बच जाते हैं। जब हम सब लोग स्कूल में जाते हैं ओर जब साइकिल वितरण होता है तो 5-10 बच्चे छूट जाये रहते हैं। उसमें हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि जो 5-10 बच्चे बच जाते हैं, इनको भी साइकिल मिलनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं आयेगी। बहुत कम छात्र-छात्राएं हैं, उन सबको नि:शुल्क साइकिल योजना में जोड़ा जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खूंटाघाट डेम है और वहां ऊपर में पर्यटन केन्द्र का एक मंदिर है। वहां तीन किलोमीटर की रोड है, उसमें कुछ-कुछ कारण से रोड नहीं बन पा रही है। यदि उसमें रोड बन जायेगी तो निश्चित रूप से खूंटाघाट डेम में पर्यटन की दृष्टि से हजारों पर्यटक जाते हैं। यह कर्रा से पाट बाबा तक तीन किलोमीटर की रोड बना दे तो अच्छा हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय और है लेकिन समय का अभाव है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- थैंक्यू। श्रीमती इंदू बंजारे जी।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिये खड़ी हुई हूं। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि सावन के अंधे को चारों तरफ हरा-हरा दिखाई देता है। वैसे ही हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार और सत्ता पक्ष के सभी साथी है। मैं इनके लोचा में फंस के अपना समय बर्बाद तो नहीं करूंगी। लेकिन यही कहना चाहूंगी कि हम जितना इनके भ्रष्टाचार को बताने का कार्य करते हैं, यह सभी को असत्य मानकर इनको सावन के अंधे की तरह सब हरा-हरा ही नजर आता है।

सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय भी है इसलिये मैं अपने क्षेत्र की जो विशेष समस्याएं हैं, उसको सदन में रखना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन है। मैं ऊर्जा विभाग से संबंधित अपनी समस्या रख रही हूं कि बिजली बिल की जो अनियमितता है, इस समस्या से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। जो अनियमित बिजली बिल भेजा जा रहा है, उससे उपभोक्तागण बहुत परेशान है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, नोटिस भेजा जा रहा है, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जितने भी उपभोक्तागण है, बिजली विभाग से संबंधित, उन सभी की इन समस्याओं को दूर करने के लिये एक जो योजना लाये हैं, वह बहुत अच्छी योजना है, लेकिन आमजनों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षिक करना चाहूंगी। साथ ही हमारी बस्ती से दूरांचल जो छोटे-छोटे घर होते हैं, छोटे-छोटे गांव में, छोटे-छोटे कस्बों में जो छोटे-छोटे घर रहते हैं, उसमें एक-दो खम्भे की जरूरत होती है। चूंकि वह गरीब वर्ग के, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं इसलिये उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। वे जब आवेदन लेकर बिजली विभाग में जाते हैं तो उनसे पैसे की मांग की जाती है और पैसे नहीं देने के कारण उनकी जो एक-दो खम्भे की आवश्यकता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम इसके संबंध में पत्र भी लिखते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पत्र को कुछ समझते नहीं है, न ही हमारे पत्र का कोई जवाब देते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे दूरांचल गांव, कस्बों में जो एक-दो खम्भों की आवश्यकता है, उसमें ऐसी योजना के माध्यम से उनको बिजली उपलब्ध होये, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी। साथ ही अभी हमारे धर्मजीत भैया ट्रांसफार्मर हटाने के संबंध में बता रहे थे, सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्कूल के सामने, आंगनबाड़ी भवन के सामने दो-तीन ऐसे ट्रांसफार्मर है, जो जस्ट स्कूल से लगा हुआ है। मैंने उसकी शिफ्टिंग के लिये

कई बार विभाग में पत्र भी भेजे हैं लेकिन आज तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं चूंकि वहां पर छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर कभी-भी अप्रिय घटना घट सकती है और ट्रांसफार्मर भवन के सामने होते हैं और हमारे बच्चे आंगन में खेलते रहते हैं। यदि ज्यादा वोल्टेज में ट्रांसफार्मर गलती से भी फट भी जायेगा तो हमारे बच्चों को जानमाल का नुकसान हो जायेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें विशेष ध्यान दे। मेरे पामगढ़ क्षेत्र में कोनारगढ़ है, जिसमें घर के ऊपर से 11 हजार वोल्ट की तार गुजरी हुई है। मैंने इसके लिये अपनी निधि से फण्ड दिया था लेकिन विभाग के द्वारा यह कहा गया कि यह नियम में नहीं है, जिस कारण वह काम रूका हुआ है। चूंकि वह घर के ऊपर से गुजरा हुआ है और वहां घनी बस्ती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन है कि वह बस्ती में एक ही घर का मामला नहीं है । यह पूरी बस्ती का मामला है अगर वह गिर जाएगा तो पूरी बस्ती के लोगों को नुकसान होगा, उनके जान-माल का नुकसान है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की जो दूसरी बड़ी समस्या है, वह अवैध रूप से रेत माफियाओं के द्वारा रेत खनन का है। मेरे क्षेत्र में नगर पंचायत शिवरीनारायण है जहां पर महानदी में रात के 10.00 बजते ही अवैध रूप से रेत का खनन किया जाता है और उसे डंपिंग करके रखा जाता है जैसे ही सुबह होती है तो उसे यह बतलाकर कि यह पहले से डंपिंग है उसे 5000 रूपये, 6000 रूपये में वसूली के रूप में बेचा जाता है। तो यह पूरा रेत माफियाओं का राज है, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। न तो विभाग के द्वारा कार्यवाही होती है और न ही किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही कोई कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन वहीं पर अगर छोटे-छोटे किसान अपने घर बनाने के लिए रेत ले जाते हैं, चूंकि वह नदी का किनारा है छोटे-छोटे गांव के लोग अपने ट्रेक्टर के माध्यम से नदी से थोड़ा बहुत रेत ले जाते हैं तो उनको पकड़कर उनके साथ कार्यवाही की जाती है, लेकिन जो बड़े धन्ना सेठ, पूंजीपति लोग हैं उनके साथ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी है कि छोटे-छोटे किसान अपने घर को बनाने के लिए अपने आंगन को सजाने के लिए थोड़ा बहुत रेत ले जाते हैं तो उनके साथ ऐसा अन्याय, अत्याचार न हो। इस ओर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन है कि आपने बजट में महाविद्लयों के लिए प्रावधान दिया है तो मेरे पामगढ़ क्षेत्र में हमारी बेटियों के लिए एक ही स्कूल, गवर्नमेंट महाविद्यालय है क्योंकि वह गरीब, मजदूर क्षेत्र है तो वहां वह इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वह पैसे खर्च करके प्राईवेट संस्थाओं में अपनी बेटियों को पढ़ा सके।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही आखिरी निवेदन है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अगर मेरे पामगढ़ में कन्या महाविद्यालय खुल जाता है तो हमारी बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारे प्रदेश में बेटियों के साथ लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, उससे पालकगण भयभीत होते हैं और वह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने में डर जाते हैं तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हमर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के अनुदान मांग बर चर्चा करके बर खड़े होए हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा विकास करत हे। चाहे युवा वर्ग होवए, चाहे मजदूर वर्ग होवए, चाहे महिला वर्ग होवए। आपमन देव हावव कि इतना सुघ्घर छत्तीसगढ़ के विकास करत हे। पूर्व में रहिस हावए भारतीय जनता पार्टी के नेता मन जो बड़े-बड़े वादा करके, सत्ता में आए रिहिस हावए, लेकिन एक भी वायदा ला पूरा नइ करिस। आप मन देखत हव कि मोर सांरगढ़ क्षेत्र में बोले रिहिस हे कि आप मन सांरगढ़ ला विधायक देवव तहान सांरगढ़ ला जिला देहौ किहिस,लेकिन सांरगढ़ ला विधायक दे दिस अउ जिला, एक बार भी नइ बोलिए कि सांरगढ़ ला जिला देबो करके। नगर में भी बोलिस कि नगर पालिका में नगर के अध्यक्ष देवव। तो हमन 100 बिस्तर अस्पताल देबव किहिस पूर्व मुख्यमंत्री रिहिस हे तेहर। ओखर बाद जो वायदा करके आए रिहिस हावए ते वायदा ला एक ठन ला भी पूरा नइ करिस। हमर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा विकास करत हे। जेमा हमन बहुत-बहुत धन्यवाद दिहौ। मेहर अउ ज्यादा नइ बोलव मोर क्षेत्र में काबर कि हमर बहुत पुराना मांग ला जइसे कि हमन जनमे नइ रहिबे तब से मांग रिहिस हे जिला के एला पूरा करिस ओकर बर बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद् दिहा, हमर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ला। अगर सांरगढ़ क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय जो दे हे एखर बर भी बहुत-बहुत धन्यवाद् दिहौ। 100 बिस्तर अस्पताल रिहिस, ओ ला भी पूरा करिस ओकर बर भी बहुत-बहुत धन्यवाद् दिहौ। साथ ही साथ जो बरमकेला क्षेत्र से हमर डोंगरी पाली आथे जेमा कि हमर उड़ीसा क्षेत्र हे, जेमा माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करे हे, ओला माननीय मुख्यमंत्री बजट में जोड़ देतिस ता बहुत कृपा होतिस। अउ हमर साथ में कोसी क्षेत्र जेमे हमर अनुसूचित जाति के लइका मन हर 20 किलोमीटर दूरिहा होथे तो सांरगढ़ में पढ़े आए जाए बर बहुत दिक्कत होथे। ता उहां भी एक ठन महाविद्यालय खोल देतिस ता हमर लइका मन शिक्षा अर्जित कर पातिस। तेखर बर हमर माननीय मुख्यमंत्री जी ला निवेदन करिहौं कि हमर सांरगढ़ क्षेत्र हा बहुत पिछड़ा हुआ हे । 15 साल ले भारतीय जनता पार्टी के सरकार रिहिस लेकिन एक भी वायदा ला पूरा नइ करिस। हमर कांग्रेस सरकार, माननीय

भूपेश बघेल जी के सरकार बहुत अच्छा विकास करत हे तो हमर माननीय मुख्यमंत्री जी ला निवेदन करिहौं। मय ज्यादा नइ बोलते हुए, अपन बात ला विराम देवत हौं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मोला बोले के समय देव, ओखर लिए आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों के विरोध में खडी हुई हूं। इसलिए विरोध में खडी हुई हूं क्योंकि सरकार का इतना बडा बजट आया, लेकिन धमतरी विधान सभा को एक रुपये का कोई भी काम नहीं दिया गया। सभी विषय आये हैं लेकिन मैं इस सदन में यह बोलना बहुत आवश्यक समझती हूं क्योकि लो-वोल्टेज की समस्या पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश में कृषि पंप के लिए ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने स्थायी पंप कनेक्शन जो बहुत सारे लंबित हैं वह तो दिये नहीं हैं। जो अस्थायी पंप कनेक्शन हैं, उनकी जो क्षमता है वह ट्रांसफार्मर उठा नहीं पाते। जब ट्रांसफार्मर खराब होते हैं तो हमारे किसान भाई फोन करते हैं कि ट्रांसफार्मर खराब है। अब सबसे ज्यादा मानसिक रूप से उनको इस पीड़ा का सामना करना पड़ता है, दो वक्त भोजन की चिंता भले नहीं है, लेकिन उनको चिंता यह है कि उनकी फसल मर रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर खराब है। ट्रांसफार्मर महीनों नहीं बदले जाते। पहले भी भाजपा की सरकार ने 15 साल काम किया, उसमें होता यह था कि विभाग में अलग-अलग क्षमता के अतिरिक्त 20-25 ट्रांसफार्मर रखे रहते थे। लेकिन यहां पर एक भी क्षमता के एक भी 20-25 ट्रांसफार्मर विभाग में नहीं रखे रहते। यह आप विभाग की गलती समझें या जो समझें। जब ट्रांसफार्मर खराब होता है, हम जब अधिकारियों से बात करते हैं कि भैया इस जगह का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है आप बदलवा दीजिए या आप नये ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करिये। वह अपने आदमी रायपुर भेजते हैं और उनका जो अधिकारी कर्मचारी रहता है वह एक हफ्ते रायपुर में पिकनिक मना लेता है और रायपुर रह जाते हैं, अपने घर की छुट्टी मनाते हैं। वह हफ्ता, 10 दिन में छुट्टी मनाकर वापिस आते हैं तब वह ट्रांसफार्मर लेकर आयेंगे। तब किसानों को बतायेंगे कि भैया ट्रांसफार्मर आ गया है। ऐसा घुमा-घुमाकर वह महीने-दो महीने में ट्रांसफार्मर मुश्किल से लगाते हैं। इसमें तो ये है कि जब प्यास लगती है तब आदमी कुआं खोदता है। इस कथन को चरितार्थ इस सरकार ने किया है। आपको ट्रांसफार्मर की व्यवस्था पहले करनी चाहिए, विभाग में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने चाहिए। इस सदन में आज दिन भर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की चर्चा हुई है। उपाध्यक्ष महोदय जी स्थिति ये है कि आपको बताऊंगी तो यकीन नहीं होगा। मैं एक कार्यक्रम में गई थी, एक महिला आरती लेकर खड़ी थी। मुझे यह लगा कि हो सकता है कि वह मुझसे मिलने आई होगी, लेकिन वह तो ट्रांसफार्मर की आरती उतारने गई थी, पटाखा फोड़ने गई थी, उसने नारियल ट्रांसफार्मर में चढ़ाया है। मुझे देखकर बहुत आश्चर्य

हुआ कि ट्रांसफार्मर कि मांग इतनी है लेकिन विभाग उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। किसान ट्रांसफार्मर खराब होता है और लग जाता है तो वह पैर छूकर धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ये तो ईद का चॉद है। ट्रांसफार्मर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, दिख गया तो बहुत अच्छी बात है वर्ना तो आप ऊपर वाले को याद करते रहिये। ये स्थिति यहां पर ट्रांसफार्मर की है। लोग सेल्फी लेकर भेजते हैं कि हमारे यहां ट्रांसफार्मर लग गया है। एक हफ्ते पहले मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि लोग फोटो लेकर भेज रहे थे, पेपरों में आ रहा था कि बरसों बाद आज हमारे यहां ट्रांसफार्मर लगा। यह उनकी खुशी झलक रही थी कि आज हमने ट्रांसफार्मर के दर्शन कर लिये हैं।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- जो 15 साल में नहीं हो पाया, वह हमारी सरकार के कार्यकाल में हो गया। आप मुख्यमंत्री जी को बधाई दो।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ट्रांसफार्मर की जो वास्तविक स्थिति है वह मैं आपको अवगत करा रही हूं। मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूं। जो वास्तविक स्थिति है उससे मैं अवगत कराना चाह रही हूं कि महिलायें इस खुशी में आरती लेकर ट्रांसफार्मर की पूजा कर रही हैं, नारियल चढ़ा रही हैं, पटाखा फोड़ रही हैं कि हमारे यहां वर्षों बाद ट्रांसफार्मर लगा है। चूंकि किसान की ये चिंता है, उसकी पीड़ा है। यदि आप विद्युत विभाग के अधिकारी से कभी किसानों के संबंध में बात कर लें तो वह अपना रोना रोते हैं, वह कहते हैं कि मेडम, क्या बतायें, सर्किट तो क्या फ्यूज के तार बदलने तक की बखत इस विभाग की नहीं है। उस विभाग में कुछ अतिरिक्त पैसे दे देने चाहिए। विद्युत के लिए आप केबल का तार बदल लें या आप चाहे फ्यूज खरीद लें, इसके लिए अतिरिक्त पैसे विभाग में रखने चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले भी अवगत कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पहले भी पत्र के माध्यम से, मौखिक रूप से अवगत कराया था। भले मैं विपक्ष की विधायक हूं लेकिन अपने क्षेत्र की समस्या, वह मेरी पीड़ा है। जो मेरे विधान सभा के लोग हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो परेशानी है वह मेरी परेशानी है। मैं पूरी जनता की बात को लेकर यहां पर आती हूं। मैं विपक्ष मे हूं इसलिए क्या मुझे काम नहीं दिया जाता, मैं विपक्ष में हूं इसलिए बजट में मेरे कामों को शामिल नहीं किया जाता। मैंने पहले ही बताया कि धमतरी में कोई भी सब-स्टेशन नहीं है। हमको पास के 10-15 कलोमीटर दूर चिटौद पर निर्भर रहना पड़ता है। जब कहीं पर लाईन चली जाती है या खराब हो जाती है तो 10 किलोमीटर की पेट्रोलिंग लगती है । तो उसमें समय भी जाया होता है और इतने स्टॉफ, कर्मचारी आपके विभाग में नहीं हैं कि वह केवल पेट्रोलिंग करते रहें। तो इस तरह की सबसे ज्यादा राजस्व नगर-निगम धमतरी में इस विभाग को प्राप्त होता है। लेकिन क्या इतनी हैसियत धमतरी की नहीं है कि वह हमको एक सब स्टेशन दे सके। हमको डी.एम.एफ. की 10 प्रतिशत की राशि बालोद से मिलती थी। अब इन्होंन नये-नये जिले बना दिये, अच्छी बात है। आपका स्थापना व्यय भी बढ़ा है। ठीक है आप मैनेज करिये,

अच्छी बात है। लेकिन हमारे हक का पैसा आप दूसरे को क्यों देंगे? हमको डी.एम.एफ. की राशि जो 10 प्रतिशत मिलती थी, आपने इसको कम करके 7 प्रतिशत कर दी। क्या उसमें हमारा अधिकार नहीं है? भले ही हम विपक्ष में हैं, पर हमारा अधिकार तो हमारा है। हम भी लाखों लोगों का दिल जीतकर यहां पर आए हैं। जतना ने हमको चुना है तो निश्चित रूप से हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। इस सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना की बात कही थी। हम झूठे वादे इसलिए बोलते हैं, क्योंकि प्रति यूनिट को बढ़ाया गया। सुरक्षा निधि के नाम पर अत्यधिक राशि जोड़कर हितग्राहियों को बिल थमाया जा रहा है। आप नहीं देंगे तो उनको धमकी दी जाती है कि तीन दिन के अंदर, पांच दिन के अंदर तुम्हारी बिजली काट दी जायेगी। यह क्या हो रहा है? आप प्रति यूनिट चार्ज बढ़ा रहे हैं और हितग्राहियों के साथ में धोखा कर रहे हैं। जो वी.सी.ए. चार्ज होता है, उसको चार वर्षों में प्रतिमाह बढ़ाया गया। हम भी हाऊस वाईफ रहे हैं। हम महिला हैं। घर की व्यवस्था कैसे बनती है, हम बहुत अच्छा से जानते हैं। हम घर में इतनी ही बिजली का उपयोग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका भी समय समाप्त हो गया। समाप्त करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- जितनी बिजली की आवश्यकता होती है, हम उतनी ही बिजली का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रति यूनिट दर घरेलू में लगातार बढ़ोत्तरी की गई, लेकिन उद्योगों से क्या विशेष स्नेह और प्रेम रहा कि उद्योगों में इन चार वर्षों में प्रति यूनिट दर घटा है। उद्योगों से प्रेम है, लेकिन जो घरेलू उपयोग करते हैं, उनसे कोई लगाव नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखना चाहती हूं। माननीय धरम भैया ने भी इसका जिक्र किया था जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब यहां पर बजट आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस बजट को पढ़ते हैं। हमको बहुत सी उम्मीदें रहती हैं। हम बहुत खुश होते हैं कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट रखा है तो हमारे लिए, हमारे विधानसभा के लिए कुछ न कुछ तो होगा। बजट में ऐसे बहुत से कार्यों का शामिल कर लिया जाता है। तो हम अपने विधानसभा में अपने जनता को बता देते हैं कि हमारा यह-यह कार्य बजट में शामिल हो गया है और उसकी समय-सीमा दो वर्ष रहती है। अब दो वर्षों में हमारा कोई भी काम स्वीकृत नहीं होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन कार्यों को करना है, उसी को स्वीकृत करिये न। बेवजह समय भी जायर होता है और हम भी गुनहगार बन जाते हैं, क्योंकि हम क्षेत्र की जनता को बता देते हैं कि यह-यह कार्य बजट में स्वीकृत हुए हैं। आपको जिस कार्य को करना है, आप विधिवत् उसी कार्य को सेलेक्ट करके उसकी स्वीकृत करके बजट में शामिल करिये। हम जनता को जबरदस्ती बता देते हैं कि हमारा यह, यह काम स्वीकृत हुआ है। अब जनता को कौन समझायें कि यह दो वर्ष के लिए है। उनको यह लगता है कि विधायक जी का कार्य स्वीकृत हो गया है और वह कहते हैं कि चलिये भूमिपूजन करेंगे। तो ऐसा धोखा, ऐसा छल हमारे साथ न करें। हमको भी जनता को जवाब देना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक

विषय खनिज विभाग पर रखना चाहती हूं कि हर क्षेत्रों में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। विशेषकर हमारे यहां जो रेत की घाटें हैं, वहां पर इतना अवैध उत्खनन हो रहा है, क्योंकि पहले ग्राम पंचायत चलाती थी, अब सरकार ने हैंडओवर ले लिया है। रायल्टी की राशि जो समय पर ग्राम पंचायतों को मिलनी चाहिए, उनको मिल नहीं पाती। जितनी गाड़िया बिना पास के, बिना रायल्टी के हैं। गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, कार्रवाई गाड़ियों पर होती हैं। खदानों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती जो अवैध रूप से चल रही हैं? उनसे विशेष संरक्षण और विशेष स्नेह खदान वालो से है?

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करें। लालजीत सिंह राठिया जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, चलना है तो नियम से चले और मैं इस अनुदान मांग का विरोध करती हूं।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री के, हमर आदरणीय भूपेश बघेल जी के अनुदान मांगों में समर्थन करते हुए अपन बात ल शुरू करत हव। माननीय मुख्यमंत्री के हमर कांग्रेस के सरकार आय के बाद छत्तीसगढ़ में हमर किसान मन म जो खुशहाली हे, युवा मन म जो खुशहाली हे। हर परिवार बर ओहर काम करे हे, जेन ल हमर छत्तीसगढ़ के जनता हर इंतजार कर रहीसे। हमर विपक्ष के साथी मन 15 साल ले सरकार म रहीन हे, लेकिन कभी किसान मन बर कभी बात ल नइ सोचीन, न करीन हे। अभी उल्टा एमन के गुरू हर झूठ बोले बर सिखा हे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आयेंगे। यही सब बात ल एमन झूठ बोल-बोल के खाली अपन बात ला रखथे अउ ऐला हमर छत्तीसगढ़ के जनता मन देखत हावएं । हमर मुख्यमंत्री जी हर पहला काम करे हे ता किसान मन के कर्जा माफ करे बर करे हे । जेमा ऐमन के व्यापारी कोचिया मन जो हे, किसान मन के पर्चा ला ले-ले के जो हे खातु निकाल ले रिहिन हे, कर्जा ले रिहिन हे । ओ कर्जा ला हमर मुख्यमंत्री जी किसान मन के सबला छूटे के काम करे हे ता हमर छत्तीसगढ के आदरणीय भूपेश बघेल जी हर करे हे । कांग्रेस के सरकार हा करे हे । अउ अतका नहीं के.सी.सी. अउ खातू-वातू, धान जतका ऋण हे ओला सब ला चुकाए के काम हमर छत्तीसगढ़ के सरकार करे हे । आज हमर किसान मन हा अतका खुशहाल हे कि आज जो हे ओमन खूब अकन के जमीन खरीदत हें, खेती-बाड़ी करत हें, रकबा ला बढ़ात हें । आज हमर सरकार हा वन अधिकार पट्टा देके गांव के किसान मन ला, ओमन के खेत मन ला मैदान करे बर, समतलीकरण करे बर जो पैसा हमर सरकार हर देत हे । आप मन देखिहा कि गांव में जब भी जइहा सबो क्षेत्र में तो जो हे पूरा किसान मन के खेत हा लहलहात हे चाहे बरसात के फसल हो, चाहे गर्मी के फसल हो ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमर गांव के किसान मन मांग के अनुसार हमर पिछले बार मोर क्षेत्र में मोर पिताजी रिहिस हे । ओहा मंत्री रिहिस हे ता उप तहसील खोले रिहिस हे तेन ला जो हे एमन के सरकार अइस ता ऐ घानी एमन बंद कर दे रिहिन हे । हमर मुख्यमंत्री जी हा हमर जिला में

गिस अउ ओला जो हे तहसहील बर घोषणा करिस अउ तहसील जो हे, हमर छाल में आज संचालित हे । हमर किसान मन जतका हमर कांग्रेस के सरकार रहिस हे ओतके कन हमर प्रदेश में हमर धान खरीदी केंद्र रहिस हे लेकिन जइसनहे हमर कांग्रेस के सरकार आये हे । धान खरीदी केंद्र, उप केंद्र खोल के किसान मन ला सुविधा पहुंचाये के काम हमर मुख्यमंत्री जी हा करे हे । कोरोनाकाल रिहिस हे, कोरोनाकाल में घला घर में सबो झन जो हे, घर में कैद होगे रिहिन हे लेकिन हमर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हा हमर कोरोनाकाल में किसान मन के खाता में पैसा डालिस । हमर मार्केट के सब झन जो हे तारीफ करत रहिन हे, हमर सरकार हा कतका कन के कर्जा माफ करे हे । कतका ट्रांसपोर्टर मन के, कतका जोन हर जो हे टैक्स पेड रहिन हे ओ सबके कर्जा ला माफ करते हुए हमर सरकार हा जो हे आज ये स्थिति में हे कि नंबर एक में जो हे दू साल ककरो कर्जा नइ ले के हमर सरकार हा करे हे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमर माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहत हंओं कि हमर इंहां 220 के.व्ही. के ट्रांसफार्मर ला भूमिपूजन करके आये हें ओ स्वीकृत होगे हे, ठेका भी होगे हे । 33 के.व्ही. के हमर सिंचरिंगा अउ टेंडानवापारा के सब-स्टेशन अउ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 100 सीट बिस्तर के हॉस्पिटल, बहुत सारा काम हमर छत्तीसगढ़ मा हमन ला दे हे । हमर विधायक निधि मन जानत हे कि हमर एक करोड़ रूपया रिहिस हे, हमर विधायक निधि मन ला क्षेत्रीय विकास निधि मा काम करे बर । हमन विपक्ष के विधायक रहे हन, हमन ला खाली 75 लाख रूपया के काम करे के आधार रिहिस हे । 25 लाख रूपया ला प्रभारी मंत्री ला अधिकार रिहिस हे । प्रभारी मंत्री हमर 25 लाख रूपया ला देवए नहीं । आज हमर मुख्यमंत्री जी हर ओ विधायक निधि ला 4 करोड़ रूपया कर दे हे जेमे 3 करोड़ रूपया ला अपन मन के विधायक मन खर्चा कर सकत हें, 1 करोड़ रूपया ला प्रभारी मंत्री हा अनुमोदन करथे ता ये विकास निधि के विकास के काम हे । हमन आदिवासी क्षेत्र ले आथन । हमर इंहां जो हे पहिली सरगुजा विकासखंड ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रीतम सिंह जी । अब समाप्त करें, बहुत लंबा समय हो जायेगा । चलिये, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमर दो ठन प्राधिकरण रहिस हे बस्तर अउ सरगुजा । जेमे अभी मध्य क्षेत्र बनाकर आदिवासी ट्राईबल क्षेत्र के देवी-देवता हमर जो हे का कथे गुड़ी मन हे अउ देवस्थल मन हे तेमन के बाउंड्री वगैरह बनाये के काम ला हमन करत हन । ये हमर आदिवासी संस्कृति जल-जंगल, जमीन के रक्षा करईया सरकार हे । बहुत अकन आदमी मन ला वन अधिकार पट्टा दे हे । हमर सरकार मा वन अधिकार पट्टा सबो ला मिलत हे अउ अभी हमर मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक गांव-गांव मा चलत हे । गांव के गरीब-दुखी मन जो हे हाट बाजार में, बस में चढ़कर जो हे ईलाज करवात हें, दवाई मिलत हे । मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना ओमन ला मिलत

हे । बहुत अकन के फायदा अभी बइगा-गुनिया सब ला पैसा हमर सरकार हा दे के काम करत हे । राजीव मितान क्लाब में गांव-गांव के मन खेलकूद, मनोरंजन बर भी बुता करत हें इस तरह से बढ़िया हमर सरकार हा काम करत हे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी में बोले बर तो बड़ अकन के बोले बर हे । आखिरी मा दू बोल ला बोले अपन बात ला समाप्त करत हौं । मोर छत्तीसगढ़ महतारी, जय होवय तोर । मोर छत्तीसगढ़ के माटी, जय होवय तोर । मोर छत्तीसगढ़ के संस्कृति, जय होवय तोर । अउ आखिरी मा मुख्यमंत्री जी बर - हमर माटी, हमर कलेवा, हमर तिहार, हम सबके हे छत्तीसगढ़िया सरकार, भूपेश बघेल भइया हमर सरकार । धन्यवाद् ।

डॉ. प्रीतम राम (लुण्ड्रा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा की कुछ बातों को रखना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए तो 15 सालों से हमारा लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र उपेक्षित था, वहां पर उन्होंने कॉलेज, एस.डी.एम.कोर्ट और चारों तरफ सड़कों का जाल फैला दिया । वे सारे कार्य संचालित हैं, इसके लिए मैं लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र की ओर से मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद् ज्ञापित करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरगुजा संभाग के दरिमा में एक एयरपोर्ट है जिसका कार्य लम्बे समय से चल रहा है लेकिन अभी तक वह शुभारंभ नहीं हो पाया है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दरिमा एयरपोर्ट का शीघ्रातिशीघ्र शुभारंभ करें । भौगोलिक दूरी के दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है । मेडिकल इमरजेंसी होने की दशा में और बिजनेस, उद्योग के विकास के लिए दरिमा एयरपोर्ट का शीघ्र शुभारंभ किया जाना आवश्यक है । उपाध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए जब मुख्यमंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र आए थे उस समय भी प्रस्ताव दिया गया था । मैं पुन: आग्रह करता हूं कि उन अविद्युतीकृत गांव हैं, पारे, टोले, मजरे बचे हैं उनको शीघ्र विद्युतीकृत कराएं । इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र के दरिमा में ही महाविद्यालय की भी मांग करता हूं । उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉक्टर साहब आपका समय हो गया है ।

डॉ. प्रीतम राम :- उद्योग के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जमीरा में एक एथेनॉल प्लांट की बात हुई थी, उसको भी देख लें यह कहां पर अटका पड़ा है । इसके लिए भी स्वीकृति प्रदान करें और आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए मेरे लखनपुर विकासखंड के कुन्नी गांव का प्रस्ताव मैंने भेजा है । माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां पर आत्मानंद स्कूल की स्वीकृति प्रदान करें । बाकी सभी बातें विस्तार से हमारे साथियों के द्वारा सदन में रखी गई हैं । छत्तीसगढ़ में अब तक विकास के जो कार्य हुए हैं निश्चित रूप से बहुत ही अद्वितीय है, कीर्तिमान् स्थापित किये हुए हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं । आपने समय दिया धन्यवाद् ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एखर बर तो कुछ बचाए ही नइ हे, नेता मानबे नइ करय कोई ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए बोलिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मध्य क्षेत्र प्राधिकरण का गठन हुआ है । पहले बस्तर और सरगुजा था । हमारे यहां के आदिवासी समाज जो मध्य क्षेत्र में रहने वाले हैं । हमको ऐसा लगा था कि मध्य क्षेत्र प्राधिकरण में उन लोगों को लाभ मिलेगा । लेकिन वे लाभ से वंचित हो गए । उसमें थोड़ी बात करके कि क्या हो सकता है । क्योंकि उनके देवगुड़ी के लिए पैसे नहीं मिलते । दूसरा कोई प्रावधान भी नहीं है कि हम उन्हें दे सकें । आखिर जब हमने मध्य क्षेत्र प्राधिकरण बनाया है तो मेरा ऐसा आग्रह था कि उनको भी लाभ मिले और कैसे मिलेगा उसका विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, नेता प्रतिपक्ष जी। दो मिनट में अपनी बात रखिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सभी साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग में अपनी बातों को रखा।

उपाध्यक्ष महोदय :- नाम नहीं है। (हंसी)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आपके जो इधर वाले हैं ना, आपका नाम ही कांट देते हैं। आप लोग नेता प्रतिपक्ष जी का नाम क्यों कांट देते हो?

श्री कुलदीप जुनेजा :- उन लोग नेता प्रतिपक्ष मानते ही नहीं हैं। जब आप खड़े होते हो, उन लोग 5 लोग बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दोनों तीनों मिलकर पूरे निपटाने के चक्कर में हो। लेकिन इतना जान लीजिए, आप लोग इस बार निपटा नहीं पाओगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- नाम नहीं था, इसलिए गलती हो गयी थी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सचेतक कौन हैं, अजय चंद्राकर। तो अजय चंद्राकर तो एखर नाम ला बिल्कुल कांटबे करही।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष बनने में उतने खुश नहीं हैं जितनी खुश वहां अजय चंद्राकर जी से उनकी सीट बदली है। क्योंकि इतने डरे रहते थे, उनका हाथ पैर बोलते-बोलते चलता था, वे बहुत घबराए रहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप लोग टोका टाकी ना करें।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, डहरिया जी, रविन्द्र चौबे जी बनने की कोशिश मत करिए। उसके लिए अक्ल लगेगी, एक दो बार और चुनाव जीतना पड़ेगा, संसदीय परंपरा प्रक्रियाओं भर में मत बोला करिए, बाकी सब विषय में अक्ल झाड़ा करिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वे हमारे वरिष्ठ हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हम रविन्द्र चौबे जी का बहुत सम्मान करते हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- हम लोग नेता प्रतिपक्ष जी का भी सम्मान करते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, ध्यान रखिएगा, चंद्राकर जी की नजर आपकी कुर्सी तरफ ज्यादा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप लोग बैठिए। मंत्री जी।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- सर, एक मिनट। चंद्राकर जी, डॉ. शिव डहरिया जी का का चीज में स्पेशलाईज्ड हे, तोला मालूम नई हे।

श्री अजय चंद्राकर :- यदि संसदीय प्रक्रिया को जानते तो आप यहां पान खाकर बैठते नहीं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा तैं गुटका खा सकत हस, ओ नई खा सकय।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान मांगों का विरोध करता हूं, कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं बहुत ही कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का दो चार बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं। कल जो घटना हुई, आप उसका वीडियो देखिए। जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही रैली में आए थे, पुलिस वालों ने किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ के उपर छोड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गोले छोड़ने के नियम हैं, पहले तो वह देखेगा कि भीड़ किधर है और खाली स्थान पर छोड़ता है। उसके पहले एलाउंस भी होता है कि हम पानी के बौछार छोड़ रहे हैं, हम आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह की घटनाएं हुई, वह अच्छा नहीं है। आप अधिकारियों को इस बारे में हिदायत दीजिए। हो सकता है कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए। यह छत्तीसगढ़ की तासीर के विपरित है। मैं आपका ध्यान दिलाने के लिए बोल रहा हूं। आप एक बार उसका पूरा वीडियो देख लीजिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है। आपके विभाग के ही जितने भी बजट पिछले बार आवंटित हुए थे, उसमें से कितना खर्च हुआ है ? सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट है उसमें आपत्ति की गयी है। विभाग में खर्च क्यों नहीं होता ? जब इस सदन ने बजट का आवंटन दिया है और खर्च नहीं कर पाना, इस प्रदेश के हित में यह शासन की अक्षमता का जीवंत प्रमाण है।

समय :

7:29 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय, यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है, वह कुप्रबंधन है। हमारा वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। अगर इस सदन ने पारित किया है आपको पैसा दिया है, आप साल डेड़ साल तक उसका उपयोग नहीं करते। मुख्यमंत्री जी, आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे, आप भेंट मुलाकात में गये। आपको दौरा करना चाहिए, अच्छी बात है। आप जब तक नीचे नहीं जाएंगे, आपको जमीनी हकीकत पता नहीं चलेगा लेकिन आप दौरे में जाते हैं तो पिछले जो दो तीन घटनाएं आपके भेंट मुलाकात दौरे के दौरान हुई। उसके बाद से जो अिधकारी आपके सामने बोलने के लिए खड़ा होता है वह प्रशिक्षित आदमी रहता है। उसको वह लोग बुलाकर 3-4 दिन तक ट्रेनिंग देते हैं। उसको 3-4 दिन तक बुलाकर ट्रेनिंग दिया जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर घुसने नहीं दिया जाता है और बोलने नहीं दिया है। कौन रामलाल है और कौन श्यामलाल है, उसी के पास माइक जाता है। इस पर आप थोड़ा सा बैन लगाइये। आप आम जनता से मिलिये।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नेता जी, दुकालू, सुकालू, सुखराम, राम-राम, सब जगह जाथे।

श्री नारायण चंदेल :- आप उनसे आराम से मिलिये, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि एडवर्स बात करेगा। सरकार के विरोध में बात करेगा, तब तो आपको जमीनी हकीकत मालूम चलेगी। यदि सभी लोग मीठा-मीठा बोलेंगे तो आप तो भ्रम में रहेंगे। आपकी आंखों में चश्मा लगाकर रखेंगे।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- नेता जी, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में 2-3 जगहों में यह प्रकरण आया है कि लोग काला झण्डा लेकर दिखाये तो उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पास बुलवाया और उनसे बात की कि आप यह बताइये कि आपको क्या समस्या है ? एक जगह लोग नारा लगा रहे थे तो उनको भी मंच में बुलवाये और उनसे भी बात की। आपने शुरू में कल की घटना की बात की तो बस में जाती हुई महिलाएं कका जिंदा हैं, बोलते हुए गईं हैं। उसका वीडियो में चल रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- मैं कहा बोल रहा हूं कि कका उसनिंदा है ? (हंसी) मैं भी तो बोल रहा हूं कि कका जिंदा हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने तो यह बात आपके ध्यान में लायी है। मुझे बोलना नहीं था क्योंकि मेरी पार्टी के सभी सदस्यों ने एक-एक करके आपके विभागों पर चर्चा की लेकिन राजा को सचेत और सतर्क करना चाहिए, हालांकि अब आपके पास समय नहीं है। इस प्रदेश में जन समस्या निवारण शिविर बंद हो गया है। पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर शिविर लगता था। 5-5, 7-7 और 10-10 गांवों के बीच में एक शिविर लगता था। पिछले 2-3 सालों से उस जन समस्या निवारण शिविर का पता नहीं है। छोटी-छोटी बातों को लेकर लोग तहसील ऑफिस आते हैं, ब्लॉक ऑफिस आते हैं। उनका पूरा समय जाया होता है और पूरा पैसा खर्चा होता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लोग समस्या निवारण शिविर लगवाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास तक आते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- खैर, वह तो मुख्यमंत्री जी की पहुंच से दूर है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन भैया के बारे में का बोलबे ? एखर बारे में बोलत रहे हस।

श्री नारायण चंदेल :- दूसरी बात यह है कि वह अपमानित होता है।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता जी, एक मिनट। उस दिन के भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि जब सदन के नेता और विपक्ष के नेता बोलते हैं तो आप उनसे अनुमति लेकर इंट्रप्ट करो। तो पहले आप उनको अनुसरण करो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, मैं उनसे अनुमति लेकर ही बात कर रहा हूं। मैं आपके नेता जी के बहुत सम्मान करथो। आप कतका करथो तेला मैं नहीं जानव लेकिन मैं ओखर बहुत सम्मान करथो।

श्री नारायण चंदेल :- लेना न, मैं जल्दी सकेले के चक्कर में हो तो ते काबर बोलत हस ?

अध्यक्ष महोदय :- सकेल भैया।

श्री नारायण चंदेल :- हम तो मुख्यमंत्री जी ला सुनना चाहत हन।

अध्यक्ष महोदय :- सब सुनना चाहत हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो जो बातें जनता के बीच में आ रही हैं, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। जन समस्या निवारण शिविर बंद है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष महोदय, कभी-कभी ऐसा होता है कि नेता जी को सुनना है करके बाकी लोग चुप हो जाते हैं। तो अब आप भी बैठ जाइये।

श्री नारायण चंदेल :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में एकल खिड़की प्रणाली है। एक खिड़की से शासन की जितनी योजनाएं हैं, वह उनके फॉर्म उपलब्ध होते हैं। वहां पर जो दो व्यक्ति रहते हैं, वह उनको बताते हैं। यदि कोई सुदूर गांव से 50-100 किलोमीटर दूर से भी आता है तो वह उनकी मदद करते हैं और उनको सहयोग करते हैं। लेकिन आप पता लगा लीजिए कि यहां पर हमारे किसी भी ऑफिस यदि कोई व्यक्ति आता है तो वह अपमानित होकर वापस जाता है। उसका किसी प्रकार से कोई काम नहीं होता है। बहुत से लोग तो इसलिए नहीं आते हैं कि ब्लॉक ऑफिस, तहसील ऑफिस, एस.डी.एम. ऑफिस जाकर कौन झंझट में फंसेगा और गांव के आदमी का इन्हीं छोटे-छोटे ऑफिसों में काम है। गांव के आदमी का किसी कलेक्टर, कमिश्नर से काम नहीं होता है। मुख्य सचिव के दरवाजे पर बहुत कम लोग आते हैं। इस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। मैं बाकी बातों पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि बाकी बातें मेरी पार्टी के सदस्यों ने की हैं। यदि कोई भी सरकार बनती है तो हम शासन को सुशासन में कैसे तब्दील करें। हम जनता के बीच में जितना ज्यादा जाएंगे, जनता जितनी हमारे नजदीक होगी, शासन और प्रशासन के नजदीक होगी तो जनता का काम सहजता, सरलता और

विनम्रता के साथ में होगा, तब जनता को लगता है कि सरकार मेरे पास में है और मैं सरकार के पास में हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। मैं प्राकृतिक आपदा से संबंधित जानकारी आपके समक्ष रखना चाहता हूं । प्राकृतिक आपदा से जो मौत होती है, उसमें सरकार 4 लाख रूपए देती है, उसकी जानकारी ले लीजिए। कोई सांप काटा, बिच्छू काटा, किसी के ऊपर गाज गिर गई तो उस गरीब परिवार को 4 लाख रूपया मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही सुनते हैं, वैसे ही दलाल सक्रिय हो जाते हैं । वहां ठेके लेने के लिए चले जाते हैं कि इसमें दो लाख हम रखेंगे और दो लाख आपके पास 8-10 दिन या 15 दिन में ले जाकर पहुंचा देंगे । ये बातें किसी सदस्य ने नहीं बोली है, जो बात मैं बोल रहा हूं । इस पर भी हमको निगरानी रखनी चाहिए । यह बात मैं आज आपको इसलिए बोल रहा हूं कि हर ब्लॉक के जन समस्या निवारण शिविर में इस प्रकार के जितने चेक हैं, जो गरीबों के लिए हैं, जो पेंशनधारियों के लिए हैं, जो प्राकृतिक आपदा से मरे हुए लोग हैं, उनका चेक ऐसे जन समस्या निवारण शिविर में वितरित होना चाहिए, ताकि उसकी आधी राशि को न लेकर भागे । इसलिए मैं आपका ध्यानाकर्षित कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन समाचार-पत्रों में पढ़ रहा था कि आपकी स्वेच्छानुदान राशि 110 करोड़ हो गई है । वह असीमित है । स्वेच्छानुदान राशि का भी सदुपयोग होना चाहिए । स्वेच्छानुदान राशि का राजनीतिकरण मत हो, मेरा आग्रह यह है । जो जरूरतमंद व्यक्ति है, वह राशि वहां तक पहुंचे चाहे कोई भी व्यक्ति हो । सभी जनता इस सरकार की है, आप सभी के मुख्यमंत्री हैं । चिह्नित करके उस राशि का वितरण न हो । हमारे जितने माननीय विधायक हैं, उन सभी के जनसम्पर्क राशि में उनकी भी वृद्धि हो जाता तो अच्छा रहता । कोई सदस्य भी गांव के दौरे में या क्षेत्र के दौरे में जाते हैं, जरूरतमंद से भेंट करते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह राशि 4 लाख से 10 लाख कर दी गई है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डी.एम.एफ. की बातें नहीं कर रहा हूं, इसकी बातें आ गई हैं । मैं रेत की बात आपके ध्यान में ला रहा हूं। मेरे जिले में एक घटना हुई । हमारे जिले में महानदी, हसदेव, लीलागर और सोन नदी है। जांजगीर में पीथमपुर और गाड़ापाली जो हसदेव का तट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरीके से जानते हैं । दो साल पहले रेत माफिया वहां के एस.डी.एम. और तहसीलदार के ऊपर रात को गाड़ी चढ़ा रहे थे । जब उनको 8-9 बजे रात को रोकने गए तो पूरे रेत घाट पर सर्च लाईट लगी थी और जेसीबी से रेत की खुदाई हो रही थी। उस नदी जी की खुदाई हो रही थी । मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि रेत माफियाओं के कारण पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं । बाहर से लोग आ गए हैं और तेजी के साथ में अपराध हो रहे हैं और नित

नये किस्म के अपराध हो रहे हैं । आप इस पर लगाम लगाईए । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रेत का जो अवैध उत्खनन हो रहा है, रेत समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे पुल और पुलिया भी कमजोर हो रहे हैं । जिस प्रकार से नदियों का चीर-हरण किया जा रहा है, वह उचित नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्लांट लगे हैं, मैं मड़वा प्लांट का उदाहरण दे देता हूं । वह मड़वा प्लांट मेरे क्षेत्र में है, वह सरकार का है और आपके अधीन है । मड़वा प्लांट में जितने भू विस्थापित हैं, उसमें सरकार का क्या एग्रीमेंट है, वह मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन भू विस्थापितों में जिनकी जमीन गई है, उनके परिवार के सदस्य, जो योग्य हैं, उनको योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। उनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए । जब वे लोग नौकरी देने की मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत रहे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमें दायर किए गए। वे कई महीने जेल में रहें। अगर उनके ऊपर फर्जी मुकदमें दायर किए गए तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप उसकी समीक्षा कराकर, उसकी मीमांसा कराकर यदि उनके ऊपर फर्जी मुकदमें लादे गये हैं तो सरकार को वापस लेना चाहिए। उनको उनका हक मिलना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कोरिया में हवाई पट्टी की घोषणा की, वह आपका पुराना क्षेत्र है। हमारा जांजगीर-चाम्पा जिला भी है, वहां रेमण्ड-लाफार्ज में पुराना हवाई पट्टी है, जो पहले विजयपथ सिंघानिया जी का था। लेकिन अभी वह मेन्टेन नहीं है। अगर सरकार चाहे तो उसको मेन्टेन कर सकती है, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। वह बिलासपुर और जांजगीर के मध्य में है। वह जांजगीर-चाम्पा जिले में है। आपको उस पर विचार करने की आवश्यकता है। वह कम खर्चे में प्रारम्भ हो सकता है। यह मैं आपको ध्याना दिलाना चाह रहा था।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के पास सामान्य प्रशासन विभाग है। हमारे जितने अच्छे अधिकारी और कर्मचारी हैं, जितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. हैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब उनसे सामान्य रूप से चर्चा होती है, जब वे किसी जिले में पोस्टिंग में जाते हैं, तो वे संशय में रहते हैं। पता नहीं कितने महीने रहेंगे। पहले कलेक्टर और एस.पी. जाते थे तो कम से कम डेढ़ साल, दो साल रहते थे। अभी तो बेचारा 2-4 महीने मे जिले को समझकर तैयार होता है और जब वह रात को सोता है, सुबह पता चलता है कि अब मैं दूसरे जिले में चला गया। इस पर थोड़ा कसावट लाने की आवश्यकता है। कोई भी अधिकारी गया है, जो अच्छा काम कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अधिकारी-कर्मचारी में जो अच्छे वर्कर हैं, वे हतोत्साहित होते हैं। बहुत से आई.ए.एस., आई.पी.एस. भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर काम करने जाना चाहते हैं। वहां पर जाना चाहते हैं, वहां सेवा देना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत सी बातें कही थी कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। आज सुबह मेरे पास विधवा महिलाएं आई थीं, जब हम विधानसभा के लिए निकल रहे थे। आप

उन विधवा महिलाओं को सुन लीजिये। उनकी क्या समस्या है, उनको क्या दु:ख है, उनका क्या दर्द है, जिन्होंने सिर मुड़वाया था। बूढ़ा तालाब के सामने धरने में बैठे 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आप किसी अधिकारी को भेज दीजिये, ये बेचारे सब मंत्री खाली हैं। (हंसी) कोई व्यक्ति चला जाये, उनकी बात सुन लें।

श्री ननकीराम कंवर :- मंत्री बेचारे नहीं हैं।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सारी बातों पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना था। लेकिन उन विधवाओं को सुन लीजिये। अगर उनको विधि सम्मत, नियमत: नियुक्ति मिल सकती है तो उनको नियुक्ति देना चाहिए। सिर्फ विधवाओं की बात नहीं है। प्रदेश में हजारों लोग हैं, जो अनुकम्पा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आवेदन लेकर खड़े हैं। कोई कलेक्टर के पास जाता है, कोई मंत्री के दरबार में जाता है। इन सारे प्रकरणों का निराकरण करिये, मेरा आपसे यही निवेदन था।

अध्यक्ष महोदय, बिजली बिल के बारे में बहुत सारी बातें आईं। लो वोल्टेज के बारे में बातें आईं। लेकिन बिजली बिल की शिकायत हर जनप्रतिनिधि के पास रोज आता है। इन्होंने तो बहुत कम बताया है, जिसका दो सौ रूपये का बिल आता है, उसका एक हजार रूपया आया है। लेकिन वर्तमान में पता नहीं कौन रीडिंग करने जाता है, कौन कम्पनी का मालिक है, आप किस-किस जिले में किसको ठेका दिए हैं। मुख्यमंत्री जी का विभाग है। लेकिन जो छोटे-छोटे गरीब परिवार हैं, हजार-दो हजार बिल नहीं आता, 20-25 हजार रूपये का बिल आता है। जब वह बिजली आफिय में लेकर जाता है, वहां पर उससे बार्गेनिंग की जाती है, वहां पर उससे मोल भाव किया जाता है, ले-देकर किसी प्रकार से, प्रकरण को निपटाता । गरीबों के साथ में यह अन्याय और अत्याचार नहीं होना चाहिये । ऐसा मेरा आग्रह है, मैं आपके अनुदान मांगों का विरोध करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी से आज्ञा लेकर थोड़ा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ । हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी जब दौरे पर गये तो मिलने नहीं दिया गया । भेंट मुलाकात में नही मिलने दिया गया । इसी से संबंधित एक किस्सा छोटा सा है । अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी कोई विचित्र आदमी भी आ जाता है । एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा के किसी आदमी को एक गरीब आदमी था, उसको पत्र दिया कि आ जाओ, हमारे दरबार में आपको ईनाम देंगे । वह रखकर गया, संतरी उसको मिलने नहीं दे रहा था । संतरी को बार-बार बताया कि राजा मेरे को चिट्ठी दिये हैं, मेरे को जाने दो, लेकिन वह जाने नहीं दिया । सौदा यह पटा कि 50-50 परशेंट ईनाम का लेंगे । वह उसके बाद अंदर गया, राजा बोला मांगो । तुमको हम बुलायें है, हम देंगे । उसने कहा कि मेरे को 10 कोड़ा मारो । राजा के किनारे जो मंत्री बैठा था, बोला मुर्ख कैसा बात कर रहा है तू । तेरे को ईनाम देंगे, अशर्फी, सोना, चांदी, वह बोला नहीं हुजूर मेरे को 10 कोड़ा ही मारो । बोले ठीक है देंगे । हो क्या गया बोले ।

क्या बताऊं हुजूर आपका चिट्ठी लेकर यहां मिलने आया था, संतरी मेरे को रोक लिया 50-50 में है तो 5 मेरे को और 5 उसको लगवाओ । फिर उसको बुलाया गया, संतरी को बताया गया, राजा साहब इनको ईनाम दिये हैं, क्या ईनाम मिलता है जानता है, नही मालूम साहब । 10 कोड़ा मिला है, 5 तू खायेगा और 5 ए खायेगा, लेकिन राजा ने आदेश दिया कि तूने मेरे बीच में आने से रोका मार इसको 10 कोड़ा बोले । पूरा उसको 10 कोड़ा लगवाया । आप भी विचार करियेगा । जनता के बीच में संतरी-फंतरी लोगों का काम नहीं होना चाहिये । अब आपका हम भाषण ध्यान से सुनेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज विभागों से संबंधित मांगों पर चर्चा में भाग लेने वाले वक्ता सर्वश्री अजय चन्द्राकर जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, श्री सौरभ सिंह जी, श्री बृहस्पत सिंह जी, श्री शिवरतन शर्मा जी, श्री शैलेश पाण्डेय जी, श्री धरमलाल कौशिक जी, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव जी, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री रामकुमार यादव जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, डॉ.विनय जायसवाल जी, श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी, श्री गुलाब कमरो जी, श्री रजनीश कुमार सिंह जी, श्रीमती इंदू बंजारे जी, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े जी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी, श्री लालजीत सिंह राठिया जी, डॉ.प्रीतम राम अंत में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, जिनके भाषण हम सब ने सुने और बड़ी कृपापूर्वक संक्षिप्त में अपना उद्बोधन समाप्त किया । इसके लिये चंदेल साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पर्ची भी आया है कि आपके पास कौन-कौन से विभाग है, उसको पढ़कर सुना दे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य प्रशासन विभाग से शुरू करता हूँ । सभी साथियों ने और नेता प्रतिपक्ष ने यह बात कही कि पहले जनदर्शन लगते थे, लोग छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर आते थे, समस्या का हल हो जाता था । जो जनदर्शन लगता था, उसका रिकार्ड हम लोगों को पता है, पिछले विधान सभा में हम लोगों ने उठाया भी था, कितने आवेदन आये, कितने का निराकरण हुआ, कितने बाकी है, वह जवाब मिलता ही नहीं था । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि छत्तीसगढ़ जनसंख्या के हिसाब से दूसरे प्रदेशों से भले ही कम है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से हमारा 9 वां बड़ा राज्य है । इस दृष्टि से हमने जितनी प्रशासनिक इकाइयां है, उसे और बढ़ाने का काम किया है। जिसमें हमने पिछली सरकार में जितनी तहसीलें थे, उसमें 90 तहसील की वृद्धि की। अभी इस बजट में भी हमने 7 नयी तहसीले घोषित की, जो कुल मिलाकर 90 होते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने 25 अनुभाग बढ़ाये। हम लोगों ने 6 जिले बढ़ाये ताकि आम जनता का प्रशासनिक इकाई से दूरी कम हो। महत्वपूर्ण यही है कि आम जनता को सुविधा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंच में हो, ताकि छोटी-छोटी समस्यायों का निराकरण करने के लिये ज्यादा दूर न जाना पड़े और इसलिये हमने यह घोषणा की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यक्षेत्र में तो तीन-तीन नये जिले बने हैं, मनेन्द्रगढ़, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और आपका

निर्वाचन क्षेत्र, सक्ती भी जिला बन गया। इस प्रकार से हमने बहुत सारी इकाइयां बढ़ाई है। जिससे आम जनता को सहूलियत हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बारे में भी सदस्यों ने बड़ी चर्चा की और नेता प्रतिपक्ष जी ने खासकर दो बार इसका उल्लेख किया कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में इस प्रकार से होता है। धर्मजीत भैया ने तो बढ़िया पुराने राजा महाराजाओं का किस्सा भी सुनाया।

श्री धर्मजीत भैया :- हंसी मजाक में।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, हंसी मजाक में क्या। वह तो वैसी है ही। बिना हनुमान जी की पूजा पाठ किये राम जी तक पहुंचा नहीं जा सकता। धर्मजीत भैया, वह तो पुरानी परंपरा है। आपने नये तरीके से बात कर दी। आज भी धर्मजीत भैया से मिलना पड़ेगा और यदि उनसे काम करवाना है तो उनके खास आदमी कौन है, उसको पकड़ो। ऐसा ही होता है ना, वह परंपरा तो चली आ रही है। लेकिन भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता से सीधा संवाद होता है। जिस एक-दो घटना के बारे में नेता प्रतिपक्ष जी ने और साथियों ने उल्लेख किया, मुझे सच में वह नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि जो परिस्थिति थी, मैं उन शब्दों को बयान नहीं कर सकता। जब वे पूरा वीडियो फूटेज देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता था। इसलिये स्वाभाविक रूप से मुझे क्रोध आया था और मुझे उस बात का दु:ख है क्योंकि केवल वह व्यक्ति नहीं है, उसको पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। लेकिन मुझे यह नहीं करना था। लेकिन उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वह बहुत ही आपत्तिजनक था, इस कारण से मुझे ऐसा करना पड़ा। बहुत सारे मामले प्रायोजित भी रहते हैं। आप लोग भी भेज देते हैं (हंसी)।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप लोग भी नहीं। आप लोग ही।

श्री भूपेश बघेल :- हां, अभी जैसे ताम्रध्वज भैया ने एक घटना बताई कि एक व्यक्ति ने कहा कि बिजली बिल बहुत अधिक आ रहा है। मैंने कहा कि बिल ले आईये, मैं देखता हूं कि कितना बिजली बिल आया है और आपका लाइन क्यों काट दी गयी है। वह लाने ही नहीं गया। जितने का बिजली बिल नहीं था, उससे ज्यादा कीमत का काला झण्डा और उससे ज्यादा गुब्बारा था। इसका मतलब ही यही है कि वह प्रायोजित था। यदि उसके पास उतने पैसे होते तो बिजली बिल पटा लेते। चूंकि उसने बिजली बिल पटाया ही नहीं इस कारण से लाइन कटी। बहुत सारे मामले प्रायोजित भी रहते हैं और बहुत सारे नये अनुभव भी आये। आम जनता से सीधे संवाद करने से बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निराकरण हुआ। आज मैं कह सकता हूं प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो अधिकांश समस्या है, उसका निपटारा हो गया। बहुत सारे निर्माण कार्य है, जो बहुत सारे सामाजिक भवन की मांग करते थे समाज के लोग। राजनीतिक लोग तो मिल लेते हैं या किसी भी दल के लोग हो, वे अपने विधायक को या पहुंच वाले जो बड़े नेता है, उसके माध्यम से सत्ता तक पहुंच जाते हैं। लेकिन समाज के लोग नहीं पहुंच पाते। उस कारण से मैंने सभी समाज के लोगों से मिलने का क्रम बनाया और जिस विधान सभा में जिस-जिस समाज के लोग

रहते हैं, वह उनसे मुलाकात भी हुई और नई जानकारी भी मिली। मुझे एक घटना याद आ रही है। हमारी सरकार ने तो 10 से 15 प्रतिशत में भूमि उपलब्ध कराने का, उसके बाद भवन निर्माण करने के लिये करोड़ो रूपये दिये हैं। एक जो महत्वपूर्ण घटना घटी है, मैं उसको साझा करना चाहता हूं। सुकमा विधान सभा की एक बात है। मैं सुकमा विधान सभा में रात रूका। वहां सब समाज के लोग आये थे। अंत में वहां जो चेम्बर के व्यापारी लोग थे, वह मुझसे मिलने आये। मैंने उनसे कहा कि पहले और अब में क्या अंतर है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा। वह सक्षम लोग थे। मैंने पूछा पहले और अब में आप क्या अंतर महसूस करते हैं। उनहोंने एक लाइन में जवाब दिया कि अब हमें रिश्ता करने में कोई तकलीफ नहीं होती (मेजों की थपथपाहट)। कितनी बड़ी बात है कि शादी बिहाव में अब हमें कोई परेशानी नहीं होती, चाहे हमारे यहां लड़का हो या लड़की हो, उसके संबंध बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। पहले यह स्थिति थी कि उन्हें रिश्ता करने में बड़ी तकलीफ होती थी, यह परिवर्तन आया है। तो यह जो हमारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, इसके माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी हुआ और हम लोगों ने लगभग 65 से अधिक विधान सभा पूरा भी कर लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथियों ने नवाचार आयोग के बारे में भी चर्चा की, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि नवाचार आयोग बनाने की जरूरत क्या है? इसमें एक सदस्य है आपने इसमें 20 लाख रूपये रखा है। हमारी सरकार ने बहुत सारे नवाचार किए। चाहे उसमें गौधन न्याय योजना की बात करें, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की बात करें, नरवा, गरूवा, घुरूवा बाड़ी के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। यहां पर माननीय सभी सदस्य हैं आज यह पानी की बात करते हैं कि नल जल योजना तो बन गई, लेकिन पानी की उपलब्धता नहीं है। यह सारी शिकायतें कर रहे हैं । आखिर जब तक के हमारे पास अण्डर ग्राउण्ड वॉटर नहीं होगा तो हम कहां से पानी उपलब्ध करा पायेंगे? आप टंकी बना लीजिए और पाईप बिछा लीजिए। आप घर-घर में टोंटी लगा लीजिए, लेकिन पानी की उपलब्धता कैसे होगी ? आज माननीय बहुत सारे सदस्यों ने एक बात कही कि खेतों में फसल सूख रहे हैं। यह बिल्कुल सही बात है यहां फसल क्यों सूख रहे हैं? क्योंकि अण्डर ग्राउण्ड वॉटर नीचे चला जा रहा है। जो पम्प है उसकी क्षमता अब उतनी नहीं रही। इस कारण से पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए हमने नरवा कार्यक्रम किया। अब उसके लिए बजट कहां है, आप कैसे कर रहे हैं ?इसके लिए हम कंवरजेन से बनाए भी। हमने पंचायत से किए, फारेस्ट विभाग से किया, उसका उपयोग भी हो रहा है और जहां-जहां हम लोगों ने किया, उसका लाभ भी दिखायी दे रहा है। हम लोग लगातार नवाचार कर रहे हैं। इसके लिए लघु वनोपज में जितने भी देखेंगे। लघु वनोपजों के साथ-साथ हमने उसके प्रसंस्करण के लिए भी खोला, जिससे संग्राहकों को ज्यादा लाभ मिल रहा है और वहां लोगों को नया रोजगार भी मिल रहा है। यहां नवाचार का बड़ा महत्व है। जब भी मेरी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होती है तो वह किसी न किसी नवाचार के बारे में चर्चा करते हैं। लोग कहते हैं कि आपको फ्रिकवेंटली कैसे बुला लेते हैं उसका

कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में जो नवाचार हो रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में यह हो रहा है (मेजों की थपथपाहट)और इसमें प्रधानमंत्री जी के बाद, नीति आयोग ने भी उल्लेख किया। जब भी व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं तब भी कोई न कोई अभी मिलेट्स के बारे में बात हुई। पिछले समय गौ-धन न्याय योजना के बारे में चर्चा हुई। तो लगातार जब भी मुलाकात होती है इस प्रकार से नवाचार के बारे में चर्चा होती है। तो हम लोगों ने यह नवाचार आयोग बनाया है। उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार और यहां की जो संपदा है, उसका सही सदुपयोग हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको वित्त विभाग के बारे में बताना चाहूंगा। वित्त विभाग में हमारी अपनी आवश्यकताएं होती हैं जिसके लिए हमने वर्ष 2023-24 के बजट में कुल 21 हजार, 788 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। इससे पूर्व वर्ष के लिए ऋण भुगतान हेतु बजट में 7 हजार 541 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया। पूर्व में लिए गए ऋणों के भारित ब्याज के अदायगी हेतु 6 हजार 684 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। राज्य के पेंशनरों के पेंशन, परिवार पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्त लाभों के भुगतान के लिए 7 हजार 384 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 1 नवबंर, 2000 से लागू की गई नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 के समस्त शासकीय सेवकों हेतु पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई। इसके फलस्वरूप भविष्य में पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु गठित पेंशन निधि में निवेश के लिए 250 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। राज्य शासन द्वारा दी जा ने वाली गारण्टी पर ऋणों के भुगतान में राज्य शासन के देयता आने की स्थिति में पुनर्भुगतान हेतु आर.बी.आई. एवम् महालेखाकार के निर्देश पर राज्य में प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया गया है। इस निधि हेतु 10 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे अजय चन्द्राकर जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही। वह बात यह है कि आपका ऋण 82 हजार करोड़ रूपए है और आपका बजट 1 लाख, 21 हजार करोड़ रूपए का है। तो यह लगभग बराबर है। उन्होंने यह बात कही थी। आप फिर से बोल लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपके दूसरे जो ऋण हैं 22, 26 हजार जो भी आंकड़ा था, उसको भी जोड़ा था और मैंने उसके बाद यह कहा था कि दोनों मिलाकर लगभग बराबर हो रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के ऋण भार को बजट से नहीं जोड़ा जाता। क्योंकि जो ऋण लिया जाता है वह 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष के लिए लिया जाता है, उसका अलग-अलग अदायगी का समय निर्धारित होता है। इसीलिए मैंने पहले पढ़कर बता दिया कि उसके ब्याज के लिए, उसके पुर्नभुगतान के लिए हमने क्या-क्या व्यवस्था की है। मैंने उस दिन भी बात रखी थी कि हमारी जो जी.एस.डी.पी. है, वह करीब 4 लाख 57 हजार 608 करोड़ की है और छत्तीसगढ़ का ऋण भार 82,125 करोड़ रुपये का है। कुल मिलाकर हमारा जो प्रतिशत है, वह 17.9 प्रतिशत है। जबकि इसी समय में आप

देखेंगे कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, हरियाणा में तो हमसे कहीं बहुत अधिक है। 20 प्रतिशत से लेकर 27 प्रतिशत तक है और भारत सरकार का तो 47 प्रतिशत है। जितना बजट है, उसका तीन गुना है। जितना इस साल बजट प्रस्तुत किया यदि उसका ऋण निकालें, मैं आपको ऋण भार बताऊं, 1 करोड़ 28 लाख 94 हजार 673 करोड़ रुपये ऋण है, जबकि आपकी जी.एस.डी.पी. 2 करोड़ 73 लाख 7 हजार 751 करोड़ रुपये है और बजट लगभग 42 लाख करोड़ रुपये है, 1 करोड़ 28 लाख 94 हजार 673 करोड़ रुपये ऋण है, तीन गुना अधिक ऋण है। ये स्थिति भारत सरकार की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कथन कि हमारा वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे थे कि वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंदर ही है। जबकि भारत सरकार के पास एक प्रश्न में लिखित उत्तर है, Shri Lalrosanga जी का प्रश्न है, उसमें भारत सरकार के वित्त मंत्री ने ये स्वीकार किया है कि हमारे एफ.आर.बी.एम. एक्ट से दोगुना हो गया है, इसलिए हम कर्मचारियों के वेतन, डी.ए. वगैरह नहीं दे पायेंगे। यह कोरोनाकाल का है। अध्यक्ष महोदय, यह लिखित उत्तर है। आप देखेंगे कि वित्तीय स्थिति किसी भी प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ की बेहतर स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि बिजली के बारे में बड़ी चर्चा हमारे साथियों ने की। ये बात बिल्कुल सही है, मुझे स्मरण आता है। डॉ. आर. सिंहदेव जी ने इसी सदन में कहा था कि जो राज्य बिजली उत्पादन करता है और खपत कम करता है वह राज्य गरीब होता है। जो राज्य बिजली उत्पादन करता है और बिजली की खपत ज्यादा करता है वह राज्य समृद्ध होता है। हमारे यहां कटौती की नहीं, सरप्लस की बात कर रहे थे। आज भी हम सरप्लस की स्थिति में हैं। हमारे यहां बिजली की कमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी कुल उत्पादन 5373 मेगावाट का है और औसत अधिकतम मांग 5217 मेगावाट की है। जितनी डिमांड है, उससे कहीं अधिक हमारे पास बिजली है। आपके समय में अधिकतम मांग 4100 मेगावाट की थी, हमारे यहां अधिकतम 5400 मेगावाट तक पहुंच गया था। बिजली की खपत लगातार बढ़ी है। यहां के किसान हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, चाहे व्यवसायी हों, उद्योगपति हों, वह लगातार जो बिजली की डिमांड कर रहे हैं उसके कारण से ये स्थिति बनी है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है 400 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह हम लोग आधी कीमत पर बिजली दे रहे हैं। इसका लाभ दिसंबर 2019 से 2022 तक के 42 लाख 20 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को 3453 करोड़ 17 लाख रुपये की रियायत हमने दी है। हम लोगों ने गौठानों में भी निर्माण किया है। हम लोग कृषि पंपों में नि:शुल्क बिजली प्रदाय कर रहे हैं। कुल कृषि पंप उपभोक्ताओं को, कुल इसमें 6 लाख 36 हजार उपभोक्ता हैं जिसमें 5 लाख 5 हजार स्थायी एवं 1 लाख 31 हजार अस्थायी पंप उपभोक्ता हैं। जो आपके समय उपभोक्ता थे, उससे यह संख्या बढ़ी है। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा विगत 04 वर्षों में 11356

करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है। वर्तमान में 6 लाख 22 हजार पंप उपभोक्ताओं को, 336 मछलीपालन उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है। इस प्रकार से जो किसान हैं, उनको लगातार हम लोग कृषि पंप उपयोग करने वाले किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। इस वर्ष भी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20,550 पंपों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 31 दिसंबर, 2023 तक के 08,283 पंप के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। शेष 12,000 पंपों के कार्य प्रगति पर है, जिसे हम लोग मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लेंगे, ऐसी हमारी योजना है। इस योजना में 4 वर्षों में लगभग 621 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ का प्रावधान था। चार वर्षों में 88,048 नग कृषि पंपों को उर्जीकृत किया गया है। इसमें वर्ष 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत 299 करोड़ का बजट अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, मैं बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के बारे में भी कहना चाहूंगा कि जो 30 यूनिट तक का खपत कर रहे थे, वह 19 लाख से अधिक परिवार थे। अब इससे 16 लाख परिवारे लाभांवित हो रहे हैं। भाई बृहस्पति ने मजराटोला विद्युतीकरण के बारे में अपने क्षेत्र के बारे में ध्यान आकर्षित किया और लगातार हम लोग मजराटोला के लिए भी प्रयासरत हैं और ज्यादा से ज्यादा उसे लाभांवित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यह प्रतिवेदन मेरे हाथ में है। उसको मैं दो लाईन पढ़ना चाहता हूं। आप स्पष्टीकरण दे देंगे, आप बता देंगे। विद्युत उत्पादन क्षमता विवरण। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 01 नवंबर, 2000 को गठित उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य में स्टेट सेक्टर में विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी। विगत 19 वर्षों में बढ़कर 3424.70 मेगावाट हो गई थी। कोरबा ताप विद्युत गृह 4x50, 2x120 मेगावाट की सभी इकाईयों को सेवानिवृत्त करने के उपरांत वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता 2978.70 मेगावाट हो गई है। स्टेट सेक्टर की वर्तमान विद्युत उत्पादन की क्षमता 2978 तापीय क्षमता, 2840 मेगावाट एवं जल विद्युत क्षमता 138 मेगावाट शामिल है। अब इसमें आप केन्द्रीय सेक्टर का जोड़कर 53 बता रहे हैं या इसी को बता रहे हैं। यह थोड़ा सा क्लियर कर दीजिये, क्योंकि जो आपकी 138 जल क्षमता है। जैसे मैंने आपको गंगरेल कहा, वह कभी 10 मेगावाट नहीं हुई। इसमें 10 मेगावाट जुड़ी है। आपके अधिकारी बैठे हैं, पूछ लीजिये। उसमें अधितकम उत्पादन 10 मेगावाट कभी नहीं रहा है। तो कृपा करके इसको क्लियर कर दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पसष्ट है कि केन्द्रीय जैसे लारा का, सीपथ का है, जो हमारा हिस्सा है, वह तो हमारा ही है। वह दूसरे का तो हो ही नहीं सकता। चूंकि बिजली बढ़ा भी है। अभी मान लीजिये उन्होंने वी.सी.ए. बढ़ाया तो उसका लोड भी तो हमको ही पड़ रहा है। यह जो 1 रूपये यूनिट बढ़ा है। वह जो कोयला बाहर से ला रहे हैं और खरीद रहे हैं तो उसका लोड जो हमको पड़ रहा है। हमारे यहां नहीं बढ़ा है, क्योंकि हमको हमारे खदानों से मिल जाता है। लेकिन भारत सरकार के निर्णय के अनुसार एन.टी.पी.सी. के जितने पावर प्लांट हैं, उनको 12 से 15 प्रतिशत बाहर से जो कोयला

है, उसको मिक्स करना है। इस कारण से जो हमारा वी.सी.ए. है, वह बढ़ा है और इस कारण से छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं का 1 रूपये यूनिट बढ़ा है, जबकि हमारा माइनस है। उनको लागत खर्च बढ़ा है तो उसको हमें लेना ही पड़ेगा। कम पड़े या ज्यादा पड़े, समझौता किसने किया, नहीं किया, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिये कि आप मड़वा की बात कर रहे थे। मड़वा में जो उत्पादन लागत लगा। यह दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा ताप विद्युत गृह है। अब वह लग गया है, उसको कुछ नहीं कर सकते। उसको भार तो लेना ही पड़ेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके समय में उत्पादन घटा है। आपने स्वयं कहा। यह मैं कहना चाहता हूं। स्टेट सेक्टर ठीक है।

श्री भूपेश बघेल :- आपने जो दूसरी बात कही कि कोरबा का जो पावर प्लांट है, उसको डिसमेंटल किया गया है। उसमें भारत सरकार की जो गाइडलाईन है, उसके हिसाब से 2020 में ही उसको खत्म कर देना था। वह अंतिम था, क्योंकि वह सबसे पुराना ताप विद्युत गृहों में से एक है पूरे देश का और उसके कारण से उसका उत्पादन लागत भी अधिक और उसमें जो परिवर्तन लाने की बात कही गयी थी जिसमें सल्फर डाईऑक्साईड है और दूसरे जो उसके सुधार के लिये वह इतना खर्चीला था तो हमारा जो उत्पादन लागत है वह बढ़ जाता । उससे अच्छा यह था कि हम नया पॉवर प्लांट लगा लें और इसलिये उसमें फैसला किया गया और केवल 25 करोड़ में कैसे उत्पादन हो जायेगा, आप यह भी कह रहे थे तो अभी हमने भारत सरकार को लिखा तो निर्देश आते-आते नवंबर हो जायेगा । हमने पत्र लिख दिया है और वहां है, वह प्रक्रिया करते-करते नवंबर बीत जायेगा, वह परमिशन मिलेगा तब तक हमारा नया सत्र आ जायेगा । चाहे विंटर सेशन की बात करें, चाहे नये सत्र की लेकिन प्रक्रिया में समय तो लगता है और इसलिये उसमें जो इस दौरान मान लो पैसा रख भी देते तो उसमें खर्चा तो होना ही नहीं है क्योंकि जब तक परमिशन नहीं आयेगी, आप आगे बढ़ नहीं सकते तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिजली की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही बहुत सारे साथी यह कह रहे थे कि प्रीपेड मीटर की बात हो रही थी । रिएम्ट डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर के बारे में साथी कह रहे थे, अभी तक केवल दो राज्यों ने ही LOI जारी किये । केवल दो ही राज्य हैं महाराष्ट्र और कोई एक राज्य है । देश में और कोई राज्य नहीं कर पाया है लेकिन दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारी जो गति है उसमें कोई कमी नहीं है, हम भी उसी रफ्तार से चल रहे हैं और निश्चित रूप से वह योजना हम लागू करेंगे, उसका लाभ जनता को मिलेगा । उसमें हम कहीं पीछे नहीं हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में भी लगातार हमारा प्रयास चल ही रहा है । उसके साथ-साथ जो साथी यह कह रहे थे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री, आपने प्रीपेड मीटर की बात की । प्रीपेड मीटर लगेगा तो जो पुराना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है उसका क्या होगा ? यह कृपापूर्वक बता दें ।

श्री भूपेश बघेल :- वह संपत्ति उसकी है वह तो वापस ही होगा । अभी जो पिछले समय अक्टूबर-नवंबर में दो महीने की सिक्योरिटी जमा रहती है । अब जिसकी खपत ज्यादा हो गयी तो उसके लिये डिमांड दे देते हैं और जिसका 2 महीने के बाद भी एवरेज बिल कम आ रहा है, यदि खपत कम हुई तो पैसा वापस भी कर देते हैं तो वह व्यावसायिक संस्था है और उस प्रकार से काम होता है और इसमें मान लो जो सिक्योरिटी का पैसा जमा है वह पैसा हितग्राहियों को वापस हो जायेगा । पैसा तो हितग्राही का ही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सब साथियों ने कहा और जो डिमांड बढ़ी है 5200-5300 मेगावाट की उस हिसाब से हम लोगों ने आवश्यकतानुसार 33/11 के.व्ही. की स्थापना के साथ-साथ 33 के.व्ही. 11 लाईन आदि के निर्माण कार्य किये जा रहे हैं और इसमें लगातार हमारी वृद्धि भी हो रही है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2023-24 में 33/11 के.व्ही. के 135 नग नये उपकेंद्र की स्थापना, 64 नये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना तथा 40 नग ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य मतलब बड़े ट्रांसफार्मर न । मैं 63 एच.पी. वाले की बात नहीं कर रहा हूं । इन 4 वर्षों में अधिकतम मांग 4160 से बढ़ाकर बढ़ गया और 5443 मेगावाट तक बढ़ा है । 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र की संख्या 1213 थी वह बढ़कर अब 1342 हो गया । वितरण ट्रांसफार्मर की संख्या 1.56 लाख से बढ़कर 2 लाख 12,000 हो गया । 33 के.व्ही. लाईन की लंबाई 21,870 किलोमीटर से बढ़कर 24,038 हो गया और 11 के.व्ही. लाईन की लंबाई 1.7 लाख किलोमीटर से बढ़कर 1.27 लाख किलोमीटर हो गया । निम्न दाब लाईन की लंबाई 1 लाख 81,000 से बढ़कर 2 लाख 18,000 किलोमीटर लंबा हो गया । उच्च दाब उपभोक्ताओं की संख्या में 2890 से बढ़कर 3546 निम्न दाब उपभोक्ताओं की संख्या 55 लाख 15,000 से बढ़कर 61 लाख 20,000 हो गया । कृषि पंप, स्थायी पंपों सहित 4 लाख 92,000 से बढ़कर 6 लाख 36,000 हो गया । बी.पी.एल. परिवारों में 19 लाख 51,000 से अब कम होकर 16 लाख हो गया इसका मतलब यह है कि उन परिवारों में बिजली की खपत बढ़ी है और इस कारण से 19 लाख 51,000 से घटकर वह 16 लाख हो गई है । इसी प्रकार से अभी कोरबा के बारे में कह रहे थे 1320 मेगावाट की स्थापना सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह की स्थापना हम लोग करेंगे। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पारेषण प्रणाली में भी काम किया है । छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमीशन कंपनी विगत 4 वर्षों में दिसम्बर 2018 से फरवरी 2023 की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि सब साथी विद्युत के मामले में बहुत चिंतित थे । इसलिए मैं इसको थोड़ा विस्तार से ले रहा हूं । छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमीशन कंपनी ने विगत 4 वर्षों में 400 के.व्ही.ए. के 01 नग उपकेन्द्र धमतरी के कुरूद में ऊर्जीकृत किया गया है । अभी तक हमारे प्रदेश में

केवल 03 थे। जब से विद्युत प्रदाय शुरू हुआ है तब से केवल 03 थे, चौथा आपके धमतरी के कुरूद में शुरू हुआ है । 220 के.व्ही.ए. के 03 नग उपकेन्द्रों को जगदलपुर, नारायणपुर एवं बिलासपुर घरदेही में ऊर्जीकृत किया गया । 132 के.व्ही.ए. के 08 नग उपकेन्द्रों को बीजापुर, उदयपुर, खैरागढ़, खरमोरा, इंदामारा, इंदागांव, माडखरोरा, सिलतरा फेस-2 में ऊर्जीकृत किया गया है । 400 के.व्ही.ए. उपकेन्द्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता 2205 एम.वी.ए. थी जो अब बढ़कर 2835 एम.वी.ए. हो गई है। 220 के.व्ही.ए. उपकेन्द्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता 7470 एम.वी.ए. थी जो बढ़कर 10100 एम.व्ही.ए. हो गई है । 132 के.व्ही.ए. उपकेन्द्र स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता 7989 एम.व्ही.ए. थी जो बढ़कर 10019 एम.व्ही.ए. हो गई है । छत्तीसगढ़ राज्य पारेषण लाईनों में विकास - 400 के.व्ही.ए. लाईनों की लम्बाई 1916 सर्किट किलोमीटर थी जो बढ़कर 1918 सर्किट किलोमीटर हो गई है । 220 के.व्ही.ए. लाईनों की लम्बाई 3602 सर्किट किलोमीटर थी जो बढ़कर 4032 सर्किट किलोमीटर हो गई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो आंकड़े बता रहे हैं, वह हम नहीं जानते । सुन रहे हैं । आपसे एक जिज्ञासा शांत करनी है । इतनी ट्रांसमीशन लाईन या पारेषण लाईन को आप बढ़ा रहे हैं । मेरे यहां के स्टेशन का भी उल्लेख किया तो छत्तीसगढ़ में आखिर लो-वोल्टेज क्यों है ? क्या आप जो लम्बाई बता रहे हैं वह पर्याप्त है या उसमें अधिक काम करने की जरूरत है, लो-वोल्टेज को कम करने के लिए और उसके लिए कोई कार्ययोजना है क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । जहां-जहां जितनी भी डिमांड हो रही है । विद्युत पम्पों की संख्या में वृद्धि हुई, निम्न दाब उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई, उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई, घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है । सभी तरफ डिमांड लगातर बढ़ी है और इसी कारण मैंने आपको बताया कि अधिकतम् 2018 के पहले 4100 मेगावाट था अब 5400 मेगावाट की हो गई है । लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से हम लोग काम करते जा रहे हैं । पूर्व मंत्री अजय जी ने जो चिंता जाहिर की उसमे बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो नए सब-स्टेशन बनेंगे उसमें 2023-24 में 09 नग उपकेन्द्र होंगे, 2024-25 में 10 और 2025-26 10 और 2026-27 में 07 नग उपकेन्द्र, कुल मिलाकर 36 की योजना आगे के लिए है । शेष जो उपकेन्द्र हैं 02 नग 400 के.व्ही.ए. धरदेही, पिथौरा, 11 नग 220 के.व्ही.ए. उपकेन्द्र यथा पाटन, दलदलसिवनी, सेमरिया, अहिवारा, राजिम, कांकेर, धर्मजयगढ़, कुम्हारी, मालदा, सारंगढ़, मुरेठी, परसतराई, बचेली, किरंदुल । 23 नग 132 के.व्ही.ए. के उपकेन्द्र यथा बैजलपुर, छावनी, अमलेश्वर, आरंग, टेमरी, मस्तूरी, मल्हार, मेटल पार्क बेतर, जनकपुर, केशकाल, सरोरा, बिलईगढ़, उरला कालोनी, चोटिया, अर्जुनी, रायगढ़, मेडिकल कॉलेज बिल्मी, बेलतरा, उसलापुर, जेवरा सिरसा, जेवरासिरसा, महाराजपुर, अंडा, जामगांव(आर), तरकेला के कार्य प्रस्तावित हैं। ये नये उपकेन्द्र खुलने हैं उसकी कार्ययोजना बनी हुई क्योंकि लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है । अब किसानों की संख्या भी बढ़ती जा

रही है तो पम्पों की संख्या भी बढ़ती जा रही है । डिमांड भी बढेगी, औद्योगिक विकास हो रहा है तो उसके लिए भी होगा। लोगों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि होने के कारण अब लोग पंखा, कूलर, ए.सी. इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। घरेलू स्तर पर खपत बढ़ता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों ने जनसंपर्क के बारे में बड़ी चर्चा की और जनसंपर्क विभाग को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आजकल वह गोदी मीडिया बड़ा प्रचलित हो गया है। मीडियाकर्मियों के बारे में बात हुई, साथ ही हमारे साथियों ने यह भी चिंता की कि अधिमान्यता प्राप्त कितने थे और उसको क्या-क्या लाभ मिलेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सरलीकरण किया। पहले तो शहरों में जो बड़े हेड ऑफिस है, वहीं के पत्रकारों को अधिमान्यता मिलती थी और अभी तक लगभग 400 थे लेकिन इन चार वर्षों में जब से सरलीकरण किया है, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और 600 तक बढ़ गया है। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वह मिल सके। पत्रकारों की जीवन बड़ी कठिनाईपूर्ण होती है। अजय जी ने, हमारे सभी साथियों ने बड़ी चिंता की और इस कारण से हमने सेवानिवृत्त पत्रकारों को जो जीवन बसर कर सके, जो 62 वर्ष की अर्हता थी, उसे घटाकर 10 वर्ष किया और सम्मान निधि 5 हजार बढ़ाकर 10 हजार रूपए किया। साथ ही उनके ईलाज के लिए भी हमने वृद्धि की। अब तो जो भवन बनाएंगे, उसके लोन में भी हम लोगों ने 50 लाख रूपए की व्यवस्था की है। हालांकि पत्रकार साथी कह रहे थे, 50 लाख में क्या होगा ? लेकिन यह टोकन मनी है, आप जैसे-जैसे मकान बनाएंगे, मकान एक दिन में तो बनना नहीं है। ब्याज का मीटर तो बाद में घूमेगा, जब आप ई.एम.आई. भरेंगे। उस समय उसकी कार्ययोजना आपके साथ बैठकर तैयार की जाएगी और उसके हिसाब से आपको अनुदान दिया जाएगा। उसी प्रकार से पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में भी चिंता जाहिर कर रहे थे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसी सत्र में वह आयेगा और उसमें पत्रकार कानून भी बनेगा। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए बजट के बारे में मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप लोगों ने जितना फोटो छपवाया है ना, उसका पेमेंट नहीं हुआ है। कल भी एक पत्रकार संपादक मेरे पास आए थे। वह पुराना पेमेंट बचा ही है। 160 करोड़ का बजट था और 400 करोड़ खर्च कर दिए थे।

श्री अजय चंद्राकर :- यह सब कोशिश के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी जो छवि बन रही है, उसको लेकर चिंतित हूं। मैं तो आपकी छवि का विक्ट्रीम हुड करके नाम लिया हूं।

श्री भूपेश बघेल :- अब भैया वह अंग्रेजी या तो महाराज साहब समझेंगे या अमरजीत भाई समझेंगे। (हंसी) देखिए ऐसा है कि यदि छत्तीसगढ़ की हित में कोई बात हो तो मुझे मांगने में कोई तकलीफ नहीं है और उसके लिए लड़ना पड़े तो उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए लड़िए तो लोग आपको शाबाशी देंगे, धन्यवाद देंगे। बस यही ज्यादा बढ़ रहा है। (व्यवधान)

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- पैसा को देवेन्द्र पाण्डे रख लिया है।

श्री ननकीराम कंवर :- आप चिंतित मत होईये। मेरे पास बहुत सारे प्रकरण हैं। मैं कल बोलूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल खिलाफ में हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, जहां भी शिकायत हो रही है, तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी गड़बड़ियां हो रही है, उसकी जांच भी करा रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष जी, एक मिनट। इसीलिए आपके अधिकारी जेल जा रहे हैं। वह भ्रष्टाचार के कारण है।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल सही बात है।

श्री ननकीराम कंवर :- आपके चीफ सेक्रेटरी के पास दिल्ली से पत्र आया है कि शासन और प्रशासन इसमें दोनों ही इन्वाल्व हैं। इसलिए उसमें कार्रवाई करना चाहिए। इसमें कार्रवाई करवा दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपको अपनी एजेंसी पर विश्वास नहीं है ?

श्री ननकीराम कंवर :- यदि मुझे विश्वास होता तो मैं क्यों आता? (हंसी)

सुश्री शकुंतला साहू :- आप उसको भी बता दीजिए कि डॉ. मैडम कौन हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- कंवर साहब, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं है। मैंने कहा कि।

श्री अमरजीत भगत :- पिछली सरकार में भी तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी।

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, मुख्यमंत्री जी खड़े हैं।

श्री अमरजीत भगत :- हां, हम आपको उसी बात को याद दिला रहे हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- आप चिंता मत कीजिए। अभी आ रहे हैं बहुत सारे लोग जाएंगे।

श्री अमरजीत भगत :- अमिताभ बच्चन जी, आप सुनिये। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके समय में भी आप अपराध को रोकने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन आपकी तो चलती ही नहीं थी।

श्री ननकीराम कंवर :- चलती थी तभी तो मेरे कारण अपराध में कमी आई थी। आप यह क्यों भूल रहे हैं ? मैं आपको कल बताऊंगा कि कहां-कहां ठीक किया था।

श्री भूपेश बघेल :- कंवर दादा, आप बैठिये। आप बहुत अच्छा करते थे। जब आप मंत्री थे तो आप सीधे दुकानों में पहुंच जाते थे (हंसी)

श्री ननकीराम कंवर :- यदि आप ऐसा करेंगे तो अपराध में कमी हो जाएगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह सीधे ढाबा में भी पहुंच जाते थे।

श्री ननकीराम कंवर :- आपकी बात तो कोई मानता नहीं है। आपकी बात तो न कोई मंत्री मानता है और न कोई अधिकारी मानता है। आप क्या बात कर रहे हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- आप सुनिये तो, आप बुजुर्ग आदमी को छोडेंगे। (हंसी) हां, अब ये इनको छेड़ने के लिए खड़े हो गये। अब आप इनको छेड़ोगे ही।

श्री कवासी लखमा :- आप इनको क्यों छेड़ोगे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, लेकिन ननकीराम जी ठीक बोल रहे हैं। क्या है कि जब वह दरवाजा नहीं खोलते हैं तो वह सीढ़ी लगाकर रात को 12 बजे उनकी फैक्ट्री में उतर जाते हैं। लखमा जी यह अच्छा काम करते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- कौशिक साहब भी पीछे से जाते थे।...(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धरम भैया, जब यह गृहमंत्री थे तो यह दारू पकड़ने गये थे।

श्री बृहस्पत सिंह :- धरम भैया, आप।...(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ए गृहमंत्री रीहिस तो एला ढाबा वाले तक कुदाए रीहिस। ए दारू पकड़े बर ढाबा में पहुंच गे रीहिस अऊ एक जगह बेलोरो में पकड़े बर गे रीहिस हे तो बेलोरो वाले एला पकड़ लीस अऊ गृहमंत्री ला 2 किलोमीटर तक घिल्लावत लेगीस हे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- कवासी लखमा जी, दीज इज...(व्यवधान)

श्री ननकीराम कंवर :- असत्य बोलने से काम नहीं चलेगा। आप सच बोलिये और जो सही है उसको बोलिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पेपर में तको छपे रीहिस हे। काली लाके दिखा भी देहुं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कंवर साहब ने एक बात कही कि जो अधिकारी गलत किये हैं, वह आज जेल में हैं। यह बिल्कुल सही बात है। जो गलत किये हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जांच तो हो जाये और जांच की रिपोर्ट तो आ जाए। आज तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। आप जून में कार्रवाई कर रहे थे। मैं आपको इस सदन में कह रहा हूं कि अगले जून तक भी उस जांच की फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो पाएगी और चालान प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। आप इतने जगहों में छापा मार रहे हैं लेकिन क्या आपको वहां पर कुछ मिल रहा है ? जिसके पास मिलना था, मिल गया, आप पकड़ लिये और आप उनको जेल भी भेज दिये। आपने अच्छा किया। लेकिन इसकी फाइनल रिपोर्ट कब आएगी और आपकी जांच पूरी कब होगी ? क्योंकि आपको जांच में इन्ट्रेस्ट ही नहीं है। यदि आपको जांच में इन्ट्रेस्ट होता तो जून से लेकर अभी तक, अभी मार्च आ गया और अभी जून आने में 3-4 महीने और बचे हैं। साल भर बीत जाएगा लेकिन वह जांच पूरी नहीं होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह अभी भी नहीं होगा। वह अगले लोकसभा चुनाव तक चलेगा क्योंकि आपको जांच करने में इन्ट्रेस्ट हीं नहीं है आपको तो बदनाम करने में इन्ट्रेस्ट है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग सब साथी चौबे जी, महाराजा साहब, लखमा दादी जी, अमरजीत जी, बृहस्पत जी, हम सब झारखंड गये थे। जैसे ही हम वहां से आये तो सबसे पहले आई.टी. का छापा पड़ा। फिर हम लोग असम गये, वहां से लौटे नहीं थे कि फिर छापा पड़ गया। उत्तर प्रदेश गये तो 2-2 बार छापा पड़ गया। हिमाचल प्रदेश गये तो फिर छापा पड़ गया। अब हम अधिवेशन करा दिये तो भी छापा पड़ गया। क्या अधिवेशन नहीं होना चाहिए ? आप कैसे करा लेंगे ? आप कार्रवाई करें, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार में फाइलों में पेपर नहीं होते थे, आपकी सरकार में फाइलों में नोट बरसते थे। शासकीय कार्यालयों में 3 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जप्त की गई। डायरी भी जप्त हुए। पेश भी हुए लेकिन आज तक कौन सी.एम. मैडम और सी.एम. सर कौन हैं, यह नहीं बता पाये। (शेम-शेम की आवाज) ई.डी. जांच कर रही है। यह तो ई.डी. के पास है तो वह इसका पता क्यों नहीं लगा पा रही है ? ई.डी. नॉन की पूरी जांच कर रही है तो उसमें गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं ? छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रूपये की चिटफंड कंपनियां हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास किये। पूरे देश में हम पहले हैं जिन्होंने 600 से अधिक डायरेक्टरों को जेल भेज दिया और उनको जेल ही नहीं भेजा बल्कि उनसे संपत्ति कुर्क किये, कोर्ट से पारित भी कराए, कोर्ट में पुट-अप किये, कोर्ट से आदेश हुआ, उसके बाद वहां से नीलामी हुई और नीलामी होने के बाद पैसा वापस किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं लगता । क्योंकि यह हजारों करोड़ का मामला है। हम लोग तो 100 करोड़ रूपए तक भी नहीं पहुंच पाये हैं । तब मैंने पत्र लिखा। E.D. तो पहले वित्त विभाग के अधीन होती थी, लेकिन अब वह H.M. के पास है । मैंने H.M. को पत्र लिखा कि सही मायने में मनी लान्ड्रिंग का केस यह है और इसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जांच शुरू नहीं हुई । फिर मैंने Enforcement Director को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है । गरीब लोगों का पैसा है, वहां कार्रवाई नहीं कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आज क्या स्थिति बन रही है ? आज आप सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, दबाव में ला रहे हैं । आपके जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि न्यायालय विपक्ष की भूमिका न निभाए और रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसे काउन्टर करते हैं । इसी छत्तीसगढ़ में जो एन.आई.ए. कोर्ट के जस्टिस तेंदूलकर हैं, उनके घर में नक्सलियों का पर्चा फेंका गया, उसके घर के आंगन में सुतली बम फोड़ा गया । उन्होंने आदेश किया था कि वह जो नक्सली नेता है, जिसने सरेंडर किया है, जो आंध्रप्रदेश की जेल में है, उससे एन.आई.ए. ने बयान क्यों नहीं लिया ? यह उन्होंने आदेश किया था, उसका बयान आजतक नहीं हुआ और उसका ट्रांसफर हो गया । आज जो लोग कहते हैं कि सबको दबाव में रखे हैं, उसका उदाहरण देता हूं । कनार्टक में विधायक का लड़का 40 लाख घूस लेते पकड़ा गया और विधायक के घर में 8 करोड़ रूपए मिलते हैं और उसको अग्रिम जमानत मिल जाती है । यह स्थिति है । आप कार्रवाई करिए, आपको कौन रोक रहा है, लेकिन दुर्भावना से मत करिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह जी कोयला के बारे में बोल रहे थे, वह मैं आपको बताना चाहूंगा । जितनी कोयला खदानें हैं, उसमें से अधिकांश खदानें तो भारत सरकार के पास है, एस.ई.सी.एल. के पास है, एक खदान सारडा के पास है और एक खदान जिंदल के पास है । दो और खदानें चल रही हैं, वह छत्तीसगढ़ सरकार का है और दूसरा राजस्थान का है । इतने ही खदानें चल रही हैं । अब यदि एस.ई.सी.एल. से चोरी हो रही है, वहां आपकी केन्द्रीय एजेंसी तैनात है और यदि वहां से कोयला चोरी होता है तो E.D. एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों और वहां के सुरक्षा अधिकारियों के यहां छापा क्यों नहीं डालती ? यह तो बाहर में हैं, जो छूट-पुट पकड़ रहे हैं और 52 खदानों से जो चोरियां हो रही हैं, उसकी जांच कौन करेगा ?

(माननीय सदस्य श्री ननकीराम कंवर के खड़े होने पर)

श्री भूपेश बघेल :- आप बैठिए तो ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोला कोयला के बारे में जानकारी नहीं हे, तै ह जबरदस्ती काबर खड़े होवथस ।

श्री ननकीराम कंवर :- तोर बर नहीं खड़े होवथौं गा । आप नहीं सुनेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- काका सुनिए । इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक वाला जो नार्को टेस्ट हुआ था, आपने उसका वीडियो देखा है ? उसको भी देख लीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब विपक्ष के साथी बोलते हैं कि मेन पावर से आप परमिट जारी कर रहे हैं । मैं इस सदन के माध्यम से आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि केवल ई परमिट जारी होता है । वर्ष 2019-20 का आप देख लें, 1570 लाख टन उत्पादन हुआ और हमको 2337 करोड़ रूपए रायल्टी मिली । 2020-21 में 1584 लाख टन उत्पादन हुआ, लगभग थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उसमें 2356 करोड़ रूपए रायल्टी मिली । 2020-21 में 1541 लाख टन उत्पादन हुआ, जिसमें हमें 2524 करोड़ रूपए रायल्टी मिली । अभी जनवरी तक 1241 लाख टन उत्पादन हुआ है, उसमें से 2428 करोड़ रूपए हमें रायल्टी मिली है। रायल्टी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि 2014 से तय हुआ था कि हर तीन साले में आपको रायल्टी बढ़ानी है । यदि तीन साल में रिव्यू कर लेते तो तीन-तीन साल में कितना हो गया ? सन् 2014 से लेकर आज 2023 चल रहा है, 9 साल हो गए। तीन बार रायल्टी बढ़ती तो हमारा कितना पैसा आता । आपको दबाव बनाना है तो वहां बनाईए न और कार्रवाई करना है तो अंदर में करिए, जहां से निकल रहा है, वहां करिए । वहां कार्यवाही क्यों नहीं करते ? जहां से निकल रहा है, वहां कार्यवाही करिये। उसको किसने रोका है ? लेकिन आपकी नीयत तो सिर्फ बदनाम करना है। उसके अलावा कोई कहानी नहीं है। क्योकि स्थिति यह है कि भा.ज.पा. के नेता पहले बयान जारी करते हैं और ई.डी. की जो प्रेस विज्ञप्ति है, वह बाद में जारी होता है और उसमें एक शब्द का भी हेरफेर नहीं होता है। (शेम-शेम की आवाजें) तो आप ही लोग डायरेक्शन दे रहे हैं तो उधर भी चल दीजिये

कि क्यों ऐसा हो रहा है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोयले का 85 प्रतिशत उत्पादन एस.ई.सी.एल. के पास है, 64 में से 55 खदान एस.ई.सी.एल. के पास है। वहां उनके पास सारे अधिकारी हैं। हमारे पास ऑनलाईन ही व्यवस्था है। इसमें कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सी.एम.डी.सी., एन.एम.डी.सी. पर आ जाता हूं। बहुत बातें आईं। तो आपने ही सी.एम.डी.सी. और एन.एम.डी.सी. ज्वाईंट वेंचर बनाया। चेयरमेन हमारे शिवरतन जी थे। एन.सी.एल. का गठन हुआ। बैठक हुई। हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा लौह खनिज उत्पादक है तो वह एन.एम.डी.सी. है और एन.एम.डी.सी. उत्पादक होते हुए भी वही खनन करता है। देश में सबसे ज्यादा मशीनें उसी के पास है। उसके बावजूद एम.डी.ओ. करो तो सौरभ भाई, एम.डी.ओ. वाला जो शब्द है, वह सन् 2014 के बाद आया। पहले एन.बी.ओ. नहीं था। ये एम.डी.ओ. उसी समय की खोज है। उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष जी गये थे। उन्होंने सहमति दी कि अब एन.एम.डी.सी. मत खोदे, प्रायवेट प्लेयर को ले आओ। आखिर बैलाडीला में विरोध क्यों हो रहा है ? सी.एम.डी.सी., एन.एम.डी.सी. जो एन.सी.एल बना। जैसे आदिवासी सुने कि यह प्रायवेट प्लेयर को जा रहा है, तब विरोध में खड़े हुए। उसके पहले विरोध में नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो कह रहे हैं, आपने जो सी.एम.डी.सी. का एम.डी.ओ., एन.सी.एल. को नियुक्त किया, उसमें लौह अयस्क का प्रति टन जो हुआ, वह 789 रूपया प्रति टन खुदाई चार्ज था। इसके बाद हमारी सरकार में हुआ, आप आरीडोंगरी के बारे में आप कह रहे है, हमने वहां एम.डी.ओ. नियुक्त किया है, उसका 630 रूपया प्रतिटन है। आप 5 साल पहले 789 रूपया प्रतिटन तय किये थे और आपके 4 साल बाद 630 रूपया किये। तो हमने पैसा बचाया या आपने बचाया ? आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। इनकी यह स्थिति है। केवल आरोप लगाना है, कहकर आरोप लगाये, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। इस सदन ने आपको अवसर दिया है तो निश्चित रूप से आप अपनी बात रखें। लेकिन सदन में असत्य जानकारी ना रखें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, विमानन विभाग, हम लोग बहुत सारी बातें सुने थे। हवाई चप्पल पहनने वाले अब हवाई जहाज में उड़ेंगे। जगदलपुर का एयरपोर्ट भी शुरू हुआ, बिलासपुर का एयरपोर्ट भी शुरू हुआ। लेकिन अब जो शुरू हुआ तो बिलासपुर एयरपोर्ट भी चल रहा है और जगदलपुर एयरपोर्ट भी चल रहा है। डिमाण्ड आ रही है कि इसका और विस्तार किया जाये। हम बिलकुल सहमत हैं। हमारी लगातार कोशिश है, हम पीछे नहीं हैं। जगदलपुर से दिल्ली है, वह केवल पैरामिलेट्री फोर्सेस के लिए है। हम तो डिमाण्ड किए हैं कि यहां से आम नागरिकों के लिए भी शुरू हो जाये। लेकिन उसमें निर्णय हो जाये, तो बहुत अच्छा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भईया और माननीय सभी सदस्यों ने जो बिलासपुर एयरपोर्ट के बारे में बातें कही, उसमें हमने 45 करोड़ रूपये की स्वीकृति दे दी है। एयरपोर्ट का विकास 3-सी से

बढ़ाकर 4-सी श्रेणी में किया जा रहा है। उसके लिए भी जो आवश्यक राशि थी, हमने उसको दे दी है। उसमें लाइटनिंग वगैरह का काम किया जा रहा है। उसके लिए 22 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं और 10 करोड़ रूपये जारी भी कर दिया है। अम्बिकापुर एयरपोर्ट को 3-सी श्रेणी में विकसित करने के लिए 48 करोड़ रूपये की स्वीकृति दे दी है, जिसमें 35 करोड़ रूपये जारी भी कर दिये हैं । अब एअरपोर्ट के लायसेंस हेतु डीजीसीए से आयोजन जमा किया जा चुका है । प्रदेश के अधोसंरचना विकास के लिये बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टा, कोरबा में हवाई पट्टा, व्यवसायिक हवाई अड्डा के रूप में करने के प्रारंभिक बजट में हम लोगो ने 4 करोड़ करने का प्रावधान किया है । हमारी कोशिश यही है कि अब उसके लिये आप पूछ रहे थे, मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर जो रक्षा मंत्री है, उससे मैंने निवेदन भी कर लिया है, चिट्ठी भी लिखा है कि हमको जमीन दे दें, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हमारे सांसद जो हैं, प्रभावशाली हैं, उनका भी आप लोग उपयोग करें । वह जमीन हमको मिल जाये, निश्चित रूप से उनका रन वे भी बढ़ाया जा सकेगा और उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, यहां कार्गो हब के लिये हम लोगों ने लगातार चिट्ठी लिखे हैं । अभी एच.एम. महोदय की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्र की जो बैठक हुई, उसमें मैंने प्रमुखता से बात उठाई थी, पूछा गया कि आपके यहां चुनाव कब है, मैं बोला अक्टूबर नवम्बर में है, अक्टूबर नवम्बर में तो नही मिलेगा, उसके बाद मिलने की गुंजाईश बनी है । उसको भी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि उससे अर्थव्यवस्था, व्यापार, बढ़ने के लिये बहुत ही जरूरी है । सरकार भी यहीं रहेगी । अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में लगातार 11 प्रकार की परियोजना का नाम इस प्रकार से है । मुख्यमंत्री समीक्षा बिल नेक्सट परियोजना, स्वान परियोजना, डिजिटल शासन की स्थापना, ई जिला परियोजना, स्टेट डाटा सेंटर, एकीकृत ई प्रोक्यूमेंट परियोजना, इक्वीलेंटर एक्सीलरेटर संस्थान, वाई फाई सिटी योजना, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना, छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबन्धन योजना, इस प्रकार से लगातार काम चल रहे हैं । आजकल तो इलेक्ट्रानिक और सूचना युग है, इसमें सारी बातें मैंने कही है और कोशिश की है, सभी साथियों का जवाब दे सकूं और अपने विभाग की भी जानकारी सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को दे सकूं । माननीय सदस्यों ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, एक रायपुर शहर में अंडर ग्राऊंड केबल के लिये स्मार्ट सिटी से 100 करोड़ का प्रोविजन करकर सीएसईबी को दे दिया । पिछले 8 सालों से यह प्रोजेक्ट रूका हुआ है, उसके कारण रायपुर शहर में पूरा एकदम मकड़जाल तारों का बिछा हुआ है, मैं चाहूंगा कि रायपुर सिटी के प्रमुख सड़कों पर अंडर ग्राउंड केबल का काम, उसके लिये पैसे भी स्मार्ट सिटी से दे रहे हैं, फिर भी वह काम नहीं हो रहा है । सीएसईबी को यह काम करना है । उसको आप करवा देंगे तो राजधानी के लिये बहुत बड़ा काम होगा ।

श्री भूपेश बघेल :- मोहन भईया, बता ही दिया है कि 8 साल से है, 3 साल तो आपने जोड़ ही लिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 8 साल और बचे है ।

श्री भूपेश बघेल :- उसमें परीक्षण कर लेते हैं । उसके बाद फिर फैसला लेंगे। आपने समय दिया अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- लगे हाथ बिलासपुर भी जोड़ लीजिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका और हमारा आज हैट्रिक हो गया । बजट भाषण, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और आपका विभाग, दोनों का हैट्रिक हो गया, बहुत हो गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी बराबरी कर रहे हैं, संभलकर रहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1,2,6,60,12,25,32,71, एवं 65 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुये।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिये - पांच सौ उन्नीस करोड़, बयासी लाख, पचपन हजार रूपये,

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये - चार सौ इकतीस करोड़, सत्तर लाख, आठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिये - सात हजार पांच सौ अन्ठावन करोड, तेईस लाख, सोलह हजार रूपये,

मांग संख्या – 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिये – दो सौ आठ करोड, पैंसठ लाख रूपये,

मांग संख्या - 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन हजार चार सौ सन्तावन करोड़, अठाईस लाख, उनचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - छः सौ चौवन करोड़, सत्रह लाख, इक्कीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 32 जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये - पांच सौ निन्यानबे करोड़, सैंतीस लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये - एक सौ छयालिस करोड़, बयासी लाख, अड़सठ हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिये - एक सौ अठाईस करोड़, छियानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में माननीय भूपेश बघेल जी के मांगों के लिये ढाई घण्टे निर्धारित थे। इसके विरूद्ध इसके विपरित इस पर 7 घण्टे 48 मिनट की चर्चा हुई है। जिसमें कांग्रेस पार्टी के 2 घण्टे 13 मिनट, भाजपा के 3 घण्टे 37 मिनट और अन्य विपक्षी दलों के 63 मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण लगभग 54 मिनट तक था और कुल समय 7 घण्टे 48 मिनट लगे हैं। आज की कार्यसूची में आपके विभाग पर चर्चा प्रस्तावित था। यदि आप लोग की अनुमति हो और सदन की सहमति हो तो चर्चा प्रारंभ की जाये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, आप 8 घण्टे बता भी रहे हैं और चर्चा के लिये भी बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो 8.00 ही बजे हैं। 12 बजे तक खत्म हो जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, 9.00 बज गये।

अध्यक्ष महोदय :- अभी 9.00 बजे है। 12.00, 1.00 बजे तक खत्म हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 17 मार्च, 2023 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(8 बजकर 48 मिनट पर विधान सभा शुक्रवार दिनांक 17 मार्च, 2023 (फाल्गुन 26, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 16 मार्च, 2023